IUC ACADEMY

INCLUSIVE UNIVERSAL CAREERS ACADEMY

Learn. Prepare. Progress. • www.iucacademy.com

IUC अकादमी नोट्स

संपूर्ण
पाठ्यक्रम • विस्तृत व्याख्या • तुलनात्मक सारणियाँ • अभ्यास प्रश्न

संपूर्ण बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा जागरूकता अध्ययन नोट्स

COMPLETE BANKING, FINANCIAL & INSURANCE AWARENESS Study Notes

IBPS PO/Clerk/RRB, SBI PO/Clerk, RBI Grade B/Assistant, NABARD, LIC AAO, GIC एवं JAIIB/CAIIB के लिए RBI मौद्रिक नीति, बैंकिंग इतिहास, PSL, NPA, Basel-III, SARFAESI, NPCI डिजिटल भुगतान, मुद्रा/पूंजी बाजार एवं बीमा सिद्धांत

विषयवार परीक्षा प्रश्न भार विभाजन (%)

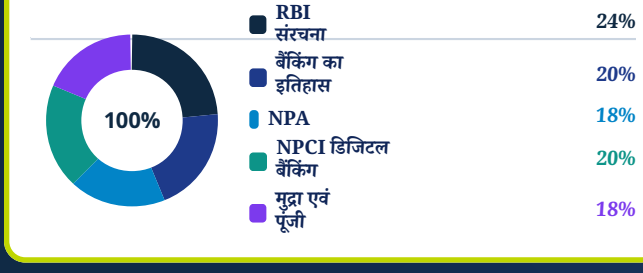

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का रुझान

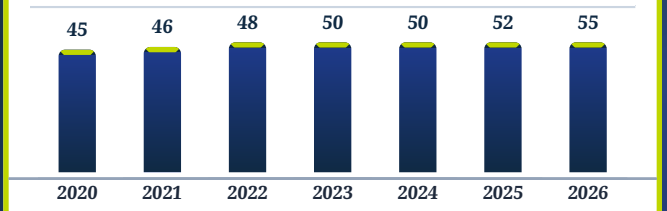

लक्षित प्रतियोगी, प्रवेश एवं विभागीय परीक्षाएँ (Target Exams Coverage)

IBPS PO/Clerk/SO/RRB • SBI PO/Clerk • RBI Grade B & Assistant • NABARD • LIC AAO/ADO • NIACL • JAIIB/CAIIB

इस पुस्तक के प्रमुख खंड एवं परीक्षा प्रश्न भार (%)

- RBI संरचना, मौद्रिक नीति (Repo, Reverse Repo, SDF, MSF, CRR, SLR) (24%)
- बैंकिंग का इतिहास, राष्ट्रीयकरण, RRB, Small Finance, Payments Bank व PSL (20%)
- NPA, Basel-III मानक, SARFAESI 2002, IBC 2016 एवं NARCL (बैड बैंक) (18%)
- NPCI डिजिटल बैंकिंग (UPI, UPI Lite, IMPS, NEFT, RTGS, RuPay, CBDC) (20%)
- मुद्रा एवं पूंजी बाजार (SEBI) तथा बीमा जागरूकता (IRDAI, LIC, योजनाएँ) (18%)

संपूर्ण पाठ्यक्रम
NCERT एवं मानक स्रोत

तुलनात्मक सारणियाँ
प्रवाह आरेख व चार्ट

स्मृति सूत्र
त्वरित रिवीजन बिंदु

अभ्यास प्रश्न
व्याख्या सहित हल

आमुख, परीक्षा भार विश्लेषण एवं अध्ययन रणनीति — संपूर्ण बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा जागरूकता अध्ययन नोट्स

IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com) • आधिकारिक अध्ययन नोट्स

प्रिय अभ्यर्थियों,

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न में अवधारणात्मक स्पष्टता और सटीक तथ्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से **IUC Academy (www.iucacademy.com)** द्वारा इन विस्तृत अध्ययन नोट्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्याय के साथ **तुलनात्मक सारणियाँ, प्रवाह आरेख, महत्वपूर्ण सूत्र, 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स, 'परीक्षा सतर्कता (सामान्य गलतियाँ)', स्मृति सूत्र (Memory Tricks)** और **व्याख्या सहित हल प्रश्न** दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने और याद रखने में पूर्ण सुगमता रहे।

कठिनाई स्तर के अनुसार लक्ष्य सटीकता एवं कट-ऑफ (%)



नियमित रिवीजन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ

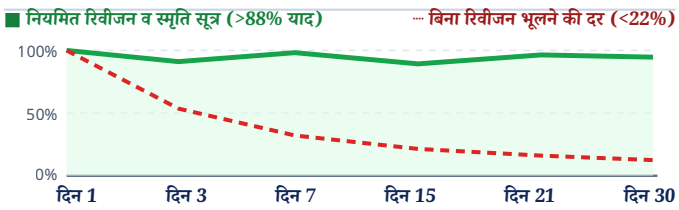

अध्यायवार एवं खंडवार प्रश्न भार सूचकांक (Topic-wise Weightage %)

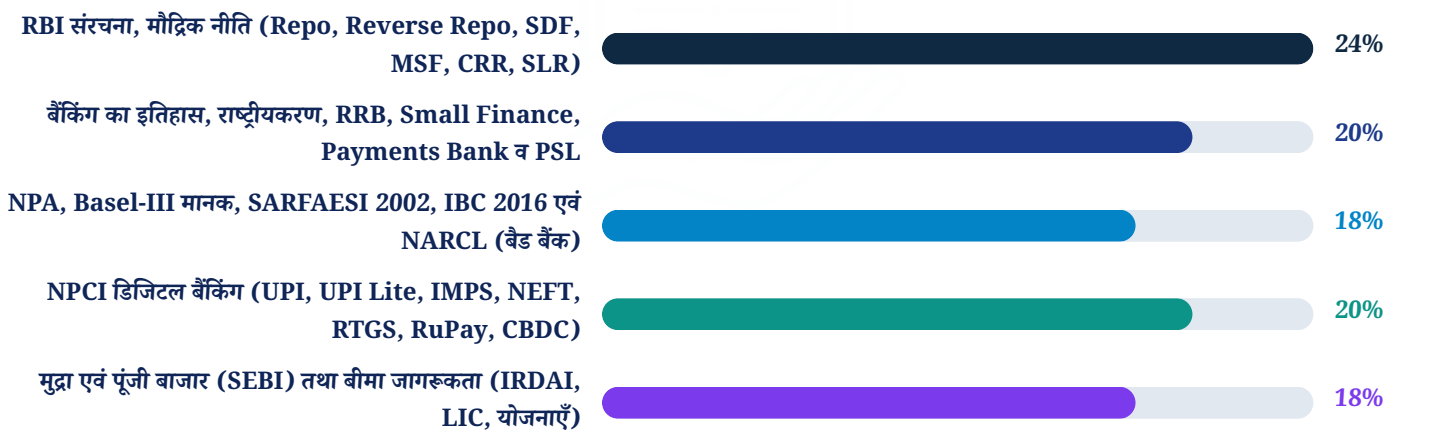

प्रामाणिक पाठ्यक्रम एवं आधिकारिक संदर्भ स्रोत (Verified Official Sources)

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) (https://www.rbi.org.in/)
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) (https://www.npci.org.in/)
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) (https://www.sebi.gov.in/)
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) (https://financialservices.gov.in/insurance-regulatory-and-development-authority-india-irdai)
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) (https://pensionsahayak.pfrda.org.in/)

विस्तृत विषय-सूची एवं अध्याय संरचना (Table of Contents)

संपूर्ण बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा जागरूकता अध्ययन नोट्स • संपूर्ण अध्याय, तुलनात्मक सारणियाँ, अभ्यास प्रश्न एवं त्वरित रिवीजन

1. मॉड्यूल 1: भारत में बैंकिंग का विकास

- 1.1 विस्तृत व्याख्या: आधुनिक बैंकिंग की ऐतिहासिक यात्रा एवं संरचनात्मक सुधार
- 1.2 तुलनात्मक सारणी: बैंकिंग विकास के प्रमुख चरण एवं अनुसूचित बनाम गैर-अनुसूचित बैंक
- 1.3 चार्ट डेटा (%): भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली में ऋण एवं जमा हिस्सेदारी संरचना (प्रतिशत वितरण)

2. मॉड्यूल 2: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के कार्य एवं मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)

- 2.1 विस्तृत व्याख्या: केंद्रीय बैंकिंग कार्य, मौद्रिक नीति समिति एवं तरलता नियंत्रण उपकरण
- 2.2 तुलनात्मक सारणी: आरबीआई के प्रमुख मौद्रिक एवं तरलता उपकरणों का विश्लेषण
- 2.3 चार्ट डेटा (%): भारत के विदेशी मुद्रा भंडार एवं न्यूनतम कोष प्रणाली की प्रतिशत संरचना

3. मॉड्यूल 3: बैंकिंग प्रकार एवं वित्तीय समावेशन

- 3.1 विस्तृत व्याख्या: विभेदित बैंकिंग, ग्रामीण साख एवं प्रमुख सरकारी योजनाएँ
- 3.2 तुलनात्मक सारणी: विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के नियामक एवं परिचालन मानक
- 3.3 चार्ट डेटा (%): प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूँजी संरचना (%)

4. मॉड्यूल 4: डिजिटल बैंकिंग एवं भुगतान प्रणाली

- 4.1 विस्तृत व्याख्या: एनपीसीआई के उत्पाद, आरबीआई भुगतान प्रणालियाँ, बैंकिंग कोड एवं डिजिटल रुपया
- 4.2 तुलनात्मक सारणी: एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एवं यूपीआई तथा प्रमुख बैंकिंग कोडों की तुलना
- 4.3 चार्ट डेटा (%): भारत में डिजिटल भुगतान लेनदेन की मात्रा बनाम मूल्य संरचना (%)

5. मॉड्यूल 5: गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए), वसूली तंत्र एवं बेसल मानक

- 5.1 विस्तृत व्याख्या: एनपीए वर्गीकरण, वसूली कानून (सरफेसी, डीआरटी, आईबीसी), बैड बैंक एवं बेसल मानक
- 5.2 तुलनात्मक सारणी: एनपीए वसूली तंत्रों एवं बेसल मानकों की तुलना
- 5.3 चार्ट डेटा (%): भारत में आरबीआई बेसल तृतीय पूँजी पर्याप्तता अनुपात (11.5%) एवं बैड बैंक की प्रतिशत संरचना

6. मॉड्यूल 6: भारतीय वित्तीय बाजार

- 6.1 विस्तृत व्याख्या: मुद्रा बाजार के लिखत एवं पूँजी बाजार (सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, आईपीओ, म्यूचुअल फंड)
- 6.2 तुलनात्मक सारणी: मुद्रा बाजार बनाम पूँजी बाजार एवं प्रमुख वित्तीय लिखतों का विश्लेषण
- 6.3 चार्ट डेटा (%): भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश एवं पूँजी जुटाने के लिखतों का संरचनात्मक अनुपात (%)

7. मॉड्यूल 7: बीमा जागरूकता एवं पेंशन क्षेत्र

- 7.1 विस्तृत व्याख्या: भारत में बीमा का विकास, एलआईसी, जीआईसी, इरडाई, बीमा के सिद्धांत एवं पेंशन योजनाएँ
- 7.2 तुलनात्मक सारणी: जीवन बीमा बनाम सामान्य बीमा एवं प्रमुख बीमा-पेंशन संस्थान
- 7.3 चार्ट डेटा (%): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) निकासी नियम एवं बीमा क्षेत्र एफडीआई सीमा (%)

8. मॉड्यूल 8: प्रमुख बैंकिंग समितियाँ, परक्राम्य लिखत अधिनियम (1881) एवं बैंकिंग लोकपाल

- 8.1 विस्तृत व्याख्या: ऐतिहासिक बैंकिंग समितियाँ, परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक व धारा 138) एवं एकीकृत लोकपाल योजना
- 8.2 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख बैंकिंग समितियाँ, एनआई एक्ट 1881 की धाराएँ एवं लोकपाल मानक
- 8.3 चार्ट डेटा (%): विमल जालान आर्थिक पूँजी ढाँचा, धारा 143-ए अंतरिम मुआवजा एवं लोकपाल कवरेज मानक (%)

9. मॉड्यूल 1: भारत में बैंकिंग का ऐतिहासिक विकास, राष्ट्रीयकरण एवं रिज़र्व बैंक की संरचना

- 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
- 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

10. मॉड्यूल 2: मौद्रिक नीति समिति (MPC), तरलता समायोजन सुविधा (LAF) एवं मौद्रिक उपकरण

- 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
- 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

11. मॉड्यूल 3: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL), ई-कुबेर PSLC पोर्टल एवं ग्रामीण विकास

- 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
- 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

12. मॉड्यूल 4: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) एवं डिजिटल भुगतान क्रांति

- 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
- 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

13. मॉड्यूल 5: एनपीए (NPA) वर्गीकरण, सरफेसी अधिनियम, आईबीसी (IBC) एवं बेसल-III मानक

- 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
- 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

14. मॉड्यूल 6: मुद्रा बाज़ार (Money Market) एवं पूंजी बाज़ार (Capital Market) तथा SEBI निवेशक चार्टर

- 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
- 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

15. मॉड्यूल 7: वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion), जन-धन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

- 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
- 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

16. मॉड्यूल 8: भारत में बीमा क्षेत्र का इतिहास, IRDAI, 100% FDI सुधार एवं बीमा के सिद्धांत

- 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
- 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

17. मॉड्यूल 9: अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs), परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 एवं बैंकिंग लोकपाल

- 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
- 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

18. मॉड्यूल 10: बैंकिंग में ग्राहक संबंध, स्वामित्व अधिकार, प्रमुख समितियाँ एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

- 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
- 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

19. अंतिम समय त्वरित वन-लाइनर रिवीजन कैप्सूल (100-पॉइंट सुपरफास्ट सार)

20. भाग 1: गहन अध्याय-विस्तार (Comprehensive Chapter Expansion)

- अध्याय 1: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का इतिहास, संरचना एवं प्रमुख कार्य

लक्षित परीक्षाएँ: आईबीपीएस (पीओ, क्लर्क, एसओ, आरआरबी), एसबीआई (पीओ, क्लर्क), आरबीआई (ग्रेड बी, असिस्टेंट), नाबार्ड, सेबी, एलआईसी (एएओ, एडीओ), एनआईएसीएल तथा विभागीय बैंक पदोन्नति परीक्षाएँ (जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी)

मॉड्यूल 1: भारत में बैंकिंग का विकास

1.1 विस्तृत व्याख्या: आधुनिक बैंकिंग की ऐतिहासिक यात्रा एवं संरचनात्मक सुधार

भारत में आधुनिक एवं संगठित बैंकिंग प्रणाली की नींव अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ी। वर्ष 1770 में कलकत्ता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित 'बैंक ऑफ हिंदुस्तान' भारत का प्रथम आधुनिक बैंक था, जो 1832 तक संचालित रहा। इसके पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में व्यापारिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तीन **प्रेसीडेंसी बैंकों** की स्थापना की गई:

- **बैंक ऑफ बंगाल (1806):** 2 जून 1806 को 'बैंक ऑफ कलकत्ता' के रूप में स्थापित हुआ और 2 जनवरी 1809 को इसका नाम बदलकर 'बैंक ऑफ बंगाल' कर दिया गया।
- **बैंक ऑफ बॉम्बे (1840):** 15 अप्रैल 1840 को बंबई प्रेसीडेंसी में स्थापित किया गया।
- **बैंक ऑफ मद्रास (1843):** 1 जुलाई 1843 को मद्रास प्रेसीडेंसी में कार्य करना प्रारंभ किया।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बैंकिंग एकीकरण की आवश्यकता को देखते हुए 27 जनवरी 1921 को इन तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय करके **इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया** का गठन किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में साख विस्तार हेतु **अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (गोरवाला समिति, 1952)** की अनुशंसा पर 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर इसे **भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)** में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1959 में भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम के माध्यम से 8 क्षेत्रीय राजसी बैंकों को इसके सहयोगी बैंकों का दर्जा दिया गया, जिनका 1 अप्रैल 2017 को पूर्णतः भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना: वर्ष 1926 में गठित **रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस (हिल्टन यंग आयोग)** ने देश में मौद्रिक नीति और मुद्रा निर्गमन के नियंत्रण हेतु एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। इसके आधार पर **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934** पारित किया गया और **1 अप्रैल 1935** को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत निजी शेयर पूँजी के साथ कलकत्ता में **भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)** की स्थापना हुई। वर्ष 1937 में इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता से स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। सर ओसबोर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे, जबकि सर सी. डी. देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर (1943) बने। स्वतंत्रता के पश्चात बैंकिंग विनियमन को सशक्त बनाने हेतु **1 जनवरी 1949** को भारतीय रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम, 1948 के तहत इसका राष्ट्रीयकरण किया गया।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969 एवं 1980): स्वतंत्र भारत में वाणिज्यिक बैंकों का ऋण प्रवाह मुख्यतः बड़े औद्योगिक घरानों तक सीमित था, जिससे कृषि, लघु उद्योग एवं ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित रहे। सामाजिक बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से भारत सरकार ने दो चरणों में निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया:

- **प्रथम चरण (19 जुलाई 1969):** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अध्यादेश के माध्यम से ऐसे **14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों** का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी कुल जमा राशि **50 करोड़ रुपये या उससे अधिक** थी। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल थे।
- **द्वितीय चरण (15 अप्रैल 1980):** ऐसे **6 अन्य निजी बैंकों** का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी कुल जमा राशि **200 करोड़ रुपये या उससे अधिक** थी। इनमें आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक तथा विजया बैंक सम्मिलित थे। (वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया)।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का महा-विलय: बैंकों की बैलेंस शीट सुदृढ़ करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और वैश्विक आकार के बैंक निर्मित करने हेतु **वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय** द्वारा प्रमुख विलय किए गए:

- **1 अप्रैल 2017:** भारतीय स्टेट बैंक में इसके 5 सहयोगी बैंकों (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर) तथा भारतीय महिला बैंक का विलय हुआ।
- **1 अप्रैल 2019: बैंक ऑफ बड़ौदा** में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया।

• **1 अप्रैल 2020 (वृहद विलय):** 10 सार्वजनिक बैंकों का 4 बड़े एंकर बैंकों में एकीकरण किया गया — (1) **पंजाब नेशनल बैंक** में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय; (2) केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय; (3) **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय; तथा (4) **इंडियन बैंक** में इलाहाबाद बैंक का विलय। इन सुधारों के पश्चात भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की कुल संख्या **12** (भारतीय स्टेट बैंक + 11 राष्ट्रीयकृत बैंक) रह गई है।

अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित बैंक:

• **अनुसूचित बैंक:** वे बैंक जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इसके लिए बैंक की प्रदत्त पूँजी और आरक्षित निधि कम से कम 5 लाख रुपये होनी चाहिए तथा वह जमाकर्ताओं के हितों के अनुकूल कार्य करता हो। इन्हें आरबीआई से बैंक दर व रेपो दर पर ऋण सुविधा तथा समाशोधन गृह की स्वत: सदस्यता प्राप्त होती है।

• **गैर-अनुसूचित बैंक:** वे बैंक जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं। ये अपना नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) आरबीआई के पास रखने के बजाय स्वयं के पास नकद रूप में रख सकते हैं और केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही आरबीआई से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

1.2 तुलनात्मक सारणी: बैंकिंग विकास के प्रमुख चरण एवं अनुसूचित बनाम गैर-अनुसूचित बैंक

तुलना का आधार / ऐतिहासिक चरण	अनुसूचित बैंक / प्रथम चरण	गैर-अनुसूचित बैंक / द्वितीय चरण	नियामक संदर्भ एवं प्रमुख विशेषताएँ
वैधानिक परिभाषा	आरबीआई अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक	आरबीआई अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से बाहर के बैंक	अनुसूचित बैंकों पर कठोर नियामक पर्यवेक्षण लागू होता है
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव	आरबीआई के पास निर्धारित प्रतिशत नकद रखना अनिवार्य	यह राशि स्वयं अपने पास या आरबीआई के पास रख सकते हैं	धारा 42(1) के तहत पाक्षिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य
आरबीआई से पुनर्वित्त सुविधा	रेपो, एमएसएफ तथा बैंक दर पर नियमित ऋण लेने के पात्र	सामान्यत: पात्र नहीं; केवल असाधारण आपातकाल में सुविधा	अनुसूचित बैंकों को समाशोधन गृह की सदस्यता स्वत: मिलती है
राष्ट्रीयकरण तुलना (1969 बनाम 1980)	**19 जुलाई 1969:** 14 बैंक (न्यूनतम जमा आधार: 50 करोड़ रुपये)	**15 अप्रैल 1980:** 6 बैंक (न्यूनतम जमा आधार: 200 करोड़ रुपये)	वित्तीय सेवा विभाग द्वारा सामाजिक बैंकिंग विस्तार हेतु क्रियान्वित
महा-विलय (2019-2020) के एंकर बैंक	**पीएनबी** (ओबीसी + यूबीआई) एवं **केनरा बैंक** (सिंडिकेट बैंक)	**यूनियन बैंक** (आंध्रा + कॉर्पोरेशन) एवं **इंडियन बैंक** (इलाहाबाद बैंक)	1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया व देना बैंक का विलय हुआ

1.3 चार्ट डेटा (%): भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली में ऋण एवं जमा हिस्सेदारी संरचना (प्रतिशत वितरण)

निम्नलिखित सारणी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न समूहों द्वारा कुल बैंकिंग संपत्तियों एवं जमाओं में संरचनात्मक योगदान (%) दर्शाती है:

बैंक श्रेणी (संरचनात्मक खंड)	कुल बैंकिंग जमा में हिस्सेदारी (%)	कुल बैंक ऋण में हिस्सेदारी (%)	दृश्य अनुपात बार (10 इकाइयाँ = 100%)	नियामक एवं परिचालन स्थिति
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (12 पीएसबी)	58.5%	55.0%	▓▓▓▓▓▓	भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारत सरकार (बहुमत हिस्सेदारी)
निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक	34.0%	37.5%	▓▓▓▓	उच्च खुदरा ऋण वृद्धि एवं डिजिटल दक्षता
विदेशी बैंक एवं लघु वित्त बैंक	4.5%	4.5%	▓	शहरी कॉर्पोरेट एवं सूक्ष्म वित्त खंड
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	3.0%	3.0%	▓	आरबीआई एवं नाबार्ड निदेश — ग्रामीण कृषि साख
कुल बैंकिंग प्रणाली	**100.0%**	**100.0%**	▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓	समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

1.4 मॉड्यूल 1 की स्मृति ट्रिक्स

★ स्मृति ट्रिक 1 (तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का क्रम और वर्ष याद करने का सूत्र):
"बंगाल (1806) में बम्बई (1840) की मद्रासी (1843) इम्पीरियल (1921) गाड़ी स्टेट (1955) पहुँची।"
व्याख्या: क्रमशः बैंक ऑफ बंगाल (1806) → बैंक ऑफ बॉम्बे (1840) → बैंक ऑफ मद्रास (1843) → तीनों मिलकर 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने → 1955 में यही भारतीय स्टेट बैंक बना।

★ स्मृति ट्रिक 2 (1 अप्रैल 2020 के चार महा-विलय याद रखने का सूत्र):
"पंजाब में ओरिएंटल-यूनाइटेड मिले, केनरा का सिंडिकेट बना, यूनियन में आंध्रा-कॉर्पोरेशन जुड़े और इंडियन ने इलाहाबाद को अपनाया।"
व्याख्या: (1) पंजाब नेशनल बैंक = ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स + यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया; (2) केनरा बैंक = सिंडिकेट बैंक; (3) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया = आंध्रा बैंक + कॉर्पोरेशन बैंक; (4) इंडियन बैंक = इलाहाबाद बैंक; तथा 2019 में **"बड़ौदा ने विजय पाकर देना शुरू किया"** (बैंक ऑफ बड़ौदा = विजया बैंक + देना बैंक)।

मॉड्यूल 2: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के कार्य एवं मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)

2.1 विस्तृत व्याख्या: केंद्रीय बैंकिंग कार्य, मौद्रिक नीति समिति एवं तरलता नियंत्रण उपकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) देश का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। इसके प्रमुख कार्यों में मौद्रिक नीति का निर्माण व क्रियान्वयन, मुद्रा का निर्गमन (धारा 22), सरकार का बैंकर एवं सार्वजनिक ऋण प्रबंधक (केंद्र व राज्य सरकारें), बैंकों का बैंकर एवं अंतिम ऋणदाता, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, तथा भुगतान एवं निपटान प्रणाली का नियामक होना शामिल है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी): उर्जित पटेल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से **आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-जेडबी** में संशोधन करके मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया।

- **संरचना (6 सदस्य):** इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं — (1) आरबीआई गवर्नर (पदेन अध्यक्ष), (2) मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर, और (3) केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी; तथा 3 बाहरी सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जिनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते।

- **निर्णय प्रक्रिया एवं मुद्रास्फीति लक्ष्य:** **मौद्रिक नीति रूपरेखा** के अंतर्गत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई - संयुक्त) आधारित मुद्रास्फीति का लचीला लक्ष्य **4% (±2% की सहनशीलता सीमा, अर्थात् न्यूनतम 2% से अधिकतम 6%)** निर्धारित है। वर्ष में कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य हैं (व्यावहारिक रूप से प्रत्येक 2 माह में द्विमासिक समीक्षा होती है) और गणपूर्ति (कोरम) 4 सदस्यों की होती है। मत बराबर होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर को **निर्णायक मत** देने का अधिकार है। यदि लगातार 3 तिमाहियों तक मुद्रास्फीति 6% से ऊपर या 2% से नीचे रहती है, तो इसे लक्ष्य की विफलता माना जाता है और आरबीआई को केंद्र सरकार को कारणों व सुधारात्मक उपायों की रिपोर्ट देनी होती है।

मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण: ये उपकरण अर्थव्यवस्था में ऋण की कुल मात्रा और तरलता को सीधे नियंत्रित करते हैं:

1. **रेपो दर:** वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर से अतिरिक्त) के संपार्श्विक के बदले अल्पकालिक तरलता (ऋण) प्रदान करता है। यह **मौद्रिक नीति समिति** की प्रमुख नीतिगत दर है।
2. **स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ):** अप्रैल 2022 में आरबीआई अधिनियम की धारा 17 में संशोधन के तहत लागू यह सुविधा तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर का नया आधार (निचली सीमा) है। इसके माध्यम से बैंक बिना किसी संपार्श्विक (बिना सरकारी प्रतिभूति के) अपनी अतिरिक्त तरलता आरबीआई के पास जमा कर ब्याज कमाते हैं। यह सामान्यतः रेपो दर से 25 आधार अंक (0.25%) कम रहती है।
3. **सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ):** वर्ष 2011 में प्रारंभ इस सुविधा के तहत अनुसूचित बैंक तीव्र नकदी संकट की स्थिति में अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कोटे की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर (निर्धारित सीमा तक) आरबीआई से एक दिवसीय ऋण ले सकते हैं। यह एलएएफ कॉरिडोर की ऊपरी सीमा है और सामान्यतः रेपो दर से 25 आधार अंक (+0.25%) अधिक होती है।
4. **रिवर्स रेपो दर:** वह दर जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों से अतिरिक्त तरलता अवशोषित करता है। वर्तमान में **परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर)** नीलामियों और एसडीएफ का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है।

5. **बैंक दर:** आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 49 के तहत वह मानक दर जिस पर आरबीआई विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या भुनाने के लिए तैयार रहता है। यह दीर्घकालिक दर है और एमएसएफ दर के साथ संरेखित रहती है। सीआरआर या एसएलआर बनाए रखने में विफल रहने वाले बैंकों पर दंड की गणना इसी दर (बैंक दर + 3% से 5%) के आधार पर की जाती है।

6. **नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर):** आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी कुल निवल माँग और सावधि देयताओं (एनडीटीएल) का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास केवल **नकद** रूप में रखना होता है। इस जमा राशि पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता और इसकी कोई न्यूनतम या अधिकतम वैधानिक सीमा नहीं है।

7. **वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर):** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत प्रत्येक बैंक को अपने एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत स्वयं के पास **नकद, स्वर्ण अथवा भार-मुक्त अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों** के रूप में रखना अनिवार्य है। इसकी अधिकतम वैधानिक सीमा 40% है।

8. **खुले बाजार की क्रियाएँ (ओएमओ):** बाजार में स्थायी तरलता को समायोजित करने हेतु आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का सीधा क्रय एवं विक्रय। जब बाजार में मुद्रास्फीति या अतिरिक्त नकदी हो, तो आरबीआई प्रतिभूतियाँ बेचता है; और नकदी की कमी होने पर प्रतिभूतियाँ खरीदता है।

9. **बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस):** वर्ष 2004 में आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच समझौते से प्रारंभ यह उपकरण भारी विदेशी पूँजी अंतर्वाह से उत्पन्न अतिरिक्त तरलता को सोखने के लिए ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करता है। इससे प्राप्त राशि सरकार के सामान्य व्यय खाते में न जाकर एक पृथक 'एमएसएस खाते' में रखी जाती है।

गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण: ये ऋण की दिशा और विशिष्ट क्षेत्रों में इसके उपयोग को नियंत्रित करते हैं:

- **मार्जिन आवश्यकताएँ (ऋण-से-मूल्य अनुपात):** प्रतिभूति के बाजार मूल्य और दिए जाने वाले ऋण की राशि के अंतर को बदलना (जैसे स्वर्ण ऋण या आवास ऋण में मार्जिन)।
- **साख की राशनिंग:** विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा तय करना।
- **नैतिक दबाव:** आरबीआई द्वारा बैंकों को पत्रों, सम्मेलनों और दिशानिर्देशों के माध्यम से नीतिगत अनुपालन हेतु प्रेरित करना।
- **प्रत्यक्ष कार्यवाही:** नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाना या व्यावसायिक प्रतिबंध (जैसे त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही फ्रेमवर्क) लगाना।

करेंसी प्रबंधन एवं विदेशी मुद्रा भंडार:

- **न्यूनतम कोष प्रणाली (1956):** आरबीआई अधिनियम की धारा 22 के तहत 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर सभी बैंक नोट जारी करने का एकाधिकार आरबीआई के पास है (1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और भारत सरकार जारी करती है)। 1956 से लागू न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई को हर समय **200 करोड़ रुपये** का कोष रखना होता है, जिसमें कम से कम **115 करोड़ रुपये का स्वर्ण** और **85 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ** होनी अनिवार्य हैं।
- **विदेशी मुद्रा भंडार के 4 घटक:** (1) विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (एफसीए — जो सबसे बड़ा हिस्सा हैं), (2) स्वर्ण भंडार, (3) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर), तथा (4) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित कोष की स्थिति (आरटीपी)।

2.2 तुलनात्मक सारणी: आरबीआई के प्रमुख मौद्रिक एवं तरलता उपकरणों का विश्लेषण

मौद्रिक उपकरण	वैधानिक धारा / प्रारंभ वर्ष	संपार्श्विक (प्रतिभूति) की आवश्यकता	मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु आरबीआई का कदम	तरलता पर प्रभाव एवं मुख्य विशेषता
रेपो दर	आरबीआई अधिनियम, धारा 12-एबी	हाँ (एसएलआर से अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ)	दर में **वृद्धि** की जाती है	बैंकों के लिए उधार महंगा होता है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति घटती है
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)	धारा 17 (अप्रैल 2022 से लागू)	**नहीं** (बिना संपार्श्विक जमा सुविधा)	दर में **वृद्धि** (रेपो - 0.25%)	एलएएफ कॉरिडोर की निचली सीमा; अतिरिक्त तरलता का अवशोषण
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)	वर्ष 2011 में प्रारंभ	हाँ (एसएलआर कोटे की सरकारी प्रतिभूतियाँ भी मान्य)	दर में **वृद्धि** (रेपो + 0.25%)	एलएएफ कॉरिडोर की ऊपरी सीमा; आपातकालीन एक-दिवसीय ऋण
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)	आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)	केवल **नकद** (आरबीआई के पास जमा)	अनुपात में **वृद्धि** की जाती है	बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता; सीधे ऋण सृजन क्षमता कम करता है

मौद्रिक उपकरण	वैधानिक धारा / प्रारंभ वर्ष	संपार्श्विक (प्रतिभूति) की आवश्यकता	मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु आरबीआई का कदम	तरलता पर प्रभाव एवं मुख्य विशेषता
वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24	नकद, स्वर्ण या अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियाँ	अनुपात में **वृद्धि** की जाती है	बैंक स्वयं के पास रखते हैं; सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज अर्जित होता है

2.3 चार्ट डेटा (%): भारत के विदेशी मुद्रा भंडार एवं न्यूनतम कोष प्रणाली की प्रतिशत संरचना

घटक / कोष श्रेणी	कुल भंडार / कोष में मानक हिस्सा (%)	न्यूनतम वैधानिक राशि (रुपये में)	दृश्य अनुपात बार (10 इकाइयाँ = 100%)	नियामक एवं प्रबंधन विवरण
न्यूनतम कोष प्रणाली: स्वर्ण कोष	57.5%	115 करोड़ रुपये	■■■■■	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन हेतु अनिवार्य स्वर्ण भाग
न्यूनतम कोष प्रणाली: विदेशी प्रतिभूतियाँ	42.5%	85 करोड़ रुपये	■■■■	कुल 200 करोड़ रुपये के न्यूनतम कोष का विदेशी मुद्रा हिस्सा
विदेशी मुद्रा भंडार: विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (एफसीए)	~82.0%	परिवर्तनशील (अधिकतम घटक)	■■■■■■■■	डॉलर, यूरो, पाउंड, येन आदि में निवेशित विदेशी परिसंपत्तियाँ
विदेशी मुद्रा भंडार: स्वर्ण भंडार	~14.5%	परिवर्तनशील (द्वितीय प्रमुख घटक)	■■	केंद्रीय बैंक द्वारा धारित भौतिक स्वर्ण भंडार
विदेशी मुद्रा भंडार: एसडीआर एवं आरटीपी	~3.5%	परिवर्तनशील (आईएमएफ कोटा आधारित)	▪	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास विशेष आहरण अधिकार व रिजर्व ट्रेंच

2.4 मॉड्यूल 2 की स्मृति ट्रिक्स

★ **स्मृति ट्रिक 3 (सीआरआर बनाम एसएलआर की धाराएँ और स्वरूप याद रखने का सूत्र):**
"42 की उम्र में आरबीआई को सिर्फ नकद (सीआरआर) दो, 24 घंटे अपने पास सोना-नकद-बॉन्ड (एसएलआर) रखो!"
व्याख्या: सीआरआर = आरबीआई अधिनियम 1934 की **धारा 42(1)** (केवल नकद, आरबीआई के पास, शून्य ब्याज); एसएलआर = बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की **धारा 24** (नकद + स्वर्ण + सरकारी प्रतिभूति, बैंक स्वयं के पास रखता है)।

★ **स्मृति ट्रिक 4 (एलएएफ कॉरिडोर एवं मुद्रास्फीति नियंत्रण का सीधा नियम):**
"फर्श पर एसडीएफ (-0.25%), बीच में रेपो, छत पर एमएसएफ/बैंक दर (+0.25%) — महंगाई बढ़े तो सबकी दरें बढ़ा दो!"
व्याख्या: एलएएफ कॉरिडोर में सबसे नीचे एसडीएफ (रेपो से 0.25% कम), मध्य में नीतिगत रेपो दर, और सबसे ऊपर एमएसएफ व बैंक दर (रेपो से 0.25% अधिक) होती है। बाजार में महंगाई (मुद्रास्फीति) रोकने के लिए आरबीआई सभी दरों को बढ़ाता है ताकि तरलता घटे।

मॉड्यूल 3: बैंकिंग प्रकार एवं वित्तीय समावेशन

3.1 विस्तृत व्याख्या: विभेदित बैंकिंग, ग्रामीण साख एवं प्रमुख सरकारी योजनाएँ

भारत में बैंकिंग प्रणाली को सार्वभौमिक बैंकों, विभेदित बैंकों, ग्रामीण एवं सहकारी संस्थानों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

1. **वाणिज्यिक बैंक:** ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जमा स्वीकार करने और ऋण देने के समस्त कार्य करते हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (12), निजी क्षेत्र के बैंक, और विदेशी बैंक शामिल हैं।

2. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी): नरसिंहम कार्यदल (1975)** की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को एक अध्यादेश (तत्पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976) के तहत 5 आरआरबी स्थापित किए गए, जिनमें मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित **'प्रथमा बैंक'** भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था।

• **पूँजी संरचना (50 : 15 : 35):** आरआरबी की अधिकृत एवं प्रदत्त पूँजी में **केंद्र सरकार का 50%**, संबंधित **राज्य सरकार का 15%**, और **प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक का 35%** योगदान होता है। इनका विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तथा पर्यवेक्षण **नाबार्ड** द्वारा किया जाता है।

3. **सहकारी बैंक:** ये सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और इनका पंजीकरण राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत होता है। ग्रामीण सहकारी बैंकों की संरचना त्रिस्तरीय होती है: (क) ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स), (ख) जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, और (ग) राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। शहरी क्षेत्रों में **शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)** कार्य करते हैं, जिन्हें बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से सीधे आरबीआई के कड़े नियामक दायरे में लाया गया है।

4. **भुगतान बैंक (पेमेंट बैंक): डॉ. नचिकेत मोर समिति** की सिफारिश पर वित्तीय समावेशन को गति देने हेतु स्थापित किए गए।

• **मुख्य मानदंड:** न्यूनतम प्रदत्त पूँजी **100 करोड़ रुपये**; प्रति ग्राहक अधिकतम **2 लाख रुपये** तक की माँग जमा (बचत व चालू खाता) स्वीकार कर सकते हैं; ये सावधि जमा (एफडी) या आवर्ती जमा (आरडी) स्वीकार **नहीं** कर सकते; ये **ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते** (केवल एटीएम/डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं); इन्हें अपनी माँग जमा का कम से कम 75% हिस्सा एसएलआर योग्य सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों में निवेश करना होता है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक था।

5. **लघु वित्त बैंक (स्मॉल फाइनेंस बैंक - एसएफबी): उषा थोराट समिति** की सिफारिश पर असंगठित क्षेत्र, लघु एवं सीमांत किसानों और सूक्ष्म उद्योगों को बैंकिंग सेवाएँ देने हेतु स्थापित।

• **मुख्य मानदंड:** आरबीआई के पूँजी एवं लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्यतः न्यूनतम प्रदत्त पूँजी **200 करोड़ रुपये** (प्रारंभ में 100 करोड़ रुपये थी); ये सभी प्रकार की जमा (एफडी/आरडी सहित) स्वीकार कर सकते हैं और ऋण भी दे सकते हैं; इन्हें अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का **75% हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल)** को देना अनिवार्य है तथा कम से कम 50% ऋण पोर्टफोलियो 25 लाख रुपये तक के ऋणों का होना चाहिए। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का पहला लघु वित्त बैंक (2016) बना।

6. **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी):** कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजीकृत वे संस्थाएँ जो ऋण, अग्रिम, शेयर/बॉन्ड अधिग्रहण और लीजिंग/हायर-परचेज का व्यवसाय करती हैं।

• **बैंक से मुख्य अंतर:** एनबीएफसी **माँग जमा (बचत/चालू खाता) स्वीकार नहीं कर सकतीं**; ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होतीं और **स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकतीं**; तथा इनके जमाकर्ताओं को जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की 5 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल मानक): आरबीआई के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मास्टर निदेश के अनुसार बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीएसई), जो भी अधिक हो, का एक निश्चित प्रतिशत 8 चिन्हित प्राथमिकता क्षेत्रों (कृषि, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य) को देना अनिवार्य है:

• **घरेलू वाणिज्यिक बैंक एवं विदेशी बैंक (20 व अधिक शाखाएँ):** कुल पीएसएल लक्ष्य **40%** (जिसमें कृषि 18% — लघु व सीमांत किसानों के लिए 10%, सूक्ष्म उद्यम 7.5%, और कमजोर वर्ग 12%)।

• **विदेशी बैंक (20 से कम शाखाएँ):** कुल पीएसएल लक्ष्य **40%** (जिसमें 32% निर्यात ऋण में और न्यूनतम 8% अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में)।

• **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) एवं लघु वित्त बैंक (एसएफबी):** कुल पीएसएल लक्ष्य **75%**।

• **शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी):** आरबीआई के संशोधित दिशानिर्देश (1 अप्रैल 2025 से प्रभावी) के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का समग्र पीएसएल लक्ष्य संशोधित कर एएनबीसी/सीईओबीएसई का **60%** निर्धारित किया गया है।

• यदि कोई बैंक अपना पीएसएल लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता, तो उसे बकाया राशि नाबार्ड द्वारा प्रबंधित **ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)** या अन्य निर्दिष्ट निधियों में जमा करनी पड़ती है, अथवा वह **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)** खरीदकर लक्ष्य पूरा कर सकता है।

वित्तीय समावेशन की प्रमुख सरकारी योजनाएँ:

1. **प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई):** प्रधानमंत्री जन-धन योजना का शुभारंभ **28 अगस्त 2014** को राष्ट्रीय मिशन के रूप में किया गया। इसका आदर्श वाक्य "मेरा खाता, भाग्य विधाता" है। इसके अंतर्गत बिना किसी न्यूनतम शेष (जीरो बैलेंस) के बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) खोला जाता है, जिसमें रूपे डेबिट कार्ड के साथ **2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा** (28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों हेतु) और पात्र खातों में **10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा** मिलती है।

2. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):** सूक्ष्म एवं लघु गैर-कॉर्पोरेट उद्यमों को वित्तपोषित करने हेतु **8 अप्रैल 2015** को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ की गई। इसमें बिना गारंटी के ऋण की 4 श्रेणियाँ हैं:

• **शिशु:** 50,000 रुपये तक का ऋण।

• **किशोर:** 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक का ऋण।

• **तरुण:** 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का ऋण।

• **तरुण प्लस:** अद्यतन मुद्रा योजना प्रावधानों के तहत जिन उद्यमियों ने 'तरुण' श्रेणी का ऋण लेकर सफलतापूर्वक चुका दिया है, उन्हें **10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक** का ऋण प्रदान किया जाता है।

3. **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी): आर. वी. गुप्ता समिति** की सिफारिश पर **अगस्त 1998** में नाबार्ड और आरबीआई द्वारा किसानों को फसल उत्पादन, कटाई के बाद के खर्च और कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु समय पर ऋण देने के लिए प्रारंभ किया गया। वर्ष 2019 से इसमें पशुपालन और मत्स्य पालन को भी जोड़ दिया गया है।

3.2 तुलनात्मक सारणी: विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के नियामक एवं परिचालन मानक

तुलना का आधार	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	लघु वित्त बैंक (एसएफबी)	भुगतान बैंक (पेमेंट बैंक)
सिफारिशकर्ता समिति	हिल्टन यंग / बैंकिंग आयोग	**नरसिंहम कार्यदल (1975)**	**उषा थोराट समिति**	**नचिकेत मोर समिति**
कुल पीएसएल लक्ष्य	**40%** (एएनबीसी का)	**75%** (एएनबीसी का)	**75%** (एएनबीसी का)	लागू नहीं (ऋण देने पर प्रतिबंध)
जमा स्वीकार्यता सीमा	सभी प्रकार की जमा (कोई ऊपरी सीमा नहीं)	सभी प्रकार की जमा (बचत, चालू, सावधि)	सभी प्रकार की जमा (बचत, चालू, सावधि)	केवल माँग जमा (**अधिकतम 2 लाख रुपये** प्रति ग्राहक)
ऋण एवं क्रेडिट कार्ड	सभी प्रकार के ऋण एवं क्रेडिट कार्ड मान्य	मुख्यतः ग्रामीण, कृषि एवं प्राथमिकता ऋण	लघु व्यवसाय, एमएसएमई व सूक्ष्म ऋण मान्य	**ऋण एवं क्रेडिट कार्ड पूर्णतः प्रतिबंधित**
नियामक संदर्भ	आरबीआई पीएसएल निदेश	आरआरबी पीएसएल निदेश (50:15:35 पूँजी)	आरबीआई बेसल एवं लाइसेंसिंग निदेश	न्यूनतम 100 करोड़ रुपये पूँजी; 75% जी-सेक निवेश

3.3 चार्ट डेटा (%): प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूँजी संरचना (%)

मानक श्रेणी / संस्था	निर्धारित प्रतिशत लक्ष्य (%)	दृश्य अनुपात बार (10 इकाइयाँ = 100%)	नियामक विवरण एवं उप-लक्ष्य
वाणिज्यिक बैंक: कुल पीएसएल लक्ष्य	40.0%	■■■■□□□□□□	आरबीआई मास्टर निदेश के तहत एएनबीसी का 40%
पीएसएल उप-लक्ष्य: कृषि क्षेत्र	18.0%	■■□□□□□□□□	इसमें 10% लघु एवं सीमांत किसानों के लिए आरक्षित
पीएसएल उप-लक्ष्य: कमजोर वर्ग	12.0%	■□□□□□□□□□	अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वयं सहायता समूह व अल्पसंख्यक
शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी): संशोधित पीएसएल लक्ष्य	60.0%	■■■■■■□□□□	आरबीआई 2025 संशोधन के अनुसार एएनबीसी का 60%
आरआरबी एवं लघु वित्त बैंक: कुल पीएसएल लक्ष्य	75.0%	■■■■■■■□□□	ग्रामीण एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता अनुपात
आरआरबी पूँजी हिस्सेदारी (केंद्र : राज्य : प्रायोजक)	50% : 15% : 35%	■■■■□■■■	केंद्र सरकार (50%), राज्य सरकार (15%), प्रायोजक बैंक (35%)

3.4 मॉड्यूल 3 की स्मृति ट्रिक्स

★ स्मृति ट्रिक 5 (आरआरबी पूँजी अनुपात और विभेदित बैंक समितियाँ याद रखने का सूत्र):
"केंद्र 50, प्रायोजक 35, राज्य 15 का ग्रामीण साथ (नरसिंहम); नचिकेत ने पेमेंट किया, उषा ने स्मॉल फाइनेंस दिया!"
व्याख्या: आरआरबी में केंद्र सरकार 50%, प्रायोजक बैंक 35% और राज्य सरकार 15% पूँजी लगाती है (नरसिंहम समिति, 1975)। पेमेंट बैंक = नचिकेत मोर समिति; स्मॉल फाइनेंस बैंक = उषा थोराट समिति।

★ स्मृति ट्रिक 6 (मुद्रा योजना के 4 चरण और पीएसएल लक्ष्य याद रखने का सूत्र):
"शिशु 50 हजार का, किशोर 5 लाख का, तरुण 10 लाख का और तरुण प्लस 20 लाख का! पीएसएल में वाणिज्यिक 40%, यूसीबी 60%, आरआरबी-एसएफबी 75%!"
व्याख्या: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की चारों ऋण सीमाएँ (50 हजार, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख) और पीएसएल के तीनों मुख्य स्लैब (40%, 60%, 75%) एक ही पंक्ति में याद हो जाते हैं।

मॉड्यूल 4: डिजिटल बैंकिंग एवं भुगतान प्रणाली

4.1 विस्तृत व्याख्या: एनपीसीआई के उत्पाद, आरबीआई भुगतान प्रणालियाँ, बैंकिंग कोड एवं डिजिटल रुपया

भारत की खुदरा डिजिटल भुगतान क्रांति की रीढ़ **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)** है, जिसकी स्थापना आरबीआई और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के अंतर्गत दिसंबर 2008 में कंपनी अधिनियम की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 — गैर-लाभकारी संस्था) के तहत एक 'अम्ब्रेला संगठन' के रूप में की गई थी।

एनपीसीआई के प्रमुख उत्पाद एवं प्लेटफॉर्म:

1. **यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस):** 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया **यूपीआई प्लेटफॉर्म** एक त्वरित मोबाइल भुगतान प्रणाली है, जो 24×7×365 कार्य करती है। इसमें आभासी भुगतान पते (वीपीए/यूपीआई आईडी) के माध्यम से बिना बैंक खाता संख्या बताए व्यक्ति-से-व्यक्ति और व्यक्ति-से-व्यापारी अंतरण होता है। सामान्य यूपीआई लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपये प्रतिदिन है, जबकि पूँजी बाजार, बीमा, शिक्षा और अस्पतालों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये तक है। बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए **यूपीआई 123-पे** और छोटे मूल्य के ऑफलाइन लेनदेन के लिए **यूपीआई लाइट** संचालित है।
2. **रूपे:** 'रुपया' और 'पेमेंट' शब्दों के मेल से बना **रूपे कार्ड नेटवर्क** मार्च 2012 में लॉन्च किया गया भारत का स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है, जो डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करता है तथा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का भी समर्थन करता है।
3. **आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा):** 22 नवंबर 2010 को प्रारंभ यह सेवा मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से 24×7 अंतर-बैंक तत्काल धन अंतरण प्रदान करती है। इसकी अधिकतम लेनदेन सीमा **5 लाख रुपये** है।
4. **नैच (राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह):** यह उच्च मात्रा वाले आवर्ती भुगतानों (जैसे सरकारी सब्सिडी/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, वेतन, लाभांश, पेंशन तथा ईएमआई/बीमा प्रीमियम कटौती) के लिए एक केंद्रीकृत वेब-आधारित समाशोधन प्रणाली है, जिसने पुरानी ईसीएस प्रणाली का स्थान लिया है।
5. **एईपीएस (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली):** यह बैंक मित्र के पास माइक्रो-एटीएम पर केवल **आधार संख्या और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण** के माध्यम से नकद निकासी, जमा, बैलेंस पूछताछ और आधार-से-आधार फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है।
6. **भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी):** 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया यूपीआई आधारित मोबाइल एप्लिकेशन, जिसका नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है।
7. **एनईटीसी फास्टैग:** रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (**आरएफआईडी**) तकनीक पर आधारित यह टैग वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है, जिससे टोल प्लाजा पर बिना रुके लिंक्ड खाते या वॉलेट से स्वतः टोल शुल्क कट जाता है।
8. **ई-रुपी:** 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया **ई-रुपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म** एक संपर्क-रहित, नकदी-रहित और उद्देश्य-विशिष्ट एवं व्यक्ति-विशिष्ट प्रीपेड **क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई-वाउचर** है। इसके लाभार्थी के पास बैंक खाता या स्मार्टफोन होना भी आवश्यक नहीं है।

आरबीआई द्वारा प्रबंधित भुगतान प्रणालियाँ एवं समाशोधन तंत्र:

• **एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण):** नवंबर 2005 में प्रारंभ यह राष्ट्रव्यापी प्रणाली **आस्थगित निवल निपटान (डीएनएस)** के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें लेनदेन आधे-आधे घंटे के कुल **48 बैचों** में 24×7×365 निपटाए जाते हैं। इसमें न्यूनतम या अधिकतम राशि की कोई वैधानिक सीमा नहीं है (यद्यपि नकद आधारित वॉक-इन एनईएफटी की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है)।

• **आरटीजीएस (वास्तविक समय सकल निपटान):** मार्च 2004 में प्रारंभ यह प्रणाली बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए है, जिसमें निर्देश प्राप्त होते ही वास्तविक समय में और सकल आधार (बिना किसी अन्य लेनदेन के साथ बंडल किए) पर तुरंत निपटान होता है। यह भी 24×7×365 उपलब्ध है। इसकी **न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपये** है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है।

• **सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम):** वर्ष 2010 में लागू इस प्रणाली में भौतिक चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक की शाखा तक ले जाने के बजाय, चेक की **इलेक्ट्रॉनिक इमेज और एमआईसीआर डेटा** को समाशोधन गृह के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे चेक क्लीयरेंस तेज और सुरक्षित हो गया है।

प्रमुख वित्तीय एवं बैंकिंग पहचान कोड:

• **आईएफएससी (भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड):** यह **11 वर्णों का अल्फान्यूमेरिक (अक्षर व अंक मिश्रित) कोड** है, जिसका उपयोग एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। इसके **प्रथम 4 अक्षर बैंक का नाम**, **5वाँ अंक सदैव शून्य ('0')** (भविष्य के उपयोग हेतु आरक्षित), और **अंतिम 6 वर्ण बैंक शाखा** को दर्शाते हैं।

• **एमआईसीआर (चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान कोड):** चेक के निचले हिस्से में आयरन ऑक्साइड युक्त चुंबकीय स्याही से मुद्रित यह **9 अंकों का संख्यात्मक कोड** है। इसके **प्रथम 3 अंक शहर (पिनकोड के अनुरूप)**, **मध्य के 3 अंक बैंक**, और **अंतिम 3 अंक बैंक शाखा** को दर्शाते हैं।

• **स्विफ्ट कोड (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन):** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संदेशों और सीमा-पार भुगतान के लिए प्रयुक्त यह **8 या 11 वर्णों का अल्फान्यूमेरिक कोड** (जिसे बैंक पहचानकर्ता कोड — बीआईसी भी कहते हैं) है। इसमें प्रथम 4 अक्षर बैंक कोड, अगले 2 अक्षर देश कोड, अगले 2 अक्षर स्थान कोड, और अंतिम 3 वैकल्पिक अक्षर शाखा कोड होते हैं।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी - डिजिटल रुपया / ई-रुपया): भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संप्रभु मुद्रा का डिजिटल रूप है, जो आरबीआई की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दर्ज होता है। इसे दो श्रेणियों में जारी किया गया है: (1) **डिजिटल रुपया - थोक:** अंतर-बैंक निपटान और सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए; तथा (2) **डिजिटल रुपया - खुदरा:** आम नागरिकों और व्यापारियों के दैनिक लेनदेन के लिए टोकन आधारित डिजिटल मुद्रा।

4.2 तुलनात्मक सारणी: एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एवं यूपीआई तथा प्रमुख बैंकिंग कोडों की तुलना

प्रणाली / कोड का नाम	संचालन संस्था	निपटान तंत्र / कोड संरचना	न्यूनतम एवं अधिकतम राशि सीमा	प्रमुख परीक्षा बिंदु एवं उपलब्धता
एनईएफटी	भारतीय रिज़र्व बैंक	आस्थगित निवल निपटान (आधे घंटे के 48 बैच)	न्यूनतम: कोई सीमा नहीं (1 रु.) / अधिकतम: कोई सीमा नहीं	दिसंबर 2019 से 24×7×365 उपलब्ध; वॉक-इन नकद सीमा 50,000 रुपये
आरटीजीएस	भारतीय रिज़र्व बैंक	वास्तविक समय सकल निपटान	**न्यूनतम: 2 लाख रुपये** / अधिकतम: कोई सीमा नहीं	दिसंबर 2020 से 24×7×365 उपलब्ध; उच्च मूल्य कॉर्पोरेट अंतरण
आईएमपीएस	एनपीसीआई	तत्काल अंतर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक अंतरण	न्यूनतम: 1 रुपया / **अधिकतम: 5 लाख रुपये**	मोबाइल नंबर व एमएमआईडी (7 अंकों का कोड) या खाता+आईएफएससी आधारित
यूपीआई	एनपीसीआई	तत्काल मोबाइल वीपीए/क्यूआर आधारित अंतरण	सामान्य सीमा: **1 लाख रुपये** (विशिष्ट श्रेणियों में 5 लाख रुपये)	11 अप्रैल 2016 को प्रारंभ; यूपीआई 123-पे (फीचर फोन) व यूपीआई लाइट
आईएफएससी बनाम एमआईसीआर बनाम स्विफ्ट	आरबीआई / स्विफ्ट (बेल्जियम)	**आईएफएससी:** 11 (4 बैंक + 0 + 6 शाखा); **एमआईसीआर:** 9 (3 शहर + 3 बैंक + 3 शाखा)	**स्विफ्ट:** 8 या 11 वर्ण (4 बैंक + 2 देश + 2 स्थान + 3 शाखा)	एमआईसीआर चेक समाशोधन (सीटीएस) हेतु और स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय संदेश हेतु

4.3 चार्ट डेटा (%): भारत में डिजिटल भुगतान लेनदेन की मात्रा बनाम मूल्य संरचना (%)

डिजिटल भुगतान माध्यम	कुल लेनदेन संख्या में हिस्सा (%)	कुल लेनदेन मूल्य में हिस्सा (%)	दृश्य अनुपात बार (संख्या के अनुसार)	प्रमुख उपयोग क्षेत्र
यूपीआई (खुदरा डिजिटल भुगतान)	~80.0%	~12.0%	▓▓▓▓▓▓▓▓	एनपीसीआई यूपीआई आंकड़े — सर्वाधिक खुदरा लेनदेन संख्या
आरटीजीएस (वृहद मूल्य अंतरण)	~0.2%	~68.0%	▒▒▒▒▒▒▒▒	संख्या में न्यूनतम किंतु कुल मूल्य में सर्वोच्च हिस्सेदारी
एनईएफटी एवं आईएमपीएस	~8.8%	~15.0%	▓▒▒▒▒▒▒▒	मध्यम एवं व्यावसायिक निधि अंतरण
कार्ड नेटवर्क, नैच, फास्टैग व अन्य	~11.0%	~5.0%	▓▒▒▒▒▒▒▒	ईएमआई, सब्सिडी (नैच), टोल (फास्टैग) व पीओएस स्वाइप
कुल डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी	**100.0%**	**100.0%**	▓▓▓▓▓▓▓▓	भारत का कागज-रहित एवं नकदी-रहित भुगतान तंत्र

4.4 मॉड्यूल 4 की स्मृति ट्रिक्स

★ स्मृति ट्रिक 7 (आईएफएससी, एमआईसीआर, स्विफ्ट और एमएमआईडी के अंकों व संरचना का सूत्र):
"एमएमआईडी के 7, एमआईसीआर के 9 (शहर-बैंक-शाखा 3-3-3), आईएफएससी के 11 में 5वाँ शून्य रहे और स्विफ्ट 8 या 11 से विदेश बहे!"
व्याख्या: एमएमआईडी = 7 अंक; एमआईसीआर = 9 अंक (3 शहर + 3 बैंक + 3 शाखा); आईएफएससी = 11 अल्फान्यूमेरिक (4 बैंक + 5वाँ अंक हमेशा '0' + 6 शाखा); स्विफ्ट = 8 या 11 वर्ण (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग)।

★ स्मृति ट्रिक 8 (एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई की सीमाओं का सूत्र):
"एनईएफटी में बैच 48 सीमा कोई नहीं, आरटीजीएस 2 लाख से शुरू, आईएमपीएस 5 लाख और यूपीआई 1 से 5 लाख तक जाए!"
व्याख्या: एनईएफटी = 48 बैच, कोई न्यूनतम/अधिकतम सीमा नहीं; आरटीजीएस = न्यूनतम 2 लाख रुपये, अधिकतम असीमित; आईएमपीएस = अधिकतम 5 लाख रुपये; यूपीआई = सामान्य 1 लाख रुपये (शिक्षा/स्वास्थ्य/आईपीओ में 5 लाख रुपये)।

मॉड्यूल 5: गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए), वसूली तंत्र एवं बेसल मानक

5.1 विस्तृत व्याख्या: एनपीए वर्गीकरण, वसूली कानून (सरफेसी, डीआरटी, आईबीसी), बैड बैंक एवं बेसल मानक

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए): भारतीय रिज़र्व बैंक के आय निर्धारण एवं परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, जब किसी ऋण या अग्रिम पर मूलधन या ब्याज की किस्त **90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय** रहती है, तो वह ऋण खाता बैंक के लिए 'गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)' बन जाता है।

- **कृषि ऋण के लिए विशेष नियम:** अल्पावधि फसलों (जिनकी पकने की अवधि 1 वर्ष से कम है) के लिए यदि मूलधन या ब्याज **2 फसली मौसमों** तक अतिदेय रहे, और दीर्घावधि फसलों के लिए **1 फसली मौसम** तक अतिदेय रहे, तब उसे एनपीए घोषित किया जाता है।

दबावग्रस्त खातों (विशेष उल्लेख खाते - एसएमए) एवं एनपीए का क्रमिक वर्गीकरण:

ऋण के एनपीए बनने से पूर्व ही तनाव की पहचान करने के लिए आरबीआई ने 90 दिनों की अवधि को तीन **विशेष उल्लेख खातों (एसएमए)** में बाँटा है:

- **एसएमए-0:** किस्त 1 से 30 दिनों तक अतिदेय।
- **एसएमए-1:** किस्त 31 से 60 दिनों तक अतिदेय।
- **एसएमए-2:** किस्त 61 से 90 दिनों तक अतिदेय।

90 दिनों के पश्चात जब खाता एनपीए हो जाता है, तो उसकी आयु के आधार पर उसे निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

1. **अवमानक परिसंपत्तियाँ (सब-स्टैंडर्ड एसेट्स):** वह खाता जो **12 माह या उससे कम अवधि** के लिए एनपीए की श्रेणी में रहा हो। (इस पर सुरक्षित ऋण हेतु 15% और असुरक्षित ऋण हेतु 25% प्रावधान करना होता है)।

2. **संदिग्ध परिसंपत्तियाँ (डाउटफुल एसेट्स):** वह खाता जो अवमानक श्रेणी में 12 माह पूर्ण कर चुका हो (अर्थात् 12 माह से अधिक समय से एनपीए हो)। इसे 3 उप-श्रेणियों में बाँटा जाता है: **डी-1 (1 वर्ष तक संदिग्ध — 25% प्रावधान)**, **डी-2 (1 से 3 वर्ष तक संदिग्ध — 40% प्रावधान)**, और **डी-3 (3 वर्ष से अधिक संदिग्ध व असुरक्षित भाग — 100% प्रावधान)**।

3. **हानि परिसंपत्तियाँ (लॉस एसेट्स):** वह खाता जिसे बैंक के आंतरिक या बाहरी लेखापरीक्षक अथवा आरबीआई निरीक्षण द्वारा अप्राप्य घोषित कर दिया गया हो, किंतु जिसे अभी पूरी तरह बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। इस पर **100% प्रावधान** अनिवार्य है।

ऋण वसूली तंत्र एवं वैधानिक ढाँचा:

1. **ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी):** तिवारी समिति (1981) और नरसिंहम समिति (1991) की सिफारिशों पर 'बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993' के तहत स्थापित किए गए। डीआरटी केवल **20 लाख रुपये या उससे अधिक** के बकाया ऋण मामलों की सुनवाई करता है (पूर्व में यह सीमा 10 लाख रुपये थी)। डीआरटी के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में अपील की जा सकती है।

2. **सरफेसी अधिनियम, 2002 (वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002):** इस अधिनियम ने बैंकों को न्यायालय या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना, 60 दिनों का नोटिस देकर, डिफॉल्टर कर्जदार की गिरवी रखी संपत्ति को जब्त करने, उसका प्रबंधन अपने हाथ में लेने और उसे बेचकर ऋण वसूलने का सीधा अधिकार दिया।

• **अपवाद (जहाँ सरफेसी लागू नहीं होता):** (क) **असुरक्षित ऋण**; (ख) **1 लाख रुपये से कम** का बकाया ऋण; (ग) जब बकाया राशि मूलधन और ब्याज के **20% से कम** रह गई हो; तथा (घ) **कृषि भूमि**।

3. **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी 2016):** टी. के. विश्वनाथन समिति की सिफारिश पर 2016 में लागू इस संहिता ने कॉर्पोरेट, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के दिवाला समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित की। इसका नियामक **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)** है। कॉर्पोरेट मामलों का न्यायनिर्णयन **राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)** और व्यक्तिगत मामलों का **डीआरटी** करता है। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को मूल रूप से 180 दिनों (+90 दिन विस्तार, अधिकतम **330 दिनों की समग्र सीमा**) में पूरा करना होता है और इसमें आवेदन के लिए न्यूनतम डिफॉल्ट राशि **1 करोड़ रुपये** है।

4. **एनएआरसीएल (राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड / बैड बैंक):** वर्ष 2021 में स्थापित यह भारत का 'बैड बैंक' है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 51% हिस्सेदारी है। यह बैंकों से 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के बड़े एनपीए खातों को **15 : 85 संरचना** (15% नकद भुगतान और 85% भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा रसीदें) पर खरीदता है, जबकि इसका सहयोगी संगठन **आईडीआरसीएल (जिसमें निजी क्षेत्र की 51% हिस्सेदारी है)** उन संपत्तियों के प्रबंधन व बिक्री का कार्य करता है।

5. **त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (पीसीए फ्रेमवर्क):** **भारतीय रिज़र्व बैंक** द्वारा कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों पर समय रहते नियंत्रण लगाने की यह व्यवस्था **3 प्रमुख मानकों** की निगरानी करती है: (1) पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर), (2) परिसंपत्ति गुणवत्ता (निवल एनपीए अनुपात), और (3) उत्तोलन अनुपात (लीवरेज अनुपात)।

बेसल मानक (बेसल प्रथम, द्वितीय, तृतीय) एवं पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर / सीआरएआर):

स्विट्ज़रलैंड के बेसल शहर में स्थित 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स' की **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (1974 में स्थापित)** बैंकों की जोखिम सहन क्षमता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करती है:

• **बेसल प्रथम (1988):** यह केवल ऋण जोखिम पर केंद्रित था और इसने 8% न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात निर्धारित किया। भारत ने इसे 1992 में अपनाया।

• **बेसल द्वितीय (2004):** यह **3 स्तंभों** पर आधारित था — (1) न्यूनतम पूँजी आवश्यकता (ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम), (2) पर्यवेक्षी समीक्षा, और (3) बाजार अनुशासन।

• **बेसल तृतीय (2010 — 2008 की वैश्विक मंदी के बाद):** **आरबीआई के बेसल तृतीय पूँजी विनियमन मास्टर परिपत्र** के अनुसार बैंकों की पूँजी गुणवत्ता और तरलता को सुदृढ़ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बेसल-तृतीय मानक में न्यूनतम सीआरएआर 8% (+2.5% पूँजी संरक्षण बफर = 10.5%) है, जबकि **आरबीआई मानकों के अनुसार भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम सीआरएआर 9% (+2.5% पूँजी संरक्षण बफर = कुल 11.5%)** रखना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त बेसल-तृतीय में दो तरलता अनुपात शामिल हैं: **एलसीआर (तरलता कवरेज अनुपात — 30 दिनों के तीव्र तनाव हेतु उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियाँ)** और **एनएसएफआर (निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात — 1 वर्ष की दीर्घकालिक स्थिरता हेतु)**।

5.2 तुलनात्मक सारणी: एनपीए वसूली तंत्रों एवं बेसल मानकों की तुलना

वसूली तंत्र / मानक	स्थापना / अधिनियम वर्ष	न्यूनतम पात्रता राशि / मानदंड	न्यायनिर्णयन / नियामक संस्था	समय-सीमा एवं प्रमुख विशेषता
लोक अदालत	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987	**20 लाख रुपये तक** के ऋण विवाद	दीवानी न्यायालय के समकक्ष दर्जा	आपसी समझौते से त्वरित समाधान; इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)	आरडीडीबीएफआई अधिनियम, 1993	**20 लाख रुपये और उससे अधिक**	डीआरटी एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी)	6 माह में निपटान का लक्ष्य; अपील हेतु 30 दिन (बकाया का 50% जमा करने पर)
सरफेसी अधिनियम	वर्ष 2002	**1 लाख रुपये से अधिक** (सुरक्षित ऋण)	न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बैंक स्वयं	60 दिन का नोटिस देकर संपत्ति की जब्ती व नीलामी; कृषि भूमि पर लागू नहीं
आईबीसी संहिता	वर्ष 2016	**1 करोड़ रुपये** (कॉर्पोरेट डिफॉल्ट सीमा)	आईबीबीआई / एनसीएलटी	180 से अधिकतम **330 दिन** में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान या परिसमापन
बेसल तृतीय (भारत में मानक)	आरबीआई बेसल-तृतीय परिपत्र	जोखिम भारित संपत्तियों का **11.5%**	बेसल समिति एवं आरबीआई	9% सीआरएआर (7% टियर-1 + 2% टियर-2) + 2.5% पूँजी संरक्षण बफर

5.3 चार्ट डेटा (%): भारत में आरबीआई बेसल तृतीय पूँजी पर्याप्तता अनुपात (11.5%) एवं बैड बैंक की प्रतिशत संरचना

पूँजी / वसूली घटक	आरबीआई मानक (%)	अंतर्राष्ट्रीय बेसल-तृतीय मानक (%)	दृश्य अनुपात बार (आरबीआई 11.5% पैमाना)	तकनीकी विवरण एवं परीक्षा बिंदु
सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1)	5.5%	4.5%	▓▓▓

मॉड्यूल 6: भारतीय वित्तीय बाजार

6.1 विस्तृत व्याख्या: मुद्रा बाजार के लिखत एवं पूँजी बाजार (सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, आईपीओ, म्यूचुअल फंड)

भारतीय वित्तीय बाजार को परिपक्वता अवधि के आधार पर दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है:

(क) मुद्रा बाजार (अल्पकालिक बाजार)

यह **1 वर्ष या उससे कम परिपक्वता अवधि** वाले उच्च तरलता युक्त वित्तीय लिखतों का बाजार है, जिसका नियामक **भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)** है। इसके प्रमुख लिखत निम्नलिखित हैं:

1. **कॉल मुद्रा, नोटिस मुद्रा एवं सावधि (टर्म) मुद्रा:** यह मुख्य रूप से बैंकों और प्राथमिक डीलरों के बीच बिना किसी संपार्श्विक का अंतर-बैंक बाजार है:

• **कॉल मनी:** जब धन केवल **1 दिन (एक-दिवसीय)** के लिए उधार लिया या दिया जाता है।

• **नोटिस मनी:** जब धन **2 दिन से 14 दिनों** की अवधि के लिए उधार दिया जाता है।

• **टर्म मनी:** जब धन **15 दिन से 1 वर्ष** तक की अवधि के लिए उधार दिया जाता है।

2. **ट्रेजरी बिल (टी-बिल्स):** केंद्र सरकार की अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले ये शून्य-कूपन लिखत हैं। ये अंकित मूल्य से **छूट (बट्टे) पर जारी** होते हैं और परिपक्वता पर सममूल्य पर भुनाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में **3 प्रकार के टी-बिल्स** जारी होते हैं: **91 दिन, 182 दिन और 364 दिन**। इनमें न्यूनतम निवेश राशि **25,000 रुपये** और उसके गुणकों में होती है। (राज्य सरकारें टी-बिल्स जारी नहीं कर सकतीं; नकदी प्रवाह के अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए 2010 से आरबीआई के परामर्श से 91 दिनों से कम अवधि के **नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी)** भी जारी किए जाते हैं)।

3. **वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर - सीपी):** वाघुल समिति की सिफारिश पर 1990 में प्रारंभ यह उच्च रेटिंग वाली बड़ी कंपनियों, प्राथमिक डीलरों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किया जाने वाला एक **असुरक्षित वचन पत्र** है। इसकी परिपक्वता अवधि **न्यूनतम 7 दिन से अधिकतम 1 वर्ष** होती है तथा यह **5 लाख रुपये** और उसके गुणकों में जारी किया जाता है।

4. **जमा प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट - सीडी):** वर्ष 1989 में प्रारंभ यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा डीमैट रूप में जारी किया जाने वाला एक परक्राम्य मुद्रा बाजार लिखत है। बैंकों द्वारा जारी सीडी की परिपक्वता अवधि 7 **दिन से 1 वर्ष** (वित्तीय संस्थानों के लिए 1 से 3 वर्ष) होती है और इसकी न्यूनतम निवेश राशि भी **5 लाख रुपये** और उसके गुणकों में होती है।

(ख) पूँजी बाजार (दीर्घकालिक बाजार)

यह **1 वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि** वाले शेयर (इक्विटी) और ऋण (बॉन्ड/डिबेंचर) लिखतों का बाजार है, जिसका नियामक **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)** है।

• **प्राथमिक बाजार:** इसे 'नया निर्गम बाजार' कहते हैं, जहाँ कंपनियाँ पहली बार जनता को नई प्रतिभूतियाँ जारी करके सीधे पूँजी जुटाती हैं। जब कोई असूचीबद्ध कंपनी पहली बार जनता को शेयर जारी करती है तो उसे **प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ)** कहते हैं, और जब पहले से सूचीबद्ध कंपनी पुनः नए शेयर जारी करती है तो उसे **अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ)** कहते हैं। आईपीओ में आवेदन हेतु **सेबी** ने **आस्बा (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन)** अनिवार्य किया है, जिसमें शेयर आवंटित होने तक निवेशक की राशि उसके बैंक खाते में ही अवरुद्ध (ब्लॉक) रहती है और उस पर ब्याज मिलता रहता है।

• **द्वितीयक बाजार (स्टॉक एक्सचेंज):** जहाँ पूर्व में जारी प्रतिभूतियों का निवेशकों के बीच क्रय-विक्रय होता है। भारत में प्रतिभूति बाजार में **टी+1 (व्यापार के अगले कार्यदिवस पर) एवं त्वरित (टी+0) निपटान चक्र** लागू किया गया है।

• **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई):** 1875 में प्रेमचंद रॉयचंद द्वारा 'नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन' के रूप में स्थापित यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका संवेदी सूचकांक **सेंसेक्स** है, जिसमें **30 प्रमुख कंपनियों** के फ्री-फ्लोट बाजार पूँजीकरण को शामिल किया जाता है (आधार वर्ष 1978-79 = 100)।

• **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई):** फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में स्थापित यह भारत का सबसे बड़ा तकनीकी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका प्रमुख सूचकांक **निफ्टी-50** है, जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की **50 शीर्ष कंपनियाँ** शामिल हैं (आधार वर्ष 1995 = 1000)।

• **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी):** 12 अप्रैल 1988 को एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित हुआ और हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाले के पश्चात **30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम, 1992** के माध्यम से इसे पूर्ण **सांविधिक और स्वायत्त नियामक** का दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है।

• **म्यूचुअल फंड, डीमैट एवं डेरिवेटिव्स (व्युत्पन्न):**

• **म्यूचुअल फंड:** छोटे निवेशकों से धन एकत्र कर पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा शेयरों, बॉन्डों व मुद्रा बाजार में निवेश करने वाली योजनाएँ, जिनका मूल्यांकन **निवल संपत्ति मूल्य (एनएवी)** पर होता है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड 1963 में गठित भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) था।

• **डीमैट खाता:** भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखने का खाता। भारत में दो मुख्य डिपॉजिटरी हैं: **एनएसडीएल (1996, एनएसई द्वारा प्रवर्तित)** और **सीडीएसएल (1999, बीएसई द्वारा प्रवर्तित)**।

• **डेरिवेटिव्स (व्युत्पन्न अनुबंध):** ऐसे वित्तीय अनुबंध जिनका मूल्य किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति (जैसे शेयर, सूचकांक, कमोडिटी या मुद्रा) के मूल्य से प्राप्त होता है। इसके 4 मुख्य प्रकार हैं: **फॉरवर्ड, फ्यूचर्स (वायदा), ऑप्शंस (विकल्प) और स्वैप**।

6.2 तुलनात्मक सारणी: मुद्रा बाजार बनाम पूँजी बाजार एवं प्रमुख वित्तीय लिखतों का विश्लेषण

लिखत / बाजार का नाम	जारीकर्ता संस्था	परिपक्वता अवधि	न्यूनतम निवेश राशि	नियामक एवं प्रमुख विशेषता
कॉल एवं नोटिस मनी	अंतर-बैंक एवं प्राथमिक डीलर	कॉल: **1 दिन** / नोटिस: **2 से 14 दिन**	अंतर-बैंक थोक मानक	आरबीआई द्वारा विनियमित; बिना किसी संपार्श्विक के
ट्रेजरी बिल (टी-बिल्स)	केवल **केंद्र सरकार** (आरबीआई द्वारा)	**91 दिन, 182 दिन एवं 364 दिन**	**25,000 रुपये** (एवं इसके गुणक)	शून्य-कूपन बॉन्ड; छूट पर जारी व सममूल्य पर मोचन; पूर्णतः जोखिम-मुक्त
वाणिज्यिक पत्र (सीपी)	उच्च रेटिंग वाली कॉर्पोरेट कंपनियाँ	**7 दिन से 1 वर्ष** तक	**5 लाख रुपये** (एवं इसके गुणक)	असुरक्षित वचन पत्र; कार्यशील पूँजी जुटाने हेतु जारी
जमा प्रमाणपत्र (सीडी)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)	**7 दिन से 1 वर्ष** (बैंकों हेतु)	**5 लाख रुपये** (एवं इसके गुणक)	डीमैट रूप में परक्राम्य लिखत; बैंक तरलता जुटाने हेतु जारी करते हैं
पूँजी बाजार (बीएसई / एनएसई)	कॉर्पोरेट कंपनियाँ (आईपीओ / एफपीओ / बॉन्ड)	दीर्घकालिक (**1 वर्ष से अधिक**)	खुदरा आईपीओ लॉट आकार (आस्बा)	सेबी द्वारा विनियमित; बीएसई (सेंसेक्स-30) व एनएसई (निफ्टी-50)

6.3 चार्ट डेटा (%): भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश एवं पूँजी जुटाने के लिखतों का संरचनात्मक अनुपात (%)

वित्तीय बाजार खंड	कुल बाजार कारोबार / आवंटन में हिस्सा (%)	दृश्य अनुपात बार (10 इकाइयाँ = 100%)	नियामक प्राधिकरण एवं जोखिम प्रोफाइल
सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं ट्रेजरी बिल	38.0%	▓▓▓▓	भारतीय रिज़र्व बैंक — संप्रभु गारंटी (शून्य डिफॉल्ट जोखिम)
इक्विटी एवं डेरिवेटिव्स बाजार (बीएसई व एनएसई)	32.0%	▓▓▓	सेबी — उच्च तरलता एवं बाजार आधारित प्रतिफल
कॉर्पोरेट बॉन्ड, सीपी एवं सीडी	18.0%	▓▓	आरबीआई (मुद्रा बाजार) एवं सेबी (सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बॉन्ड)
म्यूचुअल फंड एवं खुदरा एसआईपी प्रवाह	12.0%	▓	सेबी (म्यूचुअल फंड विनियमन, 1996) — विविध पोर्टफोलियो निवेश
कुल वित्तीय बाजार पारिस्थितिकी	**100.0%**	▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓	मुद्रा बाजार (अल्पकालिक) + पूँजी बाजार (दीर्घकालिक)

6.4 मॉड्यूल 6 की स्मृति ट्रिक्स

★ स्मृति ट्रिक 11 (मुद्रा बाजार के लिखतों की अवधि और न्यूनतम राशि याद रखने का सूत्र):
"1 दिन कॉल, 2 से 14 नोटिस, 15 से 365 टर्म कहलाए; 91-182-364 दिन का टी-बिल 25 हजार में सरकार लाए, जबकि 7 दिन से 1 साल का सीपी (कंपनी) और सीडी (बैंक) 5 लाख में आए!"
व्याख्या: इस एक सूत्र से कॉल मनी (1 दिन), नोटिस मनी (2-14 दिन), टर्म मनी (15 दिन-1 वर्ष), टी-बिल्स (91, 182, 364 दिन — 25,000 रु. न्यूनतम, केवल केंद्र सरकार), कमर्शियल पेपर (7 दिन-1 वर्ष, 5 लाख रु. न्यूनतम, कंपनी) और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (7 दिन-1 वर्ष, 5 लाख रु. न्यूनतम, बैंक) के सभी प्रश्न हल हो जाते हैं।

★ स्मृति ट्रिक 12 (बीएसई बनाम एनएसई एवं सेबी स्थापना का सूत्र):
"1875 में बीएसई ने 30 सेंसेक्स व सीडीएसएल बनाया; 1992 में फेरवानी से एनएसई ने 50 निफ्टी व एनएसडीएल चलाया और 1988 में जन्मे सेबी ने 1992 में कानूनी हक पाया!"
व्याख्या: बीएसई (1875, सेंसेक्स = 30 शेयर, डिपॉजिटरी = सीडीएसएल); एनएसई (1992, फेरवानी समिति, निफ्टी = 50 शेयर, डिपॉजिटरी = एनएसडीएल); सेबी (स्थापना 1988, सांविधिक दर्जा 1992)।

मॉड्यूल 7: बीमा जागरूकता एवं पेंशन क्षेत्र

7.1 विस्तृत व्याख्या: भारत में बीमा का विकास, एलआईसी, जीआईसी, इरडाई, बीमा के सिद्धांत एवं पेंशन योजनाएँ

भारत में बीमा का इतिहास एवं राष्ट्रीयकरण:

• भारत में आधुनिक जीवन बीमा की शुरुआत **1818** में कलकत्ता में यूरोपियनों द्वारा स्थापित **'ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी'** से हुई। भारतीयों के साथ बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम भेदभाव के बीमा करने वाली पहली भारतीय कंपनी 1870 में स्थापित **'बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी'** थी।

• सामान्य बीमा के क्षेत्र में पहली कंपनी 1850 में कलकत्ता में स्थापित **'ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड'** थी। वर्ष 1912 में पहला भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम और 1938 में व्यापक **बीमा अधिनियम, 1938** पारित किया गया।

• **एलआईसी अधिनियम, 1956 (जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण):** 19 जून 1956 को संसद द्वारा जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित कर 245 निजी भारतीय एवं विदेशी बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट सोसाइटियों का विलय किया गया, और **1 सितंबर 1956** को 5 करोड़ रुपये की सरकारी पूँजी के साथ **भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)** की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका आदर्श वाक्य "योगक्षेमं वहाम्यहम्" (आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है — श्रीमद्भगवद्गीता से उद्धृत) है।

• **जीआईसी एवं सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण (1972): सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972** के तहत 107 निजी गैर-जीवन बीमा कंपनियों को मिलाकर **22 नवंबर 1972** को **भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी री)** की स्थापना की गई और इसके अधीन 4 सहायक कंपनियाँ बनाई गईं: (1) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कोलकाता), (2) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मुंबई), (3) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (नई दिल्ली), और (4) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (चेन्नई)। दिसंबर 2000 में जीआईसी को भारत की एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी (**जीआईसी री**) घोषित कर चारों कंपनियों को इससे स्वतंत्र कर दिया गया।

इरडाई (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) की भूमिका:

आरबीआई के पूर्व गवर्नर **आर. एन. मल्होत्रा समिति (1993)** की सिफारिश पर बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने और एक स्वतंत्र नियामक बनाने हेतु **इरडा अधिनियम, 1999** पारित किया गया तथा **अप्रैल 2000** में **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई)** का गठन हुआ। इसका मुख्यालय **हैदराबाद (तेलंगाना)** में है (2001 में दिल्ली से स्थानांतरित)। इसमें 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इरडाई ने वर्ष 2047 तक **"सबके लिए बीमा (2047 तक)"** का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 'बीमा सुगम' (डिजिटल मार्केटप्लेस), 'बीमा विस्तार' (ऑल-इन-वन किफायती उत्पाद) और 'बीमा वाहक' (महिला केंद्रित ग्राम स्तरीय वितरण बल) की शुरुआत की गई है तथा शिकायत निवारण हेतु **बीमा भरोसा पोर्टल** संचालित है।

बीमा के 7 मूलभूत सिद्धांत (जीवन बीमा बनाम सामान्य बीमा):

1. **परम सद्भाव का सिद्धांत:** बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति दोनों को अनुबंध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य (जैसे पुरानी बीमारी, संपत्ति का जोखिम) बिना छुपाए पूरी सच्चाई से प्रकट करने चाहिए। यह जीवन और सामान्य दोनों बीमाओं पर लागू होता है।

2. **बीमा योग्य हित का सिद्धांत:** बीमित व्यक्ति का बीमा की विषय-वस्तु में ऐसा वित्तीय हित होना चाहिए कि उसके सुरक्षित रहने से उसे लाभ हो और नष्ट होने से आर्थिक हानि हो। जीवन बीमा में यह हित पॉलिसी लेते समय होना अनिवार्य है, जबकि समुद्री बीमा में दावा के समय और अग्नि/सामान्य बीमा में पॉलिसी लेने व दावा दोनों समय होना आवश्यक है।

3. **क्षतिपूर्ति का सिद्धांत:** बीमा का उद्देश्य बीमित व्यक्ति को हानि से ठीक पहले वाली वित्तीय स्थिति में वापस लाना है, न कि मुनाफा कमाना। **यह सिद्धांत केवल सामान्य बीमा (अग्नि, समुद्री, मोटर आदि) पर लागू होता है; जीवन बीमा पर लागू नहीं होता**, क्योंकि मानव जीवन का मूल्य धन में नहीं आँका जा सकता (जीवन बीमा 'आश्वासन' का अनुबंध है)।

4. **प्रस्थापन या अधिकार समर्पण का सिद्धांत (सब्रोगेशन):** क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने के पश्चात, क्षतिग्रस्त संपत्ति के अवशेषों और तीसरे पक्ष से वसूली करने के बीमित व्यक्ति के सभी कानूनी अधिकार बीमा कंपनी को स्वतः स्थानांतरित हो जाते हैं। यह भी **केवल सामान्य बीमा** पर लागू होता है।

5. **अंशदान का सिद्धांत:** यदि किसी व्यक्ति ने एक ही संपत्ति का एक से अधिक बीमा कंपनियों से बीमा कराया है (दोहरा बीमा), तो हानि होने पर सभी बीमा कंपनियाँ अपने-अपने बीमा अनुपात में मिलकर केवल वास्तविक हानि के बराबर ही भुगतान करेंगी। यह भी **केवल सामान्य बीमा** पर लागू होता है (जीवन बीमा में व्यक्ति जितनी चाहे पॉलिसियाँ ले सकता है और सभी से पूरा दावा मिलता है)।

6. **आसन्न कारण का सिद्धांत:** जब हानि एक से अधिक कारणों से हुई हो, तो दावा तय करने के लिए सबसे निकटतम और प्रत्यक्ष प्रभावी कारण को देखा जाता है, न कि दूरस्थ कारण को।

7. **हानि अल्पीकरण का सिद्धांत:** दुर्घटना के समय बीमित व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी संपत्ति को बचाने के लिए वैसे ही समझदारी भरे प्रयास करे जैसे वह बीमा न होने पर करता।

पेंशन क्षेत्र: पीएफआरडीए, एनपीएस एवं अटल पेंशन योजना:

• **पीएफआरडीए (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण):** भारत सरकार के 'ओएसिस प्रोजेक्ट' की सिफारिश पर अगस्त 2003 में स्थापित इस संस्था को **पीएफआरडीए अधिनियम, 2013** के माध्यम से 1 फरवरी 2014 को सांविधिक दर्जा मिला। इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में है और ग्राहकों की शिकायत निवारण हेतु **पेंशन सहायक पोर्टल** कार्यरत है।

• **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस):** 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए और 1 मई 2009 से देश के सभी नागरिकों (18 से 70 वर्ष आयु वर्ग) के लिए लागू एक अंशदायी पेंशन प्रणाली है। इसमें प्रत्येक ग्राहक को 12 अंकों का **प्रान (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या)** दिया जाता है और इसमें दो खाते होते हैं: **टियर-1 (अनिवार्य सेवानिवृत्ति खाता — कर लाभ सहित)** और **टियर-2 (स्वैच्छिक बचत खाता — कभी भी निकासी योग्य)**।

• **अटल पेंशन योजना (एपीवाई):** 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रारंभ और 1 जून 2015 से प्रभावी यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इसमें **18 से 40 वर्ष** की आयु के गैर-आयकरदाता नागरिक शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उनके अंशदान के अनुसार **1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये प्रतिमाह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन** मिलती है।

7.2 तुलनात्मक सारणी: जीवन बीमा बनाम सामान्य बीमा एवं प्रमुख बीमा-पेंशन संस्थान

तुलना का आधार	जीवन बीमा (आश्वासन अनुबंध)	सामान्य बीमा (गैर-जीवन बीमा)	पेंशन क्षेत्र (एनपीएस एवं एपीवाई)
प्रमुख सार्वजनिक संस्था एवं स्थापना	**भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)** — 1 सितंबर 1956	**जीआईसी री** (1972) एवं 4 सार्वजनिक कंपनियाँ	**पीएफआरडीए** — अधिनियम 2013 (मुख्यालय: नई दिल्ली)
नियामक प्राधिकरण	**इरडाई** — अधिनियम 1999 (मुख्यालय: हैदराबाद)	**इरडाई** — बीमा अधिनियम 1938 व 1999	पीएफआरडीए (वित्त मंत्रालय के अधीन)
अनुबंध की प्रकृति व अवधि	दीर्घकालिक आश्वासन अनुबंध (घटना निश्चित, समय अनिश्चित)	सामान्यतः 1 वर्षीय क्षतिपूर्ति अनुबंध (नवीकरणीय)	सेवानिवृत्ति कोष (60 वर्ष की आयु के पश्चात वार्षिकी/पेंशन)
क्षतिपूर्ति, प्रस्थापन व अंशदान सिद्धांत	**लागू नहीं होते** (मानव जीवन अमूल्य है; बहु-पॉलिसी दावा मान्य)	**पूर्णतः लागू होते हैं** (केवल वास्तविक हानि की भरपाई)	अंशदान एवं संचित कोष के निवेश प्रतिफल पर आधारित
परम सद्भाव एवं बीमा योग्य हित	दोनों सिद्धांत लागू (पॉलिसी लेते समय बीमा योग्य हित अनिवार्य)	दोनों सिद्धांत लागू (लेते समय व दावे के समय हित अनिवार्य)	एनपीएस आयु: 18-70 वर्ष; एपीवाई आयु: 18-40 वर्ष (1000-5000 रु. पेंशन)

7.3 चार्ट डेटा (%): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) निकासी नियम एवं बीमा क्षेत्र एफडीआई सीमा (%)

नियम / नियामक मानक	निर्धारित प्रतिशत (%)	दृश्य अनुपात बार (10 इकाइयाँ = 100%)	वैधानिक एवं परीक्षापयोगी विवरण
एनपीएस परिपक्वता (60 वर्ष): कर-मुक्त एकमुश्त निकासी	60.0%		60 वर्ष की आयु पर कुल संचित कोष का अधिकतम 60% हिस्सा एकमुश्त कर-मुक्त निकाला जा सकता है
एनपीएस परिपक्वता (60 वर्ष): अनिवार्य वार्षिकी	40.0%		नियमित मासिक पेंशन हेतु न्यूनतम 40% कोष से वार्षिकी योजना खरीदना अनिवार्य
एनपीएस समय-पूर्व निकासी (60 वर्ष से पहले): अनिवार्य वार्षिकी	80.0%		60 वर्ष से पूर्व बाहर निकलने पर 80% राशि वार्षिकी में और केवल 20% एकमुश्त मिलती है
केंद्र/राज्य सरकार एनपीएस नियोक्ता अंशदान	14.0%		कर्मचारी का अंशदान मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10% और सरकार का अंशदान 14%
बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा	74.0%		बीमा (संशोधन) अधिनियम 2021 द्वारा 49% से बढ़ाकर 74% किया गया

7.4 मॉड्यूल 7 की स्मृति ट्रिक्स

★ **स्मृति ट्रिक 13 (जीवन बीमा बनाम सामान्य बीमा के सिद्धांतों का भेद याद रखने का सूत्र):**
"सद्भाव, हित और आसन्न कारण सब में समाए; पर क्षतिपूर्ति, प्रस्थापन और अंशदान जीवन बीमा में कभी न आए!"
व्याख्या: परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है कि कौन-सा सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता — याद रखें कि क्षतिपूर्ति, प्रस्थापन और अंशदान केवल सामान्य बीमा पर लागू होते हैं, जीवन बीमा पर नहीं।

★ **स्मृति ट्रिक 14 (एलआईसी, जीआईसी, इरडाई और अटल पेंशन योजना के वर्षों व मुख्यालयों का सूत्र):**
"56 में एलआईसी (मुंबई), 72 में जीआईसी (मुंबई), 99 के एक्ट से हैदराबाद में इरडाई; 18 से 40 की उम्र में अटल पेंशन ने 1 से 5 हजार की गारंटी दिलाई!"
व्याख्या: एलआईसी (1956, मुंबई), जीआईसी (1972, मुंबई), इरडाई (1999 अधिनियम, 2000 स्थापना, मुख्यालय हैदराबाद), अटल पेंशन योजना (18-40 वर्ष प्रवेश आयु, 60 वर्ष बाद 1000 से 5000 रुपये मासिक पेंशन)।

मॉड्यूल 8: प्रमुख बैंकिंग समितियाँ, परक्राम्य लिखत अधिनियम (1881) एवं बैंकिंग लोकपाल

8.1 विस्तृत व्याख्या: ऐतिहासिक बैंकिंग समितियाँ, परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक व धारा 138) एवं एकीकृत लोकपाल योजना

(क) प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय समितियाँ

1. **नरसिंहम समिति प्रथम (1991) एवं द्वितीय (1998):**

• **वित्तीय प्रणाली पर समिति (1991):** इसने सीआरआर और एसएलआर को चरणबद्ध रूप से कम करने, ब्याज दरों को नियंत्रण-मुक्त करने, 4-स्तरीय बैंकिंग संरचना बनाने, एनपीए की पहचान व वर्गीकरण के पारदर्शी मानदंड लागू करने तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (एआरसी) बनाने की सिफारिश की।

• **बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर समिति (1998):** इसने पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) को बढ़ाने, मजबूत बैंकों के आपसी विलय को प्रोत्साहित करने, संकीर्ण बैंकिंग की अवधारणा और सरफेसी जैसे कड़े वसूली कानून बनाने की अनुशंसा की।

2. **डॉ. नचिकेत मोर समिति (2013):** 'छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति' ने प्रत्येक वयस्क भारतीय को 1 जनवरी 2016 तक बैंक खाता उपलब्ध कराने, **भुगतान बैंकों** की स्थापना करने, और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में समायोजित भार देने की सिफारिश की।

3. **पी. जे. नायक समिति (2014):** 'भारत में बैंकों के बोर्डों के शासन की समीक्षा करने के लिए समिति' ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम करने, 1969 व 1980 के राष्ट्रीयकरण अधिनियमों को निरस्त कर सभी सरकारी बैंकों को कंपनी अधिनियम के तहत लाने और शीर्ष नियुक्तियों के लिए **बैंक बोर्ड ब्यूरो (2016 में गठित, जो अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो — एफएसआईबी बन चुका है)** की स्थापना करने की सिफारिश की।

4. **उर्जित पटेल समिति (2014):** 'मौद्रिक नीति ढाँचे की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए विशेषज्ञ समिति' ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के स्थान पर **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई - संयुक्त)** को मुख्य मुद्रास्फीति मानक बनाने, **4% (±2%)** का मुद्रास्फीति लक्ष्य रखने और **6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)** गठित करने की ऐतिहासिक सिफारिश की।

5. **विमल जालान समिति (2019):** इसने **भारतीय रिज़र्व बैंक** के **आर्थिक पूँजी ढाँचे** की समीक्षा की और सिफारिश की कि आरबीआई का आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) उसकी बैलेंस शीट के **5.5% से 6.5%** के बीच रखा जाना चाहिए, जिसके आधार पर आरबीआई केंद्र सरकार को अतिरिक्त अधिशेष (लाभांश) हस्तांतरित करता है। (2013 में विमल जालान समिति ने नए निजी बैंक लाइसेंस — बंधन बैंक व आईडीएफसी फर्स्ट बैंक — की भी जांच की थी)।

(ख) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

1 मार्च 1882 से लागू इस अधिनियम में मुख्य रूप से 3 परक्राम्य लिखतों को परिभाषित किया गया है:

• **धारा 4 — वचन पत्र:** एक लिखित और हस्ताक्षरित लिखत (बैंक नोट या करेंसी नोट को छोड़कर) जिसमें लेखक किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार एक निश्चित राशि चुकाने की **बिना शर्त प्रतिज्ञा** करता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं: निर्माता (देनदार) और आदाता (लेनदार)।

• **धारा 5 — विनिमय बिल:** एक लिखित और हस्ताक्षरित लिखत जिसमें लेखक किसी निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित राशि चुकाने का **बिना शर्त आदेश** देता है। इसमें 3 पक्ष होते हैं: आहरता, अदाकर्ता और आदाता।

• **धारा 6 — चेक:** यह एक ऐसा विनिमय बिल है जो किसी **निर्दिष्ट बैंकर** पर आहरित किया जाता है और जो माँग पर देय होता है। इसमें चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज और ट्रंकेटेड चेक (सीटीएस) भी शामिल हैं।

• **चेक के प्रमुख प्रकार:** (1) **वाहक चेक:** जिसका भुगतान खिड़की पर प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को हो जाता है; (2) **आदेश चेक:** जिसका भुगतान केवल नामित व्यक्ति या उसके द्वारा पृष्ठांकित व्यक्ति को होता है; (3) **रेखांकित चेक:** चेक के बाएँ ऊपरी कोने पर दो समानांतर तिरछी रेखाएँ खींचने से उसका नकद भुगतान काउंटर पर नहीं होता, बल्कि राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है; (4) **कालबाह्य चेक:** जारी करने की तिथि से **3 माह** बीत जाने के बाद चेक अमान्य हो जाता है; (5) **उत्तर-दिनांकित चेक:** जिस पर भविष्य की तारीख लिखी हो; (6) **पूर्व-दिनांकित चेक:** जिस पर वास्तविक प्रस्तुति से पहले की तारीख (किंतु 3 माह के भीतर) लिखी हो।

• **धारा 138 — खाते में अपर्याप्त निधि के कारण चेक का अनादरण (चेक बाउंस):** यदि कोई चेक बैंक खाते में अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो जाता है, तो आदाता को बैंक से मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर जारीकर्ता को नोटिस देना होता है। यदि नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता, तो यह एक दंडनीय अपराध है जिसमें **अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास या चेक राशि के दोगुने तक का जुर्माना या दोनों** हो सकते हैं। (धारा 143-ए के तहत न्यायालय अंतरिम मुआवजे के रूप में चेक राशि का 20% तक दिलाने का आदेश दे सकता है)।

(ग) बैंकिंग लोकपाल एवं रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना

ग्राहकों की बैंकिंग शिकायतों के त्वरित और निःशुल्क समाधान हेतु आरबीआई ने 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की थी। 11 नवंबर 2021 को तीन अलग-अलग लोकपाल योजनाओं (बैंकिंग लोकपाल 1995, एनबीएफसी लोकपाल 2018 और डिजिटल लेनदेन लोकपाल 2019) को मिलाकर **'एक राष्ट्र, एक लोकपाल'** के सिद्धांत पर **रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना** लागू की गई, जिसे **आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 (1 जुलाई 2026 से प्रभावी)** के रूप में अद्यतन और सुदृढ़ किया गया है:

• **व्यापक कवरेज:** इसमें सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, **50 करोड़ रुपये या अधिक जमा आधार वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक/राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक**, **100 करोड़ रुपये या अधिक संपत्ति आकार वाली ग्राहक-इंटरफेस एनबीएफसी**, भुगतान प्रणाली प्रतिभागी और **क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (जैसे सिबिल)** शामिल हैं।

• **शिकायत प्रक्रिया एवं मुआवजा सीमा:** यदि बैंक को शिकायत करने के **30 दिनों के भीतर** उत्तर नहीं मिलता या ग्राहक उत्तर से असंतुष्ट है, तो वह 1 वर्ष के भीतर **आरबीआई शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल**, चंडीगढ़ स्थित केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र या टोल-फ्री नंबर **14448** पर शिकायत दर्ज कर सकता है।

• लोकपाल वास्तविक वित्तीय हानि के लिए **20 लाख रुपये तक का मुआवजा (पंचाट)** दे सकता है, और इसके अतिरिक्त ग्राहक के समय की बर्बादी, खर्च तथा **मानसिक उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपये तक का अतिरिक्त मुआवजा** दे सकता है। लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (आरबीआई के प्रभारी डिप्टी गवर्नर/कार्यकारी निदेशक) के समक्ष अपील की जा सकती है।

8.2 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख बैंकिंग समितियाँ, एनआई एक्ट 1881 की धाराएँ एवं लोकपाल मानक

समिति / अधिनियम धारा / योजना	वर्ष / वैधानिक संदर्भ	अध्यक्ष / मुख्य प्रावधान	परीक्षापयोगी प्रमुख सिफारिश / दंड या सीमा
नरसिंहम समिति (प्रथम एवं द्वितीय)	1991 एवं 1998	एम. नरसिंहम	सीआरआर/एसएलआर कटौती, 90-दिवसीय एनपीए मानक, डीआरटी, सरफेसी व बैंक विलय
नचिकेत मोर एवं पी. जे. नायक समिति	2013 एवं 2014	डॉ. नचिकेत मोर / डॉ. पी. जे. नायक	नचिकेत मोर: **भुगतान बैंक**; पी. जे. नायक: **बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब एफएसआईबी)** व शासन सुधार
उर्जित पटेल एवं विमल जालान समिति	2014 एवं 2019	डॉ. उर्जित पटेल / डॉ. विमल जालान	उर्जित पटेल: **एमपीसी व सीपीआई 4%±2%**; विमल जालान: **आरबीआई आर्थिक पूँजी ढाँचा (5.5%-6.5% सीआरबी)**
एनआई एक्ट 1881: धारा 4, 5, 6 एवं 138	1881 (1 मार्च 1882 से लागू)	वचन पत्र (4), विनिमय बिल (5), चेक (6)	**धारा 138 (चेक बाउंस):** 2 वर्ष तक की जेल या चेक राशि का दोगुना जुर्माना (या दोनों); चेक वैधता 3 माह
एकीकृत लोकपाल योजना	आरबीआई लोकपाल 2021 / 2026	एक राष्ट्र, एक लोकपाल (टोल-फ्री: 14448)	वित्तीय क्षति हेतु **20 लाख रुपये** तक पंचाट + मानसिक संताप हेतु **1 लाख रुपये** तक अतिरिक्त मुआवजा

8.3 चार्ट डेटा (%): विमल जालान आर्थिक पूँजी ढाँचा, धारा 143-ए अंतरिम मुआवजा एवं लोकपाल कवरेज मानक (%)

मानक / वैधानिक प्रावधान	निर्धारित प्रतिशत / अनुपात मानक	दृश्य अनुपात बार (मानक तीव्रता पैमाना)	नियामक एवं वैधानिक स्पष्टीकरण
विमल जालान समिति: आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी)	5.5% से 6.5%	▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓	आरबीआई की बैलेंस शीट के 5.5%-6.5% हिस्से को जोखिम बफर रखकर शेष अधिशेष सरकार को देय
पी. जे. नायक समिति: सरकारी हिस्सेदारी सीमा प्रस्ताव	< 50.0%	▓▓▓▓▓▓▓▓	सरकारी बैंकों में स्वामित्व को 50% से नीचे लाकर बोर्ड-संचालित कंपनी बनाने का सुझाव
एनआई एक्ट धारा 143-ए: अंतरिम मुआवजा सीमा	20.0% (अधिकतम)	▓▓▓▓	चेक बाउंस मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता को चेक राशि के 20% तक अंतरिम राहत
डीआरएटी अपील पूर्व जमा आवश्यकता	50.0% (न्यूनतम 25%)	▓▓▓▓▓▓▓▓	डीआरटी के आदेश के विरुद्ध अपील करने हेतु कर्जदार को ऋण राशि का 50% जमा करना होता है
एकीकृत लोकपाल मुआवजा अनुपात (वित्तीय : मानसिक)	20 लाख रु. : 1 लाख रु.	▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓	आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना के तहत सेवा में कमी पर अधिकतम राहत

8.4 मॉड्यूल 8 की स्मृति ट्रिक एवं संपूर्ण 15 स्मृति ट्रिक्स की त्वरित पुनरीक्षण तालिका

★ स्मृति ट्रिक 15 (एनआई एक्ट 1881 की धाराएँ, समितियाँ और बैंकिंग लोकपाल का मास्टर सूत्र):
"धारा 4 में वचन दिया, 5 में बिल का आदेश किया, 6 में 3 महीने का चेक काटा और 138 में बाउंस होने पर 2 साल जेल व दोगुना जुर्माना पाया! 30 दिन बैंक न सुने तो 14448 पर लोकपाल ने 20 लाख (+1 लाख) दिलाया!"
व्याख्या: परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 4 (वचन पत्र), धारा 5 (विनिमय बिल), धारा 6 (चेक — वैधता 3 माह), धारा 138 (चेक अनादरण — 2 वर्ष कारावास या दोगुना जुर्माना); तथा रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (30 दिन प्रतीक्षा, हेल्पलाइन 14448, अधिकतम 20 लाख रुपये मुआवजा + 1 लाख रुपये मानसिक उत्पीड़न मुआवजा)।

संपूर्ण 15 स्मृति ट्रिक्स की एकीकृत संदर्भ सारणी (परीक्षा पूर्व 5-मिनट रिवीजन गाइड)

ट्रिक संख्या	संबंधित मॉड्यूल	मुख्य विषय-वस्तु	परीक्षा हेतु मुख्य स्मृति कुंजी
ट्रिक 1	मॉड्यूल 1	प्रेसीडेंसी बैंक एवं एसबीआई	बंगाल (1806) → बॉम्बे (1840) → मद्रास (1843) → इम्पीरियल (1921) → एसबीआई (1955)
ट्रिक 2	मॉड्यूल 1	सार्वजनिक बैंकों का महा-विलय	पीएनबी (ओबीसी+यूबीआई), केनरा (सिंडिकेट), यूनियन (आंध्रा+कॉर्पोरेशन), इंडियन (इलाहाबाद), बॉब (विजया+देना)
ट्रिक 3	मॉड्यूल 2	सीआरआर बनाम एसएलआर धाराएँ	धारा 42(1) आरबीआई एक्ट = सीआरआर (केवल नकद); धारा 24 बीआर एक्ट = एसएलआर (नकद+स्वर्ण+बॉन्ड)
ट्रिक 4	मॉड्यूल 2	एलएएफ कॉरिडोर व महंगाई नियंत्रण	एसडीएफ (रेपो - 0.25%) < रेपो दर < एमएसएफ/बैंक दर (रेपो + 0.25%); मुद्रास्फीति में दरें बढ़ती हैं
ट्रिक 5	मॉड्यूल 3	आरआरबी पूँजी व बैंक समितियाँ	आरआरबी = 50% (केंद्र) : 35% (प्रायोजक) : 15% (राज्य); नचिकेत मोर (पेमेंट), उषा थोराट (एसएफबी)
ट्रिक 6	मॉड्यूल 3	मुद्रा योजना व पीएसएल स्लैब	शिशु (50 हजार), किशोर (5 लाख), तरुण (10 लाख), तरुण प्लस (20 लाख); पीएसएल: 40%, 60% (यूसीबी), 75%
ट्रिक 7	मॉड्यूल 4	बैंकिंग पहचान कोडों के अंक	एमएमआईडी = 7 अंक; एमआईसीआर = 9 अंक (3+3+3); आईएफएससी = 11 वर्ण (5वाँ '0'); स्विफ्ट = 8 या 11 वर्ण
ट्रिक 8	मॉड्यूल 4	एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई	एनईएफटी (48 बैच, सीमा नहीं); आरटीजीएस (न्यूनतम 2 लाख); आईएमपीएस (5 लाख); यूपीआई (1-5 लाख)
ट्रिक 9	मॉड्यूल 5	एसएमए, एनपीए एवं वसूली सीमाएँ	एसएमए (0,1,2 = 1-90 दिन); >90 दिन एनपीए; सरफेसी (>1 लाख), लोक अदालत/डीआरटी (20 लाख), आईबीसी (1 करोड़)
ट्रिक 10	मॉड्यूल 5	बेसल-तृतीय पूँजी पर्याप्तता 11.5%	सीईटी-1 (5.5%) + एटी-1 (1.5%) = टियर-1 (7%) + टियर-2 (2%) = सीआरएआर (9%) + सीसीबी (2.5%) = 11.5%
ट्रिक 11	मॉड्यूल 6	मुद्रा बाजार के लिखत व राशि	कॉल (1 दिन), नोटिस (2-14 दिन); टी-बिल्स (91,182,364 दिन — 25,000 रु.); सीपी व सीडी (7 दिन-1 वर्ष — 5 लाख रु.)
ट्रिक 12	मॉड्यूल 6	बीएसई, एनएसई एवं सेबी स्थापना	बीएसई (1875, सेंसेक्स-30, सीडीएसएल); एनएसई (1992, फेरवानी समिति, निफ्टी-50, एनएसडीएल); सेबी (1988/1992 एक्ट)
ट्रिक 13	मॉड्यूल 7	बीमा के सिद्धांतों का अंतर	क्षतिपूर्ति, प्रस्थापन और अंशदान केवल सामान्य बीमा पर लागू होते हैं, जीवन बीमा पर कभी नहीं
ट्रिक 14	मॉड्यूल 7	एलआईसी, जीआईसी, इरडाई व एपीवाई	एलआईसी (1956), जीआईसी (1972), इरडाई (1999 एक्ट, हैदराबाद); अटल पेंशन (18-40 वर्ष, 1000-5000 रु.)
ट्रिक 15	मॉड्यूल 8	एनआई एक्ट 1881 व बैंकिंग लोकपाल	धारा 4 (वचन पत्र), 5 (बिल), 6 (चेक-3 माह), 138 (2 वर्ष जेल/2 गुना जुर्माना); लोकपाल (14448, 20 लाख+1 लाख रु.)

यह खंड अखिल भारतीय बैंकिंग परीक्षाओं (आईबीपीएस पीओ/क्लर्क/आरआरबी, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक ग्रेड-बी/सहायक, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, एलआईसी एएओ, एनआईएसीएल, ईपीएफओ एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं) के लिए **समावेशी सार्वभौमिक करियर अकादमी (IUC Academy)** द्वारा विकसित 10 सचित्र प्रमुख अध्ययन इकाई और 100-पॉइंट वन-लाइनर रिवीजन कैप्सूल प्रस्तुत करता है।

मॉड्यूल 1: भारत में बैंकिंग का ऐतिहासिक विकास, राष्ट्रीयकरण एवं रिज़र्व बैंक की संरचना

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 1: भारत में बैंकिंग का ऐतिहासिक विकास, राष्ट्रीयकरण एवं रिज़र्व बैंक की संरचना

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: प्रेसीडेंसी बैंकों से आधुनिक भारतीय रिज़र्व बैंक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तक का सफर

[नोड 1: प्रेसीडेंसी बैंक से इंपीरियल बैंक एवं एसबीआई (1806–1955)]
- बैंक ऑफ बंगाल (1806), बैंक ऑफ बॉम्बे (1840) और बैंक ऑफ मद्रास (1843) का विलय
- 27 जनवरी 1921 को 'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' का गठन
- गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को 'भारतीय स्टेट बैंक' (SBI) में रूपांतरण

▼

[नोड 2: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना एवं राष्ट्रीयकरण (1934–1949)]
- हिल्टन यंग आयोग (1926 — रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस) की अनुशंसा
- आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में ₹5 करोड़ की पूंजी से स्थापना
- 1937 में मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित; 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का पूर्ण राष्ट्रीयकरण

▼

[नोड 3: वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दो ऐतिहासिक चरण (1969 एवं 1980)]
- प्रथम चरण (19 जुलाई 1969): ₹50 करोड़+ जमा वाले 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण
- द्वितीय चरण (15 अप्रैल 1980): ₹200 करोड़+ जमा वाले 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण
- 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में विलय

▼

[नोड 4: मेगा बैंक विलय एवं आधुनिक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ढांचा (2017–2026)]
- 2017 में एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों व भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय
- 2019–2020 के मेगा एकीकरण के बाद भारत में वर्तमान में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs)
- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS — नवंबर 1994) द्वारा संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का एकीकृत पर्यवेक्षण

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारतीय बैंकिंग विकास के प्रमुख मील के पत्थर, समितियाँ एवं नियामक प्रावधान

ऐतिहासिक चरण / संस्थान	स्थापना / प्रभावी तिथि	संबंधित अधिनियम / आयोग / समिति	प्रमुख संरचनात्मक एवं वित्तीय प्रावधान	प्रथम प्रमुख / ऐतिहासिक तथ्य	प्रामाणिक संदर्भ स्रोत
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	1 अप्रैल 1935 (राष्ट्रीयकरण: 1 जनवरी 1949)	हिल्टन यंग आयोग (1926) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934	केंद्रीय निदेशक मंडल में कुल 21 सदस्य (1 गवर्नर + अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर + 16 निदेशक); लेखा वर्ष: 1 अप्रैल से 31 मार्च	प्रथम गवर्नर: **सर ओसबोर्न स्मिथ**; प्रथम भारतीय गवर्नर: **सी.डी. देशमुख** (1943)	भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक प्रतिवेदन
वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS)	नवंबर 1994	आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की समिति के रूप में गठित	वाणिज्यिक बैंकों (SCBs), लघु वित्त बैंकों (SFBs), भुगतान बैंकों (PBs), एनबीएफसी और सहकारी बैंकों का एकीकृत पर्यवेक्षण	आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं	BFS पर्यवेक्षण — RBI
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	1 जुलाई 1955	अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (**ए.डी. गोरेवाला समिति**) एवं एसबीआई अधिनियम, 1955	भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक; हाल ही में ₹25,000 करोड़ का भारत का सबसे बड़ा QIP (Qualified Institutional Placement) संपन्न किया	इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया (1921) का उत्तराधिकारी; मुख्यालय: मुंबई	वित्तीय सेवाएं विभाग वर्षांत समीक्षा — PIB

ऐतिहासिक चरण / संस्थान	स्थापना / प्रभावी तिथि	संबंधित अधिनियम / आयोग / समिति	प्रमुख संरचनात्मक एवं वित्तीय प्रावधान	प्रथम प्रमुख / ऐतिहासिक तथ्य	प्रामाणिक संदर्भ स्रोत
बैंकों का राष्ट्रीयकरण (चरण 1 व 2)	चरण 1: 19 जुलाई 1969; चरण 2: 15 अप्रैल 1980	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं 1980	1969 में ₹50 करोड़ से अधिक जमा वाले **14 बैंक** तथा 1980 में ₹200 करोड़ से अधिक जमा वाले **6 बैंक** राष्ट्रीयकृत हुए	ग्रामीण और कृषि क्षेत्र तक संस्थागत ऋण पहुंचाना मुख्य उद्देश्य रहा	भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेख
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)	2 अक्टूबर 1975	**एम. नरसिंहम कार्यदल (1975)** एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976	पूंजी स्वामित्व अनुपात: **केंद्र सरकार (50%) : राज्य सरकार (15%) : प्रायोजक बैंक (35%)**	प्रथम आरआरबी: **प्रथमा बैंक** (मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश — सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निर्देश — RBI
मुद्रा निर्गमन एवं न्यूनतम कोष प्रणाली	1956 (संशोधित)	आरबीआई अधिनियम, 1934 की **धारा 22** (नोट निर्गमन का एकाधिकार) एवं **धारा 33**	**न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System):** कुल **₹200 करोड़** का कोष अनिवार्य (**₹115 करोड़ का स्वर्ण** + **₹85 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियां**)	₹1 का नोट और सभी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होते हैं, किंतु उनका वितरण आरबीआई करता है	आरबीआई प्रकाशन — RBI
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) हेतु PLI योजना	19 नवंबर 2024 (वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी)	वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग - DFS) का संशोधित दिशानिर्देश	पूर्णकालिक निदेशकों (WTDs) के साथ-साथ अब **स्केल-IV से स्केल-VIII तक के वरिष्ठ कार्यपालकों** को भी प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (PLI) में शामिल किया गया	सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और समग्र बैंक प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन	वित्तीय सेवाएं विभाग — PIB

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (अधिकृत आरबीआई एवं पीआईबी तथ्य):

1. पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की वित्तीय सेवाएं विभाग वर्षांत समीक्षा के अनुसार, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** ने हाल ही में **₹25,000 करोड़** का भारत का अब तक का सबसे बड़ा **योग्य संस्थागत नियोजन (Qualified Institutional Placement - QIP)** सफलतापूर्वक निष्पादित किया है तथा विदेशी बाज़ार से 4.5% कूपन दर पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड भी जुटाए हैं।

2. **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** द्वारा लिखित पुस्तक 'द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी: इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन' (The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution) ने हिल्टन यंग आयोग (1926) के समक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक की वैचारिक आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

3. सीमित देयता (Limited Liability) के आधार पर भारतीयों द्वारा प्रबंधित प्रथम बैंक **अवध कमर्शियल बैंक (1881, फैजाबाद)** था, जबकि पूर्णतः भारतीय पूंजी और प्रबंधन वाला प्रथम स्वदेशी बैंक **पंजाब नेशनल बैंक (1894, लाहौर — संस्थापक: लाला लाजपत राय व दयाल सिंह मजीठिया)** था।

4. भारत में वर्तमान में **12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs)** हैं: भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक (IUC Academy बैंकिंग पोर्टल)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1 (₹1 के नोट पर हस्ताक्षर बनाम अन्य करेंसी नोट):** ₹2 से लेकर ₹2000/₹500 तक के सभी बैंक नोट आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 22 के अंतर्गत जारी होते हैं और उन पर **आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर** होते हैं; किंतु **₹1 के करेंसी नोट** पर **वित्त सचिव (Finance Secretary), भारत सरकार** के हस्ताक्षर होते हैं!

• **जाल 2 (आरबीआई का लेखा वर्ष परिवर्तन):** पहले आरबीआई का लेखा वर्ष (Accounting Year) **1 जुलाई से 30 जून** होता था, किंतु विमल जालान समिति की सिफारिश पर वर्ष **2020–21 से इसे भारत सरकार के वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च)** के समान कर दिया गया है!

• **जाल 3 (आरआरबी पूंजी हिस्सेदारी):** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी का अनुपात **50 : 15 : 35** है—परीक्षा में विकल्प में 50:35:15 देकर भ्रमित किया जाता है, अतः ध्यान रखें कि **राज्य सरकार का हिस्सा सबसे कम (15%)** और **प्रायोजक बैंक का 35%** होता है (आरआरबी निर्देश — RBI)।

5. IUC स्मृति ट्रिक

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **सूत्र (आरआरबी हिस्सेदारी व राष्ट्रीयकरण सूत्र):** "केंद्र का **आधा (50%)**, प्रायोजक का **पैंतीस (35%)**, राज्य का **पंद्रह (15%)**; **69 में 14 (50 करोड़)** और **80 में 6 (200 करोड़)** का राष्ट्रीयकरण!"

• **डिकोडिंग:**

1. **50 : 35 : 15** = केंद्र सरकार (50%) : प्रायोजक बैंक (35%) : राज्य सरकार (15%)
2. **1969 = 14 बैंक** (न्यूनतम जमा ₹50 करोड़)
3. **1980 = 6 बैंक** (न्यूनतम जमा ₹200 करोड़) (**IUC Academy**)।

मॉड्यूल 2: मौद्रिक नीति समिति (MPC), तरलता समायोजन सुविधा (LAF) एवं मौद्रिक उपकरण

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 2: मौद्रिक नीति समिति (MPC), तरलता समायोजन सुविधा (LAF) एवं मौद्रिक उपकरण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: मौद्रिक नीति समिति (MPC) से बाज़ार तरलता एवं मुद्रास्फीति नियंत्रण तंत्र

[नोड 1: मौद्रिक नीति समिति (MPC — धारा 45ZB, आरबीआई अधिनियम 1934)]
| • उर्जित पटेल समिति (2014) की सिफारिश पर वर्ष 2016 में गठित 6-सदस्यीय वैधानिक निकाय
| • 3 सदस्य आरबीआई से (गवर्नर [पदेन अध्यक्ष], मौद्रिक नीति प्रभारी डिप्टी गवर्नर व 1 अधिकारी)
| • 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित (4 वर्ष का कार्यकाल, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं)
▼
[नोड 2: लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting - FIT)]
| • उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI - Combined / खुदरा मुद्रास्फीति) आधारित लक्ष्य: 4% (±2% सहनशीलता बैंड)
| • न्यूनतम सीमा: 2% तथा अधिकतम सीमा (Upper Tolerance Limit): 6%
| • वर्ष में कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य (व्यवहार में द्वि-मासिक अर्थात् 6 बैठकें); कोरम: 4 सदस्य
▼
[नोड 3: प्रत्यक्ष आरक्षित अनुपात (Direct Reserve Ratios — CRR एवं SLR)]
| • नकद आरक्षित अनुपात (CRR — धारा 42, RBI Act): NDTL का वह अंश जो बैंक आरबीआई के पास केवल नकद रखते हैं
| • वैधानिक तरलता अनुपात (SLR — धारा 24, BR Act 1949): NDTL का वह अंश जो बैंक स्वयं नकद/स्वर्ण/G-Sec में रखते हैं
▼
[नोड 4: नीतिगत दर गलियारा (Policy Rate Corridor — LAF, SDF एवं MSF)]
| • फर्श (Floor): स्थायी जमा सुविधा दर (SDF Rate — बिना गिरवी के तरलता अवशोषण)
| • केंद्र (Policy Rate): रेपो दर (Repo Rate — सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण)
| • छत (Ceiling): सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF Rate) एवं बैंक दर (Bank Rate)

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारतीय रिज़र्व बैंक के मात्रात्मक एवं गुणात्मक मौद्रिक नीति उपकरण

मौद्रिक उपकरण (Instrument)	वैधानिक आधार / प्रकृति	तकनीकी परिभाषा एवं कार्यप्रणाली	संपार्श्विक (Collateral / G-Sec) की आवश्यकता	मुद्रास्फीति (Inflation) रोकने हेतु आरबीआई का कदम	प्रामाणिक संदर्भ स्रोत
रेपो दर (Repo Rate)	LAF का प्रमुख नीतिगत दर उपकरण	वह निश्चित ब्याज दर जिस पर आरबीआई तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक (Overnight) तरलता प्रदान करता है	**हाँ अनिवार्य** (SLR कोटे से अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियां)	रेपो दर में **वृद्धि** की जाती है (जिससे ऋण महंगा हो और बाज़ार में मुद्रा आपूर्ति घटे)	आरबीआई मौद्रिक शब्दावली — RBI
स्थायी जमा सुविधा (SDF - Standing Deposit Facility)	अप्रैल 2022 में लागू (धारा 17, आरबीआई अधिनियम संशोधन)	वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से **बिना किसी सरकारी प्रतिभूति (Collateral) के** अतिरिक्त तरलता अवशोषित करता है; यह नीतिगत गलियारे का **नया फर्श (Floor)** है	**नहीं** (बिना संपार्श्विक / Uncollateralised)	SDF दर में **वृद्धि** की जाती है (प्रायः रेपो दर से 25 bps कम रहती है)	मौद्रिक नीति एवं SDF/MSF — RBI
रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)	LAF का पारंपरिक तरलता अवशोषण उपकरण	वह निश्चित दर जिस पर आरबीआई पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के बदले बैंकों से ओवरनाइट तरलता अवशोषित करता है	**हाँ अनिवार्य** (सरकारी प्रतिभूतियों का संपार्श्विक)	तरलता सोखने हेतु VRRR (Variable Rate Reverse Repo) नीलामी का संचालन	आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — RBI
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF - Marginal Standing Facility)	2011 में लागू; नीतिगत गलियारे की **छत (Ceiling)**	वह सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आपात स्थिति में अपने **SLR पोर्टफोलियो में से भी निर्धारित सीमा तक प्रतिभूतियां रखकर** दंडात्मक दर पर ओवरनाइट ऋण ले सकते हैं	**हाँ** (इसमें SLR कोटे की प्रतिभूतियों में से डिप करने की अनुमति होती है)	MSF दर में **वृद्धि** (प्रायः रेपो दर से 25 bps अधिक रहती है)	आरबीआई मौद्रिक शब्दावली — RBI
बैंक दर (Bank Rate)	आरबीआई अधिनियम, 1934 की **धारा 49**	वह मानक दर जिस पर आरबीआई विनिमय बिलों (Bills of Exchange) या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या पुनरभुनाने (Rediscount) के लिए तैयार रहता है	कोई तात्कालिक रेपो संपार्श्विक नहीं; CRR/SLR चूक पर दंड दर इसी से जुड़ी है	बैंक दर में **वृद्धि** (यह MSF दर के बराबर संरेखित रहती है)	आरबीआई मौद्रिक शब्दावली — RBI
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)	आरबीआई अधिनियम, 1934 की **धारा 42(1)**	प्रत्येक बैंक को अपनी शुद्ध मांग और सावधि देयताओं (NDTL) का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास **नकद** में रखना होता है (इस पर आरबीआई **कोई ब्याज नहीं** देता)	केवल नकद (Cash)	CRR में **वृद्धि** (बैंकों की ऋण देने की क्षमता तुरंत घट जाती है)	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की **धारा 24**	बैंकों को अपने NDTL का एक निश्चित प्रतिशत स्वयं के पास तरल संपत्तियों (**नकद, स्वर्ण या भार-रहित सरकारी प्रतिभूतियों**) में रखना होता है (अधिकतम सीमा: 40%)	नकद, स्वर्ण एवं अनुमोदित G-Secs	SLR में **वृद्धि**	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (अधिकृत आरबीआई तथ्य):

1. भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों को उनके परिचालन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए **30 दिसंबर 2023** से **SDF (स्थायी जमा सुविधा)** और **MSF (सीमांत स्थायी सुविधा)** दोनों के अंतर्गत तरलता सुविधाओं के रिवर्सल (Reversal) की अनुमति **सप्ताहांत (शनिवार-रविवार) और छुट्टियों के दिनों में भी** दे दी गई है।

2. यदि मौद्रिक नीति समिति (MPC) लगातार **तीन तिमाहियों (Three Consecutive Quarters)** तक मुद्रास्फीति को 2% से 6% के निर्धारित दायरे में रखने में विफल रहती है, तो इसे 'मौद्रिक नीति लक्ष्य की विफलता' माना जाता है और आरबीआई को केंद्र सरकार को कारणों तथा सुधारात्मक उपायों की लिखित रिपोर्ट देनी होती है।

3. वर्ष 2021 में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाज़ार (Secondary Market) से व्यवस्थित क्रय हेतु **G-SAP (Government Securities Acquisition Programme)** 1.0 और 2.0 तथा अपनी ई-कुबेर प्रणाली में **ASISO (Automated Sweep-In and Sweep-Out)** सुविधा शुरू की थी (आरबीआई प्रकाशन)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1 (CRR बनाम SLR का अधिनियम):** यह बैंकिंग परीक्षाओं का सबसे लोकप्रिय प्रश्न है! **CRR (नकद आरक्षित अनुपात)** का प्रावधान **आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42** में है, जबकि **SLR (वैधानिक तरलता अनुपात)** का प्रावधान **बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act), 1949 की धारा 24** में है!

• **जाल 2 (रेपो बनाम MSF में SLR कोटे का अंतर):** **रेपो दर** पर ऋण लेते समय बैंक अपने **अनिवार्य SLR कोटे की प्रतिभूतियों का उपयोग नहीं कर सकते** (उन्हें केवल अतिरिक्त/Excess SLR प्रतिभूतियां ही रखनी होती हैं), जबकि **MSF (सीमांत स्थायी सुविधा)** में बैंक निर्धारित सीमा तक अपने **अनिवार्य SLR पोर्टफोलियो में से भी प्रतिभूतियां निकालकर (Dipping into SLR portfolio)** ऋण ले सकते हैं (आरबीआई मौद्रिक शब्दावली)।

• **जाल 3 (नीतिगत गलियारे का नया फर्श):** अप्रैल 2022 से पहले 'रिवर्स रेपो दर' LAF कॉरिडोर का फर्श (Floor) थी, किंतु अब **SDF (Standing Deposit Facility)** नीतिगत गलियारे का **फर्श (Floor)** है और **MSF** इसकी **छत (Ceiling)** है।

5. IUC स्मृति ट्रिक

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **सूत्र (मौद्रिक नीति कॉरिडोर व अधिनियम):** "फर्श पर ***SDF*** (बिना गिरवी), बीच में **रेपो**, छत पर ***MSF*-बैंक दर**; ***CRR* = *RBI-42*** (केवल नकद, शून्य ब्याज), ***SLR* = *BR-24*** (नकद+सोना+बॉन्ड)!"

• **डिकोडिंग:**

1. **क्रम:** **SDF दर < रेपो दर < MSF दर = बैंक दर**
2. **CRR:** आरबीआई एक्ट 1934 (धारा 42) — आरबीआई के पास केवल नकद
3. **SLR:** बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 (धारा 24) — बैंक के स्वयं के पास नकद/स्वर्ण/G-Sec (IUC Academy)।

मॉड्यूल 3: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL), ई-कुबेर PSLC पोर्टल एवं ग्रामीण विकास

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 3: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL), ई-कुबेर PSLC पोर्टल एवं ग्रामीण विकास

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) की 8 श्रेणियाँ एवं PSLC व्यापार तंत्र

[नोड 1: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (PSL) की 8 अनिवार्य श्रेणियाँ]
│ (1. कृषि 2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम [MSME] 3. निर्यात ऋण 4. शिक्षा
│ 5. आवास 6. सामाजिक अवसंरचना 7. नवीकरणीय ऊर्जा 8. अन्य व कमज़ोर वर्ग)
▼
[नोड 2: बैंक-वार PSL लक्ष्य निर्धारण (ANBC या CEOBE का प्रतिशत)]
│ • घरेलू वाणिज्यिक बैंक व विदेशी बैंक (20+ शाखाएं): 40%
│ • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) एवं लघु वित्त बैंक (SFBs): 75%
│ • शहरी सहकारी बैंक (UCBs): चरणबद्ध लक्ष्य एवं कमज़ोर वर्ग उप-लक्ष्य
▼
[नोड 3: ई-कुबेर पोर्टल पर PSLC (Priority Sector Lending Certificates) व्यापार]
│ • 4 प्रकार के PSLC: PSLC-Agriculture, PSLC-SF/MF, PSLC-Micro Enterprises, PSLC-General
│ • बिना किसी क्रेडिट जोखिम (Risk) या भौतिक ऋण हस्तांतरण के केवल लक्ष्य पूर्ति हेतु अनाम (Anonymous) ट्रेडिंग
▼
[नोड 4: लक्ष्य चूक (Shortfall) पर RIDF / ग्रामीण अवसंरचना कोष में अनिवार्य अंशदान]
│ • जिस बैंक का PSL लक्ष्य अधूरा रहता है, उसे नाबार्ड (RIDF), सिडबी या NHB के कोष में कम ब्याज पर राशि जमा करनी पड़ती है

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: विभिन्न बैंक श्रेणियों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्य एवं उप-लक्ष्य

बैंक की श्रेणी	कुल PSL लक्ष्य (ANBC या CEOBE का %)	कृषि क्षेत्र उप-लक्ष्य (लघु एवं सीमांत किसान - SMF सहित)	सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises) उप-लक्ष्य	कमज़ोर वर्ग (Weaker Sections) उप-लक्ष्य	प्रामाणिक संदर्भ स्रोत
घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (PSBs व निजी बैंक) एवं 20+ शाखाओं वाले विदेशी बैंक	**40%**	**18%** (जिसमें लघु एवं सीमांत किसानों - SMF के लिए **10%** अनिवार्य है)	**7.5%**	**12%**	वाणिज्यिक बैंक PSL मास्टर निदेश — RBI
20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक (Foreign Banks < 20 Branches)	**40%**	कोई पृथक कृषि उप-लक्ष्य नहीं (अधिकतम 32% निर्यात ऋण में हो सकता है, न्यूनतम 8% अन्य PSL में)	लागू नहीं	लागू नहीं	PSL मास्टर निदेश — RBI
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks - RRBs)	**75%**	**18%** (लघु एवं सीमांत किसानों हेतु **10%**)	**7.5%**	**15%** (वाणिज्यिक बैंकों से अधिक!)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक PSL निदेश — RBI
लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks - SFBs)	**75%**	**18%** (लघु एवं सीमांत किसानों हेतु **10%**)	**7.5%**	**12%**	PSL मास्टर निदेश — RBI
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (Primary Urban Co-operative Banks - UCBs)	**60% से 75%** (चरणबद्ध ग्लाइड पाथ के अनुसार)	कोई पृथक कृषि उप-लक्ष्य अनिवार्य नहीं	**7.5%**	**12%**	शहरी सहकारी बैंक PSL निदेश — RBI
भुगतान बैंक (Payment Banks)	**ऋण देने की अनुमति नहीं**	भुगतान बैंक कोई ऋण (Loan) या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते (केवल जमा व विप्रेषण)	लागू नहीं	लागू नहीं	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (अधिकृत आरबीआई PSL तथ्य):

1. भारतीय रिज़र्व बैंक के PSL अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) के अनुसार, **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLCs)** का क्रय-विक्रय आरबीआई के कोर बैंकिंग समाधान पोर्टल **'ई-कुबेर' (e-Kuber)** के माध्यम से पूरी तरह **अनाम (Anonymous) आधार** पर किया जाता है, अर्थात् क्रेता या विक्रेता बैंक अपने काउंटरपार्टी का चयन स्वयं नहीं कर सकते। ई-कुबेर पर PSLC बाज़ार का सामान्य व्यापार समय **प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:30 बजे** तक (शनिवार, रविवार और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों को छोड़कर) होता है।

2. आरबीआई के 6 नवंबर 2026 के वाणिज्यिक बैंक PSL निदेश के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा निर्धारित सीमाओं और शर्तों के अधीन **प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)** खाताधारकों को दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट (Overdraft) सुविधा भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) के अंतर्गत वर्गीकृत होने के योग्य है।

3. कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए **गैर-कॉर्पोरेट किसानों (Non-Corporate Farmers)** को दिए जाने वाले ऋण में **सीमांत किसान (Marginal Farmers)** वे हैं जिनके पास **1 हेक्टेयर तक** भूमि है, और **लघु किसान (Small Farmers)** वे हैं जिनके पास **1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर तक** भूमि है (PSL मास्टर निदेश — RBI)।

4. कृषि एवं ग्रामीण अवसंरचना के शीर्ष विकास बैंक **नाबार्ड (NABARD — राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)** की स्थापना **शिवरमन समिति (B. Sivaraman Committee / CRAFICARD)** की सिफारिश पर **12 जुलाई 1982** को हुई थी (मुख्यालय: मुंबई) और **ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF — 1995-96)** का संचालन नाबार्ड द्वारा ही किया जाता है।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1 (आरआरबी में कमज़ोर वर्ग का उप-लक्ष्य 15% है, 12% नहीं):** अधिकांश छात्र सभी बैंकों के लिए कमज़ोर वर्ग (Weaker Sections) का लक्ष्य 12% याद कर लेते हैं। सावधान रहें—वाणिज्यिक बैंकों, SFBs और UCBs के लिए कमज़ोर वर्ग का लक्ष्य **12%** है, किंतु **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs)** के लिए कमज़ोर वर्ग का उप-लक्ष्य **15%** है (**आरआरबी PSL निदेश — RBI**)!

• **जाल 2 (PSLC की वैधता तिथि):** किसी भी वित्तीय वर्ष में खरीदे गए सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLCs) उसी वित्तीय वर्ष के अंत में अर्थात् **31 मार्च** को स्वतः समाप्त (Expire) हो जाते हैं!

5. IUC स्मृति ट्रिक

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **सूत्र (सीमांत व लघु किसान भूमि सीमा एवं PSL लक्ष्य):** "1 हेक्टेयर तक **सीमांत**, 1 से 2 हेक्टेयर **लघु** किसान; वाणिज्यिक बैंक **40%**, ग्रामीण व लघु वित्त बैंक **75%** का मान!"

• **डिकोडिंग:**

1. **सीमांत किसान (Marginal Farmer):** ≤ 1 हेक्टेयर | **लघु किसान (Small Farmer):** > 1 से ≤ 2 हेक्टेयर
2. **40% PSL लक्ष्य:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं विदेशी बैंक
3. **75% PSL लक्ष्य:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) एवं लघु वित्त बैंक (SFBs) (**IUC Academy**)।

मॉड्यूल 4: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) एवं डिजिटल भुगतान क्रांति

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 4: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) एवं डिजिटल भुगतान क्रांति

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: भारत के खुदरा डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का स्थापत्य

[नोड 1: नियामक एवं संस्थागत आधार (PSS Act 2007 एवं NPCI 2008)]
| • भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ (IBA) की पहल
| • कंपनी अधिनियम की धारा 8 (पूर्व धारा 25) के अंतर्गत 'गैर-लाभकारी' (Not-for-Profit) अंब्रेला संगठन के रूप में NPCI का गठन
▼
[नोड 2: आरबीआई द्वारा संचालित वृहद भुगतान प्रणालियाँ (RTGS एवं NEFT)]
| • RTGS (Real Time Gross Settlement): उच्च मूल्य के लेनदेन हेतु (न्यूनतम ₹2 लाख, अधिकतम सीमा नहीं; 24x7x365)
| • NEFT (National Electronic Funds Transfer): आस्थगित नेट निपटान (Deferred Net Settlement - आधे घंटे के बैच; न्यूनतम ₹1; 24x7x365)
▼
[नोड 3: NPCI के प्रमुख खुदरा भुगतान उत्पाद (UPI, IMPS, RuPay, NACH, AePS, NETC)]
| • IMPS (2010) RuPay (2012) NACH व BBPS UPI व BHIM (2016) FASTag (NETC) e-RUPI (2021)
| • UPI लाइट (ऑफ़लाइन पिन-रहित छोटा भुगतान), UPI 123Pay (फीचर फोन हेतु) एवं UPI One World (अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों हेतु)
▼
[नोड 4: NPCI की 3 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ एवं डिजीसाथी हेल्पलाइन]
| • 1. NIPL (अंतर्राष्ट्रीय विस्तार) 2. NBBL (भारत बिलपे) 3. NBSL (एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड) + डिजीसाथी (24x7 सहायता)

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ (NPCI एवं RBI उत्पाद)

भुगतान प्रणाली / उत्पाद	संचालक संस्था एवं प्रारंभ वर्ष	तकनीकी कार्यप्रणाली एवं विशेषता	न्यूनतम व अधिकतम लेनदेन सीमा	विशेष परीक्षा बिंदु	प्रामाणिक संदर्भ स्रोत
UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफेस)	NPCI (11 अप्रैल 2016)	एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में कई बैंक खातों को जोड़कर VPA (Virtual Payment Address), QR कोड या मोबाइल नंबर से तत्काल 24x7 फंड ट्रांसफर	न्यूनतम: ₹1; सामान्य अधिकतम सीमा: **₹1 लाख** प्रति लेनदेन (पूंजी बाज़ार, बीमा, चिकित्सा व शिक्षा/IPO हेतु **₹2 लाख से ₹5 लाख** तक)	**UPI One World** वॉलेट सेवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों व पर्यटकों को बिना भारतीय बैंक खाते के भुगतान की सुविधा देती है	UPI उत्पाद विवरण — NPCI
BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी)	NPCI (30 दिसंबर 2016)	डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर समर्पित UPI-आधारित आधिकारिक मोबाइल भुगतान ऐप	प्रति लेनदेन व प्रतिदिन सीमा UPI मानदंडों के अनुरूप	इसके प्रबंधन हेतु विशेष सहायक कंपनी **NBSL (NPCI BHIM Services Limited)** गठित की गई है	भीम ऐप — NPCI
IMPS (तत्काल भुगतान सेवा)	NPCI (22 नवंबर 2010)	मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से 24x7x365 रीयल-टाइम इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर; MMID (7 अंकों का कोड) या खाता+IFSC आधारित	न्यूनतम: ₹1; अधिकतम: **₹5 लाख** प्रति लेनदेन (पहले ₹2 लाख थी, जिसे बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया)	भारत की पहली 24x7 त्वरित खुदरा अंतर-बैंक भुगतान सेवा	IMPS अवलोकन — NPCI
NACH (राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह)	NPCI	भारी मात्रा वाले आवर्ती (Recurring/Bulk) भुगतानों जैसे लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन, सरकारी सब्सिडी (DBT) तथा ऋण EMI/म्यूचुअल फंड SIP की वसूली हेतु वेब-आधारित प्रणाली	थोक एवं आवर्ती लेनदेन (ECS प्रणाली का एकीकृत राष्ट्रीय रूप)	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और आधार पेमेंट ब्रिज (APB) का मुख्य आधार	NACH सदस्य एवं प्रणाली — NPCI
RuPay, FASTag (NETC), AePS एवं e-RUPI	NPCI	**RuPay:** स्वदेशी कार्ड नेटवर्क; **NETC FASTag:** RFID तकनीक आधारित कैशलेस टोल; **AePS:** बायोमेट्रिक आधार माइक्रो-ATM; **e-RUPI:** उद्देश्य-विशिष्ट प्रीपेड वाउचर	कार्ड, बायोमेट्रिक व प्रीपेड वाउचर के नियमों के अनुसार	**डिजीसाथी (DigiSaathi):** डिजिटल भुगतान संबंधी प्रश्नों के लिए 24x7 स्वचालित चैटबॉट व हेल्पलाइन (14431 / 1800-891-3333)	डिजीसाथी — NPCI
RTGS एवं NEFT	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	**RTGS:** रीयल-टाइम में एक-एक निर्देश का सकल निपटान; **NEFT:** आधे-आधे घंटे के 48 दैनिक बैचों में नेट निपटान	**RTGS:** न्यूनतम **₹2 लाख**, अधिकतम कोई सीमा नहीं; **NEFT:** न्यूनतम ₹1, अधिकतम कोई सीमा नहीं	दिसंबर 2019 से NEFT और दिसंबर 2020 से RTGS दोनों को **24x7x365** उपलब्ध करा दिया गया है	आरबीआई भुगतान प्रणाली — RBI

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (अधिकृत NPCI तथ्य):

1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आरबीआई और एनपीसीआई बोर्ड के अनुमोदन से एनपीसीआई की **तीन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ (Wholly Owned Subsidiaries)** कार्यरत हैं:

- **1. NIPL (NPCI International Payments Limited):** UPI और RuPay को वैश्विक स्तर पर (फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरीशस, नेपाल, भूटान आदि देशों में) ले जाने के लिए।
- **2. NBBL (NPCI Bharat BillPay Limited):** भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के संचालन के लिए।
- **3. NBSL (NPCI BHIM Services Limited):** भीम (BHIM) ऐप और संबद्ध सेवाओं के विस्तार के लिए।

2. **FASTag** (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन - NETC) **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID)** तकनीक पर कार्य करता है, जबकि संपर्क-रहित (Contactless / Tap & Pay) कार्ड **नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC)** तकनीक पर कार्य करते हैं।

3. **IFSC (Indian Financial System Code) 11 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड** होता है (प्रथम 4 अक्षर बैंक का नाम, **5वां अक्षर सदैव शून्य '0'** भविष्य के उपयोग हेतु, और अंतिम 6 अंक बैंक शाखा की पहचान बताते हैं), जबकि **MICR (Magnetic Ink Character Recognition)** चेक समाशोधन में प्रयुक्त **9 अंकों का संख्यात्मक कोड** है (प्रथम 3 अंक शहर पिनकोड, बीच के 3 अंक बैंक कोड, अंतिम 3 अंक शाखा कोड) और **MMID (Mobile Money Identifier)** IMPS में प्रयुक्त **7 अंकों का कोड** है।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1 (RTGS/NEFT बनाम UPI/IMPS का संचालक):** परीक्षा में पूछा जाता है—"निम्नलिखित में से कौन-सा उत्पाद NPCI द्वारा संचालित **नहीं** किया जाता है?" याद रखें: **UPI, IMPS, RuPay, NACH, AePS, CTS, NFS, BBPS, NETC (FASTag) और e-RUPI** का संचालन **NPCI** करता है (NPCI होमपेज), जबकि **RTGS** और **NEFT** का स्वामित्व व संचालन सीधे **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** के पास है!

• **जाल 2 (FASTag बनाम Contactless Card तकनीक): FASTag** में **RFID** (Radio Frequency Identification) तकनीक होती है, न कि NFC! वहीं बिना पिन के ₹5,000 तक के टैप-एंड-पे कार्ड में **NFC** (Near Field Communication) तकनीक होती है।

5. IUC स्मृति ट्रिक

★ **IUC स्मृति ट्रिक:**

• **सूत्र (बैंकिंग कोड्स के अंकों की संख्या):** "*MMID* के **7**, *MICR* के **9**, पैन (*PAN*) के **10**, *IFSC* के **11**, आधार के **12**, *PRAN* के **12**, *UAN* के **12**, और *LEI* के **20** अंक याद रखें!"

• **डिकोडिंग:**

1. **7 अंक:** MMID (Mobile Money Identifier)
2. **9 अंक:** MICR (Magnetic Ink Character Recognition — 3 शहर + 3 बैंक + 3 शाखा)
3. **10 वर्ण:** PAN (Permanent Account Number — 5 अक्षर + 4 अंक + 1 अक्षर)
4. **11 वर्ण:** IFSC (Indian Financial System Code — 5वां वर्ण सदैव '0') एवं SWIFT कोड (8 या 11 वर्ण)
5. **20 वर्ण:** LEI (Legal Entity Identifier — ₹50 करोड़+ के कॉर्पोरेट ऋण व बड़े RTGS/NEFT लेनदेन हेतु) (IUC Academy)।

मॉड्यूल 5: एनपीए (NPA) वर्गीकरण, सरफेसी अधिनियम, आईबीसी (IBC) एवं बेसल-III मानक

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 5: एनपीए (NPA) वर्गीकरण, सरफेसी अधिनियम, आईबीसी (IBC) एवं बेसल-III मानक

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: ऋण खाते के तनावग्रस्त होने (SMA) से एनपीए वर्गीकरण एवं समाधान (IBC) तक का चक्र

[नोड 1: विशेष उल्लेख खाते (Special Mention Accounts — SMA-0, SMA-1, SMA-2)]
| • एनपीए बनने से पूर्व की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Signals):
| • SMA-0: मूलधन या ब्याज 1 से 30 दिन तक बकाया | SMA-1: 31 से 60 दिन बकाया | SMA-2: 61 से 90 दिन बकाया
▼
[नोड 2: गैर-निष्पादित आस्तियाँ (NPA — 90 दिन से अधिक बकाया) की 3 श्रेणियाँ]
| • 1. अवमानक आस्ति (Sub-standard Asset): 12 माह तक एनपीए रहने वाली आस्ति
| • 2. संदिग्ध आस्ति (Doubtful Asset): 12 माह से अधिक समय तक अवमानक श्रेणी में रहने वाली आस्ति
| • 3. हानि आस्ति (Loss Asset): बैंक/ऑडिटर/आरबीआई द्वारा अप्राप्य (Uncollectible) घोषित आस्ति
▼
[नोड 3: वसूली एवं समाधान तंत्र (DRT, SARFAESI 2002, ARC/NARCL एवं IBC 2016)]
| • SARFAESI अधिनियम, 2002: ₹1 लाख+ के सुरक्षित ऋणों में न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना गिरवी संपत्ति की नीलामी
| • दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC, 2016): NCLT के माध्यम से समयबद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान (CIRP)
▼
[नोड 4: बेसल-III (Basel-III) पूंजी पर्याप्तता मानक (CRAR एवं सुरक्षा बफर)]
| • बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS — बेसल, स्विट्ज़रलैंड) के मानक
| • भारत में आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम CRAR: 9% + पूंजी संरक्षण बफर (CCB: 2.5%) = कुल 11.5%

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: एनपीए श्रेणियाँ, वसूली कानून (SARFAESI बनाम IBC) एवं बेसल-III पूंजी मानक

विषय / मानदंड	तकनीकी प्रावधान एवं समय-सीमा	नियामक मानक / संख्यात्मक आंकड़े	अपवाद / विशेष शर्तें	प्रामाणिक संदर्भ स्रोत
एनपीए (Non-Performing Asset) की परिभाषा	जब किसी ऋण पर ब्याज या मूलधन की किस्त **90 दिनों से अधिक** समय तक अतिदेय (Overdue) रहती है	**कृषि ऋण अपवाद:** अल्पावधि फसलों (Short Duration Crops) के लिए **2 फसली मौसम (Two Crop Seasons)** और दीर्घावधि फसलों के लिए **1 फसली मौसम** तक बकाया रहने पर एनपीए घोषित होता है	एनपीए होने के बाद 12 माह तक 'Sub-standard', उसके बाद 'Doubtful' और अंततः 'Loss Asset'	आरबीआई विवेकपूर्ण मानदंड — RBI
IBC 2016 (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता)	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया **(CIRP)** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण **(NCLT)** के समक्ष चलती है; नियामक: **IBBI**	सितंबर 2025 तक NCLT में **8,659 CIRPs** स्वीकार किए गए, जिनमें से **3,865 मामलों** में कॉर्पोरेट देनदारों को बचाया गया और 1,300 अनुमोदित योजनाओं से ऋणदाताओं ने **₹3.99 लाख करोड़** (परिसमापन मूल्य का **170.09%**) वसूल किए	व्यक्तिगत दिवाला मामलों का न्यायनिर्णयन प्राधिकरण **DRT (ऋण वसूली अधिकरण)** होता है, जबकि कंपनियों के लिए **NCLT**	IBC निष्पादन आंकड़े — PIB
SARFAESI अधिनियम, 2002	*Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002*	केवल **सुरक्षित ऋणों (Secured Loans)** पर लागू, जहां बकाया राशि ₹1 लाख से अधिक हो और मूल ऋण का 20% से अधिक बकाया हो (60 दिन का नोटिस दिया जाता है)	**कृषि भूमि (Agricultural Land) पर SARFAESI अधिनियम लागू नहीं होता है!**	आरबीआई तनावग्रस्त आस्तियां — RBI
बेसल-III (Basel-III) मानक (भारत में आरबीआई मानदंड)	3 स्तंभ: 1. न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, 2. पर्यवेक्षी समीक्षा, 3. बाज़ार अनुशासन	**अंतर्राष्ट्रीय बेसल-III मानक:** न्यूनतम CRAR = 8% (CCB सहित 10.5%); **भारतीय (RBI) मानक:** न्यूनतम CRAR = **9%** (**CET-1: 5.5%**, AT-1: 1.5%, Tier-1 कुल: **7%**, Tier-2: 2%) + **CCB (2.5%)** = **11.5%**	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और शहरी सहकारी बैंकों हेतु न्यूनतम CRAR **9%** है, जबकि SFBs व Payment Banks हेतु **15%** है	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन
NBFC स्केल-आधारित विनियमन (SBR Framework)	1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी; आकार और प्रणालीगत महत्व के आधार पर **4 परतें (Layers)**	**1. Base Layer (NBFC-BL) 2. Middle Layer (NBFC-ML) 3. Upper Layer (NBFC-UL) 4. Top Layer**	**NBFC-UL (अपर लेयर)** के लिए जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम **9% CET-1 पूंजी** रखना अनिवार्य है	NBFC स्केल-आधारित विनियमन — RBI
शहरी सहकारी बैंक (UCB) 4-स्तरीय ढांचा	एन.एस. विश्वनाथन समिति की सिफारिश पर 19 जुलाई 2022 को संशोधित नियामक ढांचा जारी	एकल जिले में कार्यरत **Tier-1 UCB** हेतु न्यूनतम नेट वर्थ **₹2 करोड़** तथा अन्य सभी UCBs (Tier 1 से Tier 4) हेतु **₹5 करोड़** (ग्लाइड पाथ: मार्च 2028 तक, 50% लक्ष्य मार्च 2026 तक)	₹5,000 करोड़ या अधिक की संपत्ति वाले सभी UCBs को **मुख्य जोखिम अधिकारी (CRO)** नियुक्त करना अनिवार्य	UCB नियामक ढांचा — RBI

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (अधिकृत पीआईबी एवं आरबीआई तथ्य):

1. पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की वित्तीय सेवाएं विभाग रिपोर्ट के अनुसार, **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC, 2016)** के तहत सितंबर 2025 तक NCLT में 8,659 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं (CIRPs) दर्ज हुईं, जिनमें से 1,300 स्वीकृत समाधान योजनाओं के माध्यम से ऋणदाताओं को **₹3.99 लाख करोड़** की वसूली हुई—जो उन कंपनियों के परिसमापन मूल्य (Liquidation Value - ₹2.35 लाख करोड़) का **170.09%** और उचित मूल्य (Fair Value) का **93.79%** है!

2. भारत में बड़े तनावग्रस्त ऋणों (₹500 करोड़ और उससे अधिक के एनपीए खातों) के समाधान हेतु एक 'बैड बैंक' (Bad Bank) संरचना स्थापित की गई है, जिसमें दो संस्थाएं शामिल हैं: **1. NARCL (National Asset Reconstruction Company Limited — संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए, जिसमें PSBs की 51% हिस्सेदारी है)** और **2. IDRCL (India Debt Resolution Company Limited — संपत्ति के प्रबंधन व मूल्य संवर्धन के लिए, जिसमें निजी क्षेत्र की 51% हिस्सेदारी है)**; केंद्र सरकार इसके द्वारा जारी सिक्योरिटी रिसीट्स (SRs) पर **₹30,600 करोड़** की संप्रभु गारंटी देती है।

3. आरबीआई द्वारा भारत में तीन बैंकों को **'घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक' (D-SIBs — Domestic Systemically Important Banks / 'Too Big To Fail')** घोषित किया गया है: **1. भारतीय स्टेट बैंक (SBI)**, **2. एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)** और **3. आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)**।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1 (अंतर्राष्ट्रीय बेसल-III बनाम आरबीआई का बेसल-III CRAR प्रतिशत):** परीक्षा में प्रश्न को ध्यान से पढ़ें! यदि पूछा जाए कि **"बेसल समिति (BCBS) के अनुसार न्यूनतम CRAR कितना है?"** तो उत्तर **8%** (CCB सहित 10.5%) है; किंतु यदि पूछा जाए कि **"आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों के लिए न्यूनतम CRAR कितना है?"** तो उत्तर **9%** (2.5% CCB सहित **11.5%**) है!

• **जाल 2 (SARFAESI अधिनियम और कृषि भूमि):** SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत बैंक बिना कोर्ट गए डिफॉल्टर की संपत्ति जब्त कर सकते हैं, किंतु **धारा 31(i)** के तहत **कृषि भूमि (Agricultural Land)** को SARFAESI अधिनियम के दायरे से **पूर्णतः मुक्त** रखा गया है!

5. IUC स्मृति ट्रिक

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **सूत्र (SMA से NPA और बेसल-III सूत्र):** "30-30 दिन के तीन ***SMA* (0, 1, 2)**, **90 दिन** पार होते ही ***NPA***; बेसल में भारत का **9% *CRAR*** + **2.5% बफर** = **11.5%** तैयार!"

• **डिकोडिंग:**

1. **SMA-0:** 1–30 दिन | **SMA-1:** 31–60 दिन | **SMA-2:** 61–90 दिन | **NPA:** > 90 दिन
2. **CRAR (9%):** Tier-1 (7% = CET-1 का 5.5% + AT-1 का 1.5%) + Tier-2 (2%) + CCB (2.5%) = **11.5%** (IUC Academy)।

मॉड्यूल 6: मुद्रा बाज़ार (Money Market) एवं पूंजी बाज़ार (Capital Market) तथा SEBI निवेशक चार्टर

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 6: मुद्रा बाज़ार (Money Market) एवं पूंजी बाज़ार (Capital Market) तथा SEBI निवेशक चार्टर

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: भारतीय वित्तीय बाज़ार का द्वि-स्तरीय ढांचा (अल्पावधि बनाम दीर्घावधि)

[नोड 1: मुद्रा बाज़ार (Money Market — परिपक्वता: 1 दिन से 364 दिन / < 1 वर्ष | नियामक: RBI)]
| • असुरक्षित अंतर-बैंक बाज़ार: कॉल मनी (1 दिन), नोटिस मनी (2–14 दिन), टर्म मनी (15–364 दिन)
| • प्रमुख प्रपत्र: ट्रेज़री बिल (T-Bills: 91, 182, 364 दिन), वाणिज्यिक पत्र (CP), जमा प्रमाणपत्र (CD) एवं नकद प्रबंधन बिल (CMB < 91 दिन)
▼
[नोड 2: पूंजी बाज़ार (Capital Market — परिपक्वता: 1 वर्ष से अधिक | नियामक: SEBI)]
| • प्राथमिक बाज़ार (Primary Market): नई प्रतिभूतियों का प्रथम निर्गमन — IPO, FPO, Rights Issue, QIP, Private Placement
| • द्वितीयक बाज़ार (Secondary Market): पूर्व-निर्गमित शेयरों का क्रय-विक्रय — BSE (1875 - Sensex) एवं NSE (1992 - Nifty 50)
▼
[नोड 3: बाज़ार अवसंरचना संस्थान (MIIs) एवं निवेश मध्यस्थ (SEBI Investor Charter)]
| • MIIs: स्टॉक एक्सचेंज (BSE, NSE, MSEI), डिपॉजिटरी (NSDL, CDSL) और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन
| • मध्यस्थ: म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTAs), FPI एवं वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)
▼
[नोड 4: सेबी निवेशक संरक्षण एवं शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES एवं T+1/T+0 निपटान)]
| • SCORES (SEBI Complaint Redressal System — 'हर इन्वेस्टर की ताकत'): ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल
| • SEBI निवेशक चार्टर: निवेशकों के 21 अधिकारों व पारदर्शिता का एकीकृत ढांचा तथा त्वरित ट्रेड सेटलमेंट

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: मुद्रा बाज़ार और पूंजी बाज़ार के प्रमुख वित्तीय प्रपत्र (Instruments)

वित्तीय प्रपत्र (Instrument)	बाज़ार श्रेणी एवं नियामक	जारीकर्ता (Issuer)	न्यूनतम राशि एवं गुणज (Denomination)	परिपक्वता अवधि (Maturity Period)	प्रामाणिक संदर्भ स्रोत
ट्रेजरी बिल (Treasury Bills - T-Bills)	मुद्रा बाज़ार (RBI)	**केवल केंद्र सरकार** (राज्य सरकारें T-Bills जारी नहीं कर सकतीं; सरकार की ओर से RBI जारी करता है)	न्यूनतम **₹10,000** और ₹10,000 के गुणज में (शून्य कूपन बॉन्ड — सममूल्य से छूट/Discount पर जारी)	**3 प्रकार: 91 दिन, 182 दिन** और **364 दिन** (14-दिवसीय मध्यवर्ती T-Bills केवल राज्य सरकारों/केंद्रीय बैंकों हेतु)	आरबीआई वित्तीय बाज़ार — RBI
नकद प्रबंधन बिल (Cash Management Bills - CMBs)	मुद्रा बाज़ार (RBI — 2010 से शुरू)	केंद्र सरकार (अस्थायी नकदी प्रवाह असंतुलन को पूरा करने के लिए)	न्यूनतम **₹10,000** और उसके गुणज में (T-Bills की भांति डिस्काउंट पर जारी)	**91 दिनों से कम (< 91 Days)**	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन
वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper - CP)	मुद्रा बाज़ार (RBI)	उच्च रेटिंग वाली कॉर्पोरेट कंपनियाँ, प्राथमिक डीलर (PDs) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs)	न्यूनतम **₹5 लाख** और ₹5 लाख के गुणज में (**असुरक्षित वचन पत्र** — Unsecured Promissory Note)	**न्यूनतम** 7 **दिन** से लेकर **अधिकतम 1 वर्ष** तक	आरबीआई वित्तीय बाज़ार — RBI
जमा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit - CD)	मुद्रा बाज़ार (RBI)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (RRBs और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा AIFIs	न्यूनतम **₹5 लाख** और ₹5 लाख के गुणज में (डीमैट रूप में परक्राम्य प्रपत्र)	**बैंकों द्वारा: 7 दिन से 1 वर्ष** तक; **AIFIs द्वारा: 1 वर्ष से 3 वर्ष** तक	आरबीआई वित्तीय बाज़ार — RBI
कॉल मनी, नोटिस मनी एवं टर्म मनी	अंतर-बैंक मुद्रा बाज़ार (RBI)	बैंकों और प्राथमिक डीलरों के मध्य बिना किसी संपार्श्विक के अल्पकालिक ऋण	अंतर-बैंक तरलता प्रबंधन के अनुसार	**कॉल मनी: 1 दिन (Overnight); नोटिस मनी: 2 से 14 दिन; टर्म मनी: 15 दिन से 1 वर्ष**	आरबीआई मौद्रिक शब्दावली — RBI
इक्विटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, AIF एवं कॉर्पोरेट बॉन्ड	पूंजी बाज़ार (SEBI — सेबी अधिनियम, 1992)	सूचीबद्ध कंपनियाँ, एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ (AMCs) एवं संस्थागत जारीकर्ता	IPO में खुदरा निवेशक (RII) की सीमा: **₹2 लाख तक**; ASBA (Application Supported by Blocked Amount) अनिवार्य	दीर्घावधि (> 1 वर्ष); **SCORES** पोर्टल द्वारा शिकायत निवारण	निवेशक चार्टर — SEBI

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (अधिकृत सेबी तथ्य):

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के आधिकारिक निवेशक चार्टर पोर्टल तथा सेबी की बोर्ड बैठक के दस्तावेज़ के अनुसार, सेबी ने निवेशकों में पारदर्शिता, विश्वास और जागरूकता बढ़ाने के लिए **'निवेशक चार्टर' (Investor Charter)** तैयार किया है, जिसमें वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग - DEA) द्वारा सुझाए गए **21 निवेशक अधिकारों** को शामिल किया गया है। यह चार्टर सभी **बाज़ार अवसंरचना संस्थानों (MIIs — स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE/NSE और डिपॉजिटरी जैसे NSDL/CDSL)** तथा बाज़ार मध्यस्थों (स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, RTAs, म्यूचुअल फंड्स) पर लागू है (स्टॉक एक्सचेंज निवेशक चार्टर PDF — SEBI)।
2. सेबी के ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल SCORES का पूर्ण रूप **SEBI Complaint Redressal System** है और इसकी टैगलाइन **'हर इन्वेस्टर की ताकत'** है।
3. **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** की स्थापना **12 अप्रैल 1988** को एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में हुई थी, जिसे **नरसिंहम समिति** की सिफारिश पर **30 जनवरी 1992** को सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से **वैधानिक दर्जा (Statutory Status)** प्रदान किया गया (मुख्यालय: मुंबई; क्षेत्रीय कार्यालय: नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद) (SEBI आधिकारिक पोर्टल)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1 (राज्य सरकारें और ट्रेजरी बिल):** परीक्षा में कथन दिया जाता है—"केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ट्रेजरी बिल (T-Bills) जारी करती हैं।" यह कथन **गलत** है! **ट्रेजरी बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं**; राज्य सरकारें कभी भी ट्रेजरी बिल जारी नहीं करतीं, वे केवल **राज्य विकास ऋण (State Development Loans - SDLs)** जारी करती हैं!

• **जाल 2 (जमा प्रमाणपत्र - CD कौन जारी नहीं कर सकता?):** सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जमा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit - CD) जारी कर सकते हैं, किंतु **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)** और **स्थानीय क्षेत्र बैंक (Local Area Banks - LABs)** जमा प्रमाणपत्र (CD) जारी **नहीं** कर सकते!

5. IUC स्मृति ट्रिक

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **सूत्र (मुद्रा बाज़ार की समय-सीमा व न्यूनतम राशि):** "कॉल **1 दिन**, नोटिस **2 से 14**, टर्म **15 से 364**; *T-Bill* व *CMB* **10 हज़ार** के, *CP* व *CD* **5 लाख** के, और *T-Bill* के दिन **91 का पहाड़ा (91, 182, 364)**!"

• **डिकोडिंग:**

1. **91 × 1 = 91 दिन, 91 × 2 = 182 दिन, 91 × 4 = 364 दिन** (तीन प्रकार के T-Bills)
2. **CMB:** 91 दिन से कम | **न्यूनतम राशि (T-Bill व CMB):** ₹10,000
3. **CP व CD न्यूनतम राशि:** ₹5 लाख (और न्यूनतम अवधि: **7 दिन**) (IUC Academy)।

मॉड्यूल 7: वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion), जन-धन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 7: वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion), जन-धन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: भारत में सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा का स्तंभ

[नोड 1: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY — 28 अगस्त 2014 | 'मेरा खाता, भाग्य विधाता')]
| • शून्य बैलेंस (BSBD) खाता, निःशुल्क RuPay डेबिट कार्ड एवं ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर
| • ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा (जो आरबीआई के PSL लक्ष्यों के अंतर्गत मान्य है)
▼
[नोड 2: जन-सुरक्षा बीमा एवं पेंशन त्रयी (9 मई 2015 — कोलकाता से प्रारंभ)]
| • 1. PMJJBY (जीवन ज्योति बीमा): 18–50 वर्ष आयु | ₹436 वार्षिक प्रीमियम | ₹2 लाख जीवन बीमा (किसी भी कारण से मृत्यु)
| • 2. PMSBY (सुरक्षा बीमा): 18–70 वर्ष आयु | ₹20 वार्षिक प्रीमियम | ₹2 लाख दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता (₹1 लाख आंशिक)
| • 3. APY (अटल पेंशन योजना — PFRDA): 18–40 वर्ष आयु | 60 वर्ष बाद ₹1,000 से ₹5,000 मासिक गारंटीकृत पेंशन
▼
[नोड 3: सूक्ष्म उद्यमिता एवं स्वरोजगार ऋण योजनाएं (MUDRA, Stand-Up India, PM SVANidhi)]
| • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY — 8 अप्रैल 2015): शिशु (₹50 हज़ार तक), किशोर (₹5 लाख तक), तरुण (₹10 लाख तक) एवं तरुण प्लस (₹20 लाख तक)
| • स्टैंड-अप इंडिया (5 अप्रैल 2016): SC/ST एवं महिला उद्यमी को ग्रीनफील्ड उद्यम हेतु ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण
▼
[नोड 4: विशिष्ट बैंकिंग लाइसेंस एवं अनक्लेम्ड डिपॉजिट अभियान (SFBs, Payment Banks, UDGAM)]
| • नचिकेत मोर समिति भुगतान बैंक (अधिकतम जमा: ₹2 लाख) एवं उषा थोराट समिति लघु वित्त बैंक (SFBs)
| • लावारिस जमा (Unclaimed Deposits), शेयर व बीमा दावा निपटान हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान एवं RBI का 'UDGAM' पोर्टल

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन एवं जन-सुरक्षा योजनाएं (PIB आधिकारिक आंकड़ों सहित)

योजना का नाम	प्रारंभ तिथि एवं उपलब्धि मील का पत्थर	पात्र आयु वर्ग	प्रीमियम / अंशदान / ऋण सीमा	बीमा कवर / लाभ एवं प्रमुख शर्तें	प्रामाणिक संदर्भ स्रोत
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)	**28 अगस्त 2014** (अगस्त 2024 में योजना ने **10 वर्ष** पूर्ण किए)	10 वर्ष से अधिक का कोई भी नागरिक (ओवरड्राफ्ट हेतु: **18 से 65 वर्ष**)	शून्य न्यूनतम बैलेंस; **₹10,000 तक ओवरड्राफ्ट (OD)** सुविधा	RuPay कार्ड पर **₹2 लाख** का दुर्घटना बीमा (28.08.2018 के बाद खुले खातों पर; उससे पूर्व ₹1 लाख था); OD ऋण PSL के अंतर्गत योग्य	वित्तीय समावेशन 10 वर्ष — PIB
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)	**9 मई 2015** (मई 2025 में योजना ने **10 वर्ष** पूर्ण किए)	**18 से 50 वर्ष** (एक बार जुड़ने पर 55 वर्ष की आयु तक कवरेज जारी रह सकता है)	**₹436 प्रति वर्ष** (1 जून से 31 मई का वार्षिक नवीनीकरण चक्र; पहले ₹330 था)	**किसी भी कारण से मृत्यु** होने पर **₹2 लाख** का एक-वर्षीय नवीनीकरणीय जीवन बीमा कवरेज	PMJJBY 10 वर्ष — PIB
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	**9 मई 2015** (मई 2025 में योजना ने **10 वर्ष** पूर्ण किए)	**18 से 70 वर्ष**	**मात्र ₹20 प्रति वर्ष** (ऑटो-डेबिट सुविधा; पहले ₹12 प्रति वर्ष था)	दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर **₹2 लाख** तथा आंशिक स्थायी विकलांगता पर **₹1 लाख** का कवर	PMSBY 10 वर्ष — PIB
अटल पेंशन योजना (APY)	**9 मई 2015** (प्रशासक: **PFRDA**)	**18 से 40 वर्ष** (न्यूनतम 20 वर्ष का अंशदान काल; **आयकर दाता पात्र नहीं** हैं — 1 अक्टूबर 2022 से नियम)	आयु व चुनी गई पेंशन राशि के अनुसार मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अंशदान	60 वर्ष की आयु के बाद **₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000** की निश्चित मासिक पेंशन	सामाजिक सुरक्षा — PIB
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)	**8 अप्रैल 2015** (गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों हेतु)	18 वर्ष+ के उद्यमी	**शिशु:** ₹50,000 तक; **किशोर:** ₹50,000 से ₹5 लाख; **तरुण:** ₹5 लाख से ₹10 लाख; **तरुण प्लस (Tarun Plus): ₹10 लाख से ₹20 लाख तक**	'तरुण' श्रेणी का ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले उद्यमियों के लिए बजट घोषणा के तहत **'तरुण प्लस' (₹20 लाख तक)** श्रेणी जोड़ी गई	IUC Academy वित्तीय जागरूकता
भुगतान बैंक बनाम लघु वित्त बैंक (PBs vs SFBs)	नवंबर 2014 में आरबीआई द्वारा दिशानिर्देश जारी	**भुगतान बैंक:** नचिकेत मोर समिति; **लघु वित्त बैंक:** उषा थोराट समिति	**भुगतान बैंक:** प्रति ग्राहक अधिकतम जमा सीमा **₹2 लाख** (सावधि जमा/FD व ऋण वर्जित); **SFBs:** सभी प्रकार की जमा व ऋण (75% PSL)	भारत का प्रथम भुगतान बैंक: **एयरटेल पेमेंट्स बैंक**; प्रथम लघु वित्त बैंक: **कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक** (जालंधर)	लघु वित्त बैंक एवं PSL — RBI

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (अधिकृत पीआईबी एवं आरबीआई तथ्य):

1. पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की वित्तीय सेवाएं विभाग वर्षांत रिपोर्ट के अनुसार, **प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)** ने अगस्त 2024 में तथा **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)** और **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)** ने **मई 2025 में अपने सफल 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं**।

2. नागरिकों को उनके बैंकों में पड़े लावारिस जमा (Unclaimed Bank Deposits — जो खाते 10 वर्ष या अधिक से निष्क्रिय हैं और आरबीआई के **DEA Fund - Depositor Education and Awareness Fund** में हस्तांतरित हो जाते हैं), म्यूचुअल फंड, शेयर लाभांश और बीमा राशि का दावा करने में सहायता के लिए सरकार ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है (PIB विज्ञप्ति) और आरबीआई ने इसके लिए **'उद्गम' (UDGAM — Unclaimed Deposits Gateway to Access inforMation)** पोर्टल लॉन्च किया है।

3. **वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index — Financial Inclusion Index)** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष **जुलाई** माह में (बिना किसी आधार वर्ष / Without any Base Year के) प्रकाशित किया जाता है, जिसका मान **0 से 100** के बीच होता है और इसके **3 मुख्य पैरामीटर** हैं: **1. पहुंच (Access — 35% भार)**, **2. उपयोग (Usage — 45% भार)** और **3. गुणवत्ता (Quality — 20% भार)**।

4. वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रतिरूपण (Impersonation) रोकने के लिए **बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS)** को परीक्षाओं के दौरान स्वैच्छिक आधार पर **आधार प्रमाणीकरण (e-KYC)** के उपयोग हेतु अधिकृत किया है (PIB विज्ञप्ति)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

- **जाल 1 (PMJJBY बनाम PMSBY बनाम APY की अधिकतम आयु सीमा):** इन तीनों योजनाओं की न्यूनतम आयु **18 वर्ष** है, किंतु अधिकतम प्रवेश आयु अलग-अलग है!
- **अटल पेंशन योजना (APY):** 18 से **40 वर्ष**
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):** 18 से **50 वर्ष** (प्रीमियम: ₹436)
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** 18 से **70 वर्ष** (प्रीमियम: ₹20) (**PIB विज्ञप्ति**)।
- **जाल 2 (आरबीआई के FI-Index का आधार वर्ष):** परीक्षा में पूछा जाता है कि "आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) का आधार वर्ष (Base Year) क्या है?" इसका सही उत्तर है—**"कोई आधार वर्ष नहीं है (No Base Year)"**!

5. IUC स्मृति ट्रिक

★ IUC स्मृति ट्रिक:

- **सूत्र (जन-सुरक्षा आयु व प्रीमियम तथा FI-Index भार):** "अटल **40**, जीवन ज्योति **50 (₹436)**, सुरक्षा **70 (₹20)**; *FI-Index* में **पहुंच-35, उपयोग-45, गुणवत्ता-20**!"
- **डिकोडिंग:**

1. **18–40 वर्ष:** APY | **18–50 वर्ष:** PMJJBY (₹436) | **18–70 वर्ष:** PMSBY (₹20)
2. **FI-Index (35 + 45 + 20 = 100%):** Access (35%) + Usage (45%) + Quality (20%) (**IUC Academy**)।

मॉड्यूल 8: भारत में बीमा क्षेत्र का इतिहास, IRDAI, 100% FDI सुधार एवं बीमा के सिद्धांत

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 8: भारत में बीमा क्षेत्र का इतिहास, IRDAI, 100% FDI सुधार एवं बीमा के सिद्धांत

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: भारत में बीमा क्षेत्र के क्रमिक विकास एवं नियामक सुधारों की यात्रा

[नोड 1: प्रारंभिक इतिहास से राष्ट्रीयकरण युग (1818–1972)]
| • 1818: ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (कोलकाता — भारत में पहली जीवन बीमा कंपनी)
| • 1850: ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी (प्रथम साधारण बीमा) | 1870: बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी (प्रथम भारतीय जीवन बीमा)
| • 1 सितंबर 1956: 245 कंपनियों का विलय कर 'भारतीय जीवन बीमा निगम' (LIC) की स्थापना
| • 1972 (GIC Act, प्रभावी 1 जनवरी 1973): साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण (GIC एवं 4 सहायक कंपनियाँ)
▼
[नोड 2: मल्होत्रा समिति एवं IRDAI की स्थापना (1993–2000)]
| • आर.एन. मल्होत्रा समिति (1993) ने बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने और स्वतंत्र नियामक की सिफारिश की
| • IRDA अधिनियम, 1999 के तहत अप्रैल 2000 में IRDAI का गठन (मुख्यालय 2001 में दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित)
▼
[नोड 3: बीमा के 7 मौलिक कानूनी सिद्धांत एवं निक्षेप बीमा (DICGC)]
| • परम सद्भाव (Uberrimae Fidei), बीमायोग्य हित, क्षतिपूर्ति (जीवन बीमा पर लागू नहीं!), प्रस्थापन, आसन्न कारण, अंशदान व हानि न्यूनीकरण
| • DICGC (1978 — RBI की 100% सहायक): प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक अधिकतम ₹5 लाख तक का बैंक जमा बीमा (90 दिन में भुगतान)
▼
[नोड 4: ऐतिहासिक बीमा संशोधन (100% FDI एवं सुगम व्यवसाय — 2025-2026)]
| • भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई
| • विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों (Re-insurers) हेतु न्यूनतम नेट ओन्ड फंड (NOF) ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ किया गया

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: बीमा क्षेत्र के नवीनतम वैधानिक सुधार (PIB 2025-26), संस्थाएं एवं मौलिक सिद्धांत

बीमा सुधार / सिद्धांत / संस्था	वैधानिक प्रावधान / ऐतिहासिक तिथि	पूर्व नियम / स्थिति	नवीन संशोधित नियम / मुख्य विशेषता	परीक्षा हेतु विशेष बिंदु	प्रामाणिक संदर्भ स्रोत
भारतीय बीमा कंपनियों में FDI सीमा	भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2025 (30 दिसंबर 2025 को अधिसूचित)	भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा **74%** थी (और बीमा मध्यस्थों में 100%)	अब भारतीय बीमा कंपनियों में भी **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाकर 100%** कर दी गई है	स्थिर पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और '2047 तक सबके लिए बीमा' लक्ष्य को गति देने हेतु ऐतिहासिक कदम	**बीमा क्षेत्र 100% FDI सुधार — PIB**
विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं (Foreign Re-insurers) हेतु Net Owned Fund (NOF)	बीमा संशोधन प्रावधान (वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय)	विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के भारत में प्रवेश हेतु न्यूनतम नेट ओन्ड फंड (NOF) **₹5,000 करोड़** आवश्यक था	इसे **₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़** कर दिया गया है	भारत में पुनर्बीमा क्षमता (Re-insurance Capacity) बढ़ाने के लिए अधिक विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के प्रवेश को सुगम बनाया गया	**विदेशी पुनर्बीमा NOF सुधार — PIB**
शेयर हस्तांतरण हेतु IRDAI अनुमोदन सीमा एवं जागरूकता कोष	बीमा संशोधन एवं सुगम व्यवसाय (Ease of Doing Business) प्रावधान	चुकता इक्विटी पूंजी के **1%** से अधिक शेयरों के हस्तांतरण पर IRDAI की पूर्व अनुमति आवश्यक थी	शेयर हस्तांतरण की यह सीमा **1% से बढ़ाकर 5%** कर दी गई है; साथ ही **'पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष'** के गठन का प्रावधान और बीमा मध्यस्थों का एक-बारगी (One-time) पंजीकरण	बीमा घनत्व (Per Capita Premium) और बीमा पैठ (Premium as % of GDP) को बढ़ाने पर विशेष बल	**शेयर हस्तांतरण व कोष सुधार — PIB**
IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण)	आर.एन. मल्होत्रा समिति (1993) IRDA अधिनियम, **1999** (गठन: अप्रैल 2000)	प्रारंभिक मुख्यालय नई दिल्ली में था	वर्ष 2001 से मुख्यालय **हैदराबाद (तेलंगाना)** में स्थित है; 10-सदस्यीय प्राधिकरण (1 अध्यक्ष + 5 पूर्णकालिक + 4 अंशकालिक सदस्य)	लक्ष्य: **'2047 तक सभी के लिए बीमा'** तथा बीमा सुगम (Bima Sugam), बीमा विस्तार व बीमा वाहक (**बीमा त्रयी**)	**IUC Academy बीमा जागरूकता**
क्षतिपूर्ति (Indemnity) एवं प्रस्थापन (Subrogation) का सिद्धांत	बीमा अनुबंध के मौलिक कानूनी सिद्धांत	केवल वास्तविक वित्तीय हानि की भरपाई करना ताकि बीमित व्यक्ति दुर्घटना से लाभ न कमा सके	**अग्नि, समुद्री और वाहन (साधारण) बीमा पर लागू होता है**, किंतु **जीवन बीमा (Life Insurance) पर कभी लागू नहीं होता** (क्योंकि मानव जीवन का मूल्य नहीं आंका जा सकता)	**उबेरिमा फिडेई (Uberrimae Fidei):** परम सद्भाव का सिद्धांत — दोनों पक्षों द्वारा सभी भौतिक तथ्यों का सत्य प्रकटीकरण	**IUC Academy बीमा जागरूकता**
DICGC (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम)	DICGC अधिनियम, 1961 (स्थापना: **15 जुलाई 1978** — मुंबई)	पहले बैंक जमा पर बीमा कवर ₹1 लाख था	**4 फरवरी 2020** से प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक (मूलधन + ब्याज मिलाकर) बीमा कवर बढ़ाकर **₹5 लाख** कर दिया गया है	वाणिज्यिक बैंकों, विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं, RRBs, SFBs, PBs व सहकारी बैंकों पर लागू (**प्राथमिक सहकारी समितियाँ शामिल नहीं**)	**आरबीआई निक्षेप बीमा — RBI**

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (अधिकृत पीआईबी बीमा सुधार तथ्य):

1. पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की 10 जनवरी 2026 की आधिकारिक विज्ञप्ति में बीमा परीक्षाओं के लिए चार अत्यंत महत्वपूर्ण नवीनतम सुधार दर्ज हैं जिन्हें प्रत्येक अभ्यर्थी को कंठस्थ करना चाहिए:

• **प्रथम:** भारतीय बीमा कंपनियों में **FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100%** कर दी गई है (30 दिसंबर 2025 को नियम अधिसूचित)।

• **द्वितीय:** विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों (Foreign Re-insurers) के लिए **Net Owned Funds (NOF)** की आवश्यकता **₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़** कर दी गई है।

• **तृतीय:** बीमा कंपनियों की चुकता इक्विटी पूंजी के शेयरों के हस्तांतरण के लिए IRDAI से पूर्व अनुमति लेने की सीमा **1% से बढ़ाकर 5%** कर दी गई है।

• **चतुर्थ:** नागरिकों में जोखिम सुरक्षा और बीमा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए **'पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष' (Policyholders' Education and Protection Fund)** के निर्माण तथा बीमा मध्यस्थों के **एक-बारगी पंजीकरण (One-time Registration)** का प्रावधान किया गया है।

2. भारत की एकमात्र स्वदेशी राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी (National Re-insurer) **जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re — स्थापना 1972, मुख्यालय मुंबई)** है।

3. सार्वजनिक क्षेत्र की **4 साधारण बीमा कंपनियाँ** हैं: **1. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मुंबई), 2. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (चेन्नई), 3. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (नई दिल्ली)** और **4. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कोलकाता)**।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1 (बीमा पैठ बनाम बीमा घनत्व — Insurance Penetration vs Insurance Density):** यह बीमा परीक्षाओं (LIC AAO, NIACL, IBPS) का सबसे प्रसिद्ध भ्रम है!

• **बीमा पैठ (Insurance Penetration):** देश के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत (%)** के रूप में कुल बीमा प्रीमियम का अनुपात (**Insurance Premium / GDP × 100**)।

• **बीमा घनत्व (Insurance Density):** देश की **कुल जनसंख्या के सापेक्ष प्रति व्यक्ति प्रीमियम (Per Capita Premium in USD)** का अनुपात (**Total Premium / Total Population**)।

• **जाल 2 (जीवन बीमा पर कौन-से सिद्धांत लागू नहीं होते?):** जीवन बीमा (Life Insurance) एक अनिश्चित घटना/निश्चित दावा अनुबंध (Contingency Contract) है, इसलिए इस पर **'क्षतिपूर्ति का सिद्धांत' (Principle of Indemnity), 'प्रस्थापन का सिद्धांत' (Principle of Subrogation)** और **'अंशदान का सिद्धांत' (Principle of Contribution)** लागू **नहीं** होते हैं!

5. IUC स्मृति ट्रिक

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **सूत्र (4 सरकारी साधारण बीमा कंपनियों के मुख्यालय व बीमा संशोधन):** "न्यू इंडिया **मुंबई**, यूनाइटेड **चेन्नई**, ओरिएंटल **दिल्ली**, नेशनल **कोलकाता**; *FDI* **100%**, शेयर ट्रांसफर **5%**, री-इंश्योरेंस *NOF* **1000 करोड़**!"

• **डिकोडिंग:**

1. **न्यू इंडिया एश्योरेंस** = मुंबई | **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस** = चेन्नई
2. **ओरिएंटल इंश्योरेंस** = नई दिल्ली | **नेशनल इंश्योरेंस** = कोलकाता
3. **LIC मुख्यालय** = मुंबई (1 सितंबर 1956) | **IRDAI मुख्यालय** = हैदराबाद (1999/2000) (IUC Academy)।

मॉड्यूल 9: अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs), परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 एवं बैंकिंग लोकपाल

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 9: अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs), परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 एवं बैंकिंग लोकपाल

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: भारत के 5 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs) एवं बैंकिंग कानूनी संरक्षण

[नोड 1: आरबीआई द्वारा विनियमित 5 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (All-India Financial Institutions - AIFIs)]
| • 1. EXIM Bank (1982 - मुंबई) 2. NABARD (1982 - मुंबई) 3. NHB (1988 - नई दिल्ली)
| • 4. SIDBI (1990 - लखनऊ) 5. NaBFID (2021 - मुंबई — अवसंरचना वित्तपोषण हेतु 5वां AIFI)
▼
[नोड 2: परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881)]
| • धारा 4: वचन पत्र (Promissory Note) | धारा 5: विनिमय बिल (Bill of Exchange) | धारा 6: चेक (Cheque — ट्रंकेटेड व इलेक्ट्रॉनिक चेक सहित)
| • धारा 138: अपर्याप्त निधि के कारण चेक बाउंस (Dishonour of Cheque) को दंडनीय अपराध बनाना (2 वर्ष तक कारावास या दुगुना जुर्माना)
▼
[नोड 3: चेक समाशोधन प्रणाली (CTS), सकारात्मक वेतन प्रणाली (Positive Pay) एवं वैधता]
| • चेक व डिमांड ड्राफ्ट (DD) की वैधता अवधि: जारी होने की तिथि से 3 माह (90 दिन)
| • Positive Pay System (PPS): ₹50,000 और उससे अधिक के चेक जारी करने पर मुख्य विवरणों की पुनर्युष्टि
▼
[नोड 4: आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (RB-IOS — 'एक राष्ट्र, एक लोकपाल')]
| • बैंकिंग, एनबीएफसी और डिजिटल लेनदेन के तीन पुराने लोकपालों का एकीकरण; केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (CRPC): चंडीगढ़
| • मुआवज़ा सीमा: वास्तविक वित्तीय क्षति हेतु ₹20 लाख तक + मानसिक प्रताड़ना व समय की हानि हेतु ₹1 लाख तक अतिरिक्त

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारत के 5 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs) एवं परक्राम्य लिखत धाराएं

संस्थान / वैधानिक प्रावधान	स्थापना वर्ष / धारा	मुख्यालय / अधिकार क्षेत्र	संबंधित अधिनियम / सिफारिश समिति	मुख्य कार्यक्षेत्र एवं विशेष परीक्षा तथ्य	प्रामाणिक संदर्भ स्रोत
नाबार्ड (NABARD — राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)	**12 जुलाई 1982**	मुंबई, महाराष्ट्र	नाबार्ड अधिनियम, 1981 एवं **बी. शिवरमन समिति (CRAFICARD)**	कृषि, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का पुनर्वित्तपोषण (Refinancing), RIDF कोष संचालन तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण; **100% भारत सरकार स्वामित्व**	आरबीआई पर्यवेक्षण — RBI
सिडबी (SIDBI — भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक)	**2 अप्रैल 1990**	**लखनऊ, उत्तर प्रदेश**	सिडबी अधिनियम, 1989	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास हेतु शीर्ष वित्तीय संस्थान; MUDRA इसके अधीन स्थापित हुआ	आरबीआई पर्यवेक्षण — RBI
एक्ज़िम बैंक (EXIM Bank) एवं राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)	**EXIM:** 1 जनवरी 1982; **NHB:** 9 जुलाई 1988	**EXIM:** मुंबई; **NHB:** नई दिल्ली	एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981; राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (आरबीआई से 100% हिस्सेदारी सरकार को हस्तांतरित - 2019)	**EXIM:** आयात-निर्यात वित्तपोषण; **NHB:** आवास वित्त सूचकांक **'NHB RESIDEX'** जारी करता है (आवास वित्त कंपनियों - HFCs का पंजीकरण अब RBI के पास)	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन
नैबफिड (NaBFID — नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट)	**2021**	मुंबई, महाराष्ट्र	NaBFID अधिनियम, 2021	दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु स्थापित भारत का **5वां अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI)**	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act, 1881)	9 दिसंबर 1881 (प्रभावी 1 मार्च 1882)	संपूर्ण भारत	**धारा 4:** वचन पत्र (2 पक्ष); **धारा 5:** विनिमय बिल (3 पक्ष); **धारा 6:** चेक (3 पक्ष: Drawer, Drawee [सदैव बैंक], Payee)	**धारा 25:** सार्वजनिक अवकाश (Public Holidays) की घोषणा; **धारा 138:** अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक अनादरण (Cheque Bounce) पर दंड	परक्राम्य लिखत संदर्भ — RBI
आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS, 2021)	12 नवंबर 2021	केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र (**CRPC**): **चंडीगढ़**	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई अधिनियम व PSS अधिनियम के तहत 'One Nation, One Ombudsman'	यदि बैंक शिकायत करने के **30 दिनों** के भीतर समाधान नहीं करता, तो ग्राहक `cms.rbi.org.in` या टोल-फ्री नंबर **14448** पर शिकायत कर सकता है; अपील अधिकारी: **आरबीआई के कार्यकारी निदेशक (ED)**	आरबीआई उपभोक्ता संरक्षण — RBI

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (वैधानिक एवं संस्थागत तथ्य):

1. आरबीआई द्वारा विनियमित सभी 5 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (AIFIs) में से 3 का मुख्यालय **मुंबई** (NABARD, EXIM Bank, NaBFID) में, 1 का **नई दिल्ली** (NHB) में और **एकमात्र सिडबी (SIDBI) का मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ** में स्थित है!

2. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की **धारा 4 (वचन पत्र / Promissory Note)** में **2 पक्ष** होते हैं (1. निर्माता/Maker और 2. आदाता/Payee) तथा इसमें भुगतान की **बिना शर्त प्रतिज्ञा (Unconditional Undertaking)** होती है; जबकि **धारा 5 (विनिमय बिल / Bill of Exchange)** और **धारा 6 (चेक / Cheque)** में **3 पक्ष** होते हैं (1. आहर्ता/Drawer, 2. अदाकर्ता/Drawee और 3. आदाता/Payee) तथा इनमें भुगतान का **बिना शर्त आदेश (Unconditional Order)** होता है। चेक में अदाकर्ता (Drawee) **सदैव एक निर्दिष्ट बैंकर** ही होता है!

3. **चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS)** में चेक को भौतिक रूप से एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने की आवश्यकता नहीं होती; इसके स्थान पर चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज और MICR डेटा भेजा जाता है, जिससे समाशोधन समय और लागत दोनों में भारी कमी आती है।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1 (NHB और NABARD में आरबीआई की वर्तमान हिस्सेदारी):** पहले नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) दोनों में भारतीय रिज़र्व बैंक की हिस्सेदारी थी, किंतु **नरसिंहम समिति-II** की सिफारिश ("नियामक को विनियमित संस्था का स्वामी नहीं होना चाहिए") के आधार पर आरबीआई ने अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी बेच दी है—अब **नाबार्ड (NABARD)** और **राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)** दोनों में **100% स्वामित्व भारत सरकार** का है!

• **जाल 2 (स्टेल चेक बनाम पोस्ट-डेटेड चेक बनाम एंटी-डेटेड चेक):**

• **स्टेल चेक (Stale Cheque):** वह चेक जिसे उस पर अंकित तिथि से **3 महीने (90 दिन) बीत जाने के बाद** बैंक में प्रस्तुत किया जाता है (बैंक इसका भुगतान नहीं करता)।

• **पोस्ट-डेटेड चेक (Post-Dated Cheque):** जिस पर भविष्य की तारीख अंकित हो (उस तारीख से पहले भुगतान नहीं होता)।

• **एंटी-डेटेड चेक (Ante-Dated Cheque):** जिस पर बैंक में प्रस्तुत करने की तिथि से पहले की तारीख अंकित हो (परंतु 3 माह की वैधता के भीतर हो)।

5. IUC स्मृति ट्रिक

★ **IUC स्मृति ट्रिक:**

• **सूत्र (NI Act 1881 की धाराएं व 5 AIFIs):** "धारा **4 में वचन (*Promissory*)**, **5 में बिल (*BoE*)**, **6 में चेक**, **25 में छुट्टी**, और **138 में चेक बाउंस की सजा नेक**; सिडबी बैठा **लखनऊ**, *NHB* **दिल्ली**, बाकी तीनों *AIFI* **मुंबई** में एक!"

• **डिकोडिंग:**

1. **धारा 4:** वचन पत्र | **धारा 5:** विनिमय बिल | **धारा 6:** चेक | **धारा 25:** सार्वजनिक अवकाश | **धारा 138:** चेक बाउंस

2. **5 AIFIs:** SIDBI (लखनऊ), NHB (नई दिल्ली), NABARD (मुंबई), EXIM Bank (मुंबई), NaBFID (मुंबई) (IUC Academy)।

मॉड्यूल 10: बैंकिंग में ग्राहक संबंध, स्वामित्व अधिकार, प्रमुख समितियाँ एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 10: बैंकिंग में ग्राहक संबंध, स्वामित्व अधिकार, प्रमुख समितियाँ एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह: बैंकर-ग्राहक कानूनी संबंध, खातों के प्रकार एवं वैश्विक वित्तीय स्थापत्य

[नोड 1: बैंकर और ग्राहक के मध्य कानूनी संबंध (Banker-Customer Relationship)]
| • जमा खाता (सावधि/बचत/चालू): ग्राहक = ऋणदाता (Creditor) एवं बैंक = ऋणी (Debtor)
| • ऋण खाता (Loan/Advance): बैंक = ऋणदाता (Creditor) एवं ग्राहक = ऋणी (Debtor)
| • लॉकर सुविधा: बैंक = पट्टादाता (Lessor) एवं ग्राहक = पट्टेदार (Lessee) | सेफ कस्टडी: अमानतदार (Bailee) व अमानतकर्ता (Bailor)
▼
[नोड 2: बैंकर के विशेष अधिकार एवं अनिवासी खाते (NRE, NRO, FCNR-B)]
| • ग्रहणाधिकार (Right of Lien), समंजन का अधिकार (Right of Set-off) एवं गार्निशी आदेश (Garnishee Order — कोर्ट द्वारा)
| • अनिवासी भारतीय (NRI) खाते: NRE (विदेशी आय, कर-मुक्त, रूपया खाता), NRO (भारतीय आय, कर-योग्य), FCNR-B (विदेशी मुद्रा सावधि जमा)
▼
[नोड 3: भारतीय बैंकिंग सुधारों की प्रमुख ऐतिहासिक समितियाँ]
| • नरसिंहम समिति (बैंकिंग सुधार), चक्रवर्ती समिति (मौद्रिक प्रणाली), गोइपोरिया व दामोदरन समिति (ग्राहक सेवा), नचिकेत मोर (वित्तीय समावेशन)
▼
[नोड 4: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (ब्रेटन वुड्स जुड़वां एवं बहुपक्षीय विकास बैंक)]
| • 1944 (ब्रेटन वुड्स): विश्व बैंक समूह (IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID) एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF — SDR मुद्रा बास्केट) — वॉशिंगटन डी.सी.
| • ADB (1966 - मनीला), AIIB (2016 - बीजिंग), NDB (2014 - शंघाई) एवं FATF (1989 - पेरिस — मनी लॉन्ड्रिंग व टेरर फाइनेंसिंग रोधी)

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: बैंकर-ग्राहक संबंध, अनिवासी खाते (NRI Accounts) एवं प्रमुख बैंकिंग समितियाँ

विषय / लेनदेन प्रकार / समिति	बैंक की भूमिका / मुख्य प्रावधान	ग्राहक की भूमिका / कर एवं मुद्रा नियम	परीक्षा में पूछे जाने वाले विशेष बिंदु	प्रामाणिक संदर्भ स्रोत
बैंकर-ग्राहक संबंध (जमा, ऋण, लॉकर, ट्रस्ट व एजेंसी)	**जमा में:** ऋणी (Debtor); **ऋण में:** ऋणदाता (Creditor); **लॉकर में:** पट्टादाता (Lessor/Licensor); **सुरक्षित अभिरक्षा (Safe Custody) में:** अमानतदार (Bailee — भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 148)	**जमा में:** ऋणदाता (Creditor); **ऋण में:** ऋणी (Debtor); **लॉकर में:** पट्टेदार (Lessee/Licensee); **चेक संग्रह/स्थायी निर्देश में:** प्रधान (Principal) और बैंक एजेंट (Agent)	जब कोई ग्राहक बैंक में कोई वस्तु भूल जाता है, तो बैंक **'न्यासी' (Trustee)** और ग्राहक **'लाभार्थी' (Beneficiary)** बन जाता है	आरबीआई सामान्य व्यक्ति बैंकिंग FAQs — RBI
NRE बनाम NRO बनाम FCNR(B) खाते	**NRE (Non-Resident External):** विदेशी आय को भारतीय रुपये (INR) में रखने हेतु; **NRO (Non-Resident Ordinary):** भारत में अर्जित आय (किराया, पेंशन, लाभांश) को INR में रखने हेतु	**FCNR-B (Foreign Currency Non-Resident Bank):** केवल **सावधि जमा (Term Deposit — 1 से 5 वर्ष)** खाता जो विदेशी मुद्रा में ही रखा जाता है (विनिमय दर जोखिम शून्य)	**NRE** और **FCNR(B)** खातों का ब्याज भारत में **आयकर से पूर्णतः मुक्त (Tax-Free)** और पूर्णतः प्रत्यावर्तनीय (Repatriable) होता है, जबकि **NRO** खाते का ब्याज **कर-योग्य (Taxable)** होता है	आरबीआई विदेशी मुद्रा नीति — RBI
गार्निशी आदेश (Garnishee Order) बनाम कुर्की आदेश (Attachment Order)	**गार्निशी आदेश:** सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 21 नियम 46 के तहत **न्यायालय** द्वारा जारी; **कुर्की आदेश: आयकर / राजस्व अधिकारियों** द्वारा कर बकाया वसूली हेतु जारी	बैंक (Judgment Debtor's Debtor) को ग्राहक के खाते से भुगतान रोकने का आदेश	**महत्वपूर्ण अंतर:** गार्निशी आदेश भविष्य में जमा होने वाली राशि पर लागू नहीं होता (जब तक स्पष्ट न हो), किंतु आयकर का **Attachment Order** आदेश के बाद जमा होने वाली भविष्य की राशि पर भी लागू होता है!	IUC Academy बैंकिंग विधि
प्रमुख बैंकिंग सुधार समितियाँ	**एम. नरसिंहम समिति (1991 एवं 1998):** बैंकिंग क्षेत्र सुधार, SLR/CRR में कमी, NPA व सरफेसी की नींव; **पी.जे. नायक समिति (2014):** बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB / अब FSIB) व शासन सुधार	**उर्जित पटेल समिति (2014):** मौद्रिक नीति समिति (MPC) और CPI आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण; **रघुराम राजन समिति:** वित्तीय क्षेत्र सुधार; **दीपक मोहंती समिति:** वित्तीय समावेशन मध्यम अवधि पथ	**गोइपोरिया समिति** और **एम. दामोदरन समिति** बैंक ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित हैं; **कामत समिति** कोविड-19 ऋण पुनर्गठन मानदंडों से संबंधित थी	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन

विषय / लेनदेन प्रकार / समिति	बैंक की भूमिका / मुख्य प्रावधान	ग्राहक की भूमिका / कर एवं मुद्रा नियम	परीक्षा में पूछे जाने वाले विशेष बिंदु	प्रामाणिक संदर्भ स्रोत
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक (World Bank)	**ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (1944)** से स्थापित (मुख्यालय: **वॉशिंगटन डी.सी., अमेरिका**); किसी भी देश को विश्व बैंक (IBRD) का सदस्य बनने के लिए पहले **IMF का सदस्य बनना अनिवार्य** है	**IMF की विशेष आहरण अधिकार (SDR — 'Paper Gold', 1969)** बास्केट में **5 मुद्राएं** शामिल हैं: **1. अमेरिकी डॉलर ($), 2. यूरो (€), 3. चीनी रॅन्मिन्बी (युआन - 2016 में शामिल), 4. जापानी येन (¥) और 5. ब्रिटिश पाउंड (£)**	विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से भारत **ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)** का सदस्य **नहीं** है (अन्य 4 — IBRD, IDA, IFC, MIGA का सदस्य है)	IUC Academy अंतर्राष्ट्रीय वित्त

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (बैंकिंग विधि एवं वैश्विक वित्त तथ्य):

1. **FSIB (Financial Services Institutions Bureau — वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो)** ने 1 जुलाई 2022 से पूर्ववर्ती **बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB — 2016, पी.जे. नायक समिति)** का स्थान लिया है। FSIB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (LIC, GIC, NIACL आदि) और वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशकों (WTDs) व गैर-कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की सिफारिश करता है (PIB वित्तीय सेवाएं विभाग)।

2. **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टें परीक्षाओं में बार-बार पूछी जाती हैं: **1. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (World Economic Outlook - WEO)** और **2. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (Global Financial Stability Report - GFSR)**।

3. **बैंकर का समंजन अधिकार (Right of Set-off)** बैंक को यह कानूनी अधिकार देता है कि वह एक ही ग्राहक के एक खाते के क्रेडिट बैलेंस (जमा राशि) को दूसरे खाते के डेबिट बैलेंस (ऋण बकाया) के साथ समायोजित कर सके, बशर्ते दोनों खाते एक ही नाम और एक ही हैसियत (Same Capacity) में हों तथा ऋण परिपक्व (Due) हो चुका हो।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):

• **जाल 1 (लॉकर बनाम सेफ डिपॉजिट कस्टडी में संबंध):** जब ग्राहक बैंक का **लॉकर (Safe Deposit Locker)** किराए पर लेता है, तो बैंक को यह पता नहीं होता कि ग्राहक ने लॉकर के अंदर क्या रखा है—इसलिए वहां संबंध **पट्टादाता (Lessor - बैंक) और पट्टेदार (Lessee - ग्राहक)** का होता है! किंतु जब ग्राहक सीलबंद बॉक्स या आभूषण बैंक को **सुरक्षित अभिरक्षा (Safe Custody)** में सौंपता है, तब संबंध **अमानतदार (Bailee - बैंक) और अमानतकर्ता (Bailor - ग्राहक)** का होता है!

• **जाल 2 (विश्व बैंक समूह का कौन-सा अंग भारत ने जॉइन नहीं किया है?):** विश्व बैंक समूह (World Bank Group) में 5 संस्थाएं हैं: IBRD (1944), IDA (1960 — इसे 'सॉफ्ट लोन विंडो' कहा जाता है), IFC (1956), MIGA (1988) और **ICSID (1966)**। भारत **ICSID का सदस्य नहीं है**!

5. IUC स्मृति ट्रिक

★ IUC स्मृति ट्रिक:

• **सूत्र (IMF की SDR बास्केट की 5 मुद्राएं व NRI खाते):** *"SDR* में **डॉलर, यूरो, युआन, येन, पाउंड** का साथ; ***FCNR-B*** केवल विदेशी मुद्रा *FD*, ***NRE*** कर-मुक्त रुपया, ***NRO*** भारत की आय पर टैक्स के हाथ!"

• **डिकोडिंग:**

1. **SDR की 5 मुद्राएं:** US Dollar, Euro, Chinese Yuan (Renminbi), Japanese Yen, British Pound Sterling

2. **NRE:** रुपया खाता (कर-मुक्त) | **NRO:** रुपया खाता (भारत की आय, कर-योग्य) | **FCNR(B):** केवल विदेशी मुद्रा सावधि जमा (कर-मुक्त, विनिमय जोखिम मुक्त) (IUC Academy)।

अंतिम समय त्वरित वन-लाइनर रिवीजन कैप्सूल (100-पॉइंट सुपरफास्ट सार)

1. भारत में आधुनिक पद्धति का प्रथम बैंक वर्ष **1770** में कोलकाता में स्थापित **'बैंक ऑफ हिंदुस्तान'** था।

2. बैंक ऑफ बंगाल (1806), बैंक ऑफ बॉम्बे (1840) और बैंक ऑफ मद्रास (1843) तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय कर **27 जनवरी 1921** को **'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया'** बनाया गया।

3. **ए.डी. गोरेवाला समिति** की सिफारिश पर **1 जुलाई 1955** को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर **'भारतीय स्टेट बैंक' (SBI)** की स्थापना की गई।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना **हिल्टन यंग आयोग (1926)** की सिफारिश पर **आरबीआई अधिनियम, 1934** के तहत **1 अप्रैल 1935** को ₹5 करोड़ की पूंजी से कोलकाता में हुई।

5. वर्ष **1937** में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से स्थायी रूप से **मुंबई** स्थानांतरित किया गया और **1 जनवरी 1949** को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ।

6. आरबीआई के प्रथम गवर्नर **सर ओसबोर्न स्मिथ** थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर **सर सी.डी. देशमुख (1943)** थे (जिन्होंने 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया)।

7. आरबीआई के प्रतीक चिह्न (Logo) में **ताड़ का वृक्ष (Palm Tree)** और **रॉयल बंगाल टाइगर** अंकित है।

8. आरबीआई अधिनियम, 1934 की **धारा 22** आरबीआई को भारत में ₹2 से लेकर उच्चतम मूल्यवर्ग तक के करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार देती है (**आरबीआई प्रकाशन**)।

9. ₹1 का करेंसी नोट और सभी मूल्यवर्ग के सिक्के **वित्त मंत्रालय (भारत सरकार)** द्वारा जारी किए जाते हैं और ₹1 के नोट पर **वित्त सचिव** के हस्ताक्षर होते हैं।

10. भारत में नोट निर्गमन के लिए वर्ष 1956-57 से **'न्यूनतम कोष प्रणाली' (Minimum Reserve System)** अपनाई गई है, जिसके तहत आरबीआई को कुल **₹200 करोड़** का कोष (**₹115 करोड़ का स्वर्ण** + **₹85 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियां**) रखना अनिवार्य है।

11. **19 जुलाई 1969** को न्यूनतम ₹50 करोड़ जमा वाले **14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों** का और **15 अप्रैल 1980** को न्यूनतम ₹200 करोड़ जमा वाले **6 बैंकों** का राष्ट्रीयकरण किया गया।

12. मेगा बैंक विलय (2019–2020) के बाद वर्तमान में भारत में **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks - PSBs)** की कुल संख्या **12** है।

13. हाल ही में **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** ने **₹25,000 करोड़** का भारत का अब तक का सबसे बड़ा **QIP (Qualified Institutional Placement)** सफलतापूर्वक पूरा किया (**PIB वर्षांत समीक्षा**)।

14. नवंबर 2024 के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार पूर्णकालिक निदेशकों के साथ **स्केल-IV से स्केल-VIII तक के वरिष्ठ अधिकारियों** तक किया गया है (**PIB विज्ञप्ति**)।

15. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs)** की स्थापना **एम. नरसिंहम कार्यदल** की सिफारिश पर **2 अक्टूबर 1975** को हुई और भारत का पहला आरआरबी **'प्रथमा बैंक' (मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश)** था।

16. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पूंजी हिस्सेदारी का अनुपात **केंद्र सरकार (50%) : प्रायोजक बैंक (35%) : राज्य सरकार (15%)** होता है (**आरआरबी निदेश — RBI**)।

17. **वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS)** का गठन नवंबर **1994** में किया गया था, जो वाणिज्यिक बैंकों, SFBs, PBs, NBFCs और AIFIs का एकीकृत पर्यवेक्षण करता है (**RBI वार्षिक प्रतिवेदन**)।

18. **मौद्रिक नीति समिति (MPC)** का गठन **उर्जित पटेल समिति** की सिफारिश पर आरबीआई अधिनियम, 1934 की **धारा 45ZB** के तहत वर्ष **2016** में किया गया।

19. मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कुल **6 सदस्य** होते हैं (3 आरबीआई से और 3 भारत सरकार द्वारा 4 वर्ष हेतु नामित); इसकी बैठकों की गणपूर्ति (Quorum) **4 सदस्य** है और बराबर मत पड़ने पर **आरबीआई गवर्नर को निर्णायक मत (Casting Vote)** देने का अधिकार है।

20. भारत में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य (FIT) **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI - Combined)** पर आधारित **4% (±2% अर्थात् 2% से 6% के बीच)** निर्धारित है।

21. **रेपो दर (Repo Rate)** वह दर है जिस पर आरबीआई तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के बदले अल्पकालिक तरलता देता है (**RBI शब्दावली**)।

22. अप्रैल 2022 में शुरू की गई **स्थायी जमा सुविधा (SDF - Standing Deposit Facility)** बिना किसी संपार्श्विक (Collateral) के बैंकों से तरलता अवशोषित करती है और यह LAF कॉरिडोर का नया **फर्श (Floor)** है (**RBI वार्षिक रिपोर्ट**)।

23. **सीमांत स्थायी सुविधा (MSF - Marginal Standing Facility)** के तहत अनुसूचित बैंक आपात स्थिति में अपने अनिवार्य SLR कोटे में से भी निर्धारित सीमा तक प्रतिभूतियां रखकर ओवरनाइट ऋण ले सकते हैं; यह नीतिगत कॉरिडोर की **छत (Ceiling)** है।

24. 30 दिसंबर 2023 से आरबीआई ने **SDF और MSF दोनों** के अंतर्गत तरलता रिवर्सल की अनुमति सप्ताहांत और छुट्टियों के दिनों में भी प्रदान कर दी है (**RBI वार्षिक रिपोर्ट**)।

25. **नकद आरक्षित अनुपात (CRR)** की परिभाषा **आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)** में है और इस पर आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता।

26. **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)** की परिभाषा **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24** में है और इसकी वैधानिक अधिकतम सीमा **40%** है।

27. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL)** का कुल लक्ष्य ANBC/CEOBE का **40%** है (**PSL मास्टर निदेश — RBI**)।

28. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs)** और **लघु वित्त बैंकों (SFBs)** दोनों के लिए कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) का लक्ष्य **75%** निर्धारित है।

29. वाणिज्यिक बैंकों के 40% PSL लक्ष्य के भीतर **कृषि के लिए 18%** (जिसमें लघु एवं सीमांत किसानों - SMF हेतु **10%**), **सूक्ष्म उद्यमों के लिए 7.5%** और **कमज़ोर वर्गों के लिए 12%** का उप-लक्ष्य है।

30. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए कमज़ोर वर्गों (Weaker Sections) का PSL उप-लक्ष्य **15%** है।

31. आरबीआई के निदेशों के अनुसार **1 हेक्टेयर तक** भूमि वाले किसानों को **'सीमांत किसान' (Marginal Farmers)** और **1 हेक्टेयर से अधिक व 2 हेक्टेयर तक** भूमि वाले किसानों को **'लघु किसान' (Small Farmers)** कहा जाता है।

32. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (**PSLCs**) की चार श्रेणियों का अनाम व्यापार आरबीआई के **'ई-कुबेर' (e-Kuber)** पोर्टल पर प्रातः 10:00 से सायं 4:30 बजे तक होता है (**PSL FAQs — RBI**)।

33. PSL लक्ष्य पूरा न कर पाने वाले बैंकों को शेष राशि नाबार्ड के **ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF — स्थापना 1995-96)** या सिडबी/NHB के कोष में जमा करनी पड़ती है।

34. **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** की स्थापना **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के अंतर्गत आरबीआई और आईबीए द्वारा **दिसंबर 2008** में एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में की गई (**NPCI पोर्टल**)।

35. एनपीसीआई की तीन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ हैं—**NIPL** (अंतर्राष्ट्रीय भुगतान), **NBBL** (भारत बिलपे) और **NBSL** (भीम सर्विसेज) (**NPCI अधिसूचना**)।

36. **UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफेस)** की शुरुआत **11 अप्रैल 2016** को और **भीम (BHIM) ऐप** की शुरुआत **30 दिसंबर 2016** को हुई (**UPI — NPCI**)।

37. **IMPS (तत्काल भुगतान सेवा — 2010)** के माध्यम से प्रति लेनदेन अधिकतम **₹5 लाख** तक की राशि 24x7x365 तुरंत हस्तांतरित की जा सकती है (**IMPS — NPCI**)।

38. **NACH (राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह)** का उपयोग सब्सिडी (DBT), वेतन, पेंशन, लाभांश और ऋण की मासिक किस्त (EMI/SIP) के थोक व आवर्ती निपटान के लिए किया जाता है (**NACH — NPCI**)।

39. डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए 24x7 चैटबॉट और हेल्पलाइन सेवा का नाम **'डिजीसाथी' (DigiSaathi — 14431)** है (**DigiSaathi — NPCI**)।

40. **RTGS (Real Time Gross Settlement)** में न्यूनतम लेनदेन सीमा **₹2 लाख** है (अधिकतम कोई सीमा नहीं), जबकि **NEFT** में न्यूनतम सीमा ₹1 है और दोनों प्रणालियाँ आरबीआई द्वारा 24x7 संचालित होती हैं।

41. **IFSC** में **11 अल्फ़ान्यूमेरिक वर्ण** होते हैं (5वां वर्ण सदैव '0'), **MICR** में **9 संख्यात्मक अंक** होते हैं और **MMID** में **7 अंक** होते हैं।

42. **LEI (Legal Entity Identifier)** वित्तीय लेनदेन में कॉर्पोरेट संस्थाओं की विशिष्ट पहचान के लिए **20 वर्णों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड** है।

43. जब किसी ऋण खाते में मूलधन या ब्याज की किस्त **90 दिनों से अधिक** समय तक बकाया रहती है, तो उसे **गैर-निष्पादित आस्ति (NPA)** घोषित किया जाता है (**RBI वार्षिक प्रतिवेदन**)।

44. एनपीए होने से पूर्व तनावग्रस्त खातों को तीन **विशेष उल्लेख खातों (SMA)** में बांटा जाता है: **SMA-0 (1–30 दिन)**, **SMA-1 (31–60 दिन)** और **SMA-2 (61–90 दिन)**।

45. 12 महीने तक एनपीए रहने वाली आस्ति को **'अवमानक आस्ति' (Sub-standard Asset)** और 12 महीने से अधिक समय तक अवमानक रहने पर **'संदिग्ध आस्ति' (Doubtful Asset)** कहा जाता है।

46. **SARFAESI अधिनियम, 2002** बैंकों को ₹1 लाख से अधिक के सुरक्षित एनपीए ऋणों में न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना गिरवी रखी संपत्ति को जब्त कर बेचने का अधिकार देता है, किंतु यह **कृषि भूमि पर लागू नहीं होता**।

47. **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC, 2016)** के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) का न्यायनिर्णयन **NCLT** करता है और सितंबर 2025 तक इससे ऋणदाताओं ने **₹3.99 लाख करोड़ (परिसमापन मूल्य का 170.09%)** वसूल किए हैं (**PIB विज्ञप्ति**)।

48. बेसल-III मानकों के अनुसार भारत में आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित न्यूनतम **CRAR (पूंजी पर्याप्तता अनुपात) 9%** है (2.5% पूंजी संरक्षण बफर - CCB सहित **11.5%**) (**RBI वार्षिक प्रतिवेदन**)।

49. आरबीआई के **स्केल-आधारित विनियमन (SBR — 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी)** में एनबीएफसी को 4 परतों—**Base Layer (BL), Middle Layer (ML), Upper Layer (UL) और Top Layer** में विभाजित किया गया है और NBFC-UL के लिए न्यूनतम **9% CET-1 पूंजी** अनिवार्य है।

50. शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के 4-स्तरीय नियामक ढांचे में एकल जिले के **Tier-1 UCB** हेतु न्यूनतम नेट वर्थ **₹2 करोड़** और अन्य सभी UCBs हेतु **₹5 करोड़** निर्धारित है (**RBI वार्षिक प्रतिवेदन**)।

51. आरबीआई द्वारा **भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)** को **घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs)** घोषित किया गया है।

52. **मुद्रा बाज़ार (Money Market)** अल्पावधि (1 वर्ष से कम) के वित्तीय प्रपत्रों का बाज़ार है जिसका नियामक **आरबीआई (RBI)** है, जबकि **पूंजी बाज़ार (Capital Market)** दीर्घावधि (> 1 वर्ष) का बाज़ार है जिसका नियामक **सेबी (SEBI)** है।

53. अंतर-बैंक बाजार में **1 दिन (Overnight)** के ऋण को **'कॉल मनी'**, **2 से 14 दिन** के ऋण को **'नोटिस मनी'** और **15 दिन से 1 वर्ष** के ऋण को **'टर्म मनी'** कहा जाता है।

54. **ट्रेजरी बिल (T-Bills)** केवल केंद्र सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा **91 दिन, 182 दिन और 364 दिन** की परिपक्वता के लिए न्यूनतम **₹10,000** के गुणज में जारी किए जाते हैं।

55. 91 दिनों से कम अवधि के सरकारी अल्पकालिक नकदी प्रवाह असंतुलन को पूरा करने के लिए **नकद प्रबंधन बिल (Cash Management Bills - CMBs)** जारी किए जाते हैं।

56. **वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper - CP)** कंपनियों द्वारा जारी किया जाने वाला **असुरक्षित वचन पत्र** है, जिसकी न्यूनतम राशि **₹5 लाख** और अवधि 7 **दिन से 1 वर्ष** होती है।

57. **जमा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit - CD)** बैंकों द्वारा (7 दिन से 1 वर्ष हेतु) और AIFIs द्वारा (1 से 3 वर्ष हेतु) न्यूनतम **₹5 लाख** के गुणज में जारी किया जाता है (RRBs इसे जारी नहीं कर सकते)।

58. **सेबी (SEBI)** की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई और **30 जनवरी 1992** को सेबी अधिनियम, 1992 द्वारा इसे वैधानिक दर्जा मिला (मुख्यालय: मुंबई) (**SEBI पोर्टल**)।

59. सेबी ने निवेशकों के 21 अधिकारों और पारदर्शिता को सुरक्षित करने के लिए सभी MIIs (स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी) व मध्यस्थों हेतु **'निवेशक चार्टर' (Investor Charter)** लागू किया है (**SEBI निवेशक चार्टर**)।

60. सेबी के ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का नाम **'SCORES' (SEBI Complaint Redressal System)** है (**SCORES पोर्टल**)।

61. एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE — स्थापना 1875, सूचकांक: SENSEX - 30 शेयर)** है, जबकि **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE — स्थापना 1992, फेरवानी समिति)** का सूचकांक **NIFTY-50** है।

62. भारत में दो डिपॉजिटरी कार्यरत हैं—**NSDL (National Securities Depository Limited — 1996, NSE प्रवर्तित)** और **CDSL (Central Depository Services Limited — 1999, BSE प्रवर्तित)**।

63. IPO में आवेदन करते समय निवेशक के बैंक खाते में ही रकम ब्लॉक रखने की प्रणाली को **ASBA (Application Supported by Blocked Amount)** कहा जाता है।

64. **प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)** की शुरुआत **28 अगस्त 2014** को हुई और अगस्त 2024 में इसने अपने 10 वर्ष पूरे किए; इसमें **₹10,000 की ओवरड्राफ्ट** और RuPay कार्ड पर **₹2 लाख का दुर्घटना बीमा** मिलता है (**PIB विज्ञप्ति**)।

65. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY — 9 मई 2015)** में **18 से 50 वर्ष** के व्यक्तियों को **₹436 वार्षिक प्रीमियम** पर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर **₹2 लाख का जीवन बीमा कवर** मिलता है (**PIB विज्ञप्ति**)।

66. **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY — 9 मई 2015)** में **18 से 70 वर्ष** के व्यक्तियों को **₹20 वार्षिक प्रीमियम** पर दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता हेतु **₹2 लाख** और आंशिक विकलांगता हेतु **₹1 लाख** का कवर मिलता है (**PIB विज्ञप्ति**)।

67. **अटल पेंशन योजना (APY — 9 मई 2015, नियामक: PFRDA)** में **18 से 40 वर्ष** के गैर-आयकरदाता नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद **₹1,000 से ₹5,000** तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन मिलती है।

68. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY — 8 अप्रैल 2015)** में ऋण की चार श्रेणियाँ हैं: **शिशु (₹50,000 तक)**, **किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख)**, **तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख)** और **तरुण प्लस (₹10 लाख से ₹20 लाख तक)**।

69. **नचिकेत मोर समिति** की सिफारिश पर **भुगतान बैंक (Payment Banks)** और **उषा थोराट समिति** की सिफारिश पर **लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks)** स्थापित किए गए।

70. भुगतान बैंक प्रति ग्राहक अधिकतम **₹2 लाख** तक की मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, किंतु वे **ऋण (Loan) या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते** और न ही सावधि जमा (FD) खोल सकते हैं।

71. आरबीआई द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई में प्रकाशित **वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index)** का **कोई आधार वर्ष नहीं है** और इसके तीन घटक हैं: **पहुंच (35%), उपयोग (45%) और गुणवत्ता (20%)**।

72. बैंकों में 10 वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय खातों की लावारिस जमा राशि (Unclaimed Deposits) खोजने के लिए आरबीआई ने **'उद्गम' (UDGAM)** पोर्टल शुरू किया है।

73. भारत में पहली जीवन बीमा कंपनी **1818** में स्थापित **ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी** थी और **1 सितंबर 1956** को **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC — मुख्यालय: मुंबई)** की स्थापना हुई।

74. **आर.एन. मल्होत्रा समिति (1993)** की सिफारिश पर **IRDA अधिनियम, 1999** पारित हुआ और अप्रैल 2000 में **IRDAI** की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय **हैदराबाद** में है।

75. भारत सरकार ने **भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100%** कर दिया है (**PIB विज्ञप्ति**)।

76. भारत में विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों (Foreign Re-insurers) के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए आवश्यक **न्यूनतम नेट ओन्ड फंड (NOF) को ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़** कर दिया गया है (**PIB विज्ञप्ति**)।

77. बीमा कंपनियों की चुकता इक्विटी पूंजी के शेयरों के हस्तांतरण के लिए IRDAI से अनुमति लेने की सीमा **1% से बढ़ाकर 5%** कर दी गई है तथा **'पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष'** स्थापित किया गया है (**PIB विज्ञप्ति**)।

78. देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत को **'बीमा पैठ' (Insurance Penetration)** और प्रति व्यक्ति प्रीमियम (USD में) को **'बीमा घनत्व' (Insurance Density)** कहा जाता है।

79. बीमा का **'क्षतिपूर्ति का सिद्धांत' (Principle of Indemnity)** और **'प्रस्थापन का सिद्धांत' (Principle of Subrogation)** साधारण बीमा पर लागू होते हैं, किंतु **जीवन बीमा (Life Insurance) पर लागू नहीं होते**।

80. भारत की एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी **GIC Re (जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया — मुंबई)** है।

81. आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी **DICGC (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम — 1978)** प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता अधिकतम **₹5 लाख** तक की बैंक जमा राशि का बीमा करती है।

82. भारत में आरबीआई द्वारा विनियमित **5 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs)** हैं: **NABARD (1982), EXIM Bank (1982), NHB (1988), SIDBI (1990) और NaBFID (2021)**।

83. **नाबार्ड (NABARD)** की स्थापना **बी. शिवरमन समिति (CRAFICARD)** की सिफारिश पर **12 जुलाई 1982** को मुंबई में हुई और इसमें अब 100% स्वामित्व भारत सरकार का है।

84. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के विकास हेतु शीर्ष बैंक **सिडबी (SIDBI)** की स्थापना **2 अप्रैल 1990** को हुई और इसका मुख्यालय **लखनऊ (उत्तर प्रदेश)** में है।

85. **राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB — 1988, मुख्यालय: नई दिल्ली)** भारत में आवासीय संपत्तियों के मूल्यों की निगरानी के लिए **'NHB RESIDEX'** सूचकांक जारी करता है।

86. **परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act, 1881)** की **धारा 4** में वचन पत्र (Promissory Note), **धारा 5** में विनिमय बिल (Bill of Exchange) और **धारा 6** में चेक (Cheque) को परिभाषित किया गया है।

87. NI अधिनियम, 1881 की **धारा 138** खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक के अनादरण (**Cheque Bounce**) को एक दंडनीय अपराध बनाती है।

88. भारत में चेक और डिमांड ड्राफ्ट (DD) की वैधता अवधि उस पर अंकित जारी करने की तिथि से **3 महीने (90 दिन)** होती है; इसके बाद वह **'स्टेल चेक' (Stale Cheque)** कहलाता है।

89. ₹50,000 और उससे अधिक मूल्य के चेक धोखाधड़ी से बचाने के लिए आरबीआई ने **'पॉजिटिव पे सिस्टम' (Positive Pay System - PPS)** लागू किया है।

90. **आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (RB-IOS)** का केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (**CRPC**) **चंडीगढ़** में स्थित है और इसमें मुआवज़े की अधिकतम सीमा **₹20 लाख** (मानसिक उत्पीड़न हेतु ₹1 लाख अतिरिक्त) है।

91. बैंक में पैसा जमा करने पर ग्राहक **'ऋणदाता' (Creditor)** और बैंक **'ऋणी' (Debtor)** होता है, जबकि लॉकर सुविधा में बैंक **'पट्टादाता' (Lessor)** और ग्राहक **'पट्टेदार' (Lessee)** होता है।

92. अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए **NRE** और **FCNR(B)** खातों पर मिलने वाला ब्याज भारत में **आयकर से मुक्त** होता है, जबकि **NRO** खाते पर मिलने वाला ब्याज **कर-योग्य** होता है।

93. **गार्निशी आदेश (Garnishee Order)** न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जबकि आयकर बकाया वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा **कुर्की आदेश (Attachment Order)** जारी किया जाता है।

94. वर्ष 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से स्थापित **विश्व बैंक (World Bank)** और **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** दोनों का मुख्यालय **वॉशिंगटन डी.सी. (अमेरिका)** में है।

95. IMF की आरक्षित संपत्ति **SDR (Special Drawing Rights — 'Paper Gold')** की बास्केट में **5 मुद्राएं** हैं: **अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन (रॅन्मिन्बी), जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड**।

96. विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं (IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID) में से **IDA (अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ)** को विश्व बैंक की **'सॉफ्ट लोन विंडो' (रियायती ऋण खिड़की)** कहा जाता है और भारत **ICSID का सदस्य नहीं है**।

97. **एशियाई विकास बैंक (ADB — 1966)** का मुख्यालय **मनीला (फिलीपींस)** में, **AIIB (2016)** का मुख्यालय **बीजिंग** में और ब्रिक्स के **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB — 2014)** का मुख्यालय **शंघाई** में है।

98. मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने वाली वैश्विक संस्था **FATF (Financial Action Task Force — 1989)** का मुख्यालय **पेरिस (फ्रांस)** में स्थित है।

99. जब कोई खाता लगातार **24 महीने (2 वर्ष)** तक ग्राहक द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, तो उसे **निष्क्रिय खाता (Inoperative / Dormant Account)** घोषित कर दिया जाता है।

100. **समावेशी सार्वभौमिक करियर अकादमी (IUC Academy)** की पुस्तक 20 के ये 100 मास्टर वन-लाइनर बिंदु भारतीय रिज़र्व बैंक (**RBI**), **NPCI**, **SEBI** और **PIB** के नवीनतम 2025-26 दिशानिर्देशों पर आधारित हैं।

भाग 1: गहन अध्याय-विस्तार (Comprehensive Chapter Expansion)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — भाग 1: गहन अध्याय-विस्तार (Comprehensive Chapter Expansion)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
अध्याय 1: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का इतिहास, संरचना एवं प्रमुख कार्य	अध्याय 2: मौद्रिक नीति समिति (MPC), नीतिगत दरें एवं बैंकिंग राष्ट्रीयकरण (1969/1980)	अध्याय 3: PSL लक्ष्य, NPA वर्गीकरण (SMA-0/1/2), SARFAESI 2002, IBC 2016 एवं Basel-III मानक	अध्याय 4: NPCI के डिजिटल उत्पाद (UPI/IMPS/NEFT/RTGS/e-RUPI) एवं CBDC (डिजिटल रुपया)

अध्याय 1: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का इतिहास, संरचना एवं प्रमुख कार्य

1.1 भारत में बैंकिंग का ऐतिहासिक विकास एवं RBI की स्थापना

• **प्रारंभिक आधुनिक बैंकिंग:** भारत में यूरोपीय पद्धति पर आधारित **प्रथम बैंक** सन् **1770 में 'बैंक ऑफ हिंदुस्तान'** (कोलकाता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित, 1832 में बंद) था।

• **तीन प्रेसीडेंसी बैंक:** ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में तीन प्रेसीडेंसी बैंक स्थापित हुए — (1) **बैंक ऑफ बंगाल (1806/1809)**, (2) **बैंक ऑफ बॉम्बे (1840)**, और (3) **बैंक ऑफ मद्रास (1843)**। सन् **1921** में इन तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय करके **'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया'** की स्थापना की गई, जिसका **1 जुलाई 1955** को गोरेवाला समिति (*All India Rural Credit Survey Committee*) की सिफारिश पर राष्ट्रीयकरण कर **'भारतीय स्टेट बैंक' (SBI)** नाम रखा गया।

• **भारतीय पूंजी से स्थापित बैंक:** सीमित देयता (Limited Liability) के आधार पर भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक **1881 में 'अवध कमर्शियल बैंक'** (फैजाबाद) था, जबकि पूर्णतः भारतीय पूंजी और प्रबंधन वाला पहला बैंक **1894 में स्थापित 'पंजाब नेशनल बैंक' (PNB)** (संस्थापक: लाला लाजपत राय एवं दयाल सिंह मजीठिया, लाहौर) था।

• **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की उत्पत्ति:**

• डॉ. बी. आर. अंबेडकर की पुस्तक '*The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution*' (1923) की अवधारणाओं और **1926 के रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस (हिल्टन यंग कमीशन)** की सिफारिश पर केंद्रीय बैंक की रूपरेखा बनी।

• **RBI अधिनियम, 1934** पारित हुआ और **1 अप्रैल 1935** को ₹5 करोड़ की अधिकृत निजी शेयर पूंजी (₹100 प्रत्येक के 5 लाख शेयर) के साथ कोलकाता में RBI की स्थापना हुई।

• **मुख्यालय परिवर्तन:** स्थापना के समय मुख्यालय **कोलकाता** में था, जिसे **1937 में स्थायी रूप से मुंबई** स्थानांतरित कर दिया गया।

• **प्रमुख गवर्नर:** प्रथम गवर्नर — **सर ऑस्बॉर्न स्मिथ** (1935–1937, इन्होंने किसी भी भारतीय नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए); प्रथम भारतीय गवर्नर (तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर और राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर) — **सर सी. डी. देशमुख** (1943–1949); सबसे लंबे कार्यकाल वाले गवर्नर — **सर बेनेगल रामा राव** (1949–1957, 7 वर्ष 197 दिन); सबसे छोटे कार्यकाल वाले गवर्नर — **अमिताभ घोष** (मात्र 20 दिन, 1985); प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र RBI गवर्नर — **डॉ. मनमोहन सिंह** (15वें गवर्नर, 1982–1985); **25वें गवर्नर — शक्तिकांत दास** (दिसंबर 2018 – दिसंबर 2024); **26वें गवर्नर — संजय मल्होत्रा** (दिसंबर 2024 से कार्यरत)।

• **राष्ट्रीयकरण:** रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम, 1948 के तहत **1 जनवरी 1949** को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया।

• **पड़ोसी देशों का केंद्रीय बैंक:** RBI ने **अप्रैल 1947 तक बर्मा (म्याँमार)** के और **जून 1948 तक पाकिस्तान** के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया।

• **लेखा वर्ष (Accounting Year):** पहले RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता था, जिसे **बि जालान समिति** की सिफारिश पर **2020–21 से बदलकर भारत सरकार के वित्तीय वर्ष के समान (1 अप्रैल से 31 मार्च)** कर दिया गया है।

1.2 RBI का केंद्रीय निदेशक मंडल (Central Board of Directors — कुल *21* सदस्य)

RBI अधिनियम *1934* की **धारा 8** के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड में अधिकतम **21 सदस्य** होते हैं:

1. **आधिकारिक निदेशक (Official Directors — कुल 5): 1 गवर्नर** और अधिकतम **4 डिप्टी गवर्नर** (नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3–5 वर्ष की अवधि के लिए)।

2. **गैर-आधिकारिक निदेशक (Non-Official Directors — कुल 16):** केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से नामित **10 निदेशक** (4 वर्ष का कार्यकाल), **4 क्षेत्रीय बोर्डों** (मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली) से **1-1 निदेशक (कुल 4)**, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के **2 सरकारी अधिकारी** (आर्थिक मामलों के सचिव और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव)।

1.3 RBI के प्रमुख वैधानिक कार्य एवं करेंसी निर्गमन

• **नोट निर्गमन का एकाधिकार (धारा 22):** ₹1 के नोट और सभी सिक्कों को छोड़कर (जिन्हें **सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011** के तहत भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है और ₹1 के नोट पर **वित्त सचिव** के हस्ताक्षर होते हैं), भारत में ₹2 से लेकर ₹10,000 तक के मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करने का एकाधिकार RBI के पास है (**धारा 24**)।

• **न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System — 1956/1957 से लागू):** आनुपातिक कोष प्रणाली को हटाकर 1956-57 से RBI **₹200 करोड़** का न्यूनतम कोष रखता है, जिसमें कम से कम **₹115 करोड़ का स्वर्ण (Gold Bullion/Coins)** और **₹85 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियाँ (Foreign Exchange Securities)** होना अनिवार्य है।

• **मुद्रणालय एवं टकसाल:**

• **4 करेंसी नोट प्रेस: नासिक (महाराष्ट्र, 1928)** और **देवास (मध्य प्रदेश, 1975)** का स्वामित्व भारत सरकार के **SPMCIL** के पास है; जबकि **मैसूर (कर्नाटक, 1999)** और **सालबोनी (पश्चिम बंगाल, 2000)** का संचालन RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी **BRBNMPL (भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लि., मुख्यालय: बेंगलुरु, स्थापना 1995)** करती है।

• **4 सरकारी टकसाल (Mints): मुंबई (महाराष्ट्र), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), हैदराबाद (तेलंगाना)** और **नोएडा (उत्तर प्रदेश — 1988 में स्थापित नवीनतम टकसाल)**।

• **RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली 5 सहायक कंपनियाँ (Wholly Owned Subsidiaries):**

1. **DICGC** (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation — 1978, मुंबई; प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक **₹5 लाख** तक की जमा राशि का बीमा कवर)।

2. **BRBNMPL** (Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt. Ltd. — 1995, बेंगलुरु)।

3. **ReBIT** (Reserve Bank Information Technology Pvt. Ltd. — 2016, नवी मुंबई; साइबर सुरक्षा व IT ऑडिट हेतु)।

4. **IFTAS** (Indian Financial Technology and Allied Services — 2015, मुंबई; INFINET और SFMS नेटवर्क का संचालन)।

5. **RBIH** (Reserve Bank Innovation Hub — 2020, बेंगलुरु; वित्तीय नवाचार व फिनटेक प्रोत्साहन हेतु)।

अध्याय 2: मौद्रिक नीति समिति (MPC), नीतिगत दरें एवं बैंकिंग राष्ट्रीयकरण (1969/1980)

2.1 मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC)

• **उर्जित पटेल समिति (2014)** की सिफारिश पर RBI अधिनियम, *1934* में संशोधन कर **धारा 45ZB** जोड़ी गई और **2016** में **6-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC)** का गठन किया गया।

• **संरचना (6 सदस्य):**

• **3 आंतरिक सदस्य (RBI से):** RBI गवर्नर (पदेन अध्यक्ष), मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर, और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित 1 RBI अधिकारी।

• **3 बाह्य सदस्य (भारत सरकार द्वारा नियुक्त):** अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्त के विशेषज्ञ (इनका कार्यकाल **4 वर्ष** का होता है और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते)।

• **निर्णय प्रक्रिया एवं कोरम:** बैठक के लिए **4 सदस्यों का कोरम** आवश्यक है। वर्ष में कम से कम **4 बार** (व्यवहार में प्रत्येक 2 माह पर वर्ष में 6 बार) बैठक अनिवार्य है। बराबर मत (Tie) होने की स्थिति में **RBI गवर्नर को निर्णायक मत (Casting Vote / Second Vote)** देने का अधिकार है।

• **लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting):** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (**CPI - Combined**, जिसे NSO जारी करता है) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति का लक्ष्य **4% (±2% सहनशीलता बैंड, अर्थात् 2% से 6% के बीच)** निर्धारित है। यदि लगातार **3 तिमाहियों** तक औसत मुद्रास्फीति 6% से ऊपर या 2% से नीचे रहती है, तो इसे लक्ष्य की विफलता माना जाता है और RBI को केंद्र सरकार को लिखित स्पष्टीकरण देना होता है।

2.2 मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण एवं नीतिगत दरें (Policy Rates & Reserve Ratios)

उपकरण / दर का नाम	परिभाषा, विधिक धारा एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
रेपो दर (Repo Rate — पॉलिसी रेट)	वह ब्याज दर जिस पर RBI तरलता समायोजन सुविधा (**LAF**) के तहत वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों (SLR कोटे से अतिरिक्त) के बदले **अल्पकालिक (Overnight / 1–14 दिन)** ऋण देता है। मुद्रास्फीति (महंगाई) बढ़ने पर RBI रेपो रेट **बढ़ाता** है (जिससे ऋण महंगे होते हैं और बाजार से तरलता कम होती है)।
स्थायी जमा सुविधा (SDF - Standing Deposit Facility)	**अप्रैल 2022** में RBI अधिनियम की धारा 17 के तहत शुरू किया गया **तरलता अवशोषण का नया आधार (Floor of LAF Corridor)**। इसके तहत बैंक **बिना किसी सरकारी प्रतिभूति (Collateral-free)** के अपना अतिरिक्त धन RBI के पास जमा कर सकते हैं। यह हमेशा **Repo Rate से 0.25% (25 bps) कम** रहता है।
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF - Marginal Standing Facility)	**2011** में शुरू की गई आपातकालीन ओवरनाइट उधार खिड़की (**Ceiling of LAF Corridor**)। इसमें अनुसूचित बैंक अपने **SLR कोटे की सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर** (NDTL के 2% तक) RBI से रातों-रात (Overnight) ऋण ले सकते हैं। यह हमेशा **Repo Rate से 0.25% (25 bps) अधिक** रहती है।
बैंक दर (Bank Rate — धारा 49)	वह मानक दर जिस पर RBI विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या पुनः भुनाने (Rediscounting) के लिए तैयार रहता है (दीर्घकालिक ऋण व CRR/SLR चूक पर दंडात्मक दर)। यह **MSF दर के बराबर** (अर्थात् Repo + 0.25%) संरेखित रहती है।
नकद आरक्षित अनुपात (CRR - Cash Reserve Ratio)	**RBI अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)** के तहत प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी **शुद्ध मांग और सावधि देयताओं (NDTL - Net Demand and Time Liabilities)** का एक निश्चित प्रतिशत **केवल नकद (Cash)** के रूप में RBI के पास रखना होता है। RBI इस राशि पर बैंकों को **कोई ब्याज नहीं देता** है और इसकी कोई न्यूनतम या अधिकतम वैधानिक सीमा (Floor/Ceiling) नहीं है।
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR - Statutory Liquidity Ratio)	**बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24** के तहत प्रत्येक बैंक को अपने **NDTL** का एक निश्चित हिस्सा (अधिकतम सीमा **40%**) अपने पास **नकदी (Cash), स्वर्ण (Gold) या भार-रहित अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs)** के रूप में सुरक्षित रखना होता है।

2.3 भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969 एवं 1980) और महा-विलय (Mega Mergers)

• **प्रथम चरण (19 जुलाई 1969):** प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश/अधिनियम द्वारा **₹50 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि (Deposits)** वाले **14 बड़े निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण** किया गया (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक)।

• **द्वितीय चरण (15 अप्रैल 1980):** छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में **₹200 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि** वाले **6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण** किया गया (आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक)। (नोट: सितंबर 1993 में 'न्यू बैंक ऑफ इंडिया' का विलय 'पंजाब नेशनल बैंक' में कर दिया गया, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का दूसरे में पहला विलय था।)

• **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का महा-विलय (2017–2020) — वर्तमान में कुल 12 PSBs:**

1. **1 अप्रैल 2017:** SBI के **5 सहयोगी बैंकों** (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर) और **भारतीय महिला बैंक** का विलय **SBI** में हुआ।

2. **1 अप्रैल 2019: विजया बैंक** और **देना बैंक** का विलय **बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)** में हुआ (भारत का पहला त्रिपक्षीय बैंक विलय)।

3. **1 अप्रैल 2020 (10 बैंकों का 4 में महा-विलय):**

- **ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) + यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया → पंजाब नेशनल बैंक (PNB)** में विलय।
- **सिंडिकेट बैंक → केनरा बैंक** में विलय।
- **आंध्रा बैंक + कॉर्पोरेशन बैंक → यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** में विलय।
- **इलाहाबाद बैंक → इंडियन बैंक** में विलय।

4. **वर्तमान में भारत में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) हैं:** SBI + 11 राष्ट्रीयकृत बैंक (PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक)।

अध्याय 3: PSL *लक्ष्य,* NPA *वर्गीकरण (*SMA-*0/1/2),* SARFAESI *2002,* IBC *2016 एवं* Basel-III *मानक*

*3.1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (*Priority Sector Lending - PSL*)*

RBI के PSL मास्टर डायरेक्शन एवं RBI PSL FAQs के अनुसार, PSL की गणना **ANBC (Adjusted Net Bank Credit — समायोजित निवल बैंक ऋण)** या **CEOBE (Credit Equivalent Amount of Off-Balance Sheet Exposure)**, दोनों में से जो भी **अधिक** हो, के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

- **PSL के 8 प्रमुख क्षेत्र:** (1) कृषि (Agriculture), (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), (3) निर्यात ऋण (Export Credit), (4) शिक्षा (Education — भारत और विदेश दोनों में अध्ययन हेतु **₹20 लाख** तक के ऋण), (5) आवास (Housing), (6) सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure — स्कूल, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, आयुष्मान भारत अस्पताल), (7) नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy — सौर, बायोगैस, पवन ऊर्जा हेतु **₹30 करोड़** तक के ऋण; व्यक्तिगत परिवारों हेतु ₹10 लाख तक), और (8) अन्य (कमजोर वर्ग व स्टार्टअप — कृषि व MSME में लगे स्टार्टअप को **₹50 करोड़** तक का ऋण)।

बैंक की श्रेणी	कुल PSL लक्ष्य (% of ANBC/ CEOBE)	कृषि (Agriculture) उप-लक्ष्य	लघु एवं सीमांत किसान (SMF)	सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises)	कमजोर वर्ग (Weaker Sections)
घरेलू वाणिज्यिक बैंक एवं **20 व अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक**	**40%**	**18%**	**10%**	**7.5%**	**12%**
20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक	**40%**	लागू नहीं (अधिकतम 32% निर्यात ऋण में दे सकते हैं और कम से कम 8% अन्य PSL में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) (नरसिंहम समिति, 2 अक्टूबर 1975 — प्रथमा बैंक)	**75%**	**18%**	**10%**	**7.5%**	**15%**
लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks - SFBs) (उषा थोराट समिति)	**75%**	**18%**	**10%**	**7.5%**	**12%**
शहरी सहकारी बैंक (Primary Urban Co-operative Banks - UCBs)	**40% से 75%** (चरणबद्ध लक्ष्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	**7.5%**	**12%**

(नोट: यदि कोई बैंक अपना *PSL* लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे बकाया राशि ***NABARD*** के अंतर्गत स्थापित ***RIDF [Rural Infrastructure Development Fund — 1995-96]*** या *SIDBI/NHB/MUDRA* के फंड में जमा करनी होती है, अथवा वह ***PSLC [Priority Sector Lending Certificates]*** खरीद सकता है। सीमांत किसान = 1 हेक्टेयर तक भूमि; लघु किसान = 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि।)

3.2 गैर-निष्पादित आस्तियाँ (NPA Classification) एवं विशेष उल्लेख खाते (SMA-0/1/2)

RBI के IRAC (Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) मानदंडों के अनुसार, जब किसी ऋण खाते पर ब्याज या मूलधन की किस्त **90 दिनों से अधिक** समय तक अतिदेय (Overdue) रहती है, तो वह **गैर-निष्पादित आस्ति (Non-Performing Asset - NPA)** बन जाता है।

• **कृषि ऋण के लिए NPA नियम:** अल्पावधि फसलों (Short Duration Crops — 1 वर्ष से कम पकने का समय) के लिए यदि मूलधन या ब्याज **2 फसल मौसम (Two Crop Seasons)** तक बकाया रहे, और दीर्घावधि फसलों (Long Duration Crops — 1 वर्ष से अधिक) के लिए **1 फसल मौसम (One Crop Season)** तक बकाया रहे, तब वह NPA घोषित होता है।

• **NPA बनने से पूर्व प्रारंभिक चेतावनी — SMA (Special Mention Accounts) की 3 श्रेणियाँ:**

• **SMA-0:** मूलधन या ब्याज भुगतान की देय तिथि से **1 से 30 दिनों तक** अतिदेय (Overdue) रहने पर।

• **SMA-1:** मूलधन या ब्याज **31 से 60 दिनों तक** अतिदेय रहने पर।

• **SMA-2:** मूलधन या ब्याज **61 से 90 दिनों तक** अतिदेय रहने पर। (90 दिन पूरे होते ही 91वें दिन से खाता ***NPA*** घोषित हो जाता है।)

• **NPA होने के बाद आस्तियों का 3-स्तरीय वर्गीकरण:**

1. **अवमानक आस्तियाँ (Sub-Standard Assets):** वह संपत्ति जो **12 महीने या उससे कम** की अवधि के लिए NPA रही हो।

2. **संदिग्ध आस्तियाँ (Doubtful Assets):** वह संपत्ति जो **12 महीने से अधिक** समय तक 'Sub-Standard' श्रेणी में बनी रही हो (इसे आगे D1 [1 वर्ष तक], D2 [1 से 3 वर्ष] और D3 [3 वर्ष से अधिक] में बांटा जाता है)।

3. **हानि आस्तियाँ (Loss Assets):** वह संपत्ति जहाँ बैंक, आंतरिक/बाह्य लेखापरीक्षक या RBI निरीक्षण द्वारा हानि की पहचान कर ली गई है, किंतु राशि अभी पूरी तरह बट्टे खाते (Written off) में नहीं डाली गई है; इसका वसूली मूल्य शून्य या नगण्य होता है (100% प्रावधान आवश्यक)।

3.3 SARFAESI अधिनियम, 2002 एवं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC, 2016)

• **SARFAESI Act, 2002* (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002):*

• **नरसिंहम समिति-II** और **अंध्यारुजिना समिति** की सिफारिशों पर अधिनियमित।

• यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को **न्यायालय या अधिकरण के हस्तक्षेप के बिना** चूककर्ता (Defaulter) उधारकर्ता को **60 दिनों का नोटिस** देकर उसकी गिरवी रखी गई संपत्ति (Secured Asset) को जब्त करने, प्रबंधन अपने हाथ में लेने और नीलाम करने अथवा **ARC (Asset Reconstruction Company — जैसे NARCL / बैड बैंक)** को बेचने का अधिकार देता है।

• **प्रमुख अपवाद (जहाँ SARFAESI लागू नहीं होता — धारा 31):** (1) **कृषि भूमि (Agricultural Land)** पर यह अधिनियम लागू नहीं होता; (2) **असुरक्षित ऋण (Unsecured Loans — जैसे बिना गारंटी का पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड)** पर लागू नहीं होता; (3) जहाँ बकाया ऋण की राशि **₹1 लाख से कम** हो; (4) जहाँ उधारकर्ता ने मूलधन और ब्याज सहित कुल ऋण का **80% से अधिक भुगतान कर दिया हो** (अर्थात् बकाया राशि मूल ऋण के **20% से कम** बची हो)।

• SARFAESI की कार्रवाई के विरुद्ध अपील पहले **DRT (Debt Recovery Tribunal — ऋण वसूली अधिकरण, 45 दिनों के भीतर)** और उसके बाद **DRAT (Debt Recovery Appellate Tribunal, 30 दिनों के भीतर — बकाया राशि का कम से कम 50% जमा करने पर)** में की जाती है।

• **IBC, 2016* (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 — दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता):*

• **टी. के. विश्वनाथन समिति** की सिफारिश पर 2016 में पारित। इसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दिवाला समाधान करना है।

• **चार स्तंभ (4 Pillars of IBC):** (1) **नियामक: IBBI** (*Insolvency and Bankruptcy Board of India* — स्थापना: 1 अक्टूबर 2016, मुख्यालय: नई दिल्ली, 10 सदस्यीय बोर्ड); (2) **दिवाला पेशेवर (Insolvency Professionals - IPs)** व IPA; (3) **सूचना उपयोगिता (Information Utilities - IU): NeSL** (*National E-Governance Services Ltd.* — देश की पहली और एकमात्र IU); (4)

न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (Adjudicating Authority): कंपनियों और LLP के लिए **NCLT** (*National Company Law Tribunal* — अपील: NCLAT) तथा व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए **DRT** (अपील: DRAT)।

• **CIRP समय-सीमा:** कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (**CIRP**) शुरू करने के लिए न्यूनतम डिफ़ॉल्ट सीमा **₹1 करोड़** है (जबकि MSME के लिए प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी — **PPIRP** की न्यूनतम डिफ़ॉल्ट सीमा **₹10 लाख** है)। CIRP को **180 दिनों** के भीतर (+ अधिकतम 90 दिन विस्तार, और कानूनी विवादों सहित कुल अधिकतम **330 दिनों** की अनिवार्य समय-सीमा) में पूरा करना होता है, जिसमें **ऋणदाताओं की समिति (Committee of Creditors - CoC)** के **66% मताधिकार** से समाधान योजना (Resolution Plan) पारित होती है।

3.4 बेसल-III मानक (Basel-III Norms — BCBS, BIS *बेसल, स्विट्ज़रलैंड*)

स्विट्ज़रलैंड के बेसल शहर में स्थित **BIS (Bank for International Settlements — स्थापना 1930)** की **BCBS (Basel Committee on Banking Supervision — स्थापना 1974)** द्वारा बैंकों की जोखिम सहने की क्षमता के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी पर्याप्तता मानक बनाए गए हैं। बेसल-III मानकों में **जोखिम भारित आस्तियों (RWA - Risk Weighted Assets)** के अनुपात में **CRAR (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio) / CAR (Capital Adequacy Ratio)** के नियम इस प्रकार हैं:

मानदंड / पूंजी का घटक	BCBS (अंतरराष्ट्रीय बेसल-III मानक)	RBI द्वारा भारतीय बैंकों के लिए निर्धारित मानक
1. कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) (सबसे उच्च गुणवत्ता वाली मूल पूंजी)	RWA का **4.5%**	RWA का **5.5%**
2. अतिरिक्त टियर-1 पूंजी (AT-1 — Additional Tier 1) (*Perpetual Bonds* आदि)	RWA का **1.5%**	RWA का **1.5%**
कुल टियर-1 पूंजी (Total Tier-1 Capital = CET-1 + AT-1) (*Going-Concern Capital*)	**6.0%**	**7.0%**
3. टियर-2 पूंजी (Tier-2 Capital) (*Gone-Concern / Supplementary Capital*)	अधिकतम **2.0%**	अधिकतम **2.0%**
न्यूनतम कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Minimum CRAR = Tier-1 + Tier-2)	**8.0%**	**9.0%** (*RRBs* के लिए भी 9%, जबकि *SFBs* व *NBFCs* के लिए **15%**)
4. पूंजी संरक्षण बफर (CCB - Capital Conservation Buffer) (केवल *CET-1* के रूप में)	**2.5%**	**2.5%**
CCB सहित कुल CRAR (Total CRAR + CCB)	**8.0% + 2.5% = 10.5%**	**9.0% + 2.5% = 11.5%**
5. प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (CCyB - Countercyclical Capital Buffer)	**0% से 2.5%**	**0% से 2.5%** (वर्तमान में *RBI* द्वारा 0% पर रखा गया है)
6. उत्तोलन अनुपात (Leverage Ratio = Tier-1 Capital / Total Exposure)	न्यूनतम **3.0%**	**D-SIBs** (SBI, HDFC, ICICI) के लिए **4.0%** और अन्य बैंकों के लिए **3.5%**
7. तरलता कवरेज अनुपात (LCR - Liquidity Coverage Ratio)	**30 दिनों** के शुद्ध नकदी बहिर्वाह के लिए **≥ 100%** उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA)	**≥ 100%** (30 दिनों के तनाव परिदृश्य हेतु HQLA)
8. शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात (NSFR - Net Stable Funding Ratio)	**1 वर्ष** की समयावधि के लिए उपलब्ध स्थिर फंडिंग (ASF) / आवश्यक स्थिर फंडिंग (RSF) **≥ 100%**	**≥ 100%**

(नोट: भारत में *RBI* द्वारा घोषित **3 घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक [*D-SIBs — "Too Big To Fail"*] हैं: *SBI, HDFC* बैंक और *ICICI* बैंक**, जिन्हें अतिरिक्त *CET-1* पूंजी रखनी होती है।)

अध्याय 4: NPCI के डिजिटल उत्पाद (UPI/IMPS/NEFT/RTGS/e-RUPI) एवं CBDC (डिजिटल रुपया)

4.1 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

• **स्थापना एवं विधिक आधार: भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007)** के तहत RBI और IBA (Indian Banks' Association) की पहल पर **दिसंबर 2008** में स्थापित (मुख्यालय: मुंबई)। यह **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के अंतर्गत पंजीकृत एक **'गैर-लाभकारी संगठन' (Not-for-Profit Company)** है।

• **NPCI की सहायक कंपनियाँ:** (1) **NIPL (NPCI International Payments Ltd. — 2020):** फ्रांस, यूएई, सिंगापुर (PayNow लिंकेज), श्रीलंका, मॉरीशस, नेपाल, भूटान आदि देशों में UPI और RuPay के वैश्विक विस्तार हेतु; (2) **NBBL (NPCI Bharat BillPay Ltd. — 2021):** भारत बिल पेमेंट सिस्टम **(Bharat Connect / BBPS)** के संचालन हेतु; (3) **NBSL (NPCI BHIM Services Ltd. — 2024)**।

4.2 भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणालियों की तुलनात्मक मास्टर तालिका

भुगतान प्रणाली	संचालक व प्रारंभ वर्ष	न्यूनतम एवं अधिकतम लेनदेन सीमा (Transaction Limit)	निपटान तंत्र एवं प्रमुख परीक्षापयोगी विशेषताएँ
NEFT (*National Electronic Funds Transfer*)	**RBI** (नवंबर 2005)	**न्यूनतम: कोई सीमा नहीं (₹1); अधिकतम: कोई सीमा नहीं** (केवल बैंक शाखा में नकद आधारित *NEFT* के लिए प्रति लेनदेन अधिकतम **₹50,000** तथा इंडो-नेपाल रेमिटेंस में ₹2 लाख तक)	**आस्थगित निवल निपटान (DNS - Deferred Net Settlement)** पर आधारित; **16 दिसंबर 2019** से 24x7x365 उपलब्ध; प्रतिदिन **48 आधे-आधे घंटे के बैचों (Half-hourly batches)** में निपटान।
RTGS (*Real Time Gross Settlement*)	**RBI** (मार्च 2004)	**न्यूनतम: ₹2 लाख; अधिकतम: कोई ऊपरी सीमा नहीं (No Upper Limit)**	**रियल-टाइम (तत्काल)** और **सकल (Gross — बिना किसी बंडलिंग के एक-एक लेनदेन का अलग निपटान)**; उच्च मूल्य के लेनदेन हेतु; **14 दिसंबर 2020** से 24x7x365 उपलब्ध। (*NEFT* व *RTGS* में **11-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक *IFSC* कोड** प्रयोग होता है जिसमें पहले 4 अक्षर बैंक का नाम, **5वाँ अक्षर हमेशा शून्य '0'** और अंतिम 6 अक्षर शाखा कोड दर्शाते हैं।)
IMPS (*Immediate Payment Service*)	**NPCI** (22 नवंबर 2010)	**न्यूनतम: ₹1; अधिकतम: ₹5 लाख** प्रति लेनदेन (अक्टूबर 2021 में ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया)	24x7 तात्कालिक अंतर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर; **MMID (7-अंकीय Mobile Money Identifier)** + मोबाइल नंबर या खाता संख्या + IFSC द्वारा; सरलीकृत IMPS में केवल मोबाइल नंबर + बैंक नाम से **₹5 लाख** तक बिना लाभार्थी जोड़े ट्रांसफर।
UPI (*Unified Payments Interface*)	**NPCI** (11 अप्रैल 2016; BHIM ऐप: 30 दिसंबर 2016)	**सामान्य P2P व P2M: ₹1 लाख/दिन; पूंजी बाजार, बीमा, विदेशी प्रेषण, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO): ₹2 लाख से ₹5 लाख; अस्पताल (Healthcare), शैक्षणिक संस्थान (Education) एवं कर भुगतान (Tax Payment — सितंबर 2024 से): ₹5 लाख** प्रति लेनदेन	**VPA (Virtual Payment Address)** आधारित तात्कालिक भुगतान; **UPI 123Pay (मार्च 2022):** बिना इंटरनेट वाले **फीचर फोन** उपयोगकर्ताओं हेतु 4 विकल्पों (IVR नंबर, मिस्ड कॉल, OEM ऐप, साउंड-आधारित) से ₹10,000 तक लेनदेन; **UPI Lite (सितंबर 2022):** बिना UPI PIN के छोटे ऑफ़लाइन/ऑन-डिवाइस वॉलेट भुगतान — **प्रति लेनदेन अधिकतम ₹1,000** (₹500 से बढ़ाकर ₹1,000) और **कुल वॉलेट बैलेंस सीमा ₹5,000** (₹2,000 से बढ़ाकर ₹5,000); **UPI Lite X:** पूर्णतः ऑफ़लाइन (NFC आधारित) भुगतान।
e-RUPI (*Prepaid Digital Voucher*)	**NPCI** (2 अगस्त 2021)	प्रति वाउचर सामान्य सीमा **₹10,000** (जबकि सरकारी योजनाओं व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए **₹1,00,000** तक)	एक **व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट (Person & Purpose Specific)** संपर्क-रहित डिजिटल वाउचर जो लाभार्थी के मोबाइल पर **SMS स्ट्रिंग या QR कोड** के रूप में आता है। इसके लिए लाभार्थी के पास **बैंक खाता, स्मार्टफोन या इंटरनेट होना भी आवश्यक नहीं** है।
CBDC (e₹ - Digital Rupee)	**RBI** (थोक पायलट: 1 नवंबर 2022; खुदरा पायलट: 1 दिसंबर 2022)	RBI के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से विभिन्न मूल्यवर्गों में	RBI द्वारा जारी **वैध मुद्रा (Legal Tender / Sovereign Currency)** का डिजिटल रूप, जो RBI की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दर्ज होता है। इसके दो प्रकार हैं: **1. e₹-W (Wholesale CBDC):** अंतर-बैंक निपटान व सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के द्वितीयक बाजार लेनदेन हेतु; **2. e₹-R (Retail CBDC):** आम नागरिकों और व्यापारियों (P2P व P2M) हेतु इलेक्ट्रॉनिक टोकन आधारित डिजिटल नकदी।

(*NPCI* के अन्य उत्पाद: ***RuPay*** [2012 — भारत का स्वदेशी कार्ड नेटवर्क], ***NACH*** [*National Automated Clearing House* — सब्सिडी *DBT*, लाभांश व *EMI* ऑटो-डेबिट हेतु], ***CTS*** [*Cheque Truncation System* — भौतिक चेक को भेजे बिना इलेक्ट्रॉनिक इमेज व **9-अंकीय *MICR* कोड** (प्रथम 3 अंक शहर, मध्य 3 बैंक, अंतिम 3 शाखा) द्वारा समाशोधन], ***AEPS*** [*Aadhaar Enabled Payment System* — आधार व बायोमेट्रिक से बैंकिंग], ***NETC FASTag*** [*Radio Frequency Identification* - ***RFID*** तकनीक पर आधारित टोल संग्रह] और *USSD* \99\#* सेवा।)

अध्याय 5: मुद्रा बाजार (Money Market) बनाम पूंजी बाजार (Capital Market) एवं SEBI

5.1 मुद्रा बाजार (Money Market — नियामक: RBI, अवधि: 1 दिन से 364 दिन / 1 वर्ष से कम)

अल्पकालिक (1 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाले) उच्च तरलता वाले वित्तीय उपकरणों के बाजार को **मुद्रा बाजार** कहते हैं, जिसका नियमन **RBI** करता है:

1. **कॉल मनी (Call Money):** जब बैंक आपस में बिना किसी गिरवी के केवल **1 दिन (Overnight)** के लिए उधार लेते/देते हैं।
2. **नोटिस मनी (Notice Money):** जब उधार की अवधि **2 दिन से 14 दिन** तक होती है।
3. **टर्म मनी (Term Money):** जब अंतर-बैंक उधार की अवधि **15 दिन से 1 वर्ष** तक होती है।
4. **ट्रेजरी बिल (Treasury Bills / T-Bills): केवल केंद्र सरकार** द्वारा अपनी अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु RBI के माध्यम से जारी किए जाते हैं (**राज्य सरकारें T-Bills जारी नहीं कर सकतीं**; राज्य सरकारें दीर्घकालिक **SDLs - State Development Loans** जारी करती हैं)। T-Bills तीन अवधियों में जारी होते हैं: **91 दिन, 182 दिन और 364 दिन**। ये **शून्य-कूपन बॉन्ड (Zero-Coupon Bonds)** होते हैं, अर्थात् इन पर अलग से ब्याज नहीं मिलता बल्कि ये अंकित मूल्य से **बट्टे (Discount) पर जारी होते हैं और सममूल्य (Face Value/Par) पर भुनाए जाते हैं**। न्यूनतम निवेश राशि **₹25,000** (और उसके गुणकों में) है।
5. **नकद प्रबंधन बिल (Cash Management Bills - CMBs):** 2010 में भारत सरकार और RBI द्वारा शुरू; ये T-Bills के समान ही होते हैं किंतु इनकी परिपक्वता अवधि **91 दिनों से कम** होती है।
6. **अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances - WMA):** RBI अधिनियम की धारा 17(5) के तहत केंद्र और राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय के बीच अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए RBI द्वारा **90 दिनों** के लिए दिया जाने वाला अस्थायी ऋण/ओवरड्राफ्ट।
7. **जमा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit - CD): वाघुल समिति (1989)** की सिफारिश पर शुरू; अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (RRBs और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (AIFIs — NABARD, SIDBI, EXIM Bank, NHB, NaBFID) द्वारा जारी। बैंकों के लिए परिपक्वता अवधि 7 **दिन से 1 वर्ष** (AIFIs के लिए 1 से 3 वर्ष) और **न्यूनतम राशि ₹5 लाख** (और ₹5 लाख के गुणकों में) है।
8. **वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper - CP): 1990** में शुरू; उच्च रेटिंग वाली **कॉर्पोरेट कंपनियों, प्राथमिक डीलरों (PDs) और NBFCs** द्वारा जारी किया जाने वाला **असुरक्षित (Unsecured) वचन पत्र**। परिपक्वता अवधि 7 **दिन से 1 वर्ष** और **न्यूनतम निवेश राशि ₹5 लाख** (और ₹5 लाख के गुणकों में) है।

5.2 पूंजी बाजार (Capital Market — नियामक: SEBI, अवधि: 1 वर्ष से अधिक / दीर्घकालिक)

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):

• स्थापना: 12 अप्रैल 1988 को एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना हुई और हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाले की पृष्ठभूमि में **SEBI अधिनियम, 1992** द्वारा **30 जनवरी 1992** को इसे **सांविधिक दर्जा (Statutory Status)** दिया गया। **मुख्यालय:** मुंबई (बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स); क्षेत्रीय कार्यालय: नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। प्रथम अध्यक्ष: डॉ. एस. ए. दवे; प्रथम महिला अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच; वर्तमान अध्यक्ष: तुहिन कांत पांडे।

• प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज: BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज — 1875 में प्रेमचंद रॉयचंद द्वारा 'द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन' के रूप में स्थापित; एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज; सूचकांक: SENSEX [30 कंपनियाँ, आधार वर्ष 1978-79]) और **NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज — 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर स्थापित; सूचकांक: NIFTY-50 [50 कंपनियाँ, आधार वर्ष 1995])**।

• SEBI के प्रमुख सुधार व शब्दावली:

• प्राथमिक बाजार (Primary Market): जहाँ कंपनियाँ पहली बार **IPO (Initial Public Offering)**, **FPO (Follow-on Public Offer)** या **Rights Issue** के माध्यम से पूंजी जुटाती हैं।

• *ASBA (Application Supported by Blocked Amount): **IPO में आवेदन करते समय निवेशक के बैंक खाते से पैसे कटते नहीं हैं, बल्कि केवल शेयर आवंटन होने तक खाते में ही** ब्लॉक* रहते हैं (और उस पर बचत खाते का ब्याज मिलता रहता है)।

• **T+1 एवं T+0 निपटान चक्र (Settlement Cycle):** भारत विश्व के उन अग्रणी देशों में है जिसने संपूर्ण शेयर बाजार में **T+1 (Trade + 1 कार्यदिवस)** निपटान लागू किया और **मार्च 2024 से वैकल्पिक T+0 (उसी दिन निपटान)** व तात्कालिक निपटान शुरू किया।

• **SCORES 2.0:** निवेशकों की शिकायतों के ऑनलाइन निवारण हेतु SEBI का पोर्टल (*SEBI Complaints Redress System*)। **प्रज्ञा / सारथी (Saa₹thi 2.0):** निवेशक जागरूकता मोबाइल ऐप।

अध्याय 6: बीमा क्षेत्र (IRDAI, LIC, GIC) एवं वित्तीय समावेशन व जन सुरक्षा योजनाएँ

6.1 भारत में बीमा क्षेत्र का इतिहास, IRDAI एवं बीमा के मौलिक सिद्धांत

• **ऐतिहासिक विकास:** भारत में स्थापित **पहली जीवन बीमा कंपनी** सन् **1818 में कोलकाता में स्थापित 'ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी'** (विदेशी स्वामित्व) थी, जबकि भारतीयों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के सामान्य दर पर बीमा देने वाली **पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी 1870 में स्थापित 'बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी'** थी। भारत की **पहली साधारण (General) बीमा कंपनी 1850 में कोलकाता में स्थापित 'ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड'** थी। **बीमा अधिनियम, 1938** भारत में बीमा क्षेत्र का मूल कानून है।

• **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC): 19 जून 1956** को संसद द्वारा **LIC अधिनियम, 1956** पारित कर 245 निजी भारतीय एवं विदेशी बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट सोसाइटियों का राष्ट्रीयकरण/विलय करके **1 सितंबर 1956** को ₹5 करोड़ की पूंजी से LIC की स्थापना की गई। **मुख्यालय:** मुंबई ('योगक्षेम' भवन); **आदर्श वाक्य (Motto):** "योगक्षेमं वहाम्यहम्" (श्रीमद्भगवद्गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से लिया गया है — "आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है")। मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा IPO लाया गया।

• **साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण (GIC — 1972): GIBNA (General Insurance Business [Nationalisation] Act, 1972)** के तहत 1 जनवरी 1973 से 107 साधारण बीमा कंपनियों का विलय कर **GIC (General Insurance Corporation of India — अब 'GIC Re', भारत की एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमा [Reinsurance] कंपनी, मुख्यालय: मुंबई)** और **4 सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों** का गठन किया गया:

1. **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL — मुख्यालय: मुंबई)**
2. **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC — मुख्यालय: चेन्नई)**
3. **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL — मुख्यालय: नई दिल्ली)**
4. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL — मुख्यालय: कोलकाता)**

(इसके अतिरिक्त कृषि बीमा हेतु ***AIC [Agriculture Insurance Company of India Ltd. — 2002, नई दिल्ली]*** और निर्यात ऋण बीमा हेतु ***ECGC [Export Credit Guarantee Corporation of India — 1957, मुंबई]*** कार्यरत हैं।)

• *IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India — भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण):*

• **आर. एन. मल्होत्रा समिति (1993–94)** की सिफारिश पर **IRDA अधिनियम, 1999** पारित हुआ और **अप्रैल 2000** में एक सांविधिक निकाय के रूप में इसका गठन हुआ (2014 में नाम बदलकर IRDAI किया गया)।

• **मुख्यालय: हैदराबाद (तेलंगाना)** (2001 में नई दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित किया गया)।

• **संरचना (धारा 4 — कुल 10 सदस्य): 1 अध्यक्ष (Chairman)** (कार्यकाल: 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु), **5 पूर्णकालिक सदस्य** (कार्यकाल: 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु) और **4 अंशकालिक सदस्य** (अधिकतम 5 वर्ष)।

• **बीमा में FDI सीमा:** बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा **74%** (और बजट घोषणाओं के तहत संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए **100% तक** विस्तारित) तथा बीमा मध्यस्थों (Insurance Intermediaries/Brokers) में **100%** है।

• **बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक (IRDAI की 'त्रिमूर्ति'):** वर्ष **2047 तक 'सभी के लिए बीमा' (Insurance for All by 2047)** के लक्ष्य हेतु (**PIB Insurance for All**) IRDAI ने तीन पहल शुरू की हैं: (1) **बीमा सुगम:** बीमा खरीदने, दावा निपटान और पोर्टेबिलिटी हेतु वन-स्टॉप

डिजिटल ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस; (2) **बीमा विस्तार:** जीवन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना और संपत्ति कवर का एक किफायती 'ऑल-इन-वन' बंडल उत्पाद; (3) **बीमा वाहक:** प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के नेतृत्व वाला डोरस्टेप बीमा वितरण बल।

• बीमा के 7 मौलिक सिद्धांत (7 Principles of Insurance):

1. *परम सद्भाव का सिद्धांत (*Principle of Utmost Good Faith* / Uberrimae Fidei):* बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति दोनों को अनुबंध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य (जैसे पुरानी बीमारी) पूर्ण सत्यता से प्रकट करने चाहिए।

2. **बीमा योग्य हित का सिद्धांत (Principle of Insurable Interest):** बीमित व्यक्ति का बीमा की विषय-वस्तु के सुरक्षित रहने में वित्तीय हित होना चाहिए और उसके नष्ट होने पर प्रत्यक्ष वित्तीय हानि होनी चाहिए।

3. **क्षतिपूर्ति का सिद्धांत (Principle of Indemnity):** बीमित व्यक्ति को केवल वास्तविक हानि के बराबर ही मुआवजा मिलेगा ताकि वह मुनाफा न कमा सके। (महत्वपूर्ण अपवाद: **जीवन बीमा *[Life Insurance]*** और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत **लागू नहीं होता**, क्योंकि मानव जीवन का मूल्य पैसों में नहीं आंका जा सकता।)

4. **प्रस्थापन का सिद्धांत (Principle of Subrogation):** दावा (Claim) का पूरा भुगतान करने के बाद क्षतिग्रस्त संपत्ति के स्वामित्व और तीसरे पक्ष से वसूली के सभी कानूनी अधिकार बीमा कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं (केवल साधारण बीमा में लागू)।

5. **अंशदान का सिद्धांत (Principle of Contribution):** यदि किसी व्यक्ति ने एक ही संपत्ति का एक से अधिक कंपनियों से बीमा कराया है (Double Insurance), तो हानि होने पर सभी कंपनियाँ अपने-अपने बीमा अनुपात में मिलकर केवल वास्तविक हानि की ही भरपाई करेंगी (जीवन बीमा पर लागू नहीं — जीवन बीमा में सभी पॉलिसियों से पूरा भुगतान मिलता है)।

6. *आसन्न कारण का सिद्धांत (*Principle of Proximate Cause* / Causa Proxima):* यदि हानि एक से अधिक कारणों से हुई है, तो दावा देते समय सबसे निकटतम और प्रत्यक्ष प्रभावी कारण (बीमित जोखिम) को देखा जाता है, न कि दूरस्थ कारण को।

7. **हानि न्यूनीकरण का सिद्धांत (Principle of Loss Minimization):** दुर्घटना के समय बीमित व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह संपत्ति को बचाने का हर संभव प्रयास करे, ठीक वैसे ही जैसे वह बिना बीमा के करता।

*6.2 वित्तीय समावेशन एवं जन सुरक्षा योजनाएँ (*Financial Inclusion & Social Security Schemes*)*

PIB जन सुरक्षा विज्ञप्ति एवं PIB 2026 अपडेट के अनुसार भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं की मास्टर तालिका:

योजना का नाम व प्रारंभ तिथि	पात्रता आयु एवं प्रीमियम / अंशदान	बीमा कवर / लाभ एवं प्रमुख परीक्षापयोगी विशेषताएँ
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) (28 अगस्त 2014; नारा: "मेरा खाता, भाग्य विधाता")	10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक (BSBD खाता — शून्य बैलेंस)	**₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा** (आयु 18–65 वर्ष, परिवार के एक सदस्य विशेषकर महिला को; ₹2,000 तक बिना किसी शर्त के); RuPay डेबिट कार्ड पर **₹2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर** (28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों के लिए; इससे पहले ₹1 लाख था)। यह विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) (9 मई 2015, कोलकाता से शुभारंभ)	**आयु: 18 से 50 वर्ष** (कवर 55 वर्ष की आयु तक); **वार्षिक प्रीमियम: ₹436 प्रति वर्ष** (1 जून 2022 को ₹330 से बढ़ाकर ₹436 किया गया; **1 जून से 31 मई** का वार्षिक चक्र)	**किसी भी कारण से मृत्यु (Death due to any reason)** होने पर नामांकित व्यक्ति को **₹2 लाख का एकवर्षीय नवीकरणीय सावधि जीवन बीमा कवर (Term Life Cover)**। इसका संचालन LIC और अन्य जीवन बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। नया नामांकन करने पर प्रथम **30 दिनों की लियन अवधि (Lien Period)** होती है (दुर्घटना मृत्यु को छोड़कर)।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) (9 मई 2015, कोलकाता से शुभारंभ)	**आयु: 18 से 70 वर्ष**; **वार्षिक प्रीमियम: मात्र ₹20 प्रति वर्ष** (1 जून 2022 को ₹12 से बढ़ाकर ₹20 किया गया; 1 जून से 31 मई चक्र)	**दुर्घटना बीमा योजना (Accidental Insurance):** दुर्घटना में मृत्यु या दोनों आँखों / दोनों हाथों-पैरों की **पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹2 लाख**, और एक आँख या एक हाथ/पैर की **आंशिक स्थायी विकलांगता पर ₹1 लाख** का कवर।
अटल पेंशन योजना (APY) (9 मई 2015 से घोषित, 1 जून 2015 से लागू; नियामक: ***PFRDA***)	**आयु: 18 से 40 वर्ष** (1 अक्टूबर 2022 से कोई भी व्यक्ति जो **आयकर दाता *[Income Tax Payer]*** है, *APY* में नया खाता खोलने के लिए पात्र **नहीं** है)	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए; **60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर** अंशदान के आधार पर **₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 प्रति माह** की गारंटीशुदा पेंशन। अभिदाता की मृत्यु पर जीवनसाथी को समान पेंशन और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को **₹1.70 लाख से ₹8.50 लाख तक का पूरा कॉर्पस** वापस मिलता है।

योजना का नाम व प्रारंभ तिथि	पात्रता आयु एवं प्रीमियम / अंशदान	बीमा कवर / लाभ एवं प्रमुख परीक्षापयोगी विशेषताएँ
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) (8 अप्रैल 2015; *MUDRA = Micro Units Development & Refinance Agency*)	गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को **बिना किसी गारंटी (Collateral-free)** के ऋण	अब मुद्रा ऋण की **4 श्रेणियाँ** हैं: **1. शिशु (Shishu):** ₹50,000 तक; **2. किशोर (Kishore):** ₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक; **3. तरुण (Tarun):** ₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक; **4. तरुण प्लस (Tarun Plus — बजट 2024 से नया जुड़ा):** जिन उद्यमियों ने पहले 'तरुण' श्रेणी का ऋण लेकर सफलतापूर्वक चुका दिया है, उन्हें **₹10 लाख से ₹20 लाख तक** का ऋण।

1. मौद्रिक नीति के गलियारे (LAF Corridor) का स्वर्ण सूत्र:

★ **सूत्र:** SDF Rate (Floor) = Repo Rate - 0.25\% | MSF Rate (Ceiling) = Bank Rate = Repo Rate + 0.25\%
महंगाई (Inflation) नियंत्रित करने की ट्रिक: जब बाजार में महंगाई बढ़ती है → RBI सभी नीतिगत दरें (Repo, CRR, SLR) **बढ़ाता (Hike)** है → बैंकों के पास ऋण देने योग्य धन घटता है → ब्याज दरें बढ़ती हैं → बाजार में मुद्रा आपूर्ति (Liquidity) घटती है → महंगाई नियंत्रित होती है। (मंदी में इसके ठीक विपरीत दरें घटाई जाती हैं)।

2. NPA से पहले के SMA (Special Mention Accounts) की 30-30 दिन की ट्रिक:

★ **SMA-0:** 1 से 30 दिन ओवरड्यू → **SMA-1:** 31 से 60 दिन ओवरड्यू → **SMA-2:** 61 से 90 दिन ओवरड्यू → **90 दिन से अधिक** = **NPA** (Sub-standard ≤ 12 माह → Doubtful > 12 माह → Loss Asset)।

3. विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) के 4 घटक (ट्रिक: "F-G-S-R"):

★ **F** = Foreign Currency Assets (FCA — सबसे बड़ा हिस्सा), **G** = Gold (स्वर्ण भंडार), **S** = SDRs (IMF के विशेष आहरण अधिकार), **R** = Reserve Tranche Position (RTP in IMF)।

4. भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय समितियों की मास्टर सारणी:

समिति का नाम	संबंधित सुधार / सिफारिश का क्षेत्र
हिल्टन यंग कमीशन (1926)	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना (1 अप्रैल 1935)
ए. डी. गोरेवाला समिति (1954)	इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर **भारतीय स्टेट बैंक (SBI — 1 जुलाई 1955)** की स्थापना
बी. शिवरामन समिति (CRAFICARD)	**NABARD** (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक — **12 जुलाई 1982**, मुख्यालय: मुंबई) की स्थापना
एम. नरसिंहम समिति (1975 एवं 1991/1998)	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs — 2 अक्टूबर 1975)** की स्थापना तथा 1991 व 1998 के **बैंकिंग क्षेत्र सुधार** (SARFAESI, NPA मानदंड, CRR/SLR कटौती)
आर. एन. मल्होत्रा समिति (1993)	बीमा क्षेत्र में सुधार और **IRDAI (1999/2000)** की स्थापना
नचिकेत मोर समिति (2013–14)	छोटे व्यवसायों व निम्न आय वर्ग हेतु वित्तीय सेवाएँ एवं **भुगतान बैंक (Payments Banks)** की स्थापना (प्रथम: एयरटेल पेमेंट्स बैंक)
उषा थोराट समिति (2014)	**लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks - SFBs)** को लाइसेंस देना (प्रथम: कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जालंधर — 2016)
उर्जित पटेल समिति (2014)	मौद्रिक नीति ढांचे का सुदृढ़ीकरण, **CPI आधारित 4% (±2%) मुद्रास्फीति लक्ष्य** और **MPC** का गठन
पी. जे. नायक समिति (2014)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड का शासन और **बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB — अब FSIB [Financial Services Institutions Bureau, 2022])** का गठन
बिमल जालान समिति (2019)	RBI का **आर्थिक पूंजी ढांचा (Economic Capital Framework - ECF)** एवं लेखा वर्ष को **1 अप्रैल – 31 मार्च** करना
टी. के. विश्वनाथन समिति (2015)	**दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC, 2016)** का प्रारूपण
नंदन नीलेकणी समिति (2019)	भारत में **डिजिटल भुगतान का गहन विस्तार (Deepening of Digital Payments)**

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. वर्ष 1926 के किस शाही आयोग (Royal Commission) की सिफारिशों और डॉ. बी. आर. अंबेडकर की किस प्रसिद्ध पुस्तक के दिशानिर्देशों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 पारित किया गया था? **[RBI Grade B 2021, IBPS PO Mains 2022, SSC CGL 2023]**

- (A) हिल्टन यंग कमीशन (रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस) — *The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution*
- (B) चैंबरलिन कमीशन (1913) — *Administration and Finance of the East India Company*
- (C) फ्लाउड कमीशन — *The Evolution of Provincial Finance in British India*
- (D) मैकलगन समिति (1914) — *Poverty and Un-British Rule in India*

• सही उत्तर: (A)

• विस्तृत व्याख्या: 1926 में गठित **हिल्टन यंग कमीशन** ने भारत में करेंसी और साख के नियंत्रण को अलग रखने वाली दोहरी प्रणाली को समाप्त कर एक केंद्रीय बैंक ('रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया') स्थापित करने की सिफारिश की थी, जिसके समक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने अपनी 1923 की शोध पुस्तक '*The Problem of the Rupee*' के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना, मुख्यालय स्थानांतरण और राष्ट्रीयकरण की तिथियों का कौन सा अनुक्रम पूर्णतः सही है? **[SBI PO Mains 2021, RRB NTPC CBT-2 2022]**

- (A) स्थापना: 1 जनवरी 1935 (मुंबई) → मुख्यालय कोलकाता स्थानांतरित: 1937 → राष्ट्रीयकरण: 15 अगस्त 1947
- (B) स्थापना: 1 अप्रैल 1935 (कोलकाता, ₹5 करोड़ अधिकृत पूंजी) → मुख्यालय स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित: 1937 → राष्ट्रीयकरण: 1 जनवरी 1949
- (C) स्थापना: 1 जुलाई 1935 (नई दिल्ली) → मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित: 1940 → राष्ट्रीयकरण: 26 जनवरी 1950
- (D) स्थापना: 1 अप्रैल 1934 (कोलकाता) → मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित: 1935 → राष्ट्रीयकरण: 1 अप्रैल 1949

• सही उत्तर: (B)

• विस्तृत व्याख्या: RBI ने **1 अप्रैल 1935** को कोलकाता में निजी शेयरधारकों के बैंक (₹5 करोड़ की पूंजी) के रूप में कार्य प्रारंभ किया, **1937** में इसका केंद्रीय कार्यालय स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित हुआ, और रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण) अधिनियम, 1948 के तहत **1 जनवरी 1949** को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर (जिन्होंने 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा जिनके कार्यकाल में 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ) कौन थे? **[IBPS Clerk Mains 2022, SSC CGL 2022]**

- (A) सर जेम्स ब्रेड टेलर (प्रथम) और सर बेनेगल रामा राव (प्रथम भारतीय)
- (B) सर ऑस्बॉर्न स्मिथ (प्रथम) और के. जी. अंबेगांवकर (प्रथम भारतीय)
- (C) सर ऑस्बॉर्न स्मिथ (प्रथम गवर्नर, 1935–37) और सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख / सी. डी. देशमुख (प्रथम भारतीय गवर्नर, 1943–49)
- (D) लॉर्ड कीन्स (प्रथम) और एच. वी. आर. आयंगर (प्रथम भारतीय)

• सही उत्तर: (C)

• विस्तृत व्याख्या: ऑस्ट्रेलियाई बैंकर **सर ऑस्बॉर्न स्मिथ** (1935–37) RBI के पहले गवर्नर थे (उन्होंने किसी भी भारतीय करेंसी नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए); दूसरे गवर्नर सर जेम्स ब्रेड टेलर थे; और **सर सी. डी. देशमुख** (1943–49) प्रथम भारतीय गवर्नर थे, जो बाद में भारत के वित्त मंत्री भी रहे।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. वर्ष 1956–57 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी नोट छापने के लिए 'न्यूनतम कोष प्रणाली' (Minimum Reserve System - MRS) अपनाई जाती है; इसके अंतर्गत RBI को हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का कोष रखना अनिवार्य है और उसमें स्वर्ण एवं विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियों का अनुपात क्या है? **[RBI Assistant Mains 2022, SSC CGL 2023]**

• (A) कुल ₹500 करोड़ (₹300 करोड़ स्वर्ण + ₹200 करोड़ विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियाँ)

• (B) कुल ₹100 करोड़ (₹50 करोड़ स्वर्ण + ₹50 करोड़ सरकारी बॉन्ड)

• (C) कुल ₹1,000 करोड़ (₹500 करोड़ स्वर्ण + ₹500 करोड़ SDR)

• (D) कुल ₹200 करोड़ (जिसमें कम से कम ₹115 करोड़ का स्वर्ण [Gold Coin & Bullion] और ₹85 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियाँ होना अनिवार्य है)

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 1956 में आनुपातिक कोष प्रणाली को प्रतिस्थापित कर लागू की गई **न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System)** के तहत RBI मात्र **₹200 करोड़** (₹115 करोड़ स्वर्ण + ₹85 करोड़ विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियाँ) का न्यूनतम कोष रखकर अर्थव्यवस्था की आवश्यकतानुसार असीमित मात्रा में करेंसी नोट जारी कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. RBI अधिनियम, 1934 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा **6-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC)** का गठन किया गया है और इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? **[RBI Grade B Phase-I 2023, SBI PO Mains 2023]**

• (A) धारा 45ZB — इसमें 3 सदस्य RBI से और 3 बाह्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं; कोरम 4 सदस्यों का है और बराबर मत होने पर RBI गवर्नर को निर्णायक मत (Casting Vote) का अधिकार है।

• (B) धारा 22 — इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं और वित्त मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।

• (C) धारा 42(1) — इसके बाह्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और RBI गवर्नर के पास वीटो पावर (Veto Power) होती है।

• (D) धारा 35A — इसकी बैठक वर्ष में केवल 2 बार होना अनिवार्य है।

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित RBI अधिनियम, 1934 की **धारा 45ZB** के तहत गठित MPC में 6 सदस्य (3 RBI + 3 सरकार द्वारा नामित) होते हैं। RBI गवर्नर को **वीटो पावर नहीं** है, किंतु 3–3 से मत बराबर होने पर उन्हें **दूसरा या निर्णायक मत (Casting Vote)** देने का अधिकार है।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. अप्रैल 2022 में RBI द्वारा तरलता समायोजन सुविधा (LAF Corridor) के नए निचले स्तर (Floor) के रूप में शुरू की गई **'स्थायी जमा सुविधा' (Standing Deposit Facility - SDF)** की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट से अलग बनाती है? **[RBI Grade B 2022, IBPS PO Mains 2022]**

• (A) इसमें केवल विदेशी बैंक ही अपना धन जमा कर सकते हैं।

• (B) यह एक 'संपार्श्विक-मुक्त' (Collateral-free) तरलता अवशोषण उपकरण है, अर्थात् बैंकों से अतिरिक्त तरलता सोखते समय RBI को बदले में कोई सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) गिरवी नहीं देनी पड़ती, और इसकी दर रेपो दर से 25 आधार अंक (0.25%) कम होती है।

• (C) इसके तहत बैंक केवल 5 वर्ष की सावधि के लिए धन जमा कर सकते हैं।

• (D) इसकी ब्याज दर हमेशा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर से अधिक होती है।

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RBI अधिनियम की धारा 17 में 2018 में किए गए संशोधन के आधार पर 8 अप्रैल 2022 को शुरू की गई **SDF** ने फिक्स्ड रिवर्स रेपो (3.35%) का स्थान LAF कॉरिडोर के 'फ्लोर' के रूप में ले लिया। इसमें RBI को बैंकों को कोई सरकारी प्रतिभूति (Collateral) नहीं देनी पड़ती, जिससे RBI अपनी बैलेंस शीट में G-Secs की कमी से बंधे बिना बड़ी मात्रा में अतिरिक्त तरलता सोख सकता है।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. 'नकद आरक्षित अनुपात' (CRR) और 'वैधानिक तरलता अनुपात' (SLR) के वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर **सही है**? **[IBPS PO Mains 2023, RBI Assistant 2023]**

• (A) CRR बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के तहत है जबकि SLR RBI अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के तहत है।

• (B) RBI बैंकों को CRR की राशि पर रेपो दर के बराबर ब्याज देता है जबकि SLR पर कोई ब्याज नहीं मिलता।

• (C) CRR को RBI अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के तहत केवल 'नकद' (Cash) के रूप में RBI के पास रखा जाता है (जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता), जबकि SLR को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत बैंक स्वयं अपने पास नकद, स्वर्ण (Gold) या भार-रहित सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के रूप में रखते हैं (अधिकतम सीमा 40%)।

• (D) CRR की गणना कुल पूंजी पर होती है जबकि SLR की गणना केवल चालू खातों पर होती है।

• सही उत्तर: (C)

• विस्तृत व्याख्या: CRR (**धारा 42(1), RBI Act 1934**) और SLR (**धारा 24, Banking Regulation Act 1949**) दोनों की गणना बैंक की **NDTL (Net Demand and Time Liabilities)** के प्रतिशत के रूप में पखवाड़े के आधार पर की जाती है। CRR केवल नकद में RBI के पास रहता है, जबकि SLR बैंक के पास नकद, स्वर्ण या स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों में रहता है।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. स्वतंत्र भारत में वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दोनों ऐतिहासिक चरणों (1969 और 1980) के संबंध में कौन सा कथन **पूर्णतः सटीक** है? **[SSC CGL 2022, IBPS Clerk Mains 2021, RRB NTPC 2022]**

• (A) 19 जुलाई 1969 को ₹100 करोड़ से अधिक जमा वाले 10 बैंकों का और 1980 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।

• (B) 1 जुलाई 1955 को 14 बैंकों का और 19 जुलाई 1969 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।

• (C) 1969 में आरबीआई सहित 15 बैंकों का और 1980 में नाबार्ड सहित 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।

• (D) प्रथम चरण में **19 जुलाई 1969** को **₹50 करोड़ या अधिक** जमा राशि वाले **14 बड़े बैंकों** का, और द्वितीय चरण में **15 अप्रैल 1980** को **₹200 करोड़ या अधिक** जमा राशि वाले **6 अन्य बैंकों** का राष्ट्रीयकरण किया गया।

• सही उत्तर: (D)

• विस्तृत व्याख्या: चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान **19 जुलाई 1969** को 14 बैंकों (न्यूनतम जमा ₹50 करोड़) और छठी पंचवर्षीय योजना में **15 अप्रैल 1980** को 6 बैंकों (न्यूनतम जमा ₹200 करोड़) का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1993 में 'न्यू बैंक ऑफ इंडिया' का PNB में विलय हुआ और 2019–2020 के महा-विलय के बाद वर्तमान में भारत में **कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (SBI + 11 राष्ट्रीयकृत बैंक)** कार्यरत हैं।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. 1 अप्रैल 2020 को लागू हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 'महा-विलय' (Mega Merger of PSBs) में निम्नलिखित में से किस एंकर बैंक में किन बैंकों का विलय किया गया? **[IBPS PO Mains 2020, SBI Clerk Mains 2021]**

• (A) पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में — ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया; यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में — आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक; केनरा बैंक में — सिंडिकेट बैंक; इंडियन बैंक में — इलाहाबाद बैंक

• (B) बैंक ऑफ बड़ौदा में — आंध्रा बैंक और इलाहाबाद बैंक; केनरा बैंक में — देना बैंक और विजया बैंक

• (C) भारतीय स्टेट बैंक में — सिंडिकेट बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक; यूनियन बैंक में — यूनाइटेड बैंक

• (D) इंडियन ओवरसीज बैंक में — ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और देना बैंक

• सही उत्तर: (A)

• **विस्तृत व्याख्या:** 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, और **1 अप्रैल 2020** को 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का एकीकरण कर 4 बड़े बैंक बनाए गए: PNB (OBC + United), Canara (Syndicate), Union Bank (Andhra + Corporation) और Indian Bank (Allahabad Bank)।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) मास्टर डायरेक्शन के अनुसार, घरेलू वाणिज्यिक बैंकों (PSBs व Private Banks) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) व लघु वित्त बैंकों (SFBs) के लिए कुल PSL लक्ष्य (ANBC या CEOBE का प्रतिशत, जो भी अधिक हो) क्रमशः कितना निर्धारित है? **[RBI Grade B 2023, IBPS SO 2023, NABARD Grade A 2023]**

• (A) घरेलू वाणिज्यिक बैंक: 35%; RRBs और SFBs: 60%

• (B) घरेलू वाणिज्यिक बैंक (एवं 20+ शाखाओं वाले विदेशी बैंक): **40%**; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) एवं लघु वित्त बैंक (SFBs): **75%**

• (C) सभी प्रकार के बैंकों के लिए एकसमान 40%

• (D) घरेलू वाणिज्यिक बैंक: 50%; RRBs: 75%; SFBs: 60%

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RBI PSL दिशानिर्देशों के तहत घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए कुल PSL लक्ष्य **40%** है (जिसमें कृषि 18%, लघु व सीमांत किसान 10%, सूक्ष्म उद्यम 7.5% और कमजोर वर्ग 12% है), जबकि **RRBs और SFBs दोनों के लिए कुल PSL लक्ष्य 75%** है (भुगतान बैंकों पर PSL लागू नहीं होता क्योंकि वे ऋण नहीं देते)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. यदि कोई वाणिज्यिक बैंक किसी वित्तीय वर्ष में अपने निर्धारित 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण' (PSL) लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे अपनी बकाया (Shortfall) राशि किस संस्थान के अंतर्गत वर्ष 1995–96 में स्थापित **'ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि' (RIDF - Rural Infrastructure Development Fund)** में जमा करनी होती है? **[NABARD Grade A 2022, IBPS PO Mains 2021]**

• (A) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)

• (B) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

• (C) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

• (D) राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या: बी. शिवरामन समिति (CRAFICARD)** की सिफारिश पर **12 जुलाई 1982** को स्थापित **NABARD** के अंतर्गत 1995–96 में **RIDF** का गठन किया गया था। जो बैंक कृषि व कुल PSL का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, उन्हें RBI द्वारा निर्धारित कम ब्याज दर पर यह शॉर्टफॉल राशि RIDF (तथा SIDBI/NHB/MUDRA फंड) में आवंटित करनी पड़ती है।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. RBI के IRAC मानदंडों के अनुसार किसी ऋण खाते के गैर-निष्पादित आस्ति (NPA — 90 दिनों से अधिक अतिदेय) बनने से पूर्व दबाव के प्रारंभिक संकेतों की पहचान के लिए बनाए गए **'विशेष उल्लेख खातों' (Special Mention Accounts - SMA)** की तीनों उप-श्रेणियों की समयावधि क्या है? **[IBPS PO Mains 2022, SBI PO Mains 2023, RBI Grade B 2022]**

• (A) SMA-0: 1–15 दिन; SMA-1: 16–45 दिन; SMA-2: 46–90 दिन

• (B) SMA-0: 1–45 दिन; SMA-1: 46–90 दिन; SMA-2: 91–180 दिन

• (C) SMA-0: 30–60 दिन; SMA-1: 61–90 दिन; SMA-2: 91–120 दिन

• (D) **SMA-0:** मूलधन या ब्याज देय तिथि से **1 से 30 दिन** तक अतिदेय; **SMA-1: 31 से 60 दिन** तक अतिदेय; **SMA-2: 61 से 90 दिन** तक अतिदेय (और 90 दिन से अधिक होते ही खाता *NPA* बन जाता है)

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RBI ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की समय रहते पहचान के लिए मानक खातों (Standard Assets) को तीन SMA श्रेणियों में बांटा है: **SMA-0 (1–30 दिन ओवरड्यू), SMA-1 (31–60 दिन ओवरड्यू) और SMA-2 (61–90 दिन ओवरड्यू)**। 90 दिन पूरे होने के बाद भी भुगतान न होने पर खाता **NPA** हो जाता है।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. किसी ऋण खाते के NPA घोषित होने के बाद उसे 'अवमानक आस्ति' (Sub-Standard Asset) और 'संदिग्ध आस्ति' (Doubtful Asset) के रूप में वर्गीकृत करने की मानक समयावधि क्या है, तथा कृषि फसलों के ऋण के लिए NPA का क्या नियम है? **[IBPS SO 2022, SBI Clerk Mains 2023]**

• (A) Sub-Standard: जो **12 महीने या उससे कम** अवधि के लिए NPA रहा हो; Doubtful: जो **12 महीने से अधिक** समय तक Sub-Standard श्रेणी में रहा हो; तथा कृषि ऋण में **अल्पावधि फसलों के लिए 2 फसल मौसम** और **दीर्घावधि फसलों के लिए 1 फसल मौसम** तक किस्त/ब्याज बकाया रहने पर NPA होता है।

• (B) Sub-Standard: 6 महीने तक NPA; Doubtful: 6 महीने से अधिक; कृषि ऋण में भी 90 दिन का नियम लागू होता है।

• (C) Sub-Standard: 24 महीने तक NPA; Doubtful: 36 महीने से अधिक; कृषि ऋण कभी NPA नहीं होता।

• (D) Sub-Standard: 90 दिन तक; Doubtful: 91 से 180 दिन तक।

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** सामान्य वाणिज्यिक ऋणों में 90 दिन के बाद खाता NPA बनता है, जिसके प्रथम **12 माह तक वह 'Sub-Standard Asset'** कहलाता है और 12 माह के बाद भी वसूली न होने पर **'Doubtful Asset'** में चला जाता है। परंतु किसानों को राहत देने हेतु **अल्पावधि फसलों (Short Duration Crops)** के लिए **2 Crop Seasons** और **दीर्घावधि फसलों (Long Duration Crops)** के लिए **1 Crop Season** का नियम लागू होता है।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. 'SARFAESI अधिनियम, 2002' (*Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act*) के तहत बैंकों को बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के चूककर्ता की गिरवी रखी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है, किंतु निम्नलिखित में से किस मामले में SARFAESI अधिनियम **लागू नहीं होता** (धारा 31)? **[RBI Grade B 2021, IBPS PO Mains 2022, LIC AAO 2023]**

• (A) ₹10 लाख से अधिक के आवास ऋण (Home Loan) पर

• (B) कृषि भूमि (Agricultural Land) पर, ₹1 लाख से कम के बकाया ऋण पर, असुरक्षित ऋणों पर, या जहाँ मूलधन व ब्याज सहित कुल ऋण का 80% से अधिक भुगतान किया जा चुका हो (अर्थात् बकाया 20% से कम हो)

• (C) औद्योगिक मशीनरी या फैक्ट्री भवन के विरुद्ध लिए गए ऋण पर

• (D) सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए सुरक्षित वाणिज्यिक ऋणों पर

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** SARFAESI अधिनियम, 2002 की **धारा 31** के अनुसार यह कानून **कृषि भूमि**, **₹1 लाख से कम** के ऋण, **असुरक्षित (Unsecured) ऋण** और उन खातों पर लागू नहीं होता जहाँ बकाया राशि मूलधन व ब्याज के **20% से कम** रह गई हो। (मई 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद सहकारी बैंक भी SARFAESI के दायरे में आते हैं)।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता' (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC, 2016) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सही है**? **[RBI Grade B 2023, SBI PO Mains 2022]**

• (A) इसका नियामक SEBI है और कंपनियों के मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय करता है।

• (B) कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने के लिए न्यूनतम डिफ़ॉल्ट राशि ₹1 लाख है और इसे 5 वर्ष में पूरा करना होता है।

• (C) इसका नियामक **IBBI** (नई दिल्ली) है; कॉर्पोरेट कंपनियों व LLP के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण **NCLT** (अपील: NCLAT) और व्यक्तियों/साझेदारी फर्मों के लिए **DRT** (अपील: DRAT) है; सामान्य CIRP के लिए न्यूनतम डिफ़ॉल्ट सीमा **₹1 करोड़** है और कानूनी विवादों सहित अधिकतम समय-सीमा **330 दिन** है (CoC में 66% मतदान आवश्यक)।

• (D) इसके अंतर्गत केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का ही समापन किया जा सकता है।

• सही उत्तर: (C)

• विस्तृत व्याख्या: टी. के. विश्वनाथन समिति की सिफारिश पर बने **IBC 2016** में नियामक **IBBI** है, पहली सूचना उपयोगिता (Information Utility) **NeSL** है, कॉर्पोरेट मामलों के लिए अधिकरण **NCLT** है, सामान्य CIRP हेतु न्यूनतम डिफ़ॉल्ट थ्रेशोल्ड **₹1 करोड़** (MSME प्री-पैकेज्ड PPIRP हेतु ₹10 लाख) है और संपूर्ण समाधान प्रक्रिया के लिए **330 दिनों** की अनिवार्य अधिकतम समय-सीमा है।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. भारत में बड़े कॉर्पोरेट बैड लोन्स (₹500 करोड़ और उससे अधिक के संघीय एनपीए खातों) के समाधान हेतु गठित 'बैड बैंक' (Bad Bank) की दोहरी संरचना में कौन सी दो संस्थाएँ शामिल हैं और उनके भुगतान का अनुपात क्या है? **[IBPS PO Mains 2022, SBI PO Mains 2022, RBI Grade B 2023]**

• (A) CIBIL और CRISIL — 50:50 अनुपात

• (B) SIDBI और MUDRA — 60:40 अनुपात

• (C) NIIF और NaBFID — 75:25 अनुपात

• (D) **NARCL** (National Asset Reconstruction Company Ltd. — सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 51%+ हिस्सेदारी) और **IDRCL** (India Debt Resolution Company Ltd. — निजी क्षेत्र की 51%+ हिस्सेदारी); भुगतान संरचना: **15% नकद (Cash) और 85% सरकारी गारंटीकृत सुरक्षा रसीदें (Security Receipts - SRs)** (₹30,600 करोड़ की संप्रभु गारंटी के साथ)

• सही उत्तर: (D)

• विस्तृत व्याख्या: भारत के बैड बैंक मॉडल में **NARCL** (ARC के रूप में) बैंकों से **15:85 संरचना** (15% नकद + 85% सरकार द्वारा गारंटीकृत Security Receipts) पर तनावग्रस्त संपत्तियाँ खरीदती है, जबकि **IDRCL** एक सेवा कंपनी/एजेंट के रूप में उन संपत्तियों का प्रबंधन और बाजार में मूल्य संवर्धन (Turnaround/Sale) करती है।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. बेसल-III (Basel-III) मानकों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर (BCBS) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित **न्यूनतम कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Minimum CRAR / CAR)** तथा **पूंजी संरक्षण बफर (CCB - 2.5%) सहित कुल CRAR** क्रमशः कितना है? **[RBI Grade B Phase-II 2023, IBPS PO Mains 2023]**

• (A) BCBS मानक: 8.0% (CCB सहित 10.5%); RBI द्वारा भारतीय बैंकों के लिए: **9.0% (CCB 2.5% सहित कुल 11.5%)** (जिसमें *CET-1* = 5.5%, *AT-1* = 1.5% [कुल *Tier-1* = 7.0%] और *Tier-2* = 2.0% है)

• (B) BCBS मानक: 10.0%; RBI मानक: 12.0% (CCB सहित 15.0%)

• (C) BCBS और RBI दोनों के लिए एकसमान 8.0% (CCB सहित 9.5%)

• (D) BCBS मानक: 9.0%; RBI मानक: 7.5% (CCB सहित 10.0%)

• सही उत्तर: (A)

• विस्तृत व्याख्या: बेसल समिति (BCBS) ने न्यूनतम CRAR **8%** (2.5% CCB सहित **10.5%**) रखा है, किंतु RBI ने अधिक सुरक्षा के लिए भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु न्यूनतम CRAR **1 प्रतिशत अधिक अर्थात् 9.0%** (CET-1: 5.5% + AT-1: 1.5% = Tier-1: 7.0% + Tier-2: 2.0%) और **2.5% CCB मिलाकर कुल 11.5%** निर्धारित किया है।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत के किन **3 बैंकों** को 'घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक' (**D-SIBs — Domestic Systemically Important Banks**, जिन्हें "*Too Big To Fail*" कहा जाता है) के रूप में वर्गीकृत किया गया है? **[IBPS PO Mains 2023, SBI Clerk Mains 2024, RBI Assistant 2023]**

- (A) भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)
- (B) भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
- (C) एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक
- (D) भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

• सही उत्तर: (B)

• विस्तृत व्याख्या: RBI ने 2015–17 से तीन बैंकों को **D-SIBs** घोषित कर रखा है: **SBI** (बकेट 4 — अतिरिक्त CET-1 आवश्यकता), **HDFC बैंक** (बकेट 2) और **ICICI बैंक** (बकेट 1)। इन बैंकों का आकार इतना विशाल है कि इनकी विफलता संपूर्ण भारतीय वित्तीय प्रणाली को बाधित कर सकती है।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. बेसल-III मानकों के तहत बैंकों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक तरलता मजबूती मापने के लिए किन दो अनुपातों को लागू किया गया है और उनकी समय-सीमा क्या है? **[RBI Grade B 2022, IBPS SO 2022]**

- (A) CRR (14 दिन) और SLR (30 दिन)
- (B) CASA अनुपात (90 दिन) और CD अनुपात (365 दिन)
- (C) **तरलता कवरेज अनुपात (LCR - Liquidity Coverage Ratio):** आगामी **30 दिनों** के गंभीर तनाव परिदृश्य के शुद्ध नकदी बहिर्वाह के विरुद्ध ≥ 100% उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA); तथा **शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात (NSFR - Net Stable Funding Ratio): 1 वर्ष** के दीर्घकालिक क्षितिज के लिए ≥ 100% स्थिर फंडिंग
- (D) चालू अनुपात (Current Ratio) और त्वरित अनुपात (Quick Ratio)

• सही उत्तर: (C)

• विस्तृत व्याख्या: बेसल-III ने पूंजी के साथ-साथ दो तरलता मानदंड पेश किए: **LCR** बैंक को **30 दिनों** के अल्पकालिक नकदी संकट से बचाता है (HQLA / 30-day Net Cash Outflow ≥ 100%), जबकि **NSFR 1 वर्ष** की अवधि में स्थिर वित्तपोषण सुनिश्चित करता है (Available Stable Funding / Required Stable Funding ≥ 100%)।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के गठन, कानूनी दर्जे और अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **पूर्णतः सही है**? **[IBPS PO Mains 2021, SBI PO 2022, RBI Assistant 2022]**

- (A) यह RBI की 100% स्वामित्व वाली एक लाभकारी सरकारी कंपनी है जिसकी स्थापना RBI अधिनियम 1934 के तहत 2005 में हुई।
- (B) यह वित्त मंत्रालय का एक सांविधिक विभाग है जिसकी स्थापना 2014 में जन-धन योजना के साथ हुई।
- (C) यह SEBI द्वारा पंजीकृत एक स्टॉक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है।
- (D) इसकी स्थापना **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007)** के तहत RBI और भारतीय बैंक संघ (IBA) की पहल पर **दिसंबर 2008** में मुंबई में हुई, और यह **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** (पूर्व धारा 25, कंपनी अधिनियम 1956) के अंतर्गत पंजीकृत एक **'गैर-लाभकारी संगठन' (Not-for-Profit Company)** है।

• सही उत्तर: (D)

• विस्तृत व्याख्या: NPCI भारत में सभी खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों (UPI, RuPay, IMPS, NACH, CTS, AEPS, FASTag, e-RUPI, Bharat BillPay) के संचालन के लिए एक छत्र संगठन (Umbrella Organization) है, जो धारा 8 (गैर-लाभकारी) कंपनी के रूप में पंजीकृत है।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 21. निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित **नहीं** की जाती है, बल्कि सीधे **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** द्वारा संचालित और स्वामित्व में रखी जाती है? **[IBPS Clerk Mains 2022, RRB NTPC 2022, SSC CGL 2023]**

- (A) NEFT (*National Electronic Funds Transfer*) और RTGS (*Real Time Gross Settlement*)
- (B) UPI (*Unified Payments Interface*) और IMPS (*Immediate Payment Service*)
- (C) NACH (*National Automated Clearing House*) और AEPS (*Aadhaar Enabled Payment System*)
- (D) RuPay कार्ड नेटवर्क और NETC FASTag

• सही उत्तर: (A)

• विस्तृत व्याख्या: **NEFT और RTGS** का संचालन सीधे **RBI** द्वारा किया जाता है, जबकि UPI, BHIM, IMPS, RuPay, NACH, AEPS, CTS, NFS (National Financial Switch — सबसे बड़ा ATM नेटवर्क), FASTag और e-RUPI का संचालन **NPCI** द्वारा किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 22. NEFT और RTGS के माध्यम से धन हस्तांतरण के लिए आवश्यक **IFSC* (Indian Financial System Code) **और चेक समाशोधन के लिए प्रयुक्त** *MICR* (Magnetic Ink Character Recognition)* कोड में क्रमशः कितने अंक/वर्ण होते हैं और उनकी संरचना क्या है? **[IBPS PO 2021, SBI Clerk Mains 2022, SSC CHSL 2023]**

- (A) IFSC में 10 अंक और MICR में 12 अंक होते हैं।
- (B) **IFSC में 11 अल्फ़ान्यूमेरिक वर्ण** होते हैं (प्रथम 4 अक्षर बैंक का नाम, **5वाँ वर्ण हमेशा शून्य '0'** और अंतिम 6 वर्ण शाखा कोड); जबकि **MICR में 9 संख्यात्मक अंक** होते हैं (प्रथम 3 अंक शहर का पिन कोड आधारित कोड, मध्य के 3 अंक बैंक कोड और अंतिम 3 अंक शाखा कोड)।
- (C) IFSC में 9 वर्ण और MICR में 11 अंक होते हैं।
- (D) IFSC और MICR दोनों में 16-16 अंक होते हैं।

• सही उत्तर: (B)

• विस्तृत व्याख्या: IDRBT (हैदराबाद) द्वारा विकसित **IFSC 11 वर्णों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड** है (जैसे **SBIN0000300** — जहाँ 5वाँ अक्षर भविष्य के उपयोग हेतु '0' आरक्षित है), जबकि चेक के निचले हिस्से में आयरन ऑक्साइड चुंबकीय स्याही से छपा **MICR कोड 9 अंकों का संख्यात्मक कोड** है (शहर [3] + बैंक [3] + शाखा [3])। वहीं अंतरराष्ट्रीय धन प्रेषण हेतु प्रयुक्त **SWIFT कोड 8 या 11 वर्णों** का होता है।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 23. RTGS (*Real Time Gross Settlement*) और NEFT (*National Electronic Funds Transfer*) में न्यूनतम व अधिकतम लेनदेन सीमा तथा निपटान पद्धति के संबंध में कौन सा कथन **सत्य है**? **[IBPS PO Mains 2022, LIC AAO 2023]**

- (A) RTGS में न्यूनतम सीमा ₹1 लाख है और NEFT में अधिकतम सीमा ₹10 लाख है।
- (B) RTGS आस्थगित निवल निपटान (DNS) पर काम करता है जबकि NEFT रियल-टाइम सकल निपटान पर काम करता है।
- (C) **RTGS** में न्यूनतम लेनदेन सीमा **₹2 लाख** है और अधिकतम की **कोई सीमा नहीं** है (यह रियल-टाइम व एक-एक निर्देश के सकल निपटान पर कार्य करता है); जबकि **NEFT** में सामान्य खाताधारकों के लिए **न तो कोई न्यूनतम सीमा है (₹1 से शुरू) और न ही कोई अधिकतम सीमा** है (यह प्रतिदिन **48 आधे-आधे घंटे के बैचों** में DNS आधार पर कार्य करता है), और दोनों 24x7x365 उपलब्ध हैं।
- (D) NEFT और RTGS दोनों रविवार और बैंक अवकाश के दिन बंद रहते हैं।

• सही उत्तर: (C)

• विस्तृत व्याख्या: दिसंबर 2019 से NEFT और दिसंबर 2020 से RTGS **24x7x365** कर दिए गए हैं। RTGS उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए है इसलिए इसमें **न्यूनतम सीमा ₹2 लाख** है, जबकि NEFT में ऑनलाइन लेनदेन के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है (केवल बिना खाते के बैंक काउंटर पर नकद NEFT की सीमा ₹50,000 प्रति लेनदेन है)।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 24. UPI (*Unified Payments Interface*) के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों (सामान्य P2P, अस्पताल/शिक्षा/कर भुगतान) तथा **'UPI Lite'** (ऑन-डिवाइस वॉलेट) के लिए RBI द्वारा अद्यतन लेनदेन सीमाएँ क्या हैं? **[SBI PO Mains 2024, IBPS PO Mains 2024, RBI Grade B 2024]**

• (A) सामान्य UPI: ₹50,000; अस्पताल व शिक्षा: ₹1 लाख; UPI Lite: ₹200 प्रति लेनदेन

• (B) सामान्य UPI: ₹2 लाख; अस्पताल व शिक्षा: ₹10 लाख; UPI Lite: ₹2,000 प्रति लेनदेन

• (C) सभी श्रेणियों के लिए UPI की अधिकतम सीमा ₹1 लाख है।

• (D) सामान्य P2P व P2M UPI सीमा: **₹1 लाख/दिन**; **अस्पताल (Healthcare), शैक्षणिक संस्थान (Education), IPO एवं कर भुगतान (Tax Payments)** के लिए सीमा: **₹5 लाख प्रति लेनदेन**; तथा **UPI Lite** में बिना पिन के प्रति लेनदेन सीमा **₹1,000** (₹500 से बढ़ाकर) और कुल वॉलेट बैलेंस सीमा **₹5,000** (₹2,000 से बढ़ाकर) है।

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RBI ने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, IPO आवेदनों, RBI रिटेल डायरेक्ट (G-Secs) और कर भुगतान (Tax Payments) के लिए UPI की प्रति लेनदेन सीमा बढ़ाकर **₹5 लाख** कर दी है। साथ ही, छोटे मूल्य के त्वरित लेनदेन हेतु **UPI Lite** की प्रति लेनदेन सीमा ₹500 से बढ़ाकर **₹1,000** और कुल ऑन-डिवाइस वॉलेट सीमा ₹2,000 से बढ़ाकर **₹5,000** कर दी गई है (**PIB UPI Factsheet**)।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 25. बिना इंटरनेट कनेक्शन वाले **फीचर फोन (Feature Phone)** उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए मार्च 2022 में RBI और NPCI द्वारा लॉन्च की गई सेवा का नाम क्या है और इसमें लेनदेन के कितने तकनीकी विकल्प दिए गए हैं? **[IBPS PO Mains 2022, SBI Clerk Mains 2023]**

• (A) **UPI 123Pay** — इसमें 4 विकल्प हैं: (1) IVR नंबर पर कॉल करके, (2) फीचर फोन में ऐप कार्यक्षमता, (3) मिस्ड कॉल आधारित, और (4) प्रॉक्सिमिटी साउंड-आधारित (ध्वनि तरंगों द्वारा) भुगतान (प्रति लेनदेन सीमा ₹10,000 तक)

• (B) **UPI Lite X** — केवल ब्लूटूथ आधारित

• (C) **AEPS Plus** — केवल फिंगरप्रिंट स्कैनर आधारित

• (D) **e-RUPI Lite** — केवल डाकघर आधारित

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** भारत के करोड़ों फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू की गई **UPI 123Pay** सेवा (1-चुनें, 2-चुनें, 3-भुगतान करें) बिना इंटरनेट के 4 तरीकों (IVR कॉल, OEM ऐप, मिस्ड कॉल और टोन-टैग/साउंड वेव) से UPI लेनदेन की सुविधा देती है। इसके साथ डिजिटल भुगतान सहायता हेतु **'डिजीसाथी' (DigiSaathi)** 24x7 हेल्पलाइन भी शुरू की गई थी।

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 26. अगस्त 2021 में लॉन्च किए गए डिजिटल भुगतान समाधान **'e-RUPI'** के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **सत्य है**? **[RBI Grade B 2022, IBPS PO 2022, UPSC Prelims 2022]**

• (A) यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टोकरेंसी है।

• (B) यह NPCI द्वारा विकसित एक **व्यक्ति-विशिष्ट और उद्देश्य-विशिष्ट (Person & Purpose Specific)** संपर्क-रहित प्रीपेड डिजिटल वाउचर (QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित) है, जिसे भुनाने के लिए लाभार्थी के पास **बैंक खाता, स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन होना भी अनिवार्य नहीं** है।

• (C) इसका उपयोग केवल विदेशों में भारतीय पर्यटकों द्वारा होटल बिल चुकाने के लिए किया जा सकता है।

• (D) यह केवल आयकर दाताओं को कर रिफंड देने का एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है।

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या: e-RUPI** को NPCI ने वित्तीय सेवा विभाग (DFS), स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के सहयोग से अपने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है। यह कल्याणकारी सेवाओं (जैसे पोषण, टीबी दवाइयाँ, उर्वरक सब्सिडी, छात्रवृत्ति) की **लीकेज-प्रूफ डिलीवरी** सुनिश्चित करता है क्योंकि वाउचर केवल उसी व्यक्ति द्वारा और उसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए वह जारी हुआ है।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 27. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी **'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (CBDC — डिजिटल रुपया या e₹)** के संदर्भ में कौन सा कथन **सही है**? **[RBI Grade B 2023, SBI PO Mains 2023, UPSC Prelims 2023]**

• (A) यह बिटकॉइन के समान एक निजी विकेंद्रीकृत आभासी मुद्रा है जिसका मूल्य बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।

• (B) इस पर धारक को बचत बैंक खाते के समान 4% वार्षिक ब्याज मिलता है।

• (C) यह RBI द्वारा डिजिटल रूप में जारी एक **संप्रभु वैध मुद्रा (Sovereign Legal Tender)** है जो RBI की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दर्ज होती है, कागजी मुद्रा के साथ **1:1 सममूल्य** पर परिवर्तनीय है, और इसके दो रूप हैं: **e₹-W (Wholesale — अंतर-बैंक व G-Sec निपटान हेतु)** तथा **e₹-R (Retail — आम नागरिकों व व्यापारियों हेतु टोकन आधारित)**।

• (D) इसे केवल भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ही जारी और मुद्रित किया जा सकता है।

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RBI ने **1 नवंबर 2022** को थोक डिजिटल रुपया (**e₹-W**, खाता-आधारित) और **1 दिसंबर 2022** को खुदरा डिजिटल रुपया (**e₹-R**, टोकन-आधारित) का पायलट लॉन्च किया। नकदी की तरह ही डिजिटल रुपये (e₹) पर **कोई ब्याज नहीं मिलता** है (ताकि बैंक जमा से पलायन न हो) और इसे सीधे कागजी नोटों या बैंक जमा में बदला जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 28. मुद्रा बाजार (Money Market) में केंद्र सरकार द्वारा अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए RBI के माध्यम से जारी किए जाने वाले **'ट्रेजरी बिल' (Treasury Bills / T-Bills)** की मानक परिपक्वता अवधियाँ (Tenors), न्यूनतम निवेश राशि और प्रकृति क्या है?
[RBI Grade B 2022, IBPS PO Mains 2022, SSC CGL 2023]

• (A) 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन; न्यूनतम राशि ₹1,000; 8% निश्चित ब्याज दर

• (B) 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष; न्यूनतम राशि ₹1 लाख; राज्य सरकारों द्वारा जारी

• (C) 14 दिन, 28 दिन और 56 दिन; न्यूनतम राशि ₹5 लाख; केवल विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए

• (D) **91 दिन, 182 दिन और 364 दिन**; न्यूनतम निवेश राशि **₹25,000** (और ₹25,000 के गुणकों में); ये **शून्य-कूपन बॉन्ड (Zero-Coupon Bonds)** होते हैं जो अंकित मूल्य से बट्टे (Discount) पर जारी होते हैं और सममूल्य (Par/Face Value) पर भुनाए जाते हैं, तथा इन्हें **केवल केंद्र सरकार** जारी करती है (राज्य सरकारें नहीं)।

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** भारत में **T-Bills** केवल **केंद्र सरकार** द्वारा **91 दिन, 182 दिन और 364 दिन** की तीन अवधियों में जारी किए जाते हैं (जबकि 91 दिन से कम अवधि के लिए 2010 से **Cash Management Bills - CMBs** जारी होते हैं)। राज्य सरकारें T-Bills जारी नहीं कर सकतीं; वे केवल दीर्घकालिक **राज्य विकास ऋण (SDLs - State Development Loans)** जारी करती हैं।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 29. मुद्रा बाजार के दो प्रमुख लिखतों — **'जमा प्रमाणपत्र' (Certificate of Deposit - CD)** और **'वाणिज्यिक पत्र' (Commercial Paper - CP)** के संबंध में कौन सा कथन **पूर्णतः सही** है? **[RBI Grade B 2023, SBI PO Mains 2022]**

• (A) **CD** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (RRBs को छोड़कर) और AIFIs द्वारा जारी किया जाता है, जबकि **CP** उच्च रेटिंग वाली कॉर्पोरेट कंपनियों, PDs और NBFCs द्वारा जारी किया जाने वाला एक असुरक्षित वचन पत्र है; दोनों की परिपक्वता अवधि (बैंकों व कंपनियों हेतु) 7 **दिन से 1 वर्ष** है और दोनों में न्यूनतम निवेश राशि **₹5 लाख** (व ₹5 लाख के गुणकों में) है।

• (B) CD कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा और CP केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किया जाता है; न्यूनतम राशि ₹10,000 है।

• (C) CD और CP दोनों पूंजी बाजार के दीर्घकालिक शेयर हैं जिनका नियमन IRDAI करता है।

• (D) CD की अवधि 5 से 10 वर्ष और CP की अवधि 1 से 3 दिन होती है।

• सही उत्तर: (A)

• विस्तृत व्याख्या: वाघुल समिति की सिफारिश पर **CD (1989)** और **CP (1990)** शुरू किए गए। बैंकों द्वारा जारी CD और कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा जारी CP दोनों की परिपक्वता अवधि **7 दिन से 1 वर्ष** तक होती है (AIFIs 1 से 3 वर्ष के लिए CD जारी कर सकते हैं) और दोनों का न्यूनतम मूल्यवर्ग **₹5 लाख** है।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 30. अंतर-बैंक मुद्रा बाजार (Inter-bank Money Market) में बिना किसी संपार्श्विक (Uncollateralised) के उधार लिए जाने वाले **'कॉल मनी' (Call Money)**, **'नोटिस मनी' (Notice Money)** और **'टर्म मनी' (Term Money)** की परिपक्वता अवधियाँ क्रमशः क्या हैं? **[IBPS PO Mains 2021, RBI Assistant Mains 2022]**

• (A) कॉल मनी: 7 दिन; नोटिस मनी: 30 दिन; टर्म मनी: 5 वर्ष

• (B) **कॉल मनी:** 1 दिन (Overnight); **नोटिस मनी:** 2 दिन से 14 दिन तक; **टर्म मनी:** 15 दिन से 1 वर्ष तक

• (C) कॉल मनी: 1 से 14 दिन; नोटिस मनी: 15 से 90 दिन; टर्म मनी: 91 से 364 दिन

• (D) कॉल मनी: 1 घंटा; नोटिस मनी: 1 दिन; टर्म मनी: 7 दिन

• सही उत्तर: (B)

• विस्तृत व्याख्या: जब बैंक अपनी तात्कालिक CRR या तरलता आवश्यकता पूरी करने के लिए **1 दिन (Overnight)** के लिए उधार लेते हैं तो उसे **Call Money**, **2 से 14 दिनों** के लिए उधार लेते हैं तो **Notice Money**, और **15 दिन से 1 वर्ष** के लिए लेते हैं तो **Term Money** कहा जाता है।

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 31. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**SEBI**) की स्थापना कब हुई और इसे किस अधिनियम द्वारा किस वर्ष सांविधिक निकाय (Statutory Body) का दर्जा प्रदान किया गया? **[SSC CGL 2022, IBPS PO 2022, LIC AAO 2023]**

• (A) स्थापना: 1982; सांविधिक दर्जा: 1988

• (B) स्थापना: 1991; सांविधिक दर्जा: 1999

• (C) **12 अप्रैल 1988** को गैर-सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना हुई और **SEBI अधिनियम, 1992** के तहत **30 जनवरी 1992** को इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ (मुख्यालय: मुंबई)

• (D) स्थापना: 1975; सांविधिक दर्जा: 1995

• सही उत्तर: (C)

• विस्तृत व्याख्या: पूंजी बाजार, म्यूचुअल फंड और निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाले सर्वोच्च नियामक **SEBI** की स्थापना **12 अप्रैल 1988** को हुई थी और **30 जनवरी 1992** को अध्यादेश/SEBI अधिनियम, 1992 द्वारा इसे पूर्ण वैधानिक शक्तियाँ दी गईं। वर्ष 2015 में कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार के नियामक **FMC (Forward Markets Commission)** का भी SEBI में विलय कर दिया गया।

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 32. किसी कंपनी द्वारा प्राथमिक पूंजी बाजार (Primary Market) में अपने शेयर जारी करते समय प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया **'ASBA'** का पूर्ण रूप क्या है और इससे निवेशकों को क्या मुख्य लाभ होता है? **[IBPS PO Mains 2022, SBI PO Mains 2021]**

• (A) *Automated Share Brokerage Account* — इससे ब्रोकरेज शुल्क शून्य हो जाता है।

• (B) *Allotment System for Bond Applications* — इससे केवल सरकारी बॉन्ड खरीदे जाते हैं।

• (C) *Asset Backed Security Account* — इससे शेयरों के बदले तत्काल ऋण मिलता है।

• (D) **Application Supported by Blocked Amount** — इसके तहत IPO/FPO/Rights Issue में आवेदन करते समय आवेदन राशि निवेशक के बैंक खाते से बाहर नहीं निकलती, बल्कि आवंटन प्रक्रिया पूरी होने तक उसी खाते में ब्लॉक रहती है और उस पर बचत खाते का ब्याज भी मिलता रहता है।

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** SEBI द्वारा अनिवार्य की गई *ASBA (Application Supported by Blocked Amount)* प्रणाली में यदि निवेशक को IPO में शेयर आवंटित होते हैं तभी उसके खाते से उतनी राशि कटती है, और यदि आवंटन नहीं होता है तो ब्लॉक की गई राशि तुरंत अनब्लॉक हो जाती है — जिससे रिफंड के इंतजार और ब्याज की हानि की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई।

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 33. एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज **'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज' (BSE)** और भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज **'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' (NSE)** की स्थापना वर्ष तथा उनके प्रमुख बेंचमार्क सूचकांकों (SENSEX व NIFTY) में शामिल कंपनियों की संख्या क्रमशः क्या है? **[SSC CGL 2023, RRB NTPC 2022, IBPS Clerk Mains 2022]**

• (A) **BSE:** स्थापना **1875** (प्रेमचंद रॉयचंद द्वारा), सूचकांक **SENSEX में 30 कंपनियाँ** (आधार वर्ष 1978–79); **NSE:** स्थापना **1992** (फेरवानी समिति की सिफारिश पर), सूचकांक **NIFTY-50 में 50 कंपनियाँ** (आधार वर्ष 1995)

• (B) BSE: स्थापना 1905, SENSEX में 50 कंपनियाँ; NSE: स्थापना 1988, NIFTY में 30 कंपनियाँ

• (C) BSE: स्थापना 1850, SENSEX में 100 कंपनियाँ; NSE: स्थापना 1995, NIFTY में 500 कंपनियाँ

• (D) BSE: स्थापना 1921, SENSEX में 25 कंपनियाँ; NSE: स्थापना 1999, NIFTY में 40 कंपनियाँ

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर स्थित **BSE (1875)** एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका संवेदी सूचकांक **SENSEX** (1986 में दीपक मोहोनी द्वारा नामकरण) बीएसई की शीर्ष **30** फ्री-फ्लोट मार्केट कैप कंपनियों पर आधारित है। वहीं **NSE (1992)** का सूचकांक **NIFTY-50** शीर्ष **50** कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 34. भारत में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए वर्ष 1993 में गठित किस समिति की सिफारिश पर **'भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण' (IRDAI)** की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? **[LIC AAO Mains 2023, NIACL AO 2023, IBPS PO 2022]**

• (A) नरसिंहम समिति — मुख्यालय: मुंबई

• (B) **आर. एन. मल्होत्रा समिति** (IRDA अधिनियम, 1999; अप्रैल 2000 में गठन) — मुख्यालय: **हैदराबाद (तेलंगाना)**

• (C) रंगराजन समिति — मुख्यालय: नई दिल्ली

• (D) गोइपोरिया समिति — मुख्यालय: कोलकाता

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** पूर्व RBI गवर्नर **आर. एन. मल्होत्रा** की अध्यक्षता वाली समिति (1993–94) की सिफारिश पर बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला गया और **IRDA अधिनियम, 1999** के तहत अप्रैल 2000 में नियामक की स्थापना हुई। सन् 2001 में इसका मुख्यालय दिल्ली से **हैदराबाद** स्थानांतरित किया गया।

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 35. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना किस तिथि को हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका संस्कृत आदर्श वाक्य (Motto) कहाँ से लिया गया है? **[LIC AAO 2023, LIC ADO 2023, SSC CGL 2022]**

• (A) 1 अप्रैल 1935, कोलकाता — मुंडकोपनिषद से "सत्यमेव जयते"

• (B) 1 जुलाई 1955, नई दिल्ली — कठोपनिषद से "उत्तिष्ठत जाग्रत"

• (C) **1 सितंबर 1956** (LIC अधिनियम, 1956 के तहत 245 बीमा कंपनियों का विलय करके), मुख्यालय: **मुंबई** — श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय 9, श्लोक 22) से लिया गया आदर्श वाक्य **"योगक्षेमं वहाम्यहम्"** ("आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है")

• (D) 2 अक्टूबर 1972, चेन्नई — ऋग्वेद से "असतो मा सद्गमय"

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या: 1 सितंबर 1956** को स्थापित LIC का केंद्रीय कार्यालय मुंबई के 'योगक्षेम' भवन में है और इसका ध्येय वाक्य "योगक्षेमं वहाम्यहम्" भगवद्गीता से लिया गया है।

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 36. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की **4 साधारण बीमा (General Insurance) कंपनियों** और **1 राष्ट्रीय पुनर्बीमा (Reinsurance) कंपनी** के मुख्यालयों का कौन सा मिलान **पूर्णतः सही है**? **[LIC AAO Mains 2023, UIIC AO 2024, NIACL AO 2023]**

• (A) न्यू इंडिया एश्योरेंस — नई दिल्ली; ओरिएंटल इंश्योरेंस — मुंबई; नेशनल इंश्योरेंस — चेन्नई; यूनाइटेड इंडिया — कोलकाता

• (B) सभी चारों साधारण बीमा कंपनियों का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

• (C) न्यू इंडिया एश्योरेंस — कोलकाता; GIC Re — हैदराबाद; यूनाइटेड इंडिया — बेंगलुरु

• (D) **न्यू इंडिया एश्योरेंस (NIACL) एवं GIC Re (राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी) — मुंबई; ओरिएंटल इंश्योरेंस (OICL) — नई दिल्ली; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस (UIIC) — चेन्नई**; और **नेशनल इंश्योरेंस (NICL — सबसे पुरानी 1906) — कोलकाता**

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** यह बीमा परीक्षाओं का सबसे सदाबहार प्रश्न है — भारत के चार महानगरों में चार सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों के मुख्यालय हैं: **मुंबई (New India Assurance — 1919, दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित), नई दिल्ली (Oriental Insurance — 1947), चेन्नई (United India Insurance — 1938)** और **कोलकाता (National Insurance — 1906)**, जबकि भारत की एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी **GIC Re (1972)** का मुख्यालय **मुंबई** में है।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 37. बीमा के 7 मौलिक सिद्धांतों में से कौन से **दो सिद्धांत** ऐसे हैं जो सभी साधारण बीमा (अग्नि, समुद्री, मोटर बीमा आदि) अनुबंधों पर तो पूर्णतः लागू होते हैं, किंतु **जीवन बीमा (Life Insurance)** अनुबंधों पर **लागू नहीं होते** हैं? **[LIC AAO Mains 2023, NIACL AO 2022]**

• (A) **क्षतिपूर्ति का सिद्धांत (Principle of Indemnity)** तथा **प्रस्थापन एवं अंशदान का सिद्धांत (Principles of Subrogation & Contribution)** (क्योंकि मानव जीवन का मूल्यांकन पैसों में नहीं हो सकता; जीवन बीमा एक 'निश्चित मूल्य अनुबंध' *[Contract of Assurance/ Contingency]* है, न कि क्षतिपूर्ति अनुबंध)

• (B) परम सद्भाव का सिद्धांत (*Uberrimae Fidei*) और बीमा योग्य हित का सिद्धांत (*Insurable Interest*)

• (C) आसन्न कारण का सिद्धांत (*Causa Proxima*) और परम सद्भाव का सिद्धांत

• (D) उपर्युक्त सभी सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू होते हैं।

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** जीवन बीमा में **परम सद्भाव (Utmost Good Faith)** और पॉलिसी लेते समय **बीमा योग्य हित (Insurable Interest)** होना अनिवार्य है, परंतु **क्षतिपूर्ति (Indemnity), प्रस्थापन (Subrogation)** और **अंशदान (Contribution)** के सिद्धांत जीवन बीमा पर **लागू नहीं होते** हैं — इसीलिए यदि किसी व्यक्ति ने 4 अलग-अलग जीवन बीमा पॉलिसियाँ ली हैं, तो मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को चारों पॉलिसियों से पूरी बीमा राशि मिलती है।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 38. बीमा अनुबंध का वह कौन सा सिद्धांत है जो कहता है कि एक बार जब बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति को क्षतिग्रस्त संपत्ति के पूरे दावे (Claim) का भुगतान कर देती है, तो उस क्षतिग्रस्त संपत्ति के अवशेष (Salvage) और दोषी तीसरे पक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर वसूली करने के सभी अधिकार बीमित व्यक्ति से हटकर बीमा कंपनी के पास चले जाते हैं? **[LIC AAO 2023, IBPS SO 2022]**

• (A) परम सद्भाव का सिद्धांत (Principle of Utmost Good Faith)

• (B) **प्रस्थापन / अधिकार-समर्पण का सिद्धांत (Principle of Subrogation)**

• (C) आसन्न कारण का सिद्धांत (Principle of Proximate Cause)

• (D) वारंटी का सिद्धांत (Principle of Warranty)

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या: प्रस्थापन का सिद्धांत (Principle of Subrogation)** क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का ही पूरक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी से भी क्लेम ले ले और बाद में टूटी हुई गाड़ी/संपत्ति को बेचकर या दुर्घटना करने वाले तीसरे पक्ष से मुआवजा लेकर दोहरा लाभ (Double Profit) न कमा सके।

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 39. IRDAI द्वारा भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी यानी **वर्ष 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' (Insurance for All by 2047)** के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई तीन महत्वाकांक्षी पहलों (**'बीमा त्रिमूर्ति'**) का सही विवरण क्या है? **[LIC AAO Mains 2023, RBI Grade B 2024, IBPS PO Mains 2024]**

• (A) बीमा मित्र, बीमा बैंक और बीमा कार्ड

• (B) बीमा सुरक्षा, बीमा जीवन और बीमा पेंशन

• (C) **(1) बीमा सुगम (Bima Sugam):** बीमा की खरीद, बिक्री, नवीनीकरण और क्लेम निपटान हेतु वन-स्टॉप डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म; **(2) बीमा विस्तार (Bima Vistaar):** जीवन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना और संपत्ति कवर का किफायती 'ऑल-इन-वन' बंडल उत्पाद; और **(3) बीमा वाहक (Bima Vahak):** प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के नेतृत्व वाला ग्रामीण बीमा वितरण बल

• (D) बीमा शक्ति, बीमा समृद्धि और बीमा ग्राम

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति एवं IRDAI सुधारों के तहत **'बीमा सुगम'** (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर/मार्केटप्लेस), **'बीमा विस्तार'** (समग्र बंडल उत्पाद) और **'बीमा वाहक'** (महिला केंद्रित ग्राम पंचायत वितरण चैनल) को बीमा क्षेत्र के UPI क्षण के रूप में विकसित किया गया है।

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 40. 9 मई 2015 को शुरू की गई दोनों जन सुरक्षा बीमा योजनाओं — **'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (PMJJBY)** और **'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (PMSBY)** की पात्रता आयु, संशोधित वार्षिक प्रीमियम (1 जून 2022 से लागू) और बीमा कवर राशि का कौन सा मिलान **पूर्णतः सही है**? **[IBPS PO Mains 2023, SBI PO Mains 2023, LIC AAO 2023, SSC CGL 2024]**

• (A) PMJJBY: आयु 18–60 वर्ष, प्रीमियम ₹330; PMSBY: आयु 18–65 वर्ष, प्रीमियम ₹12

• (B) PMJJBY: आयु 21–55 वर्ष, प्रीमियम ₹500; PMSBY: आयु 18–75 वर्ष, प्रीमियम ₹50

• (C) दोनों योजनाओं में आयु सीमा 18–50 वर्ष और प्रीमियम ₹100 प्रति वर्ष है।

• (D) **PMJJBY (जीवन बीमा):** आयु **18 से 50 वर्ष** (कवर 55 वर्ष तक), वार्षिक प्रीमियम **₹436** (पूर्व में ₹330), किसी भी कारण से मृत्यु पर **₹2 लाख** का कवर; तथा **PMSBY (दुर्घटना बीमा):** आयु **18 से 70 वर्ष**, वार्षिक प्रीमियम **मात्र ₹20** (पूर्व में ₹12), दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर **₹2 लाख** और आंशिक स्थायी विकलांगता पर **₹1 लाख** का कवर।

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** PIB जन सुरक्षा योजना विज्ञप्ति के अनुसार, 1 जून 2022 से PMJJBY का प्रीमियम ₹330 से बढ़ाकर **₹436/वर्ष** (अधिकतम ₹1.25/दिन से भी कम) और PMSBY का प्रीमियम ₹12 से बढ़ाकर **₹20/वर्ष** कर दिया गया है। दोनों योजनाओं का वार्षिक कवरेज चक्र **1 जून से 31 मई** होता है और राशि बैंक खाते से ऑटो-डेबिट होती है।

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 41. विश्व के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम **'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' (PMJDY — शुभारंभ: 28 अगस्त 2014)** के अंतर्गत मिलने वाली **ओवरड्राफ्ट (Overdraft - OD) सुविधा** और **RuPay डेबिट कार्ड पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर** की वर्तमान अधिकतम सीमा क्या है? **[IBPS Clerk Mains 2023, RRB NTPC 2022, SBI PO 2022]**

• (A) ओवरड्राफ्ट सीमा: **₹10,000** तक (आयु 18–65 वर्ष; जिसमें ₹2,000 तक बिना किसी शर्त के); और RuPay कार्ड पर दुर्घटना बीमा कवर: **₹2 लाख** (28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए जन-धन खातों के लिए)

• (B) ओवरड्राफ्ट सीमा: ₹5,000 तक; और दुर्घटना बीमा कवर: ₹1 लाख

• (C) ओवरड्राफ्ट सीमा: ₹50,000 तक; और दुर्घटना बीमा कवर: ₹5 लाख

• (D) जन-धन खातों में कोई ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं मिलती है।

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 28 अगस्त 2018 को PMJDY के 4 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने इसे "हर परिवार से **हर वयस्क (Every Unbanked Adult)**" पर केंद्रित करते हुए ओवरड्राफ्ट सीमा को ₹5,000 से दोगुना कर **₹10,000** कर दिया और नए RuPay कार्डधारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को ₹1 लाख से बढ़ाकर **₹2 लाख** कर दिया।

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 42. केंद्रीय बजट 2024–25 की घोषणा के अनुसार **'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' (PMMY — शुभारंभ: 8 अप्रैल 2015)** के अंतर्गत एक चौथी नई ऋण श्रेणी **'तरुण प्लस' (Tarun Plus)** जोड़ी गई है; अब मुद्रा योजना की चारों श्रेणियों (शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस) की ऋण सीमाएँ क्या हैं? **[IBPS PO Mains 2024, SBI Clerk Mains 2024, RBI Grade B 2024]**

• (A) शिशु: ₹25,000 तक; किशोर: ₹2 लाख तक; तरुण: ₹5 लाख तक; तरुण प्लस: ₹10 लाख तक

• (B) **शिशु (Shishu):** ₹50,000 तक; **किशोर (Kishore):** ₹50,000 से ₹5 लाख तक; **तरुण (Tarun):** ₹5 लाख से ₹10 लाख तक; और **तरुण प्लस (Tarun Plus):** ₹10 लाख से **₹20 लाख तक** (उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने पहले 'तरुण' श्रेणी का ऋण लेकर सफलतापूर्वक चुका दिया है)

• (C) शिशु: ₹1 लाख तक; किशोर: ₹10 लाख तक; तरुण: ₹25 लाख तक; तरुण प्लस: ₹50 लाख तक

• (D) शिशु: ₹50,000 तक; किशोर: ₹1 लाख तक; तरुण: ₹5 लाख तक; तरुण प्लस: ₹15 लाख तक

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को विस्तार देने के लिए सरकार ने मुद्रा ऋण की अधिकतम सीमा ₹10 लाख से दोगुनी कर **₹20 लाख** कर दी है और इस नई श्रेणी को **'तरुण प्लस' (Tarun Plus — ₹10 लाख से ₹20 लाख)** नाम दिया है, जिसकी गारंटी *Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU)* द्वारा दी जाती है।

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 43. अटल पेंशन योजना (APY — नियामक: PFRDA) के अंतर्गत प्रवेश आयु सीमा, 60 वर्ष के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन के स्लैब और 1 अक्टूबर 2022 से लागू महत्वपूर्ण पात्रता प्रतिबंध क्या है? **[IBPS PO Mains 2023, LIC AAO 2023, SSC CGL 2023]**

• (A) आयु: 18–50 वर्ष; पेंशन: ₹5,000 से ₹10,000/माह; सरकारी कर्मचारी पात्र हैं।

• (B) आयु: 21–60 वर्ष; पेंशन: केवल ₹3,000/माह निश्चित; सभी नागरिक पात्र हैं।

• (C) प्रवेश आयु: **18 से 40 वर्ष** (न्यूनतम अंशदान अवधि 20 वर्ष); 60 वर्ष की आयु से **₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 प्रति माह** की गारंटीशुदा पेंशन; और **1 अक्टूबर 2022** से कोई भी व्यक्ति जो **आयकर दाता (Income Tax Payer)** है, APY में नया खाता खोलने के लिए पात्र **नहीं** है।

• (D) आयु: 18–70 वर्ष; पेंशन: ₹10,000/माह; केवल बीपीएल कार्डधारक पात्र हैं।

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** PFRDA द्वारा प्रशासित **अटल पेंशन योजना (APY)** में 18 से 40 वर्ष का व्यक्ति जुड़ सकता है (ताकि 60 वर्ष की आयु तक कम से कम 20 वर्ष अंशदान हो सके)। योजना का लाभ वास्तव में असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों तक पहुँचाने के लिए **1 अक्टूबर 2022** से आयकर दाताओं (Income Tax Payers) के नए नामांकन पर रोक लगा दी गई है (**PIB Jan Suraksha Release**)।

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 44. भारत में **'भुगतान बैंक' (Payments Banks — नचिकेत मोर समिति)** और **'लघु वित्त बैंक' (Small Finance Banks - SFBs — उषा थोराट समिति)** के परिचालन नियमों के बीच सबसे प्रमुख अंतर क्या है? **[RBI Grade B 2022, IBPS PO Mains 2022, SBI PO 2023]**

• (A) भुगतान बैंक ₹50 लाख तक का होम लोन दे सकते हैं जबकि लघु वित्त बैंक ऋण नहीं दे सकते।

• (B) भुगतान बैंक को CRR और SLR रखने से छूट प्राप्त है।

• (C) भुगतान बैंक केवल अनिवासी भारतीयों (NRIs) से सावधि जमा (FD) स्वीकार कर सकते हैं।

• (D) **भुगतान बैंक** प्रति ग्राहक अधिकतम **₹2 लाख तक केवल मांग जमा (Demand Deposits — बचत व चालू खाता)** स्वीकार कर सकते हैं, किंतु वे **सावधि जमा (FD/RD) स्वीकार नहीं कर सकते** और **कोई भी ऋण (Loan) या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते** (उन्हें अपनी मांग जमा का कम से कम **75% सरकारी प्रतिभूतियों/T-Bills में SLR** के रूप में निवेश करना होता है); जबकि **लघु वित्त बैंक (SFBs)** सभी प्रकार की जमाएँ (FD/RD सहित) स्वीकार कर सकते हैं और **ऋण भी दे सकते हैं** (जिनके लिए **75% PSL लक्ष्य** और कम से कम 50% ऋण ₹25 लाख तक के होने अनिवार्य हैं)।

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** भारत का पहला भुगतान बैंक **एयरटेल पेमेंट्स बैंक (2017)** था और पहला लघु वित्त बैंक **कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक (जालंधर, 2016)** था। भुगतान बैंकों में जमा की अधिकतम सीमा अप्रैल 2021 में ₹1 लाख से बढ़ाकर **₹2 लाख प्रति ग्राहक** कर दी गई, और वे ऋण जोख़िम (Credit Risk) से बचने के लिए कोई लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते।

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 45. भारत में कार्यरत **5 'अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों' (All India Financial Institutions - AIFIs)**, जिनका विनियमन और पर्यवेक्षण RBI द्वारा किया जाता है, की स्थापना वर्ष और मुख्यालय का कौन सा मिलान **पूर्णतः सही है**? **[RBI Grade B Phase-I 2023, NABARD Grade A 2023, IBPS PO Mains 2023]**

• (A) **1. EXIM Bank** (1982, मुंबई); **2. NABARD** (12 जुलाई 1982, मुंबई); **3. NHB** (9 जुलाई 1988, **नई दिल्ली** — 100% भारत सरकार के स्वामित्व में); **4. SIDBI** (2 अप्रैल 1990, **लखनऊ**); और **5. NaBFID** (*National Bank for Financing Infrastructure and Development* — 2021, मुंबई — भारत का 5वाँ AIFI)

• (B) EXIM Bank — नई दिल्ली; NABARD — लखनऊ; SIDBI — मुंबई; NHB — हैदराबाद

• (C) NABARD — 1975 (कोलकाता); SIDBI — 1982 (मुंबई); NHB — 1992 (चेन्नई)

• (D) भारत में केवल 3 AIFIs हैं और सभी के मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** बहुत ध्यान दें: भारत के 5 AIFIs में से 3 (**EXIM Bank, NABARD और 2021 में गठित 5वाँ AIFI 'NaBFID'**) का मुख्यालय **मुंबई** में है, जबकि **SIDBI (1990)** का मुख्यालय **लखनऊ (उत्तर प्रदेश)** में है और **NHB (राष्ट्रीय आवास बैंक — 1988)** का मुख्यालय **नई दिल्ली** में है (2019 में RBI ने अपनी 100% हिस्सेदारी सरकार को बेच दी, जिससे अब NHB पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है)।

अभ्यास प्रश्न #46 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 46. भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी *'*DICGC*' (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation — स्थापना 1978, मुख्यालय: मुंबई)* द्वारा बैंक डूबने या मोरेटोरियम लगने की स्थिति में प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक अधिकतम कितनी जमा राशि (मूलधन + ब्याज मिलाकर) का बीमा कवर प्रदान किया जाता है और दावे के भुगतान की समय-सीमा क्या है? **[IBPS PO Mains 2022, SBI Clerk Mains 2022, RBI Assistant 2023]**

• (A) ₹1 लाख — 1 वर्ष के भीतर भुगतान

• (B) **₹5 लाख** (4 फरवरी 2020 को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया) — और DICGC (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 18A के तहत बैंक पर प्रतिबंध (Moratorium) लगने के **90 दिनों के भीतर** जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान करना अनिवार्य है।

• (C) ₹10 लाख — 180 दिनों के भीतर भुगतान

• (D) केवल बचत खाते की पूरी राशि, सावधि जमा (FD) कवर नहीं होती।

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** DICGC भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं, RRBs, SFBs, पेमेंट्स बैंकों और सहकारी बैंकों सहित) के जमाकर्ताओं की **बचत, चालू, सावधि (FD) और आवर्ती (RD)** सभी जमाओं को मिलाकर एक बैंक में एक ही अधिकार और क्षमता (Same Right and Same Capacity) में रखे गए खातों पर **अधिकतम ₹5 लाख (मूलधन + ब्याज सहित)** का बीमा कवर देता है। इसका प्रीमियम बैंक स्वयं भरते हैं, ग्राहक से नहीं लिया जाता।

अभ्यास प्रश्न #47 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 47. भारत में **'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों' (Regional Rural Banks - RRBs)** की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर कब हुई, भारत का **प्रथम RRB** कौन सा था और किसी भी RRB में केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक (Sponsor Bank) और संबंधित राज्य सरकार की पूंजी हिस्सेदारी का अनुपात क्या होता है? **[IBPS RRB PO/Clerk Mains 2023, NABARD Grade A 2023, SSC CGL 2022]**

• (A) शिवरामन समिति (1982) — आर्यावर्त बैंक — 50 : 25 : 25

• (B) गाडगिल समिति (1969) — बड़ौदा यूपी बैंक — 60 : 20 : 20

• (C) **एम. नरसिंहम कार्यदल** की सिफारिश पर **2 अक्टूबर 1975** (RRB अधिनियम, 1976); प्रथम RRB: **'प्रथमा बैंक'** (मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश — सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित); और पूंजी हिस्सेदारी का अनुपात: **केंद्र सरकार (50%) : प्रायोजक बैंक (35%) : राज्य सरकार (15%)**

• (D) केलकर समिति (1985) — सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक — 40 : 40 : 20

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** ग्रामीण व कृषि साख के लिए 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित RRBs का विनियमन **RBI** करता है जबकि इनका पर्यवेक्षण (Supervision) **NABARD** द्वारा किया जाता है। इनमें केंद्र सरकार : प्रायोजक बैंक : राज्य सरकार की हिस्सेदारी का स्वर्ण अनुपात **50 : 35 : 15** है। (नोट: गोवा और सिक्किम राज्यों में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है)।

अभ्यास प्रश्न #48 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 48. किसी कंपनी या व्यक्ति के ऋण व साख इतिहास का मूल्यांकन करने वाली **'क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों' (CICs)** का विनियमन *CIC (Regulation) Act, 2005* के तहत RBI द्वारा किया जाता है; भारत की **प्रथम CIC** कौन सी थी और वर्तमान में RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त कुल कितनी CICs भारत में कार्यरत हैं? **[IBPS PO Mains 2023, SBI PO Mains 2023]**

• (A) केवल 1 — CIBIL (2000)

• (B) 2 — CRISIL और ICRA

• (C) 3 — CARE, Fitch और Moody's

• (D) कुल **4 CICs** कार्यरत हैं: **1. TransUnion CIBIL** (वर्ष 2000 में पारेख समिति की सिफारिश पर स्थापित **भारत की प्रथम CIC**), **2. Equifax**, **3. Experian**, और **4. CRIF High Mark** (और इनका *CIBIL* स्कोर **300 से 900** के बीच होता है)

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** बहुत से विद्यार्थी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRISIL [1987 — भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी], ICRA, CARE, Acuite, INFOMERICS — जिनका नियामक **SEBI** है) और **क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (CICs — जिनका नियामक RBI है)** में भ्रमित हो जाते हैं। RBI के तहत **4 CICs (CIBIL, Equifax, Experian, CRIF High Mark)** कार्यरत हैं और इन्हें भी अब RBI की एकीकृत लोकपाल योजना के दायरे में लाया गया है।

अभ्यास प्रश्न #49 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 49. भारत में एक खाली कागज पर लिखे या मुद्रित **'विनिमय साध्य लिखतों' (Negotiable Instruments)** — अर्थात् **वचन पत्र (Promissory Note)**, **विनिमय विपत्र (Bill of Exchange)** और **चेक (Cheque)** — को परिभाषित करने वाले **'परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881' (Negotiable Instruments Act, 1881)** की सही धाराओं और चेक की वैधता अवधि का मिलान कौन सा है? **[IBPS SO Law/Mains 2023, SBI PO Mains 2022, RBI Assistant 2022]**

• (A) **धारा 4:** वचन पत्र (Promissory Note); **धारा 5:** विनिमय विपत्र (Bill of Exchange); **धारा 6:** चेक (Cheque); **धारा 138:** खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस (Dishonour of Cheque) होने पर दंडनीय अपराध; और चेक व डिमांड ड्राफ्ट (DD) की वैधता अवधि जारी होने की तिथि से **3 महीने (90 दिन)** होती है।

• (B) धारा 10: वचन पत्र; धारा 20: चेक; चेक की वैधता अवधि 6 महीने होती है।

• (C) धारा 4: चेक; धारा 5: डिमांड ड्राफ्ट; धारा 6: हुंडी; चेक की वैधता 1 वर्ष होती है।

• (D) परक्राम्य लिखत अधिनियम 1949 में पारित हुआ था और चेक की कोई एक्सपायरी तिथि नहीं होती।

• सही उत्तर: (A)

• विस्तृत व्याख्या: *Negotiable Instruments Act, 1881* की **धारा 4 (Promissory Note)**, **धारा 5 (Bill of Exchange)** और **धारा 6 (Cheque — जो हमेशा किसी निर्दिष्ट बैंकर पर ही लिखा जाता है और मांग पर देय होता है)** अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1 अप्रैल 2012 से RBI ने चेक और डिमांड ड्राफ्ट की वैधता को 6 महीने से घटाकर **3 महीने** कर दिया है (3 महीने के बाद वह **'Stale Cheque'** कहलाता है)।

अभ्यास प्रश्न #50 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 50. नवंबर 2021 में शुरू की गई *'रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' (*RB-IOS 2021* — "One Nation, One Ombudsman")* ने किन तीन पुरानी लोकपाल योजनाओं को एकीकृत किया और इसका केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) कहाँ स्थापित किया गया है? **[RBI Grade B 2022, IBPS PO Mains 2022, SBI Clerk Mains 2022]**

• (A) बैंकिंग, बीमा और पेंशन लोकपाल — मुख्यालय: मुंबई

• (B) **(1) बैंकिंग लोकपाल योजना (1995/2006)**, **(2) एनबीएफसी लोकपाल योजना (2018)** और **(3) डिजिटल लेनदेन लोकपाल योजना (2019)** को एकीकृत किया; तथा इसका केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र **(CRPC)** व टोल-फ्री हेल्पलाइन **(14448) चंडीगढ़** में स्थापित किया गया है (मानसिक उत्पीड़न हेतु ₹1 लाख तक व वित्तीय हानि हेतु **₹20 लाख** तक के मुआवजे का अधिकार, अपील अधिकारी: RBI के कार्यकारी निदेशक)।

• (C) सेबी लोकपाल, आयकर लोकपाल और जीएसटी लोकपाल — मुख्यालय: नई दिल्ली

• (D) केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लोकपाल — मुख्यालय: कोलकाता

• सही उत्तर: (B)

• विस्तृत व्याख्या: यदि बैंक/NBFC/प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता/CIC में शिकायत करने के **30 दिनों के भीतर** समाधान नहीं मिलता है, तो ग्राहक **cms.rbi.org.in** पोर्टल या **चंडीगढ़ स्थित CRPC** (टोल-फ्री नंबर **14448**) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसमें 'ग्राहक द्वारा सही धारा चुनने की बाध्यता' (Deficiency in Service आधार) समाप्त कर दी गई है।

अभ्यास प्रश्न #51 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 51. बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की वित्तीय स्थिति खराब होने पर समय रहते सुधारात्मक प्रतिबंध लगाने के लिए RBI द्वारा लागू किए जाने वाले ढांचे को क्या कहते हैं और इसके आकलन के तीन मुख्य मापदंड (Parameters) क्या हैं? **[RBI Grade B 2022, IBPS PO Mains 2022]**

• (A) त्वरित वसूली योजना (FRP) — जमा, ऋण और शाखा संख्या

• (B) तरलता नियंत्रण तंत्र (LCM) — रेपो, रिवर्स रेपो और बैंक रेट

• (C) **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA - Prompt Corrective Action Framework)** — इसके आकलन के तीन मुख्य क्षेत्र हैं: **(1) पूंजी (Capital — CRAR व CET-1)**, **(2) आस्ति गुणवत्ता (Asset Quality — Net NPA Ratio)** और **(3) उत्तोलन (Leverage — Tier-1 Leverage Ratio)**

• (D) बैंकिंग मोरेटोरियम संहिता — केवल शेयर बाजार मूल्य आधारित

• सही उत्तर: (C)

• विस्तृत व्याख्या: RBI का **PCA (Prompt Corrective Action)** फ्रेमवर्क (जो अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ **NBFCs** पर भी लागू है) तीन संकेतकों — **पूंजी पर्याप्तता (CRAR/CET-1), शुद्ध एनपीए (Net NPA) और उत्तोलन अनुपात (Leverage Ratio)** — के निर्धारित सीमा से नीचे जाने पर बैंक को रिस्क थ्रेशोल्ड 1, 2 या 3 में रखता है और लाभांश वितरण, शाखा विस्तार तथा उच्च जोखिम वाले ऋण देने पर रोक लगाता है।

अभ्यास प्रश्न #52 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 52. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में कुल मुद्रा आपूर्ति (Money Supply Aggregates — M_1, M_2, M_3, M_4) की गणना में किस समुच्चय को क्रमशः **'संकीर्ण मुद्रा' (Narrow Money)** और किस समुच्चय को **'व्यापक मुद्रा' (Broad Money / Aggregate Monetary Resources)** कहा जाता है? **[RBI Grade B 2021, SSC CGL 2023, UPSC Prelims]**

• (A) M_3 को संकीर्ण मुद्रा और M_1 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है।

• (B) M_0 को संकीर्ण मुद्रा और M_2 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है।

• (C) केवल डाकघर की जमाओं को व्यापक मुद्रा कहा जाता है।

• (D) **M_1** ($जनता के पास करेंसी व सिक्के [CU] + बैंकों के पास मांग जमा [DD] + RBI के पास अन्य जमा [OD]) और M_2 को **'संकीर्ण मुद्रा' (Narrow Money)** कहा जाता है (जिसमें M_1 **सर्वाधिक तरल [Most Liquid]** है); जबकि **M_3** (M_1 + बैंकों के पास सावधि जमा [Time Deposits]) और M_4 को **'व्यापक मुद्रा' (Broad Money)** कहा जाता है, तथा **M_0$** को **'आरक्षित मुद्रा / उच्च शक्तिशाली मुद्रा' (Reserve Money / High Powered Money)** कहा जाता है।

• सही उत्तर: (D)

• विस्तृत व्याख्या: तरलता (Liquidity) का घटता क्रम है: **M_1 > M_2 > M_3 > M_4**। अर्थशास्त्र और RBI के आंकड़ों में **M_3** सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला मानक है जिसे **'Broad Money' (व्यापक मुद्रा या समग्र मौद्रिक संसाधन)** कहा जाता है (M_3 = M_1 + Net Time Deposits with Banking System)।

अभ्यास प्रश्न #53 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 53. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और विदेशी मुद्रा खातों के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों — **'नोस्ट्रो खाता' (Nostro Account)**, **'वोस्ट्रो खाता' (Vostro Account)** और **'लोरो खाता' (Loro Account)** का सही अर्थ क्या है? **[IBPS PO Mains 2022, SBI PO Mains 2023, RBI Grade B 2023]**

• (A) *नोस्ट्रो खाता ("Our account with you"): **किसी भारतीय बैंक द्वारा विदेश के किसी बैंक में उस विदेशी देश की मुद्रा (जैसे *USD*) में खोला गया खाता;** वोस्ट्रो खाता ("Your account with us"): **किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत के किसी बैंक में** भारतीय रुपये (*INR*) **में खोला गया खाता (जिसका उपयोग** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रुपये में निपटान *[INR Trade Settlement — SRVA]* **करने में होता है); और** लोरो खाता ("Their account with them"):* जब कोई तीसरा बैंक अन्य दो बैंकों के खाते का संदर्भ देता है।

• (B) नोस्ट्रो खाता केवल बचत खाता है, वोस्ट्रो खाता चालू खाता है और लोरो खाता एफडी खाता है।

• (C) नोस्ट्रो खाता विदेशी बैंक का भारत में डॉलर खाता है और वोस्ट्रो खाता भारतीय बैंक का अमेरिका में रुपया खाता है।

• (D) ये तीनों खाते केवल विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों के लिए खोले जाते हैं।

• सही उत्तर: (A)

• विस्तृत व्याख्या: लैटिन शब्दों में **Nostro = "हमारा"** (हमारा खाता आपके पास — जैसे SBI का न्यूयॉर्क के सिटीबैंक में डॉलर खाता), **Vostro = "आपका"** (आपका खाता हमारे पास — जैसे किसी रूसी या यूएई बैंक का भारत में SBI के पास रुपये में खुला खाता; RBI ने जुलाई 2022 से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रुपये में निपटान हेतु **Special Rupee Vostro Accounts [SRVA]** की अनुमति दी है) और **Loro = "उनका"** होता है।

अभ्यास प्रश्न #54 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 54. अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा भारत के बैंकों में खोले जाने वाले तीन प्रमुख खातों — *NRE* (Non-Resident External), *NRO* (Non-Resident Ordinary) **और** *FCNR(B)* (Foreign Currency Non-Resident [Bank]) **के बीच मुद्रा, करदेयता (*Taxability*) और खाता प्रकार के संदर्भ में कौन सा अंतर** सही है*? **[IBPS PO Mains 2023, SBI PO Mains 2022]**

• (A) NRE और NRO दोनों विदेशी मुद्रा में रखे जाते हैं और FCNR(B) केवल भारतीय रुपये में रखा जाता है।

• (B) **NRE और NRO खाते भारतीय रुपये (INR)** में रखे जाते हैं (ये बचत, चालू, FD या RD हो सकते हैं), जबकि **FCNR(B) खाता केवल विदेशी मुद्रा में और केवल 'सावधि जमा' (Term Deposit / FD — 1 से 5 वर्ष)** के रूप में ही खोला जा सकता है; साथ ही **NRE और FCNR(B) खातों के ब्याज पर भारत में कोई आयकर नहीं लगता (Tax-free) और ये पूर्णतः प्रत्यावर्तनीय (Repatriable) हैं**, जबकि **NRO खाते** (भारत में अर्जित आय जैसे किराया, पेंशन, लाभांश जमा करने हेतु) के ब्याज पर **भारत में कर (TDS) लगता है**।

• (C) NRO खाता कर-मुक्त है जबकि NRE खाते पर 30% कर लगता है।

• (D) FCNR(B) खाता केवल चालू खाते (Current Account) के रूप में खोला जा सकता है।

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** यदि कोई NRI अपनी विदेशी कमाई को बिना विनिमय दर जोखिम (Exchange Rate Risk) के सीधे डॉलर/पाउंड/यूरो/येन में ही भारत में रखना चाहता है तो वह **FCNR(B) (केवल Term Deposit, 1–5 वर्ष, कर-मुक्त)** चुनता है; यदि विदेश की कमाई को रुपये में बदलकर कर-मुक्त रखना चाहता है तो **NRE खाता** चुनता है; और यदि भारत के भीतर होने वाली आय (किराया आदि) का प्रबंधन करना चाहता है तो **NRO खाता** (प्रति वित्तीय वर्ष $1 मिलियन तक प्रत्यावर्तन सीमा) चुनता है।

अभ्यास प्रश्न #55 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 55. बैंकिंग में विभिन्न प्रकार के जोखिमों (Risks) के अंतर्गत जब किसी बैंक का कंप्यूटर सर्वर फेल हो जाए, कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की जाए या आंतरिक प्रक्रियाओं में चूक हो जाए, तो बेसल मानदंडों के अनुसार इसे किस प्रकार का जोखिम कहा जाता है? **[RBI Grade B 2022, IBPS SO 2022, LIC AAO 2023]**

• (A) साख जोखिम (Credit Risk / Default Risk)

• (B) बाजार जोखिम (Market Risk)

• (C) **परिचालन जोखिम (Operational Risk)**

• (D) नैतिक जोखिम (Moral Hazard)

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** बेसल मानकों में तीन मुख्य जोखिम हैं: (1) **Credit Risk (साख जोखिम):** उधारकर्ता द्वारा मूलधन या ब्याज न चुकाने का जोखिम; (2) **Market Risk (बाजार जोखिम):** ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों या शेयर मूल्यों में उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि का जोखिम; और (3) **Operational Risk (परिचालन जोखिम):** अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, मानवीय त्रुटियों, धोखाधड़ी, साइबर हमलों या बाहरी घटनाओं से होने वाली हानि का जोखिम।

अभ्यास प्रश्न #56 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 56. खुदरा निवेशकों (आम नागरिकों) को सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अपना गिल्ट खाता (**Retail Direct Gilt - RDG Account**) खोलकर प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs, T-Bills, SDLs, Sovereign Gold Bonds) में निःशुल्क निवेश करने की सुविधा देने के लिए नवंबर 2021 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? **[RBI Grade B 2022, IBPS PO Mains 2022]**

• (A) आरबीआई जन निवेश योजना

• (B) प्रधानमंत्री बॉन्ड कोष योजना

• (C) भारत ट्रेजरी डायरेक्ट पोर्टल

• (D) **आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना (RBI Retail Direct Scheme)** (और इसके लिए मई 2024 में *RBI* ने '*RBI Retail Direct Mobile App*' भी लॉन्च किया है)

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या: RBI Retail Direct Scheme** के तहत कोई भी खुदरा निवेशक बिना किसी शुल्क के RBI के साथ सीधे अपना **RDG (Retail Direct Gilt) खाता** खोल सकता है और **NDS-OM** (Negotiated Dealing System - Order Matching) व प्राथमिक नीलामी में UPI या नेट बैंकिंग के माध्यम से सीधे सरकारी बॉन्ड खरीद-बेच सकता है।

अभ्यास प्रश्न #57 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 57. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की नकदी प्रवाह समस्या को हल करने के लिए उनके व्यापारिक बिलों (Trade Receivables / Invoices) को कॉर्पोरेट खरीदारों के विरुद्ध ऑनलाइन भुनाने (Discounting) हेतु RBI द्वारा अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है? **[RBI Grade B 2023, SIDBI Grade A 2023, IBPS PO Mains 2022]**

• (A) **TReDS* (Trade Receivables Discounting System) (जिसके अंतर्गत वर्तमान में RXIL, Invoicemart और M1xchange आदि प्लेटफॉर्म कार्यरत हैं)*

• (B) CERSAI (*Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest*)

• (C) SFMS (*Structured Financial Messaging System*)

• (D) CCIL (*Clearing Corporation of India Ltd.*)

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या: TReDS** एक संस्थागत इलेक्ट्रॉनिक तंत्र है जहाँ MSME विक्रेता बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों, PSUs और सरकारी विभागों पर बकाया अपने व्यापारिक बिलों (Invoices) को कई बैंकों व NBFC-Factors से प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बिना किसी संपार्श्विक के तुरंत भुना सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न #58 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 58. भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs — *MSME Development Act, 2006*) के वर्गीकरण के लिए 1 जुलाई 2020 से लागू संयुक्त मानदंड (संयंत्र व मशीनरी/उपकरण में **निवेश [Investment]** और **वार्षिक कारोबार [Annual Turnover]**) तथा केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित संशोधित (2.5 गुना निवेश व 2 गुना टर्नओवर) मानदंड क्या हैं? **[RBI Grade B 2024, IBPS PO Mains 2024, SIDBI Grade A 2024]**

• (A) केवल कर्मचारियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है।

• (B) **मूल मानदंड (2020): सूक्ष्म (Micro):** निवेश ≤ ₹1 करोड़ व टर्नओवर ≤ ₹5 करोड़; **लघु (Small):** निवेश ≤ ₹10 करोड़ व टर्नओवर ≤ ₹50 करोड़; **मध्यम (Medium):** निवेश ≤ ₹50 करोड़ व टर्नओवर ≤ ₹250 करोड़ (तथा नवीनतम बजट विस्तार में इन्हें बढ़ाकर *Micro*: ₹2.5 करोड़/₹10 करोड़, *Small*: ₹25 करोड़/₹100 करोड़ और *Medium*: ₹125 करोड़/₹500 करोड़ किया गया है)।

• (C) सूक्ष्म: ₹10 लाख तक; लघु: ₹1 करोड़ तक; मध्यम: ₹5 करोड़ तक

• (D) विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए अलग-अलग निवेश सीमाएँ रखी गई हैं।

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 2020 के सुधार में विनिर्माण (Manufacturing) और सेवा (Service) उद्यमों के बीच का भेद समाप्त कर दोनों के लिए **निवेश + टर्नओवर** का एकसमान संयुक्त सूत्र **(1–5, 10–50, 50–250 करोड़)** लागू किया गया, जिसे उच्च दक्षता और रोजगार सृजन हेतु नवीनतम बजट में **2.5 गुना निवेश व 2 गुना टर्नओवर (2.5–10, 25–100, 125–500 करोड़)** तक विस्तारित किया गया है।

अभ्यास प्रश्न #59 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 59. भारत में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs — कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत) की निगरानी के लिए अक्टूबर 2022 से लागू RBI के **'आकार-आधारित विनियमन' (Scale-Based Regulation - SBR)** ढांचे में NBFCs को कितने स्तरों (Layers) में विभाजित किया गया है? **[RBI Grade B Phase-II 2023, IBPS PO Mains 2023]**

• (A) 2 स्तर (Small Layer और Large Layer)

• (B) 3 स्तर (Tier-I, Tier-II और Tier-III)

• (C) **4 स्तर (Four Layers): (1) Base Layer (NBFC-BL)** — ₹1,000 करोड़ से कम आस्ति आकार वाली गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFCs, P2P, AA आदि; **(2) Middle Layer (NBFC-ML)** — सभी जमा स्वीकार करने वाली NBFCs (NBFC-D), ₹1,000 करोड़ व अधिक आस्ति आकार वाली NBFCs, HFCs, CICs, और **SPD/IDF**; **(3) Upper Layer (NBFC-UL)** — RBI द्वारा विशेष रूप से चिह्नित शीर्ष ~10–15 बड़ी NBFCs जिन पर बैंकों जैसे कड़े नियम लागू होते हैं; और **(4) Top Layer (NBFC-TL)** — जो सामान्यतः खाली (Empty) रहता है और केवल अत्यधिक प्रणालीगत जोखिम बढ़ने पर ही भरा जाता है।

• (D) 5 स्तर (Zone 1 से Zone 5 तक)

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** IL&FS और DHFL संकट के बाद RBI ने NBFCs के पुराने वर्गीकरण (Systemically Important vs Non-Systemically Important) को बदलकर 1 अक्टूबर 2022 से **4-स्तरीय Scale-Based Regulation (SBR)** ढांचा (**Base, Middle, Upper और Top Layer**) लागू किया है, जहाँ निचले से ऊपरी स्तर की ओर जाने पर विनियामक सख्ती क्रमिक रूप से बढ़ती जाती है।

अभ्यास प्रश्न #60 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 60. बीमा क्षेत्र की महत्वपूर्ण शब्दावली — **'एक्चुअरी' (Actuary)**, **'अंडरराइटिंग' (Underwriting)**, **'फ्री-लुक पीरियड' (Free-Look Period)** और **'सरेंडर वैल्यू' (Surrender Value)** का सही अर्थ क्या है? **[LIC AAO Mains 2023, NIACL AO 2023, UIIC AO 2024]**

• (A) एक्चुअरी: बीमा एजेंट; अंडरराइटिंग: दावा खारिज करना; फ्री-लुक पीरियड: बिना प्रीमियम के 1 वर्ष का बीमा

• (B) ये सभी शब्द केवल शेयर बाजार में डेरिवेटिव ट्रेडिंग से संबंधित हैं।

• (C) सरेंडर वैल्यू वह बोनस है जो पॉलिसी की परिपक्वता के 10 वर्ष बाद मिलता है।

• (D) **एक्चुअरी (Actuary):** वह सांख्यिकीय विशेषज्ञ जो मृत्यु दर, दुर्घटना प्रायिकता और गणितीय मॉडलों के आधार पर बीमा उत्पाद के प्रीमियम और जोखिम की गणना करता है; **अंडरराइटिंग (Underwriting):** बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी जारी करने से पूर्व प्रस्तावक के जोखिम का मूल्यांकन कर यह तय करना कि बीमा किस शर्त व प्रीमियम पर दिया जाए; **फ्री-लुक पीरियड (Free-Look Period):** पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद की वह अवधि (IRDAI के नवीनतम नियमों के अनुसार अब सभी जीवन व स्वास्थ्य पॉलिसियों के लिए **30 दिन**) जिसमें यदि ग्राहक शर्तों से संतुष्ट न हो तो पॉलिसी लौटाकर अपना प्रीमियम वापस ले सकता है; और **सरेंडर वैल्यू (Surrender Value):** पॉलिसी को परिपक्वता से पहले बीच में ही बंद करने पर बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसीधारक को दिया जाने वाला नकद मूल्य।

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** बीमा परीक्षाओं में ये चारों शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से ध्यान रखें कि IRDAI ने वर्ष 2024 के अपने मास्टर सर्कुलर में ग्राहकों के हित में **'फ्री-लुक पीरियड' (Free-Look Period)** को पहले के 15 दिनों से बढ़ाकर सभी पॉलिसियों (भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों) के लिए एकसमान **30 दिन** कर दिया है।

© IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com) — सर्वाधिकार सुरक्षित।

यह खंड **भारतीय रिज़र्व बैंक (rbi.org.in)** के आधिकारिक मौद्रिक नीति ढाँचे, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934, बेसल-III मानकों, वित्तीय समावेशन योजनाओं तथा बीमा व पूँजी बाजार विनियामकों पर आधारित उच्च-स्तरीय अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करता है, जिसे **IUC Academy (www.iucacademy.com)** के बैंकिंग एवं वित्तीय परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु तैयार किया गया है।

20.1 विस्तृत तुलनात्मक सारणियाँ

सारणी 20.1: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मात्रात्मक एवं गुणात्मक मौद्रिक नीति उपकरण तथा उनका तरलता पर प्रभाव

स्रोत: **भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति ढाँचा (rbi.org.in)**

मौद्रिक नीति उपकरण	वैधानिक आधार / परिभाषा	मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु कार्रवाई	मंदी / तरलता संकुचन में कार्रवाई	अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर प्रभाव
नीतिगत रेपो दर (Policy Repo Rate)	वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण देता है	रेपो दर में वृद्धि (महँगी मुद्रा नीति / Tightening)	रेपो दर में कटौती (सस्ती मुद्रा नीति / Accommodative)	रेपो बढ़ने पर बैंक ऋण महँगे होते हैं और बाजार की तरलता घटती है
स्थायी जमा सुविधा (SDF - अप्रैल 2022)	बिना किसी संपार्श्विक (Collateral-free) के RBI द्वारा बैंकों से अतिरिक्त तरलता अवशोषित करने की दर	SDF दर में वृद्धि (LAF कॉरिडोर का निचला तल, रेपो से 25 bps कम)	SDF दर में कमी	बैंकों की अतिरिक्त नकदी RBI के पास जमा होकर बाजार तरलता को घटाती है
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF - 2011)	अनुसूचित बैंकों द्वारा अपने SLR कोटे से थोड़ा नीचे जाकर RBI से ओवरनाइट आपातकालीन ऋण लेने की दर	MSF दर में वृद्धि (LAF कॉरिडोर की ऊपरी सीमा, रेपो से 25 bps अधिक)	MSF दर में कमी	दंडात्मक दर होने के कारण यह अंतर-बैंक कॉल मनी बाजार की अस्थिरता रोकती है
नकद आरक्षित अनुपात (CRR)	RBI अधिनियम 1934 की धारा 42(1): कुल निवल माँग व सावधि देयताओं (NDTL) का RBI के पास नकद अंश	CRR में वृद्धि	CRR में कटौती	CRR पर RBI बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता; इसके बढ़ने से तुरंत ऋण क्षमता घटती है
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24: NDTL का वह अंश जो बैंक स्वयं नकद, स्वर्ण या G-Sec में रखते हैं	SLR में वृद्धि (अधिकतम वैधानिक सीमा 40%)	SLR में कटौती	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश सुनिश्चित करता है तथा साख सृजन की सीमा बांधता है
खुले बाजार की क्रियाएँ (OMO)	RBI द्वारा द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) का क्रय और विक्रय	प्रतिभूतियों का विक्रय (Sale of G-Secs)	प्रतिभूतियों का क्रय (Purchase of G-Secs)	प्रतिभूति बेचने पर बाजार से रुपया RBI में आता है; खरीदने पर बाजार में तरलता बढ़ती है
बैंक दर (Bank Rate)	RBI अधिनियम 1934 की धारा 49: विनिमय बिलों या वाणिज्यिक पत्रों की पुनर्कटौती की मानक दीर्घकालिक दर	बैंक दर में वृद्धि (MSF दर के साथ संबद्ध)	बैंक दर में कमी	CRR/SLR के रखरखाव में चूक होने पर दंडात्मक ब्याज दर की गणना बैंक दर से जुड़ी होती है
मौद्रिक नीति समिति (MPC)	RBI अधिनियम की धारा 45ZB (2016 में गठित): 6 सदस्य (3 RBI + 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित)	मुद्रास्फीति लक्ष्य: 4% (±2% सहनशीलता बैंड अर्थात् 2% से 6%)	वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें अनिवार्य; गवर्नर को निर्णायक मत (Casting Vote) का अधिकार	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI Combined) आधारित लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT)

सारणी 20.2: भारत के वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख विनियामक व विकास वित्तीय संस्थान (DFIs)

स्रोत: **भारतीय रिज़र्व बैंक (rbi.org.in)** एवं **इंडिया कोड पोर्टल (indiacode.nic.in)**

संस्थान / विनियामक	स्थापना वर्ष एवं वैधानिक अधिनियम	मुख्यालय	सिफारिशकर्ता समिति	मुख्य विनियामक एवं विकासात्मक कार्यक्षेत्र
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	1 अप्रैल 1935 (RBI अधिनियम, 1934; राष्ट्रीयकरण: 1 जनवरी 1949)	मुंबई (प्रारंभ में कोलकाता, 1937 में मुंबई स्थानांतरित)	हिल्टन यंग आयोग (रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, 1926)	मौद्रिक नीति संचालन, करेंसी निर्गमन (धारा 22), सरकार व बैंकों का बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंधन

संस्थान / विनियामक	स्थापना वर्ष एवं वैधानिक अधिनियम	मुख्यालय	सिफारिशकर्ता समिति	मुख्य विनियामक एवं विकासात्मक कार्यक्षेत्र
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)	12 अप्रैल 1988 (वैधानिक दर्जा: 30 जनवरी 1992, SEBI अधिनियम 1992)	मुंबई (महाराष्ट्र)	नरसिंहम समिति एवं उदय कोटक/फेरवानी समिति सुधार	पूँजी बाजार, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम व निवेशक हित संरक्षण
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)	12 जुलाई 1982 (नाबार्ड अधिनियम, 1981)	मुंबई (महाराष्ट्र)	बी. शिवरामन समिति (CRAFICARD - 1979)	ग्रामीण व कृषि साख का पुनर्वित्तपोषण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण, RIDF प्रबंधन
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	2 अप्रैल 1990 (सिडबी अधिनियम, 1989)	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) वित्तपोषण तंत्र	MSME क्षेत्र का पुनर्वित्तपोषण, मुद्रा (MUDRA) योजना एवं उभरते उद्यमियों को वित्तीय सहायता
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)	1999 (IRDAI अधिनियम, 1999; निगमित: अप्रैल 2000)	हैदराबाद (तेलंगाना)	आर.एन. मल्होत्रा समिति (1993 - बीमा क्षेत्र सुधार)	जीवन बीमा एवं साधारण बीमा कंपनियों का विनियमन, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)	2003 (वैधानिक दर्जा: PFRDA अधिनियम, 2013)	नई दिल्ली	ओएसीस (OASIS) परियोजना रिपोर्ट	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एवं अटल पेंशन योजना (APY) का विनियमन और विकास
राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)	9 जुलाई 1988 (राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987)	नई दिल्ली	सी. रंगराजन उच्च-स्तरीय समिति (100% भारत सरकार के स्वामित्व में)	आवास वित्त कंपनियों (HFCs) का पुनर्वित्तपोषण एवं आवासीय मूल्य सूचकांक (RESIDEX) जारी करना
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank)	1 जनवरी 1982 (एक्जिम बैंक अधिनियम, 1981)	मुंबई (महाराष्ट्र)	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण ढाँचा	भारत के विदेशी व्यापार (निर्यातकों व आयातकों) को ऋण एवं लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) प्रदान करना

सारणी 20.3: भारत में बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख समितियाँ, उनके अध्यक्ष एवं ऐतिहासिक सुधार

स्रोत: **भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन एवं अभिलेख (rbi.org.in)**

समिति का नाम	गठन वर्ष	मुख्य विषय / सुधार क्षेत्र	लागू की गई प्रमुख सिफारिशें
एम. नरसिंहम समिति (प्रथम एवं द्वितीय)	1991 एवं 1998	वित्तीय प्रणाली एवं बैंकिंग क्षेत्र सुधार	CRR व SLR में चरणबद्ध कमी, पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR), NPA वर्गीकरण व SARFAESI अधिनियम (2002) की नींव
उर्जित पटेल समिति	2013–2014	मौद्रिक नीति ढाँचे का सुदृढ़ीकरण और पुनरीक्षण	WPI के स्थान पर CPI (संयुक्त) को मुख्य मुद्रास्फीति सूचकांक बनाना, 4% (±2%) लक्ष्य तथा 6-सदस्यीय MPC का गठन
नचिकेत मोर समिति	2013–2014	छोटे व्यवसायों व निम्न आय परिवारों हेतु व्यापक वित्तीय सेवाएँ	विभेदित बैंकों (Differentiated Banks) के रूप में 'भुगतान बैंक' (Payments Banks) की स्थापना की सिफारिश
उषा थोरात समिति	2014	लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks) लाइसेंसिंग मानदंड	असंगठित क्षेत्र, छोटे किसानों व सूक्ष्म उद्योगों को ऋण देने हेतु 'लघु वित्त बैंकों' (SFBs) की स्थापना (75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण)
पी.जे. नायक समिति	2014	भारत में बैंकों के बोर्डों के शासन (Governance) की समीक्षा	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' (BBB, अब FSIB - वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो) का गठन
नंदन नीलेकणी समिति	2019	डिजिटल भुगतानों को गहरा करना (Deepening of Digital Payments)	24×7 NEFT/RTGS सुविधा, डिजिटल भुगतान पर MDR शुल्क का युक्तिकरण तथा वित्तीय समावेशन कोष का विस्तार
एम. दामोदरन समिति	2011	बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार (Customer Service in Banks)	बचत खातों में न्यूनतम शेष न होने पर अनुचित दंड रोकना, बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (BSBDA) व त्वरित शिकायत निवारण
के.वी. कामथ समिति	2020	कोविड-19 प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन (Loan Restructuring) हेतु वित्तीय मानदंड	कॉर्पोरेट ऋणों के समाधान हेतु 26 दबावग्रस्त क्षेत्रों की पहचान एवं 5 वित्तीय अनुपातों का निर्धारण

20.2 व्याख्या सहित उच्च-स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रश्न 76 से 100)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 76. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (rbi.org.in) की धारा 45ZB के अंतर्गत गठित 'मौद्रिक नीति समिति' (MPC) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पूर्णतः सत्य है?

• (क) इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं (RBI गवर्नर सहित 3 सदस्य RBI से और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष के लिए नामित), तथा भारत के लिए लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (±2% सहनशीलता बैंड अर्थात् 2% से 6%) निर्धारित है

• (ख) इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं

• (ग) यह थोक मूल्य सूचकांक (WPI) को मुद्रास्फीति के मुख्य मानक के रूप में प्रयोग करती है

• (घ) MPC की बैठक वर्ष में केवल दो बार होना अनिवार्य है और गवर्नर के पास कोई निर्णायक मत (Casting Vote) नहीं होता

• **सही उत्तर:** (क) इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं (RBI गवर्नर सहित 3 सदस्य RBI से और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष के लिए नामित), तथा भारत के लिए लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (±2% सहनशीलता बैंड अर्थात् 2% से 6%) निर्धारित है

• **विस्तृत व्याख्या:** उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर 2016 में संशोधित RBI अधिनियम की धारा 45ZB के तहत 6-सदस्यीय MPC का गठन किया गया। RBI गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और मत बराबर (Tie) होने की स्थिति में उन्हें दूसरा या निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार है। यदि लगातार तीन तिमाहियों तक CPI मुद्रास्फीति 6% से ऊपर या 2% से नीचे रहती है, तो इसे लक्ष्य की विफलता माना जाता है (rbi.org.in)।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 77. भारत में करेंसी नोटों के निर्गमन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 1957 से किस प्रणाली का पालन किया जा रहा है और इसके अंतर्गत कुल कितने मूल्य का न्यूनतम कोष रखना अनिवार्य है?

• (क) आनुपातिक कोष प्रणाली – 400 करोड़ रुपये

• (ख) न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) – कुल 200 करोड़ रुपये (जिसमें न्यूनतम 115 करोड़ रुपये का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियाँ अनिवार्य हैं)

• (ग) पूर्ण स्वर्णमान प्रणाली – 500 करोड़ रुपये का स्वर्ण

• (घ) विशेष आहरण अधिकार प्रणाली – 1000 करोड़ रुपये

• **सही उत्तर:** (ख) न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) – कुल 200 करोड़ रुपये (जिसमें न्यूनतम 115 करोड़ रुपये का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियाँ अनिवार्य हैं)

• **विस्तृत व्याख्या:** RBI अधिनियम, 1934 की धारा 22 के तहत RBI को एक रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर (जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं और जिन पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं) सभी बैंक नोट जारी करने का एकाधिकार है। 1957 से लागू न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत RBI को कुल 200 करोड़ रुपये का आरक्षित कोष (115 करोड़ स्वर्ण + 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूतियाँ) बनाए रखना होता है (rbi.org.in)।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 78. बैंकिंग शब्दावली में 'गैर-निष्पादित परिसंपत्ति' (Non-Performing Asset - NPA) उस ऋण या अग्रिम को कहा जाता है जिस पर मूलधन या ब्याज की किस्त कितने दिनों की अवधि तक अतिदेय (Overdue) बनी रहती है?

• (क) 30 दिन से अधिक

• (ख) 60 दिन से अधिक

• (ग) 90 दिन से अधिक (तथा कृषि फसलों के ऋण के मामले में दो फसल मौसमों या एक दीर्घ फसल मौसम तक)

• (घ) 180 दिन से अधिक

• **सही उत्तर:** (ग) 90 दिन से अधिक (तथा कृषि फसलों के ऋण के मामले में दो फसल मौसमों या एक दीर्घ फसल मौसम तक)

• **विस्तृत व्याख्या:** भारतीय रिज़र्व बैंक (rbi.org.in) के विवेकपूर्ण मानदंडों (Prudential Norms) के अनुसार जब किसी सावधि ऋण पर ब्याज या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है, तो उसे NPA घोषित किया जाता है। इसके पश्चात अवधि के आधार पर इसे अवमानक परिसंपत्ति (Sub-standard: ≤12 माह), संदिग्ध परिसंपत्ति (Doubtful: >12 माह) और हानि परिसंपत्ति (Loss Asset) में वर्गीकृत किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 79. 'सरफेसी अधिनियम, 2002' (SARFAESI Act, 2002) का पूर्ण रूप क्या है और यह बैंकों को क्या प्रमुख वैधानिक अधिकार प्रदान करता है?

• (क) Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act — यह बैंकों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना (गैर-कृषि भूमि पर) चूककर्ता ऋणी की गिरवी रखी गई प्रतिभूति को जब्त कर बेचने का अधिकार देता है

• (ख) Savings and Rural Financial Assistance for Economic Security in India Act — यह ग्रामीण किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण देता है

• (ग) Statutory Audit and Regulation of Financial Assets in Scheduled Institutions Act — यह बैंकों के लेखांकन की जाँच करता है

• (घ) System for Automated Recovery of Foreign Exchange and Securities in India Act — यह विदेशी मुद्रा की वसूली करता है

• **सही उत्तर:** (क) Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act — यह बैंकों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना (गैर-कृषि भूमि पर) चूककर्ता ऋणी की गिरवी रखी गई प्रतिभूति को जब्त कर बेचने का अधिकार देता है

• **विस्तृत व्याख्या:** इंडिया कोड पोर्टल (indiacode.nic.in) के अनुसार सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत यदि कोई सुरक्षित ऋण (Secured Loan) NPA बन जाता है और बकाया राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, तो बैंक धारा 13(2) के तहत 60 दिन का नोटिस देकर संपार्श्विक संपत्ति (कृषि भूमि को छोड़कर) का कब्जा ले सकता है या उसे परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) को बेच सकता है।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 80. भारतीय रिज़र्व बैंक के 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण' (Priority Sector Lending - PSL) दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (और विदेशी बैंकों जिनकी 20 या अधिक शाखाएँ हैं) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs)/लघु वित्त बैंकों (SFBs) के लिए अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का क्रमशः कितना प्रतिशत PSL में देना अनिवार्य है?

• (क) वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40% तथा RRBs और SFBs के लिए 75%

• (ख) वाणिज्यिक बैंकों के लिए 25% तथा RRBs के लिए 50%

• (ग) सभी प्रकार के बैंकों के लिए समान रूप से 40%

• (घ) वाणिज्यिक बैंकों के लिए 50% तथा SFBs के लिए 60%

• **सही उत्तर:** (क) वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40% तथा RRBs और SFBs के लिए 75%

• **विस्तृत व्याख्या:** RBI के PSL मानदंडों के अंतर्गत 8 प्रमुख श्रेणियाँ हैं (कृषि, MSME, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य कमजोर वर्ग)। घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को ANBC का 40% (जिसमें 18% कृषि और 12% कमजोर वर्ग शामिल है) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व लघु वित्त बैंकों को ANBC का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना अनिवार्य है (rbi.org.in)।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 81. नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों पर स्थापित 'भुगतान बैंकों' (Payments Banks) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिबंध लागू होता है?

• (क) वे प्रति ग्राहक 2 लाख रुपये तक की माँग जमा (बचत व चालू खाता) स्वीकार कर सकते हैं, किंतु वे किसी भी प्रकार का ऋण (Loans) या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते

• (ख) वे केवल सावधि जमा (Fixed Deposit) स्वीकार कर सकते हैं, बचत खाता नहीं खोल सकते

• (ग) उन्हें CRR और SLR रखने से पूर्णतः छूट प्राप्त है

• (घ) वे एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकते

• **सही उत्तर:** (क) वे प्रति ग्राहक 2 लाख रुपये तक की माँग जमा (बचत व चालू खाता) स्वीकार कर सकते हैं, किंतु वे किसी भी प्रकार का ऋण (Loans) या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते

• **विस्तृत व्याख्या:** भुगतान बैंक (जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) प्रति ग्राहक अधिकतम 2 लाख रुपये तक की माँग जमा स्वीकार कर सकते हैं तथा एटीएम/डेबिट कार्ड व ऑनलाइन भुगतान सेवाएँ दे सकते हैं। किंतु ऋण जोखिम से बचने के लिए वे कोई भी ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते और न ही अनिवासी भारतीय (NRI) जमा स्वीकार कर सकते हैं (**rbi.org.in**)।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 82. भारत में 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों' (Regional Rural Banks - RRBs) की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी तथा इनमें केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक (Sponsor Bank) और राज्य सरकार की पूँजी हिस्सेदारी का अनुपात क्या होता है?

• (क) एम. नरसिंहम कार्यदल – 50% : 35% : 15% (केंद्र सरकार : प्रायोजक बैंक : राज्य सरकार)

• (ख) शिवरामन समिति – 60% : 20% : 20%

• (ग) गाडगिल समिति – 50% : 25% : 25%

• (घ) गोरवाला समिति – 40% : 40% : 20%

• **सही उत्तर:** (क) एम. नरसिंहम कार्यदल – 50% : 35% : 15% (केंद्र सरकार : प्रायोजक बैंक : राज्य सरकार)

• **विस्तृत व्याख्या:** एम. नरसिंहम कार्यदल (1975) की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 'प्रथमा ग्रामीण बैंक' (मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश; प्रायोजक: सिंडिकेट बैंक) स्थापित किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत इसमें केंद्र सरकार की 50%, प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक की 35% और संबंधित राज्य सरकार की 15% अंशपूँजी होती है (**rbi.org.in**)।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 83. 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम' (DICGC - भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था) द्वारा किसी बैंक के विफल होने या मोरेटोरियम लगने पर प्रति जमाकर्ता (मूलधन एवं ब्याज सहित) अधिकतम कितनी जमा राशि का बीमा कवर प्रदान किया जाता है?

• (क) 1 लाख रुपये

• (ख) 2 लाख रुपये

• (ग) 5 लाख रुपये (तथा मोरेटोरियम लगने के 90 दिनों के भीतर भुगतान का प्रावधान)

• (घ) 10 लाख रुपये

• **सही उत्तर:** (ग) 5 लाख रुपये (तथा मोरेटोरियम लगने के 90 दिनों के भीतर भुगतान का प्रावधान)

• **विस्तृत व्याख्या:** DICGC अधिनियम, 1961 (तथा 2020 और 2021 के संशोधनों) के अंतर्गत भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों की शाखाओं, स्थानीय क्षेत्र बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और सहकारी बैंकों में प्रत्येक जमाकर्ता को एक ही बैंक की सभी शाखाओं में रखे गए बचत, चालू, सावधि व आवर्ती खातों पर संयुक्त रूप से अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा संरक्षण प्राप्त है (**rbi.org.in**)।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 84. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग पर्यवेक्षण हेतु 'बेसल-III' (Basel-III) मानकों के तीन मुख्य स्तंभ (Three Pillars) कौन-से हैं और भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR - Capital to Risk-Weighted Assets Ratio) कितना निर्धारित है?

• (क) तीन स्तंभ: (1) न्यूनतम पूँजी आवश्यकता, (2) पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया, (3) बाजार अनुशासन; तथा भारत में RBI द्वारा निर्धारित न्यूनतम CRAR 9% (2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर सहित कुल 11.5%)

• (ख) तीन स्तंभ: जमा वृद्धि, शाखा विस्तार, ऋण माफी; तथा न्यूनतम CRAR 6%

• (ग) तीन स्तंभ: स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा, सरकारी बॉन्ड; तथा न्यूनतम CRAR 15%

• (घ) तीन स्तंभ: खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, कृषि बैंकिंग; तथा न्यूनतम CRAR 4%

• **सही उत्तर:** (क) तीन स्तंभ: (1) न्यूनतम पूँजी आवश्यकता, (2) पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया, (3) बाजार अनुशासन; तथा भारत में RBI द्वारा निर्धारित न्यूनतम CRAR 9% (2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर सहित कुल 11.5%)

• **विस्तृत व्याख्या:** स्विट्ज़रलैंड के बेसल स्थित 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स' (BIS) की बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति (BCBS) ने बेसल-III मानक जारी किए। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानक न्यूनतम 8% CRAR का है, वहीं **भारतीय रिज़र्व बैंक (rbi.org.in)** ने भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के लिए अधिक सुदृढ़ता हेतु 9% न्यूनतम CRAR (+ 2.5% पूँजी संरक्षण बफर = 11.5%) निर्धारित किया है।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 85. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणालियों के बीच मुख्य परिचालन अंतर क्या है?

• (क) NEFT में निधियों का निपटान आधे-आधे घंटे के बैचों में आस्थगित निवल निपटान (DNS) आधार पर होता है और इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है; जबकि RTGS में लेनदेन का वास्तविक समय (Real-Time) में सकल आधार पर व्यक्तिगत निपटान होता है और इसकी न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपये है

• (ख) NEFT में न्यूनतम सीमा 5 लाख रुपये है और RTGS में कोई न्यूनतम सीमा नहीं है

• (ग) NEFT केवल कार्यदिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है, जबकि RTGS केवल रविवार को चलता है

• (घ) NEFT और RTGS दोनों का संचालन सेबी (SEBI) द्वारा किया जाता है

• **सही उत्तर:** (क) NEFT में निधियों का निपटान आधे-आधे घंटे के बैचों में आस्थगित निवल निपटान (DNS) आधार पर होता है और इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है; जबकि RTGS में लेनदेन का वास्तविक समय (Real-Time) में सकल आधार पर व्यक्तिगत निपटान होता है और इसकी न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपये है

• **विस्तृत व्याख्या:** RBI द्वारा संचालित NEFT (Deferred Net Settlement) में कुल 48 अर्ध-घंटे के बैचों में 24×7×365 निधि अंतरण होता है तथा इसकी न्यूनतम व अधिकतम राशि की कोई वैधानिक सीमा नहीं है। इसके विपरीत बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए बने RTGS (यह भी दिसंबर 2020 से 24×7×365 उपलब्ध है) में न्यूनतम अंतरण राशि 2,00,000 रुपये है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है (**rbi.org.in**)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 86. भारत में खुदरा भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा वर्ष 2008 में किस छाता संगठन (Umbrella Organisation) की स्थापना की गई, जिसने UPI, RuPay, IMPS और BHIM का विकास किया?

• (क) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI - National Payments Corporation of India)

• (ख) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL)

• (ग) वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवा संस्थान (IFTAS)

• (घ) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT)

• **सही उत्तर:** (क) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI - National Payments Corporation of India)

• **विस्तृत व्याख्या:** भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत RBI और IBA की पहल पर दिसंबर 2008 में कंपनी अधिनियम की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 - गैर-लाभकारी कंपनी) के रूप में NPCI की स्थापना की गई। इसी ने UPI (2016), IMPS, RuPay कार्ड, NACH, AePS और भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) विकसित किए (**rbi.org.in**)।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 87. मुद्रा आपूर्ति (Money Supply) के चार मानकों (M_1, M_2, M_3, M_4) में किसे 'संकीर्ण मुद्रा' (Narrow Money) और किसे 'व्यापक मुद्रा' (Broad Money / समग्र मौद्रिक संसाधन) कहा जाता है?

• (क) M_1 को संकीर्ण मुद्रा (जनता के पास करेंसी + बैंकों के पास माँग जमा + RBI के पास अन्य जमा) और M_3 को व्यापक मुद्रा (M_1 + बैंकों के पास सावधि जमा) कहा जाता है

• (ख) M_3 को संकीर्ण मुद्रा और M_1 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है

• (ग) केवल सिक्कों को संकीर्ण मुद्रा और डाकघर जमा को व्यापक मुद्रा कहा जाता है

• (घ) M_4 सर्वाधिक तरल मुद्रा है और M_1 सबसे कम तरल मुद्रा है

• **सही उत्तर:** (क) M_1 को संकीर्ण मुद्रा (जनता के पास करेंसी + बैंकों के पास माँग जमा + RBI के पास अन्य जमा) और M_3 को व्यापक मुद्रा (M_1 + बैंकों के पास सावधि जमा) कहा जाता है

• **विस्तृत व्याख्या:** एनसीईआरटी अर्थशास्त्र एवं RBI मानकों (rbi.org.in) के अनुसार M_1 = CU (करेंसी नोट व सिक्के) + DD (वाणिज्यिक बैंकों की निवल माँग जमा) + OD (RBI के पास अन्य जमा) सर्वाधिक तरल होने के कारण 'संकीर्ण मुद्रा' कहलाती है। जब M_1 में वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमा (Time Deposits) जोड़ दी जाती है, तो M_3 प्राप्त होता है जिसे 'व्यापक मुद्रा' (Broad Money) या समग्र मौद्रिक संसाधन कहा जाता है; वहीं M_0 को 'आरक्षित मुद्रा' (Reserve Money / High-Powered Money) कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 88. मुद्रा बाजार (Money Market) और पूँजी बाजार (Capital Market) के मध्य मूलभूत अंतर क्या है तथा 'ट्रेजरी बिल' (Treasury Bills - T-Bills) किन अवधियों के लिए जारी किए जाते हैं?

• (क) मुद्रा बाजार 1 वर्ष तक की अल्पकालिक निधियों का बाजार है (जिसका विनियामक RBI है) और पूँजी बाजार 1 वर्ष से अधिक की दीर्घकालिक निधियों का बाजार है (जिसका विनियामक SEBI है); भारत सरकार द्वारा T-Bills तीन अवधियों—91 दिन, 182 दिन और 364 दिन—के लिए जारी किए जाते हैं

• (ख) मुद्रा बाजार दीर्घकालिक शेयरों का बाजार है और T-Bills 5 वर्ष व 10 वर्ष के लिए जारी होते हैं

• (ग) राज्य सरकारें भी ट्रेजरी बिल जारी कर सकती हैं और इन पर निश्चित कूपन ब्याज मिलता है

• (घ) वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper) केवल किसानों द्वारा जारी किए जाते हैं

• **सही उत्तर:** (क) मुद्रा बाजार 1 वर्ष तक की अल्पकालिक निधियों का बाजार है (जिसका विनियामक RBI है) और पूँजी बाजार 1 वर्ष से अधिक की दीर्घकालिक निधियों का बाजार है (जिसका विनियामक SEBI है); भारत सरकार द्वारा T-Bills तीन अवधियों—91 दिन, 182 दिन और 364 दिन—के लिए जारी किए जाते हैं

• **विस्तृत व्याख्या:** मुद्रा बाजार के प्रमुख लिखतों में ट्रेजरी बिल (केवल केंद्र सरकार द्वारा 91, 182 और 364 दिन की परिपक्वता के लिए सममूल्य से बट्टे/Discount पर जारी शून्य-कूपन प्रतिभूतियाँ; न्यूनतम राशि 25,000 रुपये), वाणिज्यिक पत्र (CP - उच्च रेटिंग वाली कंपनियों द्वारा जारी असुरक्षित वचन पत्र), जमा प्रमाणपत्र (CD - बैंकों द्वारा जारी) तथा कॉल/नोटिस मनी शामिल हैं (rbi.org.in)।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 89. जब भारत सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अस्थायी रूप से प्राप्ति और व्यय के बीच असंतुलन उत्पन्न होता है, तो उस अंतर को पाटने के लिए RBI द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली अल्पकालिक अग्रिम सुविधा को क्या कहा जाता है?

• (क) अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances - WMA)

• (ख) दीर्घकालिक रेपो परिचालन (LTRO)

• (ग) बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS)

• (घ) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)

• **सही उत्तर:** (क) अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances - WMA)

• **विस्तृत व्याख्या:** RBI अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अंतर्गत वर्ष 1997 में एडहॉक ट्रेजरी बिलों की प्रणाली समाप्त कर 'अर्थोपाय अग्रिम' (WMA) शुरू किया गया। यह केंद्र और राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी बेमेल (Temporary Mismatches) को पूरा करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की सुविधा है, जिस पर नीतिगत रेपो दर के बराबर ब्याज लगता है (rbi.org.in)।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 90. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) के अंतर्गत 'वचन पत्र' (Promissory Note), 'विनिमय बिल' (Bill of Exchange) और 'चेक' (Cheque) का उल्लेख क्रमशः किन धाराओं में है तथा चेक अनादरण (Cheque Bounce) के दंड का प्रावधान किस धारा में है?

- (क) धारा 4 (वचन पत्र), धारा 5 (विनिमय बिल), धारा 6 (चेक) तथा धारा 138 (खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस होने पर दंड)
- (ख) धारा 10, धारा 11, धारा 12 तथा धारा 420
- (ग) धारा 1, धारा 2, धारा 3 तथा धारा 144
- (घ) धारा 20, धारा 25, धारा 30 तथा धारा 302
- **सही उत्तर:** (क) धारा 4 (वचन पत्र), धारा 5 (विनिमय बिल), धारा 6 (चेक) तथा धारा 138 (खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस होने पर दंड)
- **विस्तृत व्याख्या:** इंडिया कोड पोर्टल (indiacode.nic.in) के अनुसार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4 में वचन पत्र, धारा 5 में विनिमय बिल और धारा 6 में चेक (जो किसी निर्दिष्ट बैंकर पर लिखा गया विनिमय बिल है) को परिभाषित किया गया है। धारा 138 के अंतर्गत खाते में अपर्याप्त शेष के कारण चेक अनादृत होने पर अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास या चेक राशि के दोगुने तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 91. 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' (PMMY - Micro Units Development and Refinance Agency) के अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों की 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' श्रेणियों की ऋण सीमाएँ क्या हैं?

- (क) शिशु: 50,000 रुपये तक; किशोर: 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक; तरुण: 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक (तथा 'तरुण प्लस' श्रेणी में पूर्व के सफल तरुण ऋणधारकों हेतु 20 लाख रुपये तक)
- (ख) शिशु: 10,000 रुपये तक; किशोर: 1 लाख रुपये तक; तरुण: 5 लाख रुपये तक
- (ग) शिशु: 1 लाख रुपये तक; किशोर: 10 लाख रुपये तक; तरुण: 50 लाख रुपये तक
- (घ) तीनों श्रेणियों में समान रूप से 25 लाख रुपये तक
- **सही उत्तर:** (क) शिशु: 50,000 रुपये तक; किशोर: 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक; तरुण: 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक (तथा 'तरुण प्लस' श्रेणी में पूर्व के सफल तरुण ऋणधारकों हेतु 20 लाख रुपये तक)
- **विस्तृत व्याख्या:** 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) में उद्यम के विकास चरण के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियाँ हैं—शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,001 से ₹5 लाख तक) और तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख तक)। इसके अतिरिक्त बजट घोषणा के तहत जिन उद्यमियों ने पूर्व में 'तरुण' श्रेणी का ऋण लेकर सफलतापूर्वक चुका दिया है, उनके लिए 'तरुण प्लस' श्रेणी में ऋण सीमा ₹20 लाख तक बढ़ाई गई है (rbi.org.in)।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 92. बीमा के मूलभूत सिद्धांतों में 'परम सद्भाव का सिद्धांत' (Principle of Utmost Good Faith / Uberrimae Fidei) और 'क्षतिपूर्ति का सिद्धांत' (Principle of Indemnity) का क्या अर्थ है?

- (क) परम सद्भाव के सिद्धांत के अनुसार बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति दोनों को अनुबंध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का सत्य एवं पूर्ण प्रकटीकरण करना अनिवार्य है; जबकि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत (जो जीवन बीमा को छोड़कर अग्नि व समुद्री बीमा पर लागू होता है) के अनुसार बीमा का उद्देश्य केवल वास्तविक वित्तीय हानि की भरपाई करना है, लाभ कमाना नहीं
- (ख) क्षतिपूर्ति का सिद्धांत केवल जीवन बीमा पर लागू होता है और साधारण बीमा पर लागू नहीं होता
- (ग) बीमायोग्य हित (Insurable Interest) की आवश्यकता किसी भी बीमा अनुबंध में नहीं होती
- (घ) आसनस्थ कारण (Causa Proxima) का सिद्धांत केवल शेयर बाजार में लागू होता है
- **सही उत्तर:** (क) परम सद्भाव के सिद्धांत के अनुसार बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति दोनों को अनुबंध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का सत्य एवं पूर्ण प्रकटीकरण करना अनिवार्य है; जबकि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत (जो जीवन बीमा को छोड़कर अग्नि व समुद्री बीमा पर लागू होता है) के अनुसार बीमा का उद्देश्य केवल वास्तविक वित्तीय हानि की भरपाई करना है, लाभ कमाना नहीं

• **विस्तृत व्याख्या:** बीमा विधि के अंतर्गत प्रमुख सिद्धांत हैं—(1) परम सद्भाव (Uberrimae Fidei), (2) बीमायोग्य हित (Insurable Interest), (3) क्षतिपूर्ति (Indemnity - मानव जीवन का मूल्यांकन मुद्रा में संभव न होने से जीवन बीमा क्षतिपूर्ति अनुबंध नहीं बल्कि आकस्मिक अनुबंध है), (4) प्रस्थापन या अधिकार समर्पण (Subrogation), (5) अंशदान (Contribution) और (6) निकटतम कारण (Causa Proxima) (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 93. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) के राष्ट्रीयकरण के दो बड़े चरण कब संपन्न हुए थे?

• (क) प्रथम चरण: 19 जुलाई 1969 (14 बड़े वाणिज्यिक बैंक जिनकी जमा राशि ₹50 करोड़ या अधिक थी); द्वितीय चरण: 15 अप्रैल 1980 (6 अन्य बैंक जिनकी जमा राशि ₹200 करोड़ या अधिक थी)

• (ख) प्रथम चरण: 1 जनवरी 1949 (10 बैंक); द्वितीय चरण: 1 जुलाई 1955 (8 बैंक)

• (ग) प्रथम चरण: 1975 (14 बैंक); द्वितीय चरण: 1991 (6 बैंक)

• (घ) प्रथम चरण: 1965 (12 बैंक); द्वितीय चरण: 1985 (4 बैंक)

• **सही उत्तर:** (क) प्रथम चरण: 19 जुलाई 1969 (14 बड़े वाणिज्यिक बैंक जिनकी जमा राशि ₹50 करोड़ या अधिक थी); द्वितीय चरण: 15 अप्रैल 1980 (6 अन्य बैंक जिनकी जमा राशि ₹200 करोड़ या अधिक थी)

• **विस्तृत व्याख्या:** 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) बनाया गया। इसके पश्चात वित्तीय समावेशन व कृषि-प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु 19 जुलाई 1969 को ₹50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 निजी बैंकों का और 15 अप्रैल 1980 को ₹200 करोड़ से अधिक जमा वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया (**rbi.org.in**)।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 94. बैंक खातों के संदर्भ में 'नोस्ट्रो खाता' (Nostro Account) और 'वोस्ट्रो खाता' (Vostro Account) का सही अर्थ क्या है?

• (क) नोस्ट्रो खाता ('हमारा खाता आपके पास'): किसी भारतीय बैंक द्वारा विदेशी देश में किसी विदेशी बैंक के पास विदेशी मुद्रा में खोला गया खाता; वोस्ट्रो खाता ('आपका खाता हमारे पास'): किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में किसी भारतीय बैंक के पास भारतीय रुपये (INR) में खोला गया खाता

• (ख) नोस्ट्रो खाता किसानों का बचत खाता है और वोस्ट्रो खाता छात्रों का छात्रवृत्ति खाता है

• (ग) दोनों खाते केवल भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच खोले जाते हैं

• (घ) नोस्ट्रो खाता भारतीय रुपये में और वोस्ट्रो खाता केवल स्वर्ण में रखा जाता है

• **सही उत्तर:** (क) नोस्ट्रो खाता ('हमारा खाता आपके पास'): किसी भारतीय बैंक द्वारा विदेशी देश में किसी विदेशी बैंक के पास विदेशी मुद्रा में खोला गया खाता; वोस्ट्रो खाता ('आपका खाता हमारे पास'): किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में किसी भारतीय बैंक के पास भारतीय रुपये (INR) में खोला गया खाता

• **विस्तृत व्याख्या:** लैटिन शब्द 'Nostro' का अर्थ 'हमारा' (Our account with you) है—जैसे SBI द्वारा न्यूयॉर्क के सिटीबैंक में अमेरिकी डॉलर (USD) में रखा गया खाता। वहीं 'Vostro' का अर्थ 'आपका' (Your account with us) है—जैसे विदेशी बैंक द्वारा भारत में रुपये के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान (INR Trade Settlement) हेतु किसी भारतीय AD-बैंक में खोला गया विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (SRVA) (**rbi.org.in**)।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 95. चेक के प्रकारों में 'बियरर चेक' (Bearer Cheque), 'ऑर्डर चेक' (Order Cheque), 'क्रॉस्ड चेक' (Crossed Cheque) और 'स्टेल चेक' (Stale Cheque) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

• (क) क्रॉस्ड चेक (जिसके बाएँ ऊपरी कोने पर दो समानांतर तिरछी रेखाएँ खींची होती हैं) का भुगतान काउंटर पर नकद नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल बैंक खाते के माध्यम से होता है; तथा जारी होने की तिथि से 3 माह की अवधि बीत जाने के बाद चेक 'स्टेल चेक' (कालबाधित चेक) बन जाता है

• (ख) स्टेल चेक की वैधता जारी होने की तिथि से 6 माह तक रहती है

• (ग) क्रॉस्ड चेक का भुगतान बैंक काउंटर पर किसी भी व्यक्ति को नकद दिया जा सकता है

• (घ) पोस्ट-डेटेड चेक का भुगतान उस पर अंकित भविष्य की तारीख से पहले भी किया जा सकता है

• **सही उत्तर:** (क) क्रॉस्ड चेक (जिसके बाएँ ऊपरी कोने पर दो समानांतर तिरछी रेखाएँ खींची होती हैं) का भुगतान काउंटर पर नकद नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल बैंक खाते के माध्यम से होता है; तथा जारी होने की तिथि से 3 माह की अवधि बीत जाने के बाद चेक 'स्टेल चेक' (कालबाधित चेक) बन जाता है

• **विस्तृत व्याख्या:** भारतीय रिज़र्व बैंक (rbi.org.in) के निर्देशों (1 अप्रैल 2012 से प्रभावी) के अनुसार भारत में चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर और बैंकर चेक की वैधता अवधि उन पर अंकित जारी करने की तिथि से 3 माह होती है। 3 माह के बाद वह 'स्टेल चेक' (Stale Cheque) हो जाता है और बैंक उसका भुगतान नहीं करता।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 96. 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई' (Prompt Corrective Action - PCA) ढाँचा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किन बैंकों पर और किन तीन मुख्य वित्तीय मापदंडों के कमजोर होने पर लागू किया जाता है?

• (क) जब किसी वाणिज्यिक बैंक का (1) पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR), (2) परिसंपत्ति गुणवत्ता (Net NPA अनुपात) और (3) उत्तोलन अनुपात (Tier-I Leverage Ratio) निर्धारित जोखिम सीमाओं (Risk Thresholds 1, 2, 3) का उल्लंघन करते हैं

• (ख) जब कोई बैंक नई एटीएम मशीनें लगाता है

• (ग) जब किसी बैंक का शुद्ध लाभ 50% से अधिक बढ़ जाता है

• (घ) केवल विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाले डाकघरों पर

• **सही उत्तर:** (क) जब किसी वाणिज्यिक बैंक का (1) पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR), (2) परिसंपत्ति गुणवत्ता (Net NPA अनुपात) और (3) उत्तोलन अनुपात (Tier-I Leverage Ratio) निर्धारित जोखिम सीमाओं (Risk Thresholds 1, 2, 3) का उल्लंघन करते हैं

• **विस्तृत व्याख्या:** RBI का PCA ढाँचा एक प्रारंभिक हस्तक्षेप पर्यवेक्षी तंत्र है। जब किसी बैंक की पूँजी (CRAR/CET-1), परिसंपत्ति गुणवत्ता (NNPA) या उत्तोलन अनुपात (Leverage Ratio) कमजोर पड़ते हैं, तो RBI उस बैंक को PCA के अंतर्गत रखकर लाभांश वितरण, शाखा विस्तार, प्रबंधन पारिश्रमिक और उच्च-जोखिम ऋण वितरण पर प्रतिबंध लगा सकता है (rbi.org.in)।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 97. भारतीय रिज़र्व बैंक की 'एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' (Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2021) किस सिद्धांत पर आधारित है और इसमें किन पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय किया गया?

• (क) 'एक राष्ट्र, एक लोकपाल' (One Nation, One Ombudsman) के सिद्धांत पर — इसमें बैंकिंग लोकपाल योजना (2006), NBFC लोकपाल योजना (2018) और डिजिटल लेनदेन लोकपाल योजना (2019) को एकीकृत कर चंडीगढ़ में केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) स्थापित किया गया

• (ख) इसमें केवल बीमा और शेयर बाजार की शिकायतें सुनी जाती हैं

• (ग) इसमें शिकायत दर्ज करने के लिए ग्राहक को ₹5,000 का शुल्क देना पड़ता है

• (घ) यह योजना केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू होती है, निजी बैंकों या NBFCs पर नहीं

• **सही उत्तर:** (क) 'एक राष्ट्र, एक लोकपाल' (One Nation, One Ombudsman) के सिद्धांत पर — इसमें बैंकिंग लोकपाल योजना (2006), NBFC लोकपाल योजना (2018) और डिजिटल लेनदेन लोकपाल योजना (2019) को एकीकृत कर चंडीगढ़ में केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) स्थापित किया गया

• **विस्तृत व्याख्या:** नवंबर 2021 में प्रारंभ 'आरबीआई-एकीकृत लोकपाल योजना' ने क्षेत्राधिकार की सीमाओं को समाप्त कर 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' की व्यवस्था लागू की। यदि विनियमित संस्था (बैंक, NBFC, भुगतान प्रणाली ऑपरेटर या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी) शिकायत के 30 दिनों के भीतर समाधान नहीं करती, तो ग्राहक निःशुल्क CMS पोर्टल (cms.rbi.org.in) या टोल-फ्री नंबर 14448 पर शिकायत दर्ज कर सकता है (rbi.org.in)।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 98. बैंकिंग और कराधान में प्रयुक्त 'IFSC', 'MICR' और 'PAN' कोड में क्रमशः कितने अंक/अक्षर (Characters) होते हैं?

• (क) IFSC: 11 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर (प्रथम 4 बैंक कोड, 5वाँ अंक '0', अंतिम 6 शाखा कोड); MICR: 9 अंकों का संख्यात्मक कोड (प्रथम 3 शहर, मध्य 3 बैंक, अंतिम 3 शाखा); PAN: 10 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर

• (ख) IFSC: 9 अंक; MICR: 11 अक्षर; PAN: 12 अंक

• (ग) IFSC: 12 अंक; MICR: 10 अंक; PAN: 15 अक्षर

• (घ) तीनों कोड 10-10 अंकों के केवल संख्यात्मक कोड होते हैं

• **सही उत्तर:** (क) IFSC: 11 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर (प्रथम 4 बैंक कोड, 5वाँ अंक '0', अंतिम 6 शाखा कोड); MICR: 9 अंकों का संख्यात्मक कोड (प्रथम 3 शहर, मध्य 3 बैंक, अंतिम 3 शाखा); PAN: 10 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर

• **विस्तृत व्याख्या:** NEFT/RTGS/IMPS में प्रयुक्त इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (IFSC) 11 कैरेक्टर का अल्फान्यूमेरिक कोड है जिसमें पाँचवाँ कैरेक्टर सदैव शून्य ('0') होता है। चेक के निचले भाग में मुद्रित मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (MICR) कोड 9 अंकों का होता है (प्रथम 3 अंक शहर के पिन कोड से जुड़े, अगले 3 बैंक और अंतिम 3 शाखा को दर्शाते हैं), जबकि स्थायी खाता संख्या (PAN) 10 कैरेक्टर का अल्फान्यूमेरिक कोड है (rbi.org.in)।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 99. अक्टूबर 2019 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खुदरा और सूक्ष्म व लघु उद्यम (MSE) के परिवर्तनशील दर वाले ऋणों (Floating Rate Loans) के ब्याज निर्धारण में पारदर्शिता लाने हेतु किस प्रणाली को अनिवार्य किया गया?

• (क) बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर (External Benchmark Based Lending Rate - EBLR, जैसे नीतिगत रेपो दर या 3-माह/6-माह ट्रेजरी बिल प्रतिफल से संबद्ध)

• (ख) आधार दर प्रणाली (Base Rate System - 2010)

• (ग) प्रधान उधार दर (Benchmark Prime Lending Rate - BPLR - 2003)

• (घ) कोष की सीमांत लागत आधारित उधार दर (MCLR - 2016)

• **सही उत्तर:** (क) बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर (External Benchmark Based Lending Rate - EBLR, जैसे नीतिगत रेपो दर या 3-माह/6-माह ट्रेजरी बिल प्रतिफल से संबद्ध)

• **विस्तृत व्याख्या:** भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन (rbi.org.in) के अनुसार मौद्रिक नीति के संचरण (Monetary Policy Transmission) को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2019 से सभी नए फ्लोटिंग रेट व्यक्तिगत/खुदरा ऋणों (आवास, ऑटो आदि) और MSE ऋणों को बाह्य बेंचमार्क (मुख्यतः RBI की पॉलिसी रेपो दर या FBIL द्वारा प्रकाशित 3/6 माह T-Bill दर) से जोड़ना अनिवार्य किया गया है, और इसे कम से कम तीन महीने में एक बार रीसेट करना होता है।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 100. 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016' (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC, 2016) के अंतर्गत कॉर्पोरेट जगत और व्यक्तिगत मामलों के न्यायाधिकरण (Adjudicating Authority) क्रमशः कौन-से हैं तथा इसका विनियामक बोर्ड कौन-सा है?

• (क) कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए 'राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण' (NCLT) और व्यक्तियों/भागीदारी फर्मों के लिए 'ऋण वसूली अधिकरण' (DRT); तथा विनियामक निकाय 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड' (IBBI) है

• (ख) कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दोनों के लिए केवल लोक अदालत

• (ग) केवल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

• (घ) केवल उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

• **सही उत्तर:** (क) कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए 'राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण' (NCLT) और व्यक्तियों/भागीदारी फर्मों के लिए 'ऋण वसूली अधिकरण' (DRT); तथा विनियामक निकाय 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड' (IBBI) है

• **विस्तृत व्याख्या:** इंडिया कोड पोर्टल (indiacode.nic.in) के अनुसार टी.के. विश्वनाथन समिति की सिफारिश पर अधिनियमित IBC, 2016 समयबद्ध तरीके से (अधिकतम 180 दिन + 90 दिन विस्तार, समग्र सीमा 330 दिन) कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) पूरी करता है। इसमें कंपनियों के लिए निर्णायक प्राधिकारी NCLT (अपीलीय: NCLAT) और व्यक्तियों के लिए DRT (अपीलीय: DRAT) है।

संदर्भ स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) आधिकारिक डेटा पोर्टल, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) — UPI एवं डिजिटल भुगतान, तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)।

भाग (क): 5 नए उन्नत गहन अध्ययन मॉड्यूल (5 Advanced Deep-Dive Modules)

अध्याय 1: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), मौद्रिक नीति समिति (MPC) एवं तरलता समायोजन सुविधा (LAF) का अर्थशास्त्र

सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण:

1926 के **हिल्टन यंग कमीशन** (रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस) की सिफारिश पर **RBI अधिनियम, 1934** पारित हुआ और **1 अप्रैल 1935** को ₹5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ कोलकाता में भारतीय रिज़र्व बैंक (**RBI Official**) की स्थापना हुई। 1937 में इसका मुख्यालय स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया और **1 जनवरी 1949** को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर 2016 में RBI अधिनियम की **धारा 45ZB** में संशोधन कर **6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC)** का गठन किया गया (3 सदस्य RBI से — गवर्नर पदेन अध्यक्ष, मौद्रिक नीति प्रभारी डिप्टी गवर्नर व एक अधिकारी; तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष के लिए नामित)। MPC का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI — हेडलाइन मुद्रास्फीति) को **4% (±2% सहनशीलता बैंड, अर्थात 2% से 6% के बीच)** बनाए रखना है।

मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरणों में **CRR** (नकद आरक्षित अनुपात — RBI अधिनियम 1934 की धारा 42(1), जिस पर RBI बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता), **SLR** (वैधानिक तरलता अनुपात — बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24, जिसे बैंक नकद, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों G-Sec में स्वयं के पास रखते हैं), **रेपो रेट** (अल्पकालिक दर जिस पर RBI बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार देता है), **SDF** (Standing Deposit Facility — अप्रैल 2022 में बिना किसी गिरवी/Collateral के तरलता अवशोषित करने हेतु प्रारंभ, जो अब LAF कॉरिडोर का निचला तल/Floor है) और **MSF** (Marginal Standing Facility — 2011 में प्रारंभ दंडात्मक ओवरनाइट दर, जिसमें बैंक अपने SLR कोटे से भी उधार ले सकते हैं; यह LAF कॉरिडोर की ऊपरी छत/Ceiling है) शामिल हैं।

- **रोचक केस स्टडी (Case Study — जब देश में महंगाई 6% पार कर जाती है तो RBI का 'रेपो रेट' चक्र कैसे काम करता है?):**

मान लीजिए मानसून की अनियमितता और वैश्विक आपूर्ति बाधा से भारत में खुदरा महंगाई (CPI) लगातार तीन तिमाहियों तक 6.5% पर बनी रहती है। RBI अधिनियम की धारा 45ZN के तहत यदि लगातार 3 तिमाहियों तक मुद्रास्फीति 6% की ऊपरी सीमा से ऊपर (या 2% से नीचे) रहती है, तो इसे 'मौद्रिक नीति की विफलता' माना जाता है और RBI को केंद्र सरकार को लिखित स्पष्टीकरण भेजना पड़ता है। इसे रोकने के लिए MPC 'हॉकिश' (Hawkish/सख्त) रुख अपनाती है और **रेपो रेट में 25 से 50 आधार अंकों (Basis Points, जहां 100 bps = 1%) की वृद्धि** करती है। रेपो रेट बढ़ते ही बैंकों के लिए RBI से कर्ज लेना महंगा हो जाता है -> बैंक अपनी MCLR और एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट बढ़ा देते हैं -> होम लोन, ऑटो लोन और कॉर्पोरेट लोन की EMI बढ़ जाती है -> बाजार में मुद्रा की आपूर्ति (Money Supply M3) संकुचित होती है -> कुल मांग (Aggregate Demand) घटती है और कीमतें पुनः 4% के लक्ष्य की ओर लौट आती हैं!

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
RBI ने 1938 में अपना सबसे बड़े मूल्यवर्ग का करेंसी नोट **₹10,000 का नोट** छापा था (जिसे 1946 में बंद किया गया, 1954 में पुनः शुरू किया गया और 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा अंततः विमुद्रीकृत कर दिया गया), क्योंकि RBI अधिनियम 1934 की **धारा 24** के अनुसार RBI अधिकतम ₹10,000 तक का नोट ही जारी कर सकता है!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):

• **जाल 1:** "₹1 के नोट और सभी सिक्कों को कौन जारी करता है और उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?" **सावधान:** ₹2 से लेकर ₹2000/₹500 तक के सभी नोट RBI अधिनियम की धारा 22 के तहत RBI जारी करता है और उन पर **RBI गवर्नर** के हस्ताक्षर होते हैं, किंतु **₹1 का नोट और सभी सिक्के** (सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत अधिकतम ₹1000 तक का सिक्का ढाला जा सकता है) **वित्त मंत्रालय (भारत सरकार)** द्वारा जारी किए जाते हैं और ₹1 के नोट पर **वित्त सचिव (Finance Secretary)** के हस्ताक्षर होते हैं (हालांकि इनका वितरण RBI ही करता है)!

• **जाल 2:** CRR पर कोई न्यूनतम या अधिकतम वैधानिक सीमा (Floor/Cap) अब नहीं है, और SLR की अधिकतम वैधानिक सीमा **40%** है।

• **कहानी आधारित स्मृति ट्रिक (Story-Based Memory Trick — RBI के प्रमुख गवर्नर और विशेषताएं):**

• कहानी: **"ओसबोर्न (प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ) ने टेलर (जेम्स टेलर - प्रथम हस्ताक्षरकर्ता) से सूट सिलवाकर देशमुख (सी.डी. देशमुख - प्रथम भारतीय गवर्नर व राष्ट्रीयकरण के समय) को दिया, जिन्होंने बेनेगल (रामा राव - सबसे लंबा कार्यकाल) और मनमोहन (एकमात्र प्रधानमंत्री जो गवर्नर रहे) को सौंपा।"** (अमिताव घोष सबसे कम 20 दिन के लिए गवर्नर रहे, और के.जे. उदेशी प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थीं — अब तक कोई महिला RBI गवर्नर नहीं बनी है!)।

अध्याय 2: भारतीय बैंकिंग सुधार, राष्ट्रीयकरण का इतिहास, बेसल-III मानक (Basel Norms), NPA एवं PCA ढांचा

सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण:

भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत 1770 में 'बैंक ऑफ हिंदुस्तान' से हुई। तीन प्रेसीडेंसी बैंकों — बैंक ऑफ बंगाल (1806), बैंक ऑफ बॉम्बे (1840) और बैंक ऑफ मद्रास (1843) — का 1921 में विलय कर 'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' बनाया गया, जिसे **गोरेवाला समिति** की सिफारिश पर **1 जुलाई 1955** को राष्ट्रीयकृत कर **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** बना दिया गया। वित्तीय समावेशन हेतु **19 जुलाई 1969** को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों (जिनकी जमा पूंजी ₹50 करोड़ या अधिक थी) और **15 अप्रैल 1980** को 6 अन्य बैंकों (जमा पूंजी ₹200 करोड़ या अधिक) का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1991 और 1998 की **नरसिम्हम समिति-I और II** तथा 2020 के महा-विलय के पश्चात वर्तमान में भारत में **12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs — SBI + 11 राष्ट्रीयकृत बैंक)** हैं।

यदि किसी ऋण (Loan) के मूलधन या ब्याज की किस्त **90 दिनों से अधिक** समय तक बकाया (Overdue) रहती है, तो वह **गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA — Non-Performing Asset)** बन जाती है (कृषि फसलों के मामले में: लघु अवधि की फसल हेतु **2 फसल मौसम** और दीर्घ अवधि की फसल हेतु **1 फसल मौसम**)। NPA की चार श्रेणियां हैं:

1. **Standard Asset:** नियमित भुगतान (SMA-0: 1–30 दिन, SMA-1: 31–60 दिन, SMA-2: 61–90 दिन बकाया)।
2. **Sub-Standard Asset:** 12 माह तक या उससे कम अवधि का NPA।
3. **Doubtful Asset:** Sub-standard श्रेणी में 12 माह से अधिक रहने वाला NPA।
4. **Loss Asset:** जिसे बैंक या ऑडिटर/RBI ने पूर्णतः डूबा हुआ घोषित कर दिया हो।

बैंकों की वैश्विक जोखिम सहने की क्षमता के लिए स्विट्जरलैंड के बेसल (Basel) स्थित **BIS (Bank for International Settlements)** की समिति ने बेसल-I (1988), बेसल-II (2004) और **बेसल-III (2010)** मानक जारी किए। बेसल-III के तीन स्तंभ हैं: (1) न्यूनतम पूंजी आवश्यकता (CAR/CRAR — वैश्विक स्तर पर 8%, किंतु **RBI के अनुसार भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 9%** + 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर = **11.5%**), (2) पर्यवेक्षी समीक्षा (Supervisory Review), और (3) बाजार अनुशासन (Market Discipline)।

• रोचक केस स्टडी (Case Study — SARFAESI Act 2002 बनाम IBC 2016 और 'बैड बैंक' NARCL का उदय):

2002 से पहले यदि कोई बड़ा डिफॉल्टर बैंक का ऋण नहीं चुकाता था, तो बैंक को सिविल कोर्ट के लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे। **SARFAESI अधिनियम, 2002** ने बैंकों को यह शक्ति दी कि ₹1 लाख से अधिक के सुरक्षित ऋण (Secured Loan) के NPA होने पर बैंक 60 दिन का नोटिस देकर **बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के** गिरवी रखी संपत्ति (कृषि भूमि को छोड़कर!) को जब्त कर नीलाम कर सकता है। फिर 2016 में **IBC (Insolvency and Bankruptcy Code)** आया जिसने कॉर्पोरेट दिवालियापन के समाधान के लिए NCLT के माध्यम से अधिकतम **180+90 (अधिकतम 330) दिनों** की समय-सीमा तय की। और 2021 में ₹200 करोड़ से अधिक के डूबे कॉर्पोरेट ऋणों को साफ करने के लिए **NARCL (National Asset Reconstruction Company Ltd. — 'बैड बैंक')** और **IDRCL** की स्थापना की गई, जो 15% नकद और 85% सरकारी गारंटी वाली सिक्योरिटी रिसीप्ट (SR) मॉडल पर काम करते हैं!

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):

जब किसी बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR), शुद्ध NPA (Net NPA) और टियर-1 लीवरेज अनुपात खतरे के निशान को पार कर जाते हैं, तो RBI उस बैंक को **PCA (Prompt Corrective Action — त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई)** ढांचे में डाल देता है, जिसके तहत बैंक पर लाभांश बांटने, नई शाखाएं खोलने और बड़े कॉर्पोरेट लोन देने पर प्रतिबंध लग जाता है!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):

• **जाल 1:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs — **नरसिम्हम कार्यदल** की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को 'प्रथमा ग्रामीण बैंक', मुरादाबाद, उ.प्र. से प्रारंभ) में पूंजी हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? **सूत्र: केंद्र सरकार : राज्य सरकार : प्रायोजक बैंक = 50% : 15% : 35%!** छात्र अक्सर राज्य और प्रायोजक बैंक के प्रतिशत में भ्रमित हो जाते हैं।

• **जाल 2:** भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का **40%** भाग **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL — Priority Sector Lending)** को देना होता है, किंतु **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs)** और **लघु वित्त बैंकों (Small Finance Banks)** के लिए PSL लक्ष्य **75%** है (भुगतान बैंकों/Payments Banks पर PSL लागू नहीं होता क्योंकि वे ऋण नहीं दे सकते!)।

• **कहानी आधारित स्मृति ट्रिक (Story-Based Memory Trick — 2020 का 10 से 4 बैंकों में महा-विलय):**

• कहानी: **"पीएनबी (PNB) ने ओरिएंटल (OBC) और यूनाइटेड (UBI) को अपनाया; केनरा (Canara) ने सिंडिकेट बनाया; यूनियन (Union) ने आंध्रा और कॉर्पोरेशन को मिलाया; और इंडियन (Indian Bank) ने इलाहाबाद में संगम रचाया!"** (इससे पूर्व 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ था)।

अध्याय 3: NPCI, *डिजिटल भुगतान क्रांति* (UPI, RuPay, IMPS, NEFT, RTGS, AePS, CBDC e₹) *एवं फिनटेक नवाचार*

सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण:

RBI और भारतीय बैंक संघ (IBA) की पहल पर **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007)** के तहत वर्ष **2008** में **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI — npci.org.in)** की स्थापना कंपनी अधिनियम की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 — गैर-लाभकारी संगठन) के अंतर्गत एक 'अंब्रेला संगठन' के रूप में की गई।

भारत की भुगतान प्रणालियों का तकनीकी वर्गीकरण:

1. **RTGS (Real Time Gross Settlement):** RBI द्वारा संचालित; बृहद मूल्य के लेनदेन हेतु **न्यूनतम सीमा ₹2 लाख** (अधिकतम कोई सीमा नहीं), 24x7x365 उपलब्ध, रियल-टाइम आधार पर व्यक्तिगत निपटान।

2. **NEFT (National Electronic Funds Transfer):** RBI द्वारा संचालित; आस्थगित शुद्ध निपटान (Deferred Net Settlement - DNS) पर आधारित, आधे घंटे के कुल **48 बैचों** में 24x7x365 संचालित; **कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं** (बिना बैंक खाते के नकद जमा द्वारा NEFT की अधिकतम सीमा ₹50,000 प्रति लेनदेन)।

3. **IMPS (Immediate Payment Service — 2010):** NPCI द्वारा संचालित; 24x7 तात्कालिक अंतर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अधिकतम सीमा **₹5 लाख**।

4. **UPI (Unified Payments Interface — 11 अप्रैल 2016):** NPCI (NPCI UPI) द्वारा विकसित; VPA (Virtual Payment Address) के माध्यम से अनेक बैंक खातों को एक मोबाइल ऐप से जोड़ता है। सामान्य पीयर-टू-पीयर (P2P) सीमा **₹1 लाख/दिन** है, किंतु पूंजी बाजार, बीमा, IPO और विदेशी प्रेषण हेतु ₹2 लाख तथा **अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, टैक्स भुगतान और RBI रिटेल डायरेक्ट (IPO/G-Sec) हेतु सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति लेनदेन** कर दी गई है!

• रोचक केस स्टडी (Case Study — UPI के 4 उन्नत अवतार: UPI 123Pay, UPI Lite, UPI Circle और Hello! UPI):

डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के लिए NPCI ने चार क्रांतिकारी फीचर लॉन्च किए:

1. **UPI 123Pay:** बिना इंटरनेट वाले 40 करोड़ फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए (IVR नंबर, मिस्ड कॉल, फीचर फोन ऐप और ध्वनि तरंग/Sound-based भुगतान द्वारा)।

2. **UPI Lite (On-Device Wallet):** छोटे मूल्य के ऑफलाइन लेनदेन हेतु बिना UPI पिन डाले **₹500 प्रति लेनदेन** (वॉलेट की कुल क्षमता ₹2,000, जिसे अब ऑटो-टॉपअप के साथ ₹5,000 तक विस्तारित किया गया है) का तुरंत भुगतान, जिससे कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) पर भार नहीं पड़ता।

3. **UPI Circle (Delegated Payments):** प्राथमिक उपयोगकर्ता अपने परिवार के सदस्यों (बच्चों या बुजुर्गों, जिनके पास अपना बैंक खाता न हो) को द्वितीयक उपयोगकर्ता के रूप में जोड़कर ₹15,000/माह तक खर्च की सीमा दे सकता है।

4. **CBDC (Central Bank Digital Currency — डिजिटल रुपया e₹):** क्रिप्टोकरेंसी से पूर्णतः भिन्न, RBI द्वारा जारी संप्रभु वैध मुद्रा (Legal Tender) जिसके दो रूप हैं — **e₹-W (Wholesale)** अंतर-बैंक सरकारी प्रतिभूति निपटान हेतु और **e₹-R (Retail)** आम नागरिकों व व्यापारियों हेतु।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
चेक समाशोधन (Cheque Clearing) में **CTS-2010 (Cheque Truncation System)** भौतिक चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक भेजने के बजाय उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज और **MICR (Magnetic Ink Character Recognition — 9 अंकों का कोड: प्रथम 3 अंक शहर के पिनकोड से, मध्य 3 अंक बैंक और अंतिम 3 अंक शाखा)** को भेजता है, जबकि **IFSC (Indian Financial System Code — 11 अल्फान्यूमेरिक वर्ण)** में प्रथम 4 अक्षर बैंक का नाम, **5वां वर्ण सदैव '0' (शून्य)** और अंतिम 6 वर्ण शाखा को दर्शाते हैं!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
• **जाल 1:** "भुगतान बैंक (Payments Banks — **नचिकेत मोर समिति** की सिफारिश पर स्थापित, न्यूनतम पूंजी ₹100 करोड़) और लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks — **उषा थोराट समिति**, न्यूनतम पूंजी ₹200 करोड़) में मुख्य अंतर क्या है?" **सावधान:** भुगतान बैंक प्रति ग्राहक अधिकतम **₹2 लाख तक मांग जमा (Demand Deposit)** स्वीकार कर सकते हैं, किंतु वे **न तो सावधि जमा (FD/RD) स्वीकार कर सकते हैं, न ही कोई ऋण (Loan) या क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं!**
• **जाल 2: RTGS और NEFT** का संचालन **RBI** करता है, जबकि **UPI, IMPS, RuPay, FASTag, NACH, AePS, BBPS और CTS** का संचालन **NPCI** करता है!
• **कहानी आधारित स्मृति ट्रिक (Story-Based Memory Trick — भुगतान कोड के अंकों की संख्या):**

• अंकों की सीढ़ी (3 से 20 तक): **CVV (3 अंक) -> UPI PIN (4 या 6 अंक) -> MICR (9 अंक) -> PAN व PRAN (10 वर्ण) -> IFSC (11 वर्ण, 5वां '0') -> Aadhaar (12 अंक) -> GSTIN (15 वर्ण) -> Debit/Credit Card (16 अंक) -> LEI — Legal Entity Identifier (20 वर्ण, ₹50 करोड़+ के ऋण व बड़े RTGS/NEFT हेतु अनिवार्य)!**

अध्याय 4: भारतीय वित्तीय बाजार (Money Market vs Capital Market), SEBI, मुद्रास्फीति एवं राष्ट्रीय आय लेखांकन

सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण:

भारतीय वित्तीय बाजार को परिपक्वता अवधि के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है:

1. **मुद्रा बाजार (Money Market — अल्पकालिक, परिपक्वता ≤ 1 वर्ष / 364 दिन, नियामक: RBI):** इसके प्रमुख उपकरण हैं —

• **कॉल मनी (Call Money):** 1 दिन (Overnight) के लिए अंतर-बैंक उधार; **नोटिस मनी:** 2 से 14 दिन; **टर्म मनी:** 15 दिन से 1 वर्ष।

• **ट्रेजरी बिल (T-Bills):** केवल **केंद्र सरकार** द्वारा बट्टे (Discount) पर जारी शून्य-कूपन बॉन्ड; तीन अवधियां — **91 दिन, 182 दिन और 364 दिन** (न्यूनतम राशि ₹25,000 और उसके गुणक में; राज्य सरकारें T-Bills जारी नहीं कर सकतीं, वे SDLs जारी करती हैं!)।

• **नकद प्रबंधन बिल (CMB — Cash Management Bills):** 2010 में प्रारंभ, **91 दिनों से कम** अवधि के लिए सरकार के अस्थायी नकदी असंतुलन को पूरा करने हेतु।

• **वाणिज्यिक पत्र (CP — Commercial Paper):** 1990 में वाघुल समिति की सिफारिश पर प्रारंभ; उच्च रेटिंग वाली कॉर्पोरेट कंपनियों, प्राथमिक डीलरों व वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी असुरक्षित वचन पत्र; अवधि 7 **दिन से 1 वर्ष**, न्यूनतम राशि **₹5 लाख**।

• **जमा प्रमाणपत्र (CD — Certificate of Deposit):** 1989 में प्रारंभ; अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (RRBs को छोड़कर) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी; बैंकों हेतु अवधि 7 **दिन से 1 वर्ष**, न्यूनतम राशि **₹5 लाख**।

2. **पूंजी बाजार (Capital Market — दीर्घकालिक, परिपक्वता > 1 वर्ष, नियामक: SEBI):** इसमें प्राथमिक बाजार (IPO, FPO, Rights Issue) और द्वितीयक बाजार (स्टॉक एक्सचेंज — **BSE, स्थापना 1875**, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, सूचकांक: 30 शेयरों वाला **SENSEX**; तथा **NSE, स्थापना 1992** फेरवानी समिति की सिफारिश पर, सूचकांक: 50 शेयरों वाला **NIFTY**) शामिल हैं। **SEBI (sebi.gov.in)** की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को गैर-वैधानिक निकाय के रूप में हुई और **SEBI अधिनियम, 1992 (30 जनवरी 1992)** द्वारा इसे वैधानिक दर्जा मिला (मुख्यालय: मुंबई; प्रथम महिला अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच)।

• **रोचक केस स्टडी (Case Study — भारत के शेयर बाजार में 'T+1' से 'T+0' और Instant Settlement की वैश्विक छलांग):**

पहले जब कोई निवेशक शेयर बेचता था, तो पैसा उसके खाते में आने में T+2 (ट्रेडिंग दिन + 2 कार्यदिवस) लगते थे। SEBI ने पहले भारत को संपूर्ण रूप से **T+1 सेटलमेंट** लागू करने वाला प्रमुख बाजार बनाया, और मार्च 2024 से वैकल्पिक रूप से **T+0 (उसी दिन निपटान — बीटा चरण)** लागू कर दिया! इसके अतिरिक्त, IPO में आवेदन करते समय **ASBA (Application Supported by Blocked Amount)** प्रणाली काम करती है, जिसमें आवेदक का पैसा उसके बैंक खाते से कटता नहीं है, बल्कि केवल 'ब्लॉक' होता है (जिस पर उसे ब्याज मिलता रहता है) और शेयर आवंटित होने पर ही राशि कटती है।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
'मसाला
बॉन्ड' (Masala Bonds) वे बॉन्ड हैं जिन्हें भारतीय संस्थाओं द्वारा भारत के बाहर विदेशी बाजारों में जारी किया जाता है, किंतु उनका मूल्यवर्ग विदेशी मुद्रा (डॉलर) के बजाय **भारतीय रुपये (INR)** में होता है — अर्थात मुद्रा के उतार-चढ़ाव (Exchange Rate Risk) का जोखिम जारीकर्ता कंपनी पर नहीं, बल्कि विदेशी निवेशक पर होता है! IFC ने 2014 में प्रथम मसाला बॉन्ड जारी किया था, और HDFC मसाला बॉन्ड जारी करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी बनी।

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
• **जाल 1: GDP** (सकल घरेलू उत्पाद — देश की भौगोलिक सीमा के भीतर 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य, चाहे उत्पादक देशी हो या विदेशी) और **GNP** (सकल राष्ट्रीय उत्पाद — केवल देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित मूल्य) का संबंध सूत्र क्या है?

$GNP = GDP + NFIA (विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय)$

तथा **NNP at Factor Cost** को ही वास्तविक अर्थों में **'राष्ट्रीय आय' (National Income)** कहा जाता है:

$$NNP_{FC} = GNP_{MP} - मूल्यह्रास (Depreciation) - शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी)$$

• **जाल 2: फिलिप्स वक्र (Phillips Curve)** मुद्रास्फीति (Inflation) और बेरोजगारी (Unemployment) के बीच **व्युत्क्रमानुपाती (Inverse) संबंध** दर्शाता है, जबकि **लॉरेंज वक्र (Lorenz Curve) व गिनी गुणांक (Gini Coefficient)** आय की असमानता को और **लाफर वक्र (Laffer Curve)** कर की दर (Tax Rate) और कुल कर राजस्व (Tax Revenue) के संबंध को दर्शाता है!

★ कहानी आधारित स्मृति ट्रिक (Story-Based Memory Trick — मुद्रास्फीति के प्रकार):
• कहानी: **"रेंगती (Creeping: 0–3%) महंगाई जब चलने (Walking: 3–10%) लगी, तो दौड़ते (Running: 10–20%) हुए सरपट कूदने (Galloping/ Hyperinflation: 20% से 1000%+) लगी; और जब मंदी के साथ महंगाई आई तो उसे 'स्टैगफ्लेशन' (Stagflation = Stagnation + Inflation) कहा गया!"**

अध्याय 5: संपूर्ण बीमा जागरूकता (Insurance Principles, IRDAI, LIC, GIC) एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण:

भारत में आधुनिक जीवन बीमा की शुरुआत **1818 में कोलकाता में 'ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी'** (बिपिन दासगुप्ता और यूरोपीय लोगों द्वारा) से हुई, जबकि प्रथम भारतीय स्वामित्व वाली जीवन बीमा कंपनी **1870 में 'बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी'** थी और प्रथम साधारण बीमा कंपनी **1850 में कोलकाता में 'ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी'** थी।

स्वतंत्रता के बाद **19 जून 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम** पारित कर 245 भारतीय व विदेशी बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट सोसाइटियों का विलय करके **1 सितंबर 1956** को ₹5 करोड़ की सरकारी पूंजी से *भारतीय जीवन बीमा निगम (*LIC* — आदर्श वाक्य: 'योगक्षेमं वहाम्यहम्' जो भगवद्गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से लिया गया है) **की स्थापना की गई। इसी प्रकार** साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (*GIBNA*) **के तहत 107 कंपनियों को मिलाकर** 1 जनवरी 1973 **को** *GIC (General Insurance Corporation of India* — अब भारतीय राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता *'GIC Re')* * और उसकी 4 सहायक कंपनियों (नेशनल इंश्योरेंस-कोलकाता, न्यू इंडिया एश्योरेंस-मुंबई, ओरिएंटल इंश्योरेंस-नई दिल्ली, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस-चेन्नई) का गठन किया गया।

1993 में RBI के पूर्व गवर्नर **आर.एन. मल्होत्रा समिति** की सिफारिश पर **IRDA अधिनियम, 1999** पारित हुआ और अप्रैल 2000 में **IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण — मुख्यालय: हैदराबाद; आदर्श वाक्य: 'बीमाधारकों के हितों की रक्षा करना')** की स्थापना एक 10 सदस्यीय वैधानिक निकाय (1 अध्यक्ष + 5 पूर्णकालिक + 4 अंशकालिक सदस्य) के रूप में हुई। IRDAI ने '2047 तक सभी के लिए बीमा' (Insurance for All by 2047) के लक्ष्य के तहत **बीमा ट्रिनिटी (Bima Trinity — बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक)** लॉन्च किया है।

• रोचक केस स्टडी (Case Study — बीमा के 7 मौलिक कानूनी सिद्धांत और 'क्षतिपूर्ति' का नियम जीवन बीमा पर क्यों लागू नहीं होता?):
बीमा अनुबंध 7 मूल सिद्धांतों पर टिका है:

1. *परम सद्विश्वास का सिद्धांत (*Principle of Utmost Good Faith* — Uberrimae Fidei):* बीमाकर्ता और बीमित दोनों को सभी महत्वपूर्ण तथ्य (जैसे पुरानी बीमारी) सच-सच बताने होते हैं।

2. **बीमायोग्य हित (Insurable Interest):** बीमित व्यक्ति का विषय-वस्तु के सुरक्षित रहने में वित्तीय हित होना चाहिए (जीवन बीमा में पॉलिसी लेते समय और साधारण बीमा में पॉलिसी लेते समय व दुर्घटना के समय दोनों पर)।

3. **क्षतिपूर्ति का सिद्धांत (Principle of Indemnity):** बीमित को वास्तविक हानि से अधिक मुआवजा नहीं मिल सकता (अर्थात बीमा लाभ कमाने का साधन नहीं है)। **महत्वपूर्ण अपवाद:** यह सिद्धांत **जीवन बीमा (Life Insurance)** और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पर **लागू नहीं होता**, क्योंकि मानव जीवन का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं आंका जा सकता; इसलिए जीवन बीमा को 'अनुबंधित मूल्य' (Valued Policy / Assurance) कहा जाता है!

4. **प्रत्यासन का सिद्धांत (Principle of Subrogation):** दावे का पूरा भुगतान करने के बाद क्षतिग्रस्त संपत्ति (Salvage) और तीसरे पक्ष पर मुकदमा करने के सभी अधिकार बीमा कंपनी को हस्तांतरित हो जाते हैं (यह भी जीवन बीमा पर लागू नहीं होता)।

5. **अंशदान का सिद्धांत (Principle of Contribution):** यदि एक ही संपत्ति का दो कंपनियों से बीमा कराया गया है, तो दोनों कंपनियां आनुपातिक रूप से ही हानि की भरपाई करेंगी।

6. **निकटतम कारण (Causa Proxima):** दावे का भुगतान तभी होगा जब हानि का सबसे प्रत्यक्ष/निकटतम कारण पॉलिसी में कवर किए गए जोखिम (Insured Peril) से उत्पन्न हुआ हो।

7. **हानि अल्पीकरण (Loss Minimization):** दुर्घटना के समय बीमित व्यक्ति को संपत्ति को बचाने का वैसा ही प्रयास करना चाहिए जैसा वह बिना बीमा के करता।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
भारत में **बैंकाश्योरेंस (Bancassurance)** वह मॉडल है जिसमें बैंक अपनी शाखाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से किसी बीमा कंपनी के उत्पादों को बेचते हैं (जिससे बैंक को बिना जोखिम के गैर-ब्याज शुल्क आय/Fee Income मिलती है)। बीमा क्षेत्र में वर्तमान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा **74%** (और 100% प्रीमियम भारत में निवेश करने वाली कंपनियों हेतु 100% का प्रस्तावित प्रावधान) तथा पेंशन क्षेत्र में **49%** है!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
• **जाल 1: PMJJBY** (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) और **PMSBY** (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) की आयु-सीमा और प्रीमियम में अंतर:

• **PMJJBY (जीवन बीमा — किसी भी कारण से मृत्यु पर ₹2 लाख कवर):** आयु **18 से 50 वर्ष**, संशोधित वार्षिक प्रीमियम **₹436** (पहले ₹330 था)।

• **PMSBY (दुर्घटना बीमा — दुर्घटना में मृत्यु/पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख व आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख):** आयु **18 से 70 वर्ष**, संशोधित वार्षिक प्रीमियम **₹20** (पहले ₹12 था)। दोनों में प्रीमियम 1 जून से 31 मई के चक्र में ऑटो-डेबिट होता है!

• **जाल 2: पुनर्बीमा (Reinsurance)** क्या है? जब एक बीमा कंपनी अपने बड़े जोखिम का कुछ हिस्सा किसी दूसरी बड़ी बीमा कंपनी को हस्तांतरित करती है, तो उसे पुनर्बीमा कहते हैं ('बीमा कंपनियों का बीमा')। **GIC Re** भारत की एकमात्र स्वदेशी राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी है।

★ कहानी आधारित स्मृति ट्रिक (Story-Based Memory Trick — भारत के 5 विकास वित्तीय संस्थान और स्थापना वर्ष):
• कहानी: **"इंपीरियल SBI ने 55 (1955) में LIC (1956) का बीमा कराया, फिर 82 (1982) में NABARD और EXIM ने मिलकर 88 (1988) में NHB का घर बनवाया और 90 (1990) में SIDBI को लखनऊ बुलाया!"** (SBI-1955, LIC-1956, NABARD व EXIM-1982, NHB-1988 नई दिल्ली, SIDBI-1990 लखनऊ)।

भाग (ख): बुक 20 के 100 पूर्णतः हल किए गए विगत वर्षों के प्रश्न (100 Solved Chapter-wise PYQs)

अध्याय 1: RBI, मौद्रिक नीति एवं भारतीय बैंकिंग का इतिहास *(प्रश्न 1–25)*

1. **[IBPS PO Mains 2024]** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, और इसके प्रथम गवर्नर तथा प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे?

• **उत्तर:** हिल्टन यंग कमीशन (1926); प्रथम गवर्नर: सर ओसबोर्न स्मिथ (1935–37); प्रथम भारतीय गवर्नर: सर सी.डी. देशमुख (1943–49)।

• **व्याख्या:** RBI अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापित RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ (**RBI Official**)।

2. **[SBI PO 2024]** मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कुल कितने सदस्य होते हैं, इसकी बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार अनिवार्य है और कोरम (गणपूर्ति) क्या है?

• **उत्तर:** 6 सदस्य (3 RBI + 3 सरकार द्वारा नामित); वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक अनिवार्य (व्यवहार में द्विमासिक अर्थात 6 बार); कोरम: 4 सदस्य।

• **व्याख्या:** प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है, किंतु मत बराबर (3-3) होने की स्थिति में RBI गवर्नर को 'निर्णायक मत' (Casting Vote) का अधिकार है।

3. **[RBI Grade B 2024]** अप्रैल 2022 में RBI द्वारा तरलता समायोजन सुविधा (LAF) कॉरिडोर के निचले तल (Floor) के रूप में रिवर्स रेपो रेट के स्थान पर कौन-सी नई गैर-गिरवी (Uncollateralized) सुविधा शुरू की गई?

• **उत्तर:** स्थायी जमा सुविधा (SDF — Standing Deposit Facility)।

• **व्याख्या:** RBI अधिनियम की धारा 17 में 2018 के संशोधन के तहत SDF शुरू की गई, जो रेपो रेट से सामान्यतः 25 bps (0.25%) कम होती है, जबकि MSF रेपो रेट से 25 bps अधिक होती है।

4. **[IBPS Clerk Mains 2024]** भारत में करेंसी नोट छापने के लिए RBI वर्ष 1957 से किस प्रणाली का उपयोग करता है और इसके तहत कुल कितने मूल्य का कोष रखना अनिवार्य है?

• **उत्तर:** न्यूनतम आरक्षित प्रणाली (Minimum Reserve System — MRS); ₹200 करोड़ का कुल कोष।

• **व्याख्या:** इस ₹200 करोड़ में से **कम से कम ₹115 करोड़ का स्वर्ण (Gold Bullion/Coins)** और शेष **₹85 करोड़ विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (Foreign Currency Assets)** होना अनिवार्य है।

5. **[SBI Clerk 2024]** भारत में करेंसी नोटों की छपाई करने वाली 4 प्रेस और सिक्कों की ढलाई करने वाली 4 टकसालें (Mints) कहां स्थित हैं?

• **उत्तर:** 4 नोट प्रेस: नासिक (महाराष्ट्र) व देवास (मध्य प्रदेश) — दोनों भारत सरकार के SPMCIL के अधीन; तथा मैसूर (कर्नाटक) व सालबोनी (पश्चिम बंगाल) — दोनों RBI की सहायक कंपनी **BRBNMPL** के अधीन। 4 सिक्का टकसालें: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा।

• **व्याख्या:** करेंसी नोट का सुरक्षा कागज (Security Paper Mill) नर्मदापुरम (होशंगाबाद, म.प्र.) और मैसूर में बनता है।

6. **[RRB Scale-I Officer]** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की किस धारा के तहत RBI बैंकों को भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेंस देता है और किस धारा के तहत नई शाखा खोलने की अनुमति देता है?

• **उत्तर:** धारा 22 (बैंकिंग लाइसेंस) और धारा 23 (शाखा विस्तार)।

• **व्याख्या:** 'अनुसूचित बैंक' (Scheduled Banks) वे बैंक हैं जो **RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची (Second Schedule)** में सूचीबद्ध हैं और जिनकी चुकता पूंजी व आरक्षित कोष कम से कम ₹5 लाख है।

7. **[IBPS PO 2024]** RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली 5 प्रमुख सहायक कंपनियां (Fully Owned Subsidiaries) कौन-सी हैं?

• **उत्तर:** 1. DICGC (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम - 1978), 2. BRBNMPL (भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लि. - 1995), 3. ReBIT (रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्रा. लि. - 2016), 4. IFTAS (भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं), और 5. RBIH (रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब - बेंगलुरु)।

• **व्याख्या:** पूर्व में NABARD और NHB में भी RBI की हिस्सेदारी थी, किंतु अब दोनों 100% भारत सरकार के स्वामित्व में हैं।

8. **[SBI PO Mains]** DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) के तहत किसी बैंक के डूबने या लाइसेंस रद्द होने पर प्रति जमाकर्ता अधिकतम कितनी जमा राशि का बीमा कवर मिलता है?

• **उत्तर:** ₹5 लाख (मूलधन + ब्याज मिलाकर, 4 फरवरी 2020 से ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया)।

• **व्याख्या:** DICGC अधिनियम की धारा 16(1) में संशोधन के तहत अब रुग्ण बैंक के जमाकर्ताओं को **90 दिनों के भीतर** ₹5 लाख तक की बीमित राशि का अंतरिम भुगतान करना अनिवार्य है।

9. **[SSC CGL 2024]** लाला लाजपत राय के प्रयासों से 1894 में लाहौर में स्थापित प्रथम पूर्णतः स्वदेशी बैंक (भारतीय पूंजी से प्रबंधित) कौन-सा था?

• **उत्तर:** पंजाब नेशनल बैंक (PNB)।

• **व्याख्या:** 1881 में स्थापित 'अवध कमर्शियल बैंक' (फैजाबाद) सीमित देयता वाला भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था, और 1911 में सोराबजी पोचखानवाला द्वारा स्थापित 'सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया' पूर्णतः भारतीय स्वामित्व व प्रबंधन वाला पहला स्वदेशी बैंक था।

10. **[IBPS SO]** जून 2021 में RBI द्वारा लागू 'एकीकृत लोकपाल योजना' (RBI Integrated Ombudsman Scheme — 'One Nation, One Ombudsman') में किन तीन पुरानी योजनाओं का विलय किया गया?

• **उत्तर:** बैंकिंग लोकपाल योजना (2006), NBFC लोकपाल योजना (2018) और डिजिटल लेनदेन लोकपाल योजना (2019)।

• **व्याख्या:** इसका केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) **चंडीगढ़** में स्थापित किया गया है और टोल-फ्री नंबर **14448** है।

11. **[NABARD Grade A 2024]** नाबार्ड (NABARD — राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर और किस तिथि को हुई थी?

• **उत्तर:** बी. शिवरामन समिति (CRAFICARD); 12 जुलाई 1982 को (छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, मुख्यालय: मुंबई)।

• **व्याख्या:** RIDF (Rural Infrastructure Development Fund — 1995-96) का संचालन भी नाबार्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें वे वाणिज्यिक बैंक पैसा जमा करते हैं जो अपना PSL लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते।

12. **[RBI Assistant 2024]** मुद्रा की पूर्ति (Money Supply — M1, M2, M3, M4) में 'संकीर्ण मुद्रा' (Narrow Money) और 'व्यापक मुद्रा' (Broad Money) किसे कहा जाता है?

• **उत्तर:** संकीर्ण मुद्रा: **M1** (जनता के पास करेंसी व सिक्के + बैंकों की मांग जमा + RBI के पास अन्य जमा) एवं M2; व्यापक मुद्रा: **M3** (M1 + बैंकों के पास सावधि जमा/Time Deposits) एवं M4।

• **व्याख्या:** तरलता (Liquidity) का घटता क्रम M1 > M2 > M3 > M4 है, और RBI अपनी मौद्रिक नीति में **M3** को प्रमुख समग्र मौद्रिक संसाधन मानता है।

13. **[IBPS PO 2024]** 'नोटिस मनी' और 'कॉल मनी' बाजार में उधार की समय-सीमा क्या होती है?

• **उत्तर:** कॉल मनी (Call Money): 1 दिन (Overnight); नोटिस मनी (Notice Money): 2 से 14 दिन।

• **व्याख्या:** 14 दिन से अधिक और 1 वर्ष तक के अंतर-बैंक उधार को 'टर्म मनी' (Term Money) कहते हैं।

14. **[SBI Clerk Mains]** RBI ने अपना लेखा वर्ष (Accounting Year) जुलाई–जून से बदलकर सरकार के वित्तीय वर्ष के समान **अप्रैल–मार्च** कब से किया?

• **उत्तर:** वर्ष 2020-21 से (बि जालान समिति की सिफारिश पर)।

• **व्याख्या:** बिमल जालान समिति का गठन RBI के 'आर्थिक पूंजी ढांचे' (Economic Capital Framework — ECF) की समीक्षा के लिए किया गया था।

15. **[IBPS Clerk 2024]** 'लीड बैंक योजना' (Lead Bank Scheme — दिसंबर 1969, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक अग्रणी बैंक को वित्तीय समावेशन का समन्वय सौंपा जाता है) किस समिति की देन है?

• **उत्तर:** गाडगिल अध्ययन समूह और एफ.के.एफ. नरीमन समिति।

• **व्याख्या:** 'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' (Service Area Approach) 1989 में पी.डी. ओझा समिति की सिफारिश पर शुरू हुआ था।

16. **[RBI Grade B]** 'MCLR' (Marginal Cost of Funds based Lending Rate) को RBI ने बेस रेट के स्थान पर कब लागू किया था?

• **उत्तर:** 1 अप्रैल 2016 को।

• **व्याख्या:** अक्टूबर 2019 से खुदरा और MSME के फ्लोटिंग रेट ऋणों को बाहरी बेंचमार्क (जैसे रेपो रेट या T-Bill यील्ड — EBLR) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।

17. **[IBPS PO Mains]** भारत में 'प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक' (D-SIBs — Domestic Systemically Important Banks, जिन्हें 'Too Big To Fail' कहा जाता है) की सूची में RBI ने किन तीन बैंकों को रखा है?

• **उत्तर:** भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक और ICICI बैंक।

• **व्याख्या:** इन बैंकों को अपनी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (RWA) के अनुपात में अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) पूंजी रखनी होती है।

18. **[SBI PO 2024]** जब RBI खुले बाजार की क्रियाओं (OMO — Open Market Operations) के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां (G-Sec) **बेचता** है, तो बाजार की तरलता (Liquidity) पर क्या प्रभाव पड़ता है?

• **उत्तर:** बाजार से तरलता (मुद्रा आपूर्ति) **अवशोषित (कम) होती है**, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

• **व्याख्या:** इसके विपरीत जब RBI सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, तो बाजार में तरलता का संचार (Infusion) होता है।

19. **[RRB PO Mains]** 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) योजना किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड द्वारा तैयार की गई थी?

• **उत्तर:** अगस्त 1998 में; आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर।

• **व्याख्या:** 2019 के बजट से KCC की सुविधा पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी दे दी गई है।

20. **[IBPS Clerk 2024]** 'स्वयं सहायता समूह (SHG) – बैंक लिंकेज कार्यक्रम' (विश्व का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम) 1992 में किस संस्था ने शुरू किया था?

• **उत्तर:** नाबार्ड (NABARD — एस.के. कालिया समिति की सिफारिश पर)।

• **व्याख्या:** भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) के नियमन के लिए **वाई.एच. मालेगाम समिति** (2010) का गठन किया गया था।

21. **[SSC CGL 2024]** 19 जुलाई 1969 को प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री व RBI गवर्नर कौन थे?

• **उत्तर:** 14 बैंकों का; प्रधानमंत्री: इंदिरा गांधी; RBI गवर्नर: एल.के. झा।

• **व्याख्या:** दूसरे चरण (15 अप्रैल 1980 — 6 बैंक) के समय RBI गवर्नर डॉ. आई.जी. पटेल थे।

22. **[IBPS PO 2024]** 'व्हाइट लेबल एटीएम' (White Label ATM — WLA) और 'ब्राउन लेबल एटीएम' में क्या अंतर है?

• **उत्तर:** व्हाइट लेबल एटीएम का स्वामित्व और संचालन **गैर-बैंकिंग कंपनियों (NBFCs)** द्वारा किया जाता है (जिन पर किसी बैंक का लोगो नहीं होता — भारत का प्रथम WLA 'Indicash' टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस द्वारा चंद्रपुर, महाराष्ट्र में खोला गया), जबकि ब्राउन लेबल एटीएम में हार्डवेयर व लीज सेवा प्रदाता की होती है पर कैश प्रबंधन व कनेक्टिविटी प्रायोजक बैंक की होती है (और उस पर बैंक का लोगो होता है)।

• **व्याख्या:** कृषि लेनदेन हेतु एटीएम को 'ग्रीन लेबल', महिलाओं हेतु 'पिंक लेबल' और शेयर लेनदेन हेतु 'ऑरेंज लेबल एटीएम' कहते हैं।

23. **[SBI Clerk 2024]** RBI ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों को करेंसी नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में सहायता के लिए कौन-सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?

• **उत्तर:** MANI ऐप (Mobile Aided Note Identifier — जो ऑफलाइन भी आवाज और कंपन से नोट का मूल्य बताता है)।

• **व्याख्या:** इसके अतिरिक्त ₹100, ₹200 और ₹500 के नोटों के किनारों पर उभरी हुई छपाई (Intaglio Printing) में 'ब्लीड लाइन्स' (₹100 में 4, ₹200 में 4+2 जीरो, ₹500 में 5 लाइन्स) होती हैं।

24. **[RBI Grade B 2024]** RBI का 'दक्ष' (DAKSH) पोर्टल और 'प्रवाह' (PRAVAAH) पोर्टल किस उद्देश्य के लिए हैं?

• **उत्तर:** DAKSH: RBI की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली (SupTech एप्लिकेशन); PRAVAAH (Platform for Regulatory Application, Validation and AutHorisation): किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा RBI से नियामक मंजूरी या लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का केंद्रीकृत पोर्टल।

• **व्याख्या:** बिना दावे वाली जमा राशियों (Unclaimed Deposits — 10 वर्ष या अधिक से निष्क्रिय खाते) को खोजने के लिए RBI ने **UDGAM (Unclaimed Deposits - Gateway to Access inforMation)** पोर्टल लॉन्च किया है!

25. **[IBPS PO Mains 2024]** किसी बचत या चालू खाते को 'निष्क्रिय खाता' (Inoperative/Dormant Account) कब घोषित किया जाता है, और 'लावारिस जमा' (Unclaimed Deposit) कब माना जाता है?

• **उत्तर:** लगातार **2 वर्ष (24 माह)** तक ग्राहक द्वारा कोई लेनदेन न होने पर खाता 'निष्क्रिय/Dormant' हो जाता है; और **10 वर्ष** तक निष्क्रिय रहने पर उसकी राशि RBI के **DEA Fund (Depositor Education and Awareness Fund)** में हस्तांतरित कर दी जाती है।

• **व्याख्या:** ग्राहक जब चाहे KYC कराकर DEA फंड से अपनी राशि ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकता है।

अध्याय 2: बेसल मानक, NPA, डिजिटल भुगतान (NPCI), पूंजी बाजार एवं SEBI (प्रश्न 26–65)

26. **[IBPS PO 2024]** बेसल-III मानकों के अनुसार भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR / CAR) कितना निर्धारित है?

• **उत्तर:** 9% (तथा 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर CCB मिलाकर कुल 11.5%)।

• **व्याख्या:** इसमें न्यूनतम टियर-1 पूंजी 7% (जिसमें कॉमन इक्विटी टियर-1 अर्थात CET-1 कम से कम 5.5%) और टियर-2 पूंजी अधिकतम 2% होती है।

27. **[SBI PO Mains 2024]** बेसल-III में शामिल दो प्रमुख तरलता अनुपातों — **LCR** और **NSFR** — का पूर्ण रूप और न्यूनतम मानक क्या है?

• **उत्तर:** LCR: Liquidity Coverage Ratio (बैंकों को 30 दिनों के गंभीर तनाव की स्थिति से निपटने हेतु उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां HQLA रखनी होती हैं — न्यूनतम **100%**); NSFR: Net Stable Funding Ratio (1 वर्ष की दीर्घकालिक स्थिरता हेतु — न्यूनतम **100%**)।

• **व्याख्या:** ये दोनों अनुपात 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के सबक के रूप में बेसल-III में जोड़े गए।

28. **[RRB Scale-II]** भारत में प्रथम 'लोक अदालत' और ऋण वसूली अधिकरण (DRT — Debt Recovery Tribunal, 1993 के अधिनियम के तहत) कितने रुपये से अधिक के NPA मामलों की सुनवाई करते हैं?

• **उत्तर:** लोक अदालत: ₹20 लाख तक के मामले; DRT (ऋण वसूली अधिकरण): **₹20 लाख या उससे अधिक** के मामले।

• **व्याख्या:** DRT के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर DRAT (Debt Recovery Appellate Tribunal) में अपील की जा सकती है।

29. **[IBPS Clerk Mains]** सरफेसी (SARFAESI) का पूर्ण रूप क्या है और यह किस प्रकार की संपत्ति पर लागू नहीं होता?

• **उत्तर:** Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002; यह **कृषि भूमि**, ₹1 लाख से कम के ऋण, और जहां बकाया राशि मूलधन व ब्याज के 20% से कम रह गई हो, वहां लागू नहीं होता।

• **व्याख्या:** इसी अधिनियम के तहत भारत में ARCs (Asset Reconstruction Companies) का गठन हुआ।

30. **[SBI PO 2024]** सिबिल (CIBIL — Credit Information Bureau India Ltd., स्थापना 2000) द्वारा जारी किया जाने वाला क्रेडिट स्कोर कितने अंकों का होता है और उसकी रेंज क्या होती है?

• **उत्तर:** 3 अंकों का संख्यात्मक स्कोर, जिसकी रेंज **300 से 900** के बीच होती है।

• **व्याख्या:** 750 या उससे अधिक का स्कोर ऋण स्वीकृति के लिए उत्कृष्ट माना जाता है; भारत में RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां (CICs) हैं — TransUnion CIBIL, Equifax, Experian और CRIF High Mark।

31. **[IBPS PO 2024]** NPCI द्वारा विकसित 'भारत बिल पेमेंट सिस्टम' (BBPS), 'NACH' और 'AePS' के कार्य क्या हैं?

• **उत्तर:** BBPS: सभी प्रकार के आवर्ती बिलों (बिजली, पानी, गैस, डीटीएच, बीमा प्रीमियम, लोन EMI) के भुगतान का एकीकृत प्लेटफॉर्म; NACH (National Automated Clearing House): प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), वेतन, पेंशन व लाभांश के बल्क इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तथा ई-मैंडेट की प्रणाली; AePS (Aadhaar Enabled Payment System): आधार संख्या और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा बैंक मित्र/माइक्रो एटीएम पर बुनियादी बैंकिंग लेनदेन (**NPCI Official**)।

• **व्याख्या:** FASTag (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन — **RFID** तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह) भी NPCI और NHAI की संयुक्त पहल है।

32. **[RBI Assistant]** ₹50,000 या उससे अधिक के चेक भुगतान में धोखाधड़ी रोकने के लिए RBI द्वारा 1 जनवरी 2021 से लागू की गई प्रणाली को क्या कहते हैं?

• **उत्तर:** पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System — PPS)।

• **व्याख्या:** इसमें चेक जारी करने वाला व्यक्ति बैंक को पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक नंबर, तिथि, लाभार्थी का नाम और राशि की जानकारी दे देता है जिसका मिलान CTS समाशोधन के समय किया जाता है।

33. **[IBPS Clerk 2024]** चेक के मुख्य प्रकारों — 'Stale Cheque', 'Post-Dated Cheque' और 'Antedated Cheque' — में क्या अंतर है?

• **उत्तर:** Stale Cheque (कालातीत चेक): जिसकी जारी तिथि से **3 महीने** की वैधता समाप्त हो चुकी हो; Post-Dated Cheque: जिस पर भविष्य की तारीख लिखी हो (उस तारीख से पहले भुनाया नहीं जा सकता); Antedated Cheque: जिस पर चेक प्रस्तुत करने की तारीख से पहले की तारीख लिखी हो (परंतु 3 महीने पूरे न हुए हों)।

• **व्याख्या:** चेक के बाएं ऊपरी कोने पर दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींचने को 'क्रॉसिंग' (Account Payee Crossing) कहते हैं, जिससे भुगतान केवल बैंक खाते में ही हो सकता है, काउंटर पर नकद नहीं।

34. **[SBI Clerk 2024]** परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) की कौन-सी धाराएं वचन पत्र (Promissory Note), विनिमय विपत्र (Bill of Exchange), चेक (Cheque) और चेक बाउंस (Cheque Dishonour) को परिभाषित करती हैं?

• **उत्तर:** धारा 4: वचन पत्र (Promissory Note); धारा 5: विनिमय विपत्र (Bill of Exchange); धारा 6: चेक (Cheque); और **धारा 138: खाते में अपर्याप्त राशि के कारण चेक बाउंस होने पर दंड** (अधिकतम 2 वर्ष का कारावास या चेक राशि के दोगुने तक जुर्माना या दोनों)।

• **व्याख्या:** धारा 143A के तहत न्यायालय चेक बाउंस मामले के लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को चेक राशि के 20% तक अंतरिम मुआवजा दिलाने का आदेश दे सकता है।

35. **[IBPS PO Mains 2024]** भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) 'गिफ्ट सिटी' (GIFT City — Gujarat International Finance Tec-City, गांधीनगर) का एकीकृत नियामक कौन है?

• **उत्तर:** IFSCA (International Financial Services Centres Authority — स्थापना अप्रैल 2020, मुख्यालय: गांधीनगर)।

• **व्याख्या:** IFSCA ने गिफ्ट सिटी के भीतर RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA चारों नियामकों की शक्तियों को एकीकृत कर लिया है; यहीं भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (IIBX) भी स्थित है।

36. **[SEBI Grade A 2024]** शेयर बाजार में 'बुल' (Bull/तेजड़िया) और 'बेयर' (Bear/मंदड़िया) का क्या अर्थ है, तथा 'डीमैट खाता' (Demat Account) कौन-सी दो डिपॉजिटरी संस्थाएं संचालित करती हैं?

• **उत्तर:** बुल: वह निवेशक जो बाजार बढ़ने की उम्मीद में शेयर खरीदता है; बेयर: जो बाजार गिरने की उम्मीद में शेयर बेचता है। भारत की दो डिपॉजिटरी: **NSDL** (National Securities Depository Ltd. — 1996, NSE द्वारा प्रवर्तित) और **CDSL** (Central Depository Services Ltd. — 1999, BSE द्वारा प्रवर्तित)।

• **व्याख्या:** भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने की प्रक्रिया को 'डीमैटेरियलाइजेशन' (Dematerialisation) कहते हैं (**SEBI Official**)।

37. **[IBPS PO 2024]** सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) में खुदरा निवेशकों को सीधे निवेश करने की सुविधा देने के लिए RBI ने नवंबर 2021 में कौन-सी योजना शुरू की?

• **उत्तर:** RBI रिटेल डायरेक्ट योजना (RBI Retail Direct Scheme — जिसके तहत खुदरा निवेशक RBI के पास 'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता' RDG Account निःशुल्क खोल सकते हैं)।

• **व्याख्या:** सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को 'गिल्ट-एज्ड मार्केट' (Gilt-Edged Market — जोखिम-मुक्त बाजार) कहा जाता है।

38. **[RBI Grade B 2024]** 'सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड' (SGB) और 'फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड' की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

• **उत्तर:** SGB: भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा ग्राम सोने के मूल्य में जारी बॉन्ड (परिपक्वता अवधि 8 वर्ष, 5वें वर्ष के बाद निकासी विकल्प, प्रतिवर्ष 2.5% निश्चित ब्याज + सोने के मूल्यवृद्धि का लाभ, परिपक्वता पर पूंजीगत लाभ कर से मुक्त)।

• **व्याख्या:** भौतिक सोने के आयात को कम करने के लिए नवंबर 2015 में SGB योजना शुरू की गई थी।

39. **[SBI PO 2024]** 'ग्रीन शू ऑप्शन' (Green Shoe Option), 'रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस' (RHP) और 'यूनिकॉर्न' (Unicorn) शब्द किससे संबंधित हैं?

• **उत्तर:** ग्रीन शू ऑप्शन: IPO में अधिक मांग होने पर निर्धारित शेयरों से अधिक (सामान्यतः 15% तक) शेयर आवंटित करने व मूल्य स्थिर रखने का प्रावधान; रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस: IPO से पूर्व कंपनी द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें शेयरों की संख्या तो होती है पर अंतिम मूल्य (Issue Price) नहीं होता; यूनिकॉर्न: वह निजी स्टार्टअप कंपनी जिसका मूल्यांकन **1 बिलियन डॉलर ($1 Billion)** या अधिक हो गया हो।

• **व्याख्या:** $10 बिलियन से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप को 'डेकाकॉर्न' (Decacorn) कहते हैं।

40. **[IBPS Clerk 2024]** 'नोस्त्रो खाता' (Nostro Account) और 'वोस्त्रो खाता' (Vostro Account) में क्या अंतर है?

• **उत्तर:** नोस्त्रो खाता ("*Our account with you*"): किसी भारतीय बैंक द्वारा विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में खोला गया खाता (जैसे SBI का न्यूयॉर्क के सिटीबैंक में डॉलर खाता); वोस्त्रो खाता ("*Your account with us*"): किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में किसी भारतीय बैंक में **भारतीय रुपये (INR)** में खोला गया खाता।

• **व्याख्या:** रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार (International Trade Settlement in INR) के लिए RBI ने 'स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट' (SRVA) की अनुमति दी है; जब कोई तीसरा बैंक इन दोनों के खाते का संदर्भ लेता है तो उसे 'लोरो खाता' (Loro Account — "*Their account with them*") कहते हैं!

41. **[RRB PO 2024]** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) की संशोधित परिभाषा (1 जुलाई 2020 से लागू, तथा बजट 2025-26 में विस्तारित) के अनुसार निवेश और वार्षिक टर्नओवर के मानदंड क्या हैं?

• **उत्तर:** 2020 मानक (विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए एकसमान):

• **सूक्ष्म (Micro):** निवेश ≤ ₹1 करोड़ और टर्नओवर ≤ ₹5 करोड़;

• **लघु (Small):** निवेश ≤ ₹10 करोड़ और टर्नओवर ≤ ₹50 करोड़;

• **मध्यम (Medium):** निवेश ≤ ₹50 करोड़ और टर्नओवर ≤ ₹250 करोड़।

• **व्याख्या:** MSME पंजीकरण हेतु सरकार ने 'उद्यम पोर्टल' (Udyam Registration Portal) और विवाद समाधान हेतु 'चैंपियंस पोर्टल' व 'समाधान पोर्टल' शुरू किया है; TReDS (Trade Receivables Discounting System — RXIL, M1xchange, Invoicemart) MSME के बिलों को भुनाने का प्लेटफॉर्म है।

42. **[IBPS PO 2024]** प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY — 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ, Micro Units Development & Refinance Agency) के तहत 'शिशु', 'किशोर', 'तरुण' और नए जोड़े गए 'तरुण प्लस' (Tarun Plus) ऋण की सीमाएं क्या हैं?

• **उत्तर:** शिशु: ₹50,000 तक; किशोर: ₹50,001 से ₹5 लाख तक; तरुण: ₹5 लाख से ₹10 लाख तक; और **तरुण प्लस (बजट 2024-25 में घोषित): ₹10 लाख से ₹20 लाख तक** (उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने पूर्व का तरुण ऋण सफलतापूर्वक चुका दिया है)!

• **व्याख्या:** मुद्रा योजना में बिना किसी गारंटी (Collateral-free) के गैर-कृषि लघु व्यवसाय ऋण दिए जाते हैं।

43. **[SBI Clerk Mains]** भुगतान संतुलन (Balance of Payments — BoP) के दो मुख्य खाते कौन-से हैं और 'चालू खाता घाटा' (CAD — Current Account Deficit) किसे कहते हैं?

• **उत्तर:** चालू खाता (Current Account — वस्तुओं का आयात-निर्यात/दृश्य मदें + सेवाओं का व्यापार, निवेश आय व प्रेषण/अदृश्य मदें) और पूंजी खाता (Capital Account — FDI, FPI, बाह्य वाणिज्यिक उधार ECB व NRI जमा)। जब किसी देश का वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात उसके कुल निर्यात से अधिक होता है, तो उसे चालू खाता घाटा (CAD) कहते हैं।

• **व्याख्या:** विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से धन प्रेषण (Remittances — सर्वाधिक प्राप्ति भारत को >$120 बिलियन) चालू खाते के 'अदृश्य हस्तांतरण' (Secondary Income) का भाग है।

44. **[SSC CGL 2024]** भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves — जिसका संरक्षक RBI है) के 4 घटक कौन-से हैं?

• **उत्तर:** 1. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA — सबसे बड़ा घटक), 2. स्वर्ण भंडार (Gold), 3. विशेष आहरण अधिकार (SDR — IMF की 'पेपर गोल्ड' मुद्रा), और 4. IMF के पास आरक्षित ट्रेंच स्थिति (Reserve Tranche Position - RTP)।

• **व्याख्या:** IMF की SDR बास्केट में 5 मुद्राएं शामिल हैं — अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन (रेनमिनबी - 2016 में शामिल), जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग।

45. **[IBPS PO 2024]** भारत सरकार के बजट में 'राजकोषीय घाटा' (Fiscal Deficit), 'राजस्व घाटा' (Revenue Deficit) और 'प्राथमिक घाटा' (Primary Deficit) के सूत्र क्या हैं?

• **उत्तर:**

• राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियां

• राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां) — अर्थात सरकार की कुल उधारी आवश्यकता!

• प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान (Interest Payments)

• **व्याख्या:** FRBM अधिनियम, 2003 (एन.के. सिंह समीक्षा समिति) का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को अनुशासित सीमा में रखना है।

46. **[RBI Grade B]** भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI — Combined) कौन जारी करता है और इनके आधार वर्ष क्या हैं?

• **उत्तर:** WPI: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय (DPIIT — आधार वर्ष 2011-12, इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, सेवाएं नहीं); CPI (Combined): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** — आधार वर्ष 2012 (इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं)।

• **व्याख्या:** औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI-IW (आधार वर्ष 2016) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 'लेबर ब्यूरो' द्वारा जारी किया जाता है।

47. **[IBPS Clerk 2024]** भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (Annual Financial Statement — केंद्रीय बजट) का उल्लेख है, और रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष मिलाया गया?

• **उत्तर:** अनुच्छेद 112 (संविधान में 'बजट' शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है); वर्ष 2017-18 के बजट में **विवेक देबरॉय समिति** की सिफारिश पर 92 साल पुरानी परंपरा (1924 की एकवर्थ समिति द्वारा अलग किए गए रेल बजट) को समाप्त कर आम बजट में मिला दिया गया।

• **व्याख्या:** स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षण्मुखम चेट्टी ने और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था; सर्वाधिक 10 बार बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया।

48. **[SBI PO 2024]** GST (वस्तु एवं सेवा कर — 'एक राष्ट्र, एक कर') किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और किस तिथि से लागू हुआ, तथा GST परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?

• **उत्तर:** 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 (**विजय केलकर समिति** की सिफारिश पर); **1 जुलाई 2017** से लागू; **अनुच्छेद 279A** के तहत GST परिषद (अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री) का गठन।

• **व्याख्या:** GST परिषद में केंद्र का मतभार 1/3 और सभी राज्यों का मिलाकर 2/3 होता है, तथा किसी भी निर्णय के लिए 3/4 (75%) भारित बहुमत आवश्यक है; असम GST विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य था।

49. **[IBPS PO Mains]** 'अकाउंट एग्रीगेटर' (AA) नेटवर्क क्या है और इसे किस श्रेणी की NBFC के रूप में लाइसेंस दिया जाता है?

• **उत्तर:** अकाउंट एग्रीगेटर (NBFC-AA) RBI द्वारा विनियमित एक डिजिटल डेटा-शेयरिंग ढांचा है, जो ग्राहक की स्पष्ट डिजिटल सहमति (Consent) से उसके बैंक, बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन और GST के वित्तीय डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप में ऋणदाता (FIU) को सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराता है।

• **व्याख्या:** AA स्वयं ग्राहक के डेटा को न तो पढ़ सकता है (Data-blind) और न ही स्टोर या बेच सकता है।

50. **[RRB Scale-I]** 'किसान विकास पत्र' (KVP), 'सुकन्या समृद्धि योजना' (SSY) और 'लोक भविष्य निधि' (PPF) में न्यूनतम व अधिकतम जमा सीमा तथा परिपक्वता नियम क्या हैं?

• **उत्तर:**

• **सुकन्या समृद्धि योजना (SSY — 22 जनवरी 2015, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का भाग):** 10 वर्ष से कम आयु की बालिका हेतु (अधिकतम 2 बेटियां), न्यूनतम ₹250/वर्ष व अधिकतम ₹1.5 लाख/वर्ष, 15 वर्ष तक जमा और खाता खुलने से 21 वर्ष में परिपक्व (EEE कर-मुक्त श्रेणी)।

• **PPF (1968):** न्यूनतम ₹500 व अधिकतम ₹1.5 लाख/वर्ष, परिपक्वता अवधि 15 वर्ष।

• **व्याख्या:** वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में अधिकतम जमा सीमा ₹15 लाख से बढ़ाकर **₹30 लाख** कर दी गई है और 'महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र' में 2 वर्ष के लिए ₹2 लाख तक 7.5% ब्याज मिलता है।

51. **[IBPS PO 2024]** भारत में राष्ट्रीय आय (National Income) का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था और 'राष्ट्रीय आय समिति' (1949) के अध्यक्ष कौन थे?

• **उत्तर:** सर्वप्रथम अनुमान: दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 में अपनी पुस्तक *Poverty and Un-British Rule in India* में (प्रति व्यक्ति आय ₹20 बताई); वैज्ञानिक पद्धति से प्रथम अनुमान: प्रो. वी.के.आर.वी. राव (1931-32); और 1949 की राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष: **प्रो. पी.सी. महालनोबिस**।

• **व्याख्या:** वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना NSO (आधार वर्ष 2011-12) द्वारा तीन विधियों — उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि — से की जाती है।

52. **[SBI Clerk 2024]** 'बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया' (BCSBI) और 'भारतीय बैंक संघ' (IBA — स्थापना 1946, मुंबई) का मुख्य कार्य क्या है?

• **उत्तर:** IBA भारत में कार्यरत बैंकों का एक स्वैच्छिक प्रतिनिधि संघ है जो बैंकिंग कर्मियों के वेतन समझौते और अंतर-बैंक समन्वय करता है; जबकि तारापोर समिति की सिफारिश पर 2006 में गठित BCSBI ग्राहकों के प्रति बैंकों की सेवा प्रतिबद्धताओं की निगरानी करता था (जिसे बाद में RBI के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग CEPD में समाहित कर दिया गया)।

• **व्याख्या:** IDRBT (बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान — हैदराबाद, 1996) ने ही भारत में INFINET और NEFT/RTGS की तकनीकी नींव रखी थी।

53. **[IBPS SO]** 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (MDR) और 'इंटरचेंज शुल्क' (Interchange Fee) किसे कहते हैं?

• **उत्तर:** MDR वह शुल्क है जो कोई व्यापारी (Merchant) अपने स्टोर पर ग्राहक से डेबिट या क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के बदले बैंक को चुकाता है; और उस शुल्क का जो हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंक (Issuing Bank) को POS मशीन लगाने वाले बैंक (Acquiring Bank) से मिलता है, उसे इंटरचेंज शुल्क कहते हैं।

• **व्याख्या:** डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI पर MDR को **शून्य (0%)** कर रखा है।

54. **[RBI Grade B 2024]** 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन' (PCA) ढांचा, जिसे RBI ने 2002 में शुरू किया और नवंबर 2021 में संशोधित किया (अक्टूबर 2022 से बड़ी NBFCs पर भी लागू), में बैंक के प्रदर्शन को मापने के लिए कौन-से 3 जोखिम संकेतकों (Risk Thresholds 1, 2, 3) की निगरानी की जाती है?

• **उत्तर:** 1. पूंजी (CRAR और CET-1 अनुपात), 2. परिसंपत्ति गुणवत्ता (Net NPA अनुपात), और 3. लीवरेज (Tier-1 Leverage Ratio)।

• **व्याख्या:** संशोधित PCA ढांचे में से 'रिटर्न ऑन एसेट्स' (RoA — लाभप्रदता) को संकेतक सूची से हटा दिया गया है; PCA क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और भुगतान बैंकों पर लागू नहीं होता।

55. **[IBPS PO 2024]** 'Factoring' और 'Forfaiting' में क्या अंतर है?

• **उत्तर:** फैक्टरिंग (Factoring) में कोई व्यवसाय अपने घरेलू या अल्पकालिक प्राप्य बिलों (Accounts Receivable — सामान्यतः 90 से 180 दिन) को किसी वित्तीय संस्था (Factor) को बट्टे पर बेचकर तुरंत नकदी प्राप्त करता है (यह With Recourse या Without Recourse दोनों हो सकता है); जबकि फॉरफेटिंग (Forfaiting) **अंतरराष्ट्रीय व्यापार (निर्यात)** में मध्यम से दीर्घकालिक पूंजीगत वस्तुओं के प्राप्य बिलों को **100% Without Recourse** (अर्थात पूर्ण जोखिम फॉरफेटर का) आधार पर भुनाने की प्रक्रिया है।

• **व्याख्या:** भारत में फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 (संशोधन 2021) लागू है।

56. **[SBI PO 2024]** 'Call Money', 'CBLO / TREPS' और 'Commercial Bills' किस बाजार के साधन हैं?

• **उत्तर:** मुद्रा बाजार (Money Market)।

• **व्याख्या:** CCIL (Clearing Corporation of India Ltd. — 2001) ने CBLO (Collateralized Borrowing and Lending Obligation) के स्थान पर 2018 से **TREPS (Tri-Party Repo Dealing System)** लागू कर दिया है।

57. **[IBPS Clerk Mains]** 'Bancassurance', 'Mutual Fund' (भारत का प्रथम म्यूचुअल फंड: **UTI — 1963**) और 'ULIP' का नियामक कौन है?

• **उत्तर:** बैंकाश्योरेंस: RBI और IRDAI दोनों; म्यूचुअल फंड: **SEBI** (AMFI — Association of Mutual Funds in India इसका उद्योग संघ है); और ULIP (Unit Linked Insurance Plan — बीमा + निवेश का मिश्रित उत्पाद): **IRDAI**।

• **व्याख्या:** 2010 में ULIP के नियमन को लेकर SEBI और IRDAI के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश लाकर स्पष्ट किया कि ULIP का नियमन IRDAI ही करेगा।

58. **[RRB PO Mains]** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS — 1 जनवरी 2004 से सरकारी कर्मचारियों व 2009 से सभी नागरिकों हेतु) और अटल पेंशन योजना (APY — 9 मई 2015) का नियामक कौन है?

• **उत्तर:** PFRDA (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण — स्थापना 2003, वैधानिक दर्जा PFRDA अधिनियम 2013 द्वारा, मुख्यालय: नई दिल्ली)।

• **व्याख्या:** अटल पेंशन योजना (आयु 18–40 वर्ष, असंगठित क्षेत्र के गैर-आयकरदाता श्रमिकों हेतु) में 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 (₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000, ₹5000) की गारंटीकृत मासिक पेंशन मिलती है; सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से **एकीकृत पेंशन योजना (UPS — Unified Pension Scheme)** भी लागू की है जिसमें 25 वर्ष की सेवा पर अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलता है!

59. **[IBPS PO 2024]** 'G-Sec' (सरकारी प्रतिभूतियों) की नीलामी के लिए RBI के कोर बैंकिंग समाधान **'ई-कुबेर' (e-Kuber)** पर इस्तेमाल होने वाली दो बोलियां — 'Competitive Bidding' और 'Non-Competitive Bidding' — किसके लिए हैं?

• **उत्तर:** कॉम्पिटिटिव बिडिंग: बड़े संस्थागत निवेशकों (बैंकों, बीमा कंपनियों, प्राइमरी डीलरों) के लिए जो अपनी यील्ड/मूल्य की बोली लगाते हैं; नॉन-कॉम्पिटिटिव बिडिंग: **खुदरा निवेशकों (Retail Investors)** के लिए जिन्हें बिना बोली लगाए भारित औसत मूल्य पर निश्चित आवंटन (कुल इश्यू का 5% आरक्षित) मिलता है।

• **व्याख्या:** ई-कुबेर RBI का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) है जिसे 2012 में लागू किया गया था।

60. **[SBI Clerk 2024]** विश्व आर्थिक मंच (WEF), IMF और विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख वार्षिक रिपोर्टें कौन-सी हैं?

• **उत्तर:**

• **IMF:** *World Economic Outlook* (*WEO*) और *Global Financial Stability Report* (*GFSR*);

• **World Bank:** *World Development Report* (*WDR*) और *Global Economic Prospects* (*GEP*);

• **WEF (दावोस):** *Global Competitiveness Report*, *Global Gender Gap Report* और *Global Risks Report*।

• **व्याख्या:** 'मानव विकास सूचकांक' (HDI — पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा 1990 में विकसित) **UNDP** द्वारा जारी किया जाता है।

61. **[IBPS PO Mains]** भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank — स्थापना 1 जनवरी 1982, मुख्यालय मुंबई) और 'ECGC' (Export Credit Guarantee Corporation of India — 1957, मुंबई) के कार्यों में क्या अंतर है?

• **उत्तर:** EXIM बैंक आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता और ऋण (Lines of Credit) प्रदान करता है, जबकि ECGC वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय निर्यातकों को विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न किए जाने के जोखिम के विरुद्ध **निर्यात ऋण बीमा (Export Credit Insurance)** और बैंकों को गारंटी प्रदान करता है।

• **व्याख्या:** सरकार ने निर्यात अवसंरचना और बीमा को मजबूत करने के लिए 'NIRVIK योजना' (निर्यात ऋण विकास योजना) भी शुरू की है।

62. **[RBI Grade B]** भारत का 5वां अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI — All India Financial Institution) कौन-सा बना है?

• **उत्तर:** NaBFID (National Bank for Financing Infrastructure and Development — राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक, स्थापना 2021, मुख्यालय: मुंबई)।

• **व्याख्या:** RBI के अधीन अब कुल **5 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs)** हैं — 1. EXIM Bank (1982), 2. NABARD (1982), 3. NHB (1988), 4. SIDBI (1990) और 5. NaBFID (2021)!

63. **[IBPS Clerk 2024]** 'PM SVANidhi' (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि — 1 जून 2020 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ) योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन है और इसमें तीन किस्तों में कितना कार्यशील पूंजी ऋण मिलता है?

• **उत्तर:** कार्यान्वयन एजेंसी: **SIDBI**; प्रथम किस्त: **₹10,000**, समय पर चुकाने पर द्वितीय किस्त: **₹20,000**, और तृतीय किस्त: **₹50,000** (7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन पर ₹1,200/वर्ष तक कैशबैक सहित)।

• **व्याख्या:** इसी प्रकार पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों (18 व्यवसायों) के लिए 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई **'पीएम विश्वकर्मा योजना'** में 5% रियायती ब्याज पर प्रथम चरण में ₹1 लाख और दूसरे चरण में ₹2 लाख (कुल ₹3 लाख) का ऋण तथा ₹15,000 का ई-वाउचर टूलकिट प्रोत्साहन मिलता है।

64. **[SBI PO 2024]** प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY — 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना, नारा: 'मेरा खाता, भाग्य विधाता') के तहत मिलने वाली ओवरड्राफ्ट (OD) सीमा और RuPay कार्ड दुर्घटना बीमा कवर कितना है?

• **उत्तर:** ओवरड्राफ्ट (OD) सीमा: **₹10,000** (पहले ₹5,000 थी; ₹2,000 तक बिना किसी शर्त के, आयु सीमा 18–65 वर्ष); RuPay डेबिट कार्ड दुर्घटना बीमा कवर: **₹2 लाख** (28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों पर; उससे पूर्व ₹1 लाख)।

• **व्याख्या:** जन-धन खाते को 'BSBDA' (Basic Savings Bank Deposit Account — शून्य बैलेंस खाता) के रूप में खोला जाता है और 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग का भी खाता खोला जा सकता है।

65. **[IBPS PO 2024]** 'M-Cap' (बाजार पूंजीकरण), 'IPO', 'FPO' और 'OFS' (Offer for Sale) क्या हैं?

• **उत्तर:** बाजार पूंजीकरण ($Market Cap = कंपनी के कुल बकाया शेयरों की संख्या × एक शेयर का वर्तमान बाजार मूल्य$); IPO (Initial Public Offering): जब कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार आम जनता को शेयर जारी कर स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होती है; FPO (Follow-on Public Offer): जब पहले से सूचीबद्ध कंपनी पुनः नए शेयर जारी करती है; OFS: जब कंपनी के प्रवर्तक (Promoters) बिना नए शेयर छापे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी मौजूदा हिस्सेदारी घटाते हैं।

• **व्याख्या:** SEBI के नियमों के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (Minimum Public Shareholding - MPS) कम से कम **25%** होनी चाहिए (अर्थात प्रवर्तकों की हिस्सेदारी अधिकतम 75% हो सकती है)।

अध्याय 3: संपूर्ण बीमा जागरूकता — LIC, GIC, IRDAI *एवं बीमा शब्दावली (प्रश्न 66–100)*

66. **[LIC AAO 2024]** भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर और किस अधिनियम के तहत हुई?

• **उत्तर:** आर.एन. मल्होत्रा समिति (1993-94); IRDA अधिनियम, 1999 (स्थापना: अप्रैल 2000; मुख्यालय 2001 में नई दिल्ली से **हैदराबाद** स्थानांतरित किया गया)।

• **व्याख्या:** बीमा अधिनियम, 1938 भारत में बीमा क्षेत्र का मूल विधान है।

67. **[NIACL AO 2024]** भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहां है और मई 2022 में आए इसके ऐतिहासिक IPO में सरकार ने अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी?

• **उत्तर:** 1 सितंबर 1956 को (LIC अधिनियम, 1956 के तहत); मुख्यालय: मुंबई ('योगक्षेम' भवन); मई 2022 के IPO में सरकार ने अपनी 3.5% हिस्सेदारी (₹21,000 करोड़) बेची।

• **व्याख्या:** LIC के अध्यक्ष पद के स्थान पर अब सरकार ने 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक' (CEO & MD — प्रथम सिद्धार्थ मोहंती) का पद सृजित कर दिया है।

68. **[LIC ADO 2024]** भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल कितनी साधारण बीमा (Non-Life / General Insurance) कंपनियां हैं और उनके मुख्यालय कहां हैं?

• **उत्तर:** 4 साधारण बीमा कंपनियां + 2 विशेषीकृत बीमा कंपनियां:

1. **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. (NIACL):** मुंबई (1919 में दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित — भारत की सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी);
2. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. (NICL):** कोलकाता (1906 — भारत की सबसे पुरानी विद्यमान साधारण बीमा कंपनी);
3. **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. (OICL):** नई दिल्ली (1947);
4. **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. (UIIC):** चेन्नई (1938);

विशेषीकृत: **AIC (Agriculture Insurance Company of India — 2002, नई दिल्ली)** और **ECGC (1957, मुंबई)**।

• **व्याख्या:** GIC Re (मुंबई, 1972) सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी है।

69. **[LIC AAO Mains]** बीमा में 'Indemnity' (क्षतिपूर्ति) और 'Subrogation' (प्रत्यासन) के सिद्धांत किस प्रकार के बीमा पर लागू नहीं होते और क्यों?

• **उत्तर: जीवन बीमा (Life Insurance)** और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पर लागू नहीं होते, क्योंकि मानव जीवन या अंग की क्षति का वास्तविक मौद्रिक मूल्यांकन असंभव है।

• **व्याख्या:** जीवन बीमा एक 'आश्वासन अनुबंध' (Contract of Assurance / Contingent Contract) है जिसमें मृत्यु या परिपक्वता होने पर पूर्व-निर्धारित बीमा राशि (Sum Assured) का पूर्ण भुगतान किया जाता है।

70. **[UIIC AO 2024]** बीमा शब्दावली में 'Peril' (जोखिम का कारण), 'Hazard' (जोखिम बढ़ाने वाली स्थिति) और 'Deductible' (कटौती योग्य राशि) का क्या अर्थ है?

• **उत्तर:** Peril: वह घटना जिससे वास्तविक क्षति होती है (जैसे आग लगना, बाढ़, चोरी, कार दुर्घटना); Hazard: वह स्थिति जो Peril की संभावना या गंभीरता को बढ़ा देती है (जैसे कार के ब्रेक खराब होना = Physical Hazard, बीमित का बेईमान होना = Moral Hazard, बीमा होने के कारण लापरवाह हो जाना = Morale Hazard); Deductible: दावे की वह प्रारंभिक निश्चित राशि जो बीमा कंपनी के भुगतान से पहले पॉलिसीधारक को स्वयं अपनी जेब से वहन करनी होती है।

• **व्याख्या:** Deductible रखने से छोटे-मोटे दावे कम होते हैं और बीमित व्यक्ति सावधानी बरतता है।

71. **[LIC AAO 2024]** 'Surrender Value' (समर्पण मूल्य), 'Paid-up Value' (चुकता मूल्य) और 'Free-Look Period' (फ्री-लुक अवधि) किसे कहते हैं?

• **उत्तर:**

• **Surrender Value:** यदि पॉलिसीधारक परिपक्वता से पहले ही पॉलिसी बंद कर देता है, तो कंपनी द्वारा उसे लौटाई जाने वाली नकद राशि (कम से कम 2 पूर्ण वर्षों का प्रीमियम भरने के बाद ही देय);

• **Paid-up Value:** जब पॉलिसीधारक प्रीमियम देना बंद कर देता है किंतु पॉलिसी सरेंडर नहीं करता, तो पॉलिसी कम बीमा राशि (Reduced Sum Assured) के साथ परिपक्वता तक चालू रहती है;

• **Free-Look Period:** पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तिथि से **30 दिन** (IRDAI के 2024 के नए मास्टर सर्कुलर में इसे 15 दिन से बढ़ाकर सभी पॉलिसियों हेतु **30 दिन** कर दिया गया है!) की वह अवधि जिसमें ग्राहक शर्तों से असंतुष्ट होने पर पॉलिसी रद्द कर अपना प्रीमियम वापस ले सकता है!

• **व्याख्या:** प्रीमियम की देय तिथि बीतने के बाद बिना पॉलिसी लैप्स हुए प्रीमियम जमा करने के लिए मिलने वाले अतिरिक्त समय को **'ग्रेस पीरियड' (Grace Period — मासिक प्रीमियम हेतु 15 दिन, और तिमाही/छमाही/वार्षिक प्रीमियम हेतु 30 दिन)** कहते हैं।

72. **[NIACL Assistant]** 'Actuary' (बीमांकक) कौन होता है और 'Underwriting' (जोखिम अंकन) क्या है?

• **उत्तर:** Actuary वह गणितीय और सांख्यिकीय विशेषज्ञ होता है जो मृत्यु दर तालिका (Mortality Table), संभाव्यता और ब्याज दरों का विश्लेषण करके बीमा उत्पादों का प्रीमियम, रिजर्व और बोनस निर्धारित करता है; जबकि Underwriting वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीमा कंपनी किसी प्रस्तावक के जोखिम का मूल्यांकन कर यह तय करती है कि उसे बीमा दिया जाए या नहीं और किस प्रीमियम दर पर दिया जाए।

• **व्याख्या:** भारत में बीमांककों का वैधानिक संस्थान 'Institute of Actuaries of India' (IAI — मुंबई) है।

73. **[IBPS PO 2024]** किसी देश में बीमा के विकास को मापने के दो वैश्विक मानकों — **'बीमा पैठ' (Insurance Penetration)** और **'बीमा घनत्व' (Insurance Density)** — के सूत्र क्या हैं?

• **उत्तर:**

• $Insurance Penetration (बीमा पैठ \%) = ((देश में एकत्रित कुल बीमा प्रीमियम / देश की कुल GDP)) × 100$

• Insurance Density (बीमा घनत्व \) = (देश में एकत्रित कुल बीमा प्रीमियम (US डॉलर में) / देश की कुल जनसंख्या)$ (अर्थात प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम)।

• **व्याख्या:** परीक्षक अक्सर इन दोनों की परिभाषाओं को आपस में बदलकर प्रश्न पूछते हैं — याद रखें: **Penetration = Percentage of GDP**, और **Density = Dollar per Population**!

74. **[LIC AAO 2024]** 'Term Insurance' (टर्म प्लान), 'Endowment Plan' (बंदोबस्ती बीमा) और 'Whole Life Policy' (आजीवन बीमा) में मुख्य अंतर क्या है?

• **उत्तर:** टर्म प्लान: शुद्ध जोखिम कवर (Pure Protection) जिसमें पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर ही नॉमिनी को बीमा राशि मिलती है और जीवित बचने पर कुछ नहीं मिलता (सबसे कम प्रीमियम, सर्वाधिक कवर; हालांकि TROP में प्रीमियम वापस मिलता है); एंडोमेंट प्लान: बीमा + बचत का संयोजन

जिसमें मृत्यु होने पर या अवधि पूर्ण होने (Maturity) पर दोनों ही स्थितियों में राशि मिलती है; होल लाइफ पॉलिसी: जो बीमित व्यक्ति के पूरे जीवनकाल (99 या 100 वर्ष की आयु तक) तक कवर देती है।

• **व्याख्या:** 'Annuity' (वार्षिकी/पेंशन प्लान) जीवन बीमा के ठीक विपरीत काम करती है — इसमें व्यक्ति एकमुश्त या किस्तों में पैसा जमा करता है और कंपनी उसे जीवित रहने तक नियमित मासिक/वार्षिक पेंशन देती है।

75. **[UIIC AO 2024]** बीमा पॉलिसी में 'Nomination' (नामांकन — बीमा अधिनियम 1938 की **धारा 39**) और 'Assignment' (समनुदेशन — **धारा 38**) में कानूनी अंतर क्या है?

• **उत्तर:** नामांकन (धारा 39) के तहत पॉलिसीधारक केवल उस व्यक्ति (Nominee) को नियुक्त करता है जो उसकी मृत्यु होने पर दावे की राशि प्राप्त करेगा (इसमें पॉलिसीधारक का स्वामित्व बना रहता है); जबकि समनुदेशन (धारा 38) के तहत पॉलिसीधारक (Assignor) पॉलिसी के अपने सभी अधिकार, स्वामित्व और हित किसी दूसरे व्यक्ति या बैंक (Assignee — जैसे होम लोन के बदले पॉलिसी गिरवी रखते समय) को कानूनी रूप से हस्तांतरित कर देता है!

• **व्याख्या:** वैध Assignment होते ही पुराना Nomination स्वतः रद्द (Cancel) हो जाता है (केवल बीमा कंपनी को पॉलिसी लोन के लिए किए गए Assignment को छोड़कर)।

76. **[LIC ADO 2024]** 'Co-insurance' (सह-बीमा), 'Double Insurance' (दोहरा बीमा) और 'Reinsurance' (पुनर्बीमा) में क्या अंतर है?

• **उत्तर:** सह-बीमा: जब किसी बहुत बड़ी औद्योगिक परियोजना के जोखिम को दो या अधिक बीमा कंपनियां आपस में मिलकर निश्चित अनुपात में सीधे साझा करती हैं; दोहरा बीमा: जब कोई व्यक्ति स्वयं एक ही विषय-वस्तु पर दो अलग-अलग कंपनियों से पॉलिसी ले लेता है; पुनर्बीमा: जब एक बीमा कंपनी अपने स्वीकार किए गए जोखिम का एक भाग दूसरी पुनर्बीमा कंपनी (जैसे GIC Re) को हस्तांतरित करती है।

• **व्याख्या:** साधारण बीमा में दोहरा बीमा होने पर 'अंशदान का सिद्धांत' (Contribution) लागू होता है, जबकि जीवन बीमा में व्यक्ति जितनी चाहे उतनी पॉलिसियां ले सकता है और मृत्यु पर सभी पॉलिसियों से पूर्ण दावा मिलता है!

77. **[NIACL AO 2024]** मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारत में सड़कों पर चलने वाले प्रत्येक वाहन के लिए कौन-सा बीमा कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है, और 'हिट एंड रन' मामलों में मुआवजा कितना कर दिया गया है?

• **उत्तर:** तृतीय-पक्ष दायित्व बीमा (Third-Party Liability Insurance — जो वाहन से किसी तीसरे व्यक्ति की मृत्यु, चोट या संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करता है); हिट एंड रन मामलों में मृत्यु पर मुआवजा ₹25,000 से बढ़ाकर **₹2 लाख** और गंभीर चोट पर ₹12,500 से बढ़ाकर **₹50,000** कर दिया गया है।

• **व्याख्या:** वाहन के स्वयं के नुकसान के लिए 'ओन डैमेज' (Own Damage - OD) कवर लिया जाता है; प्रत्येक वर्ष दावा न करने पर नवीनीकरण प्रीमियम में मिलने वाली छूट को **'नो क्लेम बोनस' (NCB — 20% से 50% तक)** कहते हैं।

78. **[LIC AAO 2024]** IRDAI की 'बीमा लोकपाल योजना' (Insurance Ombudsman — बीमा लोकपाल नियम, 2017) के तहत देश में कितने बीमा लोकपाल कार्यालय हैं और वे अधिकतम कितने रुपये तक के दावों का निपटारा कर सकते हैं?

• **उत्तर:** देश भर में **17 बीमा लोकपाल कार्यालय** हैं; और वे अधिकतम **₹50 लाख** (पहले ₹30 लाख था) तक के बीमा विवादों/शिकायतों का निःशुल्क एवं त्वरित निपटारा कर सकते हैं!

• **व्याख्या:** IRDAI की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली का नाम **'बीमा भरोसा' (Bima Bharosa — पूर्व नाम IGMS)** है।

79. **[IBPS PO 2024]** IRDAI के 'Bima Trinity' (बीमा त्रयी) के तीन स्तंभ — **बीमा सुगम**, **बीमा विस्तार** और **बीमा वाहक** — क्या हैं?

• **उत्तर:**

1. **बीमा सुगम (Bima Sugam):** जीवन, स्वास्थ्य और साधारण बीमा की खरीद, सेवा, पोर्टेबिलिटी और दावा निपटान के लिए वन-स्टॉप डिजिटल ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस ('बीमा का UPI');

2. **बीमा विस्तार (Bima Vistaar):** ग्रामीण और आम परिवारों के लिए जीवन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना और संपत्ति कवर को मिलाकर बनाया गया किफायती 'ऑल-इन-वन' समग्र उत्पाद;

3. **बीमा वाहक (Bima Vahak):** प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व वाला स्थानीय वितरण चैनल जो ग्रामीण घरों तक बीमा पहुंचाएगा।

• **व्याख्या:** IRDAI ने राज्य-वार बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक 'लीड इंश्योरर' (State Insurance Plan) भी नियुक्त किया है।

80. **[SBI PO 2024]** 'आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY, 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से प्रारंभ — विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना) के तहत प्रति परिवार कितना स्वास्थ्य कवर मिलता है और 2024 में इसमें किस आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा गया?

• **उत्तर:** द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती (Secondary & Tertiary Hospitalization) हेतु **₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष** का कैशलेस कवर; 2024 में **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों** (चाहे उनकी आय कुछ भी हो) को 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड' के माध्यम से ₹5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान किया गया है!

• **व्याख्या:** इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी **NHA (National Health Authority)** है।

81. **[NABARD Grade A]** 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY — 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ) के तहत किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दरें (खरीफ, रबी और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए) क्या हैं?

• **उत्तर:** खरीफ फसलों (धान, मक्का, बाजरा आदि) के लिए: **2%**; रबी फसलों (गेहूं, चना, सरसों आदि) के लिए: **1.5%**; और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों (गन्ना, कपास, फल-सब्जी आदि) के लिए: **5%**!

• **व्याख्या:** शेष एक्चुरियल प्रीमियम का भार केंद्र और राज्य सरकारें (सामान्य राज्यों में 50:50 और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात में) वहन करती हैं; वर्ष 2020 से यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए **स्वैच्छिक (Voluntary)** कर दी गई है।

82. **[LIC AAO 2024]** बीमा में 'Rider' (राइडर), 'Floater Policy' (फ्लोटर पॉलिसी) और 'Sub-limit / Co-payment' क्या हैं?

• **उत्तर:** राइडर: मूल बीमा पॉलिसी के साथ थोड़ा अतिरिक्त प्रीमियम देकर जोड़ा जाने वाला वैकल्पिक अतिरिक्त लाभ (जैसे Accidental Death & Disability Rider, Critical Illness Rider, Waiver of Premium Rider); फ्लोटर पॉलिसी: एक ही बीमा राशि (Sum Insured) के अंतर्गत पूरे परिवार के सभी सदस्यों को कवर करने वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी; को-पेमेंट (Co-payment): दावा राशि का वह निश्चित प्रतिशत (जैसे 10% या 20%) जो पॉलिसीधारक को स्वयं चुकाना होता है और शेष 80-90% बीमा कंपनी देती है।

• **व्याख्या:** 2024 में IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा में पूर्व-मौजूदा बीमारियों (Pre-Existing Diseases - PED) की अधिकतम प्रतीक्षा अवधि (Waiting Period) को 48 माह से घटाकर **अधिकतम 36 माह (3 वर्ष)** और मोराटोरियम अवधि को 8 वर्ष से घटाकर **5 वर्ष** कर दिया है!

83. **[NIACL AO]** एक बीमा एजेंट जो केवल एक जीवन बीमा, एक साधारण बीमा और एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकता है उसे 'Tied Agent' कहते हैं; तो उस मध्यस्थ को क्या कहते हैं जो अधिकतम 9 जीवन, 9 साधारण और 9 स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के उत्पाद बेच सकता है?

• **उत्तर:** कॉर्पोरेट एजेंट (Corporate Agent — जैसे बैंक) या **IMF (Insurance Marketing Firm)**।

• **व्याख्या:** इसके विपरीत **'बीमा ब्रोकर' (Insurance Broker)** ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता है और बाजार की किसी भी बीमा कंपनी का उत्पाद ग्राहक के सर्वोत्तम हित में बेच सकता है।

84. **[LIC ADO]** जीवन बीमा पॉलिसी के लैप्स (Lapse) हो जाने के बाद उसे पुनः चालू कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और इसके लिए IRDAI ने कितनी समय-सीमा दी है?

• **उत्तर:** पुनरुज्जीवन (Revival of Policy); पहले अदत्त प्रीमियम (First Unpaid Premium) की तिथि से **5 वर्ष (Non-linked उत्पादों हेतु) और 3 वर्ष (ULIP उत्पादों हेतु)** के भीतर बकाया प्रीमियम और ब्याज चुकाकर पॉलिसी को रिवाइव कराया जा सकता है।

• **व्याख्या:** यदि पॉलिसी रिवाइव नहीं कराई जाती और कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम भरा जा चुका है, तो वह स्वतः 'Reduced Paid-up Policy' में बदल जाती है।

85. **[IBPS PO 2024]** 'Keyman Insurance Policy' (कीमैन बीमा पॉलिसी) क्या है?

• **उत्तर:** यह किसी कंपनी या व्यवसाय द्वारा अपने किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कर्मचारी, निदेशक या विशेषज्ञ (Key Person — जिसकी अचानक मृत्यु या अक्षमता से कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है) के जीवन पर ली जाने वाली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें प्रीमियम कंपनी भरती है और लाभार्थी (Nominee/Beneficiary) भी स्वयं कंपनी ही होती है!

• **व्याख्या:** कीमैन बीमा में केवल 'टर्म प्लान' (बिना किसी बोनस या मैच्योरिटी लाभ के) ही जारी किया जा सकता है।

86. **[UIIC AO]** समुद्री बीमा (Marine Insurance — विश्व का सबसे पुराना बीमा रूप, जिसकी शुरुआत लंदन के लॉयड्स कॉफी हाउस से हुई) के दो मुख्य प्रकार कौन-से हैं?

• **उत्तर:** 1. **Marine Hull Insurance:** जहाज के ढांचे, इंजन और मशीनरी की सुरक्षा के लिए; 2. **Marine Cargo Insurance:** जहाज द्वारा ले जाए जा रहे माल (Cargo) की सुरक्षा के लिए।

• **व्याख्या:** समुद्री यात्रा के दौरान पूरे जहाज और यात्रियों को डूबने से बचाने के लिए कप्तान द्वारा जानबूझकर कुछ भारी माल समुद्र में फेंक देने को **'जेटिसन' (Jettison)** कहते हैं, और इस सामूहिक बलिदान की हानि को सभी पक्षों द्वारा साझा करने को **'जनरल एवरेज' (General Average)** कहते हैं।

87. **[LIC AAO 2024]** भारत में बीमा पॉलिसियों को डीमैट (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में रखने के लिए 'ई-इंश्योरेंस अकाउंट' (eIA) की सुविधा देने वाली 4 अधिकृत 'इंश्योरेंस रिपॉजिटरी' (Insurance Repositories) कौन-सी हैं?

• **उत्तर:** 1. NSDL Database Management Ltd. (NDML), 2. CDSL Insurance Repository Ltd. (CDSL IR), 3. Karvy Insurance Repository Ltd., और 4. CAMS Insurance Repository Services Ltd.।

• **व्याख्या:** एक पॉलिसीधारक केवल **एक ही ई-इंश्योरेंस अकाउंट (eIA)** खोल सकता है जिसमें उसकी सभी कंपनियों की जीवन, स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियां एक साथ सुरक्षित रहती हैं।

88. **[SBI PO 2024]** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार — आयु 18 से 40 वर्ष, मासिक आय ≤ ₹15,000) को 60 वर्ष की आयु के बाद **₹3,000/माह** की पेंशन देने के लिए श्रम मंत्रालय और LIC द्वारा संचालित योजना कौन-सी है?

• **उत्तर:** प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM — 2019)।

• **व्याख्या:** इसी तर्ज पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए **'पीएम किसान मानधन योजना' (PM-KMY)** और छोटे व्यापारियों के लिए **'राष्ट्रीय व्यापारी मानधन योजना'** संचालित है, जिनमें सभी का पेंशन फंड प्रबंधक **LIC** है।

89. **[IBPS Clerk 2024]** केंद्र सरकार द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से शुरू की गई 'पीएम-किसान' (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि और कितनी किस्तों में दी जाती है?

• **उत्तर:** प्रतिवर्ष **₹6,000** (प्रत्येक 4 माह पर **₹2,000 की 3 समान किस्तों** में DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में)।

• **व्याख्या:** यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है।

90. **[RBI Grade B 2024]** RBI के 'फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स' (FI-Index — वित्तीय समावेशन सूचकांक, जो 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है) के तीन मुख्य पैरामीटर और उनके भारांक (Weights) क्या हैं?

• **उत्तर:** 1. **पहुंच (Access):** 35% भारांक, 2. **उपयोग (Usage):** 45% भारांक (सर्वाधिक), और 3. **गुणवत्ता (Quality):** 20% भारांक।

• **व्याख्या:** FI-Index का कोई आधार वर्ष नहीं है और यह प्रतिवर्ष जुलाई माह में मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया जाता है।

91. **[LIC AAO 2024]** बीमा में 'Reinstatement Value Policy', 'Valued Policy' और 'Floating Policy' क्या हैं?

• **उत्तर:** Reinstatement Value Policy (अग्नि बीमा): जिसमें क्षतिग्रस्त संपत्ति के मूल्यह्रास (Depreciation) को काटे बिना उसे ठीक वैसी ही नई संपत्ति से बदलने की लागत दी जाती है; Valued Policy: जिसमें बीमा कराते समय ही दुर्लभ कलाकृतियों, पेंटिंग या आभूषणों का मूल्य दोनों पक्षों की सहमति से तय कर लिया जाता है; Floating Policy: जब किसी व्यापारी का माल एक साथ कई अलग-अलग गोदामों में रखा हो और उन सभी को एक ही पॉलिसी से कवर किया जाए।

• **व्याख्या:** अग्नि बीमा (Fire Insurance) में 'अवमूल्यन खंड' (Average Clause) के तहत यदि किसी ने कम मूल्य का बीमा (Under-insurance) कराया है, तो दावे का भुगतान भी उसी अनुपात में कम किया जाता है।

92. **[IBPS PO 2024]** 'MUDRA' (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd.) किस वित्तीय संस्थान की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी?

• **उत्तर:** SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक — मुख्यालय: लखनऊ)।

• **व्याख्या:** मुद्रा स्वयं सीधे आम नागरिकों को ऋण नहीं देती, बल्कि यह बैंकों, MFIs और NBFCs को **पुनर्वित्त (Refinance)** उपलब्ध कराती है।

93. **[SBI PO Mains]** 'Sovereign Green Bonds' (सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड), 'Blue Bonds' और 'Masala Bonds' में क्या अंतर है?

• **उत्तर:** सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड: सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा और हरित पर्यावरण परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु जारी बॉन्ड; ब्लू बॉन्ड: समुद्री और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु जारी बॉन्ड (सेशेल्स ने 2018 में विश्व का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड जारी किया); मसाला बॉन्ड: विदेशों में भारतीय रुपये (INR) में जारी बॉन्ड।

• **व्याख्या:** जापान में विदेशी संस्थाओं द्वारा येन में जारी बॉन्ड को 'समुराई बॉन्ड', ब्रिटेन में पाउंड में जारी बॉन्ड को 'बुलडॉग बॉन्ड', चीन में रेनमिनबी में जारी बॉन्ड को 'पांडा बॉन्ड' और अमेरिका में डॉलर में जारी बॉन्ड को 'यांकी बॉन्ड' कहते हैं!

94. **[IBPS Clerk 2024]** बैंकिंग में 'CASA अनुपात' (CASA Ratio) क्या है और उच्च CASA अनुपात बैंक के लिए क्यों फायदेमंद होता है?

• **उत्तर:** $CASA Ratio = (चालू खाता जमा (Current Account) + बचत खाता जमा (Savings Account) / बैंक की कुल जमा राशि (Total Deposits))$। चूंकि बैंक चालू खाते (Current Account) पर **0% ब्याज** और बचत खाते (Savings Account) पर बहुत कम (2.7%–3.5%) ब्याज देते हैं (जबकि FD/RD पर 6.5%–7.5% ब्याज देना पड़ता है), इसलिए उच्च CASA अनुपात से बैंक की धन जुटाने की लागत (Cost of Funds) कम हो जाती है और शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM — Net Interest Margin) बढ़ जाता है!

• **व्याख्या:** चालू और बचत खातों को 'मांग जमा' (Demand Deposits) और सावधि व आवर्ती खातों (FD/RD) को 'सावधि जमा' (Time/Term Deposits — **RAFA**) कहते हैं।

95. **[LIC AAO 2024]** 'Cashless Claim' और 'Reimbursement Claim' (स्वास्थ्य बीमा में) का समन्वय करने वाली मध्यस्थ संस्था को क्या कहते हैं जिसे IRDAI द्वारा लाइसेंस दिया जाता है?

• **उत्तर:** TPA (Third Party Administrator — तृतीय पक्ष प्रशासक)।

• **व्याख्या:** IRDAI ने 2024 के नए दिशानिर्देशों में स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि अस्पताल में कैशलेस भर्ती की मंजूरी **1 घंटे के भीतर** और डिस्चार्ज के समय अंतिम दावा मंजूरी **3 घंटे के भीतर** दी जानी चाहिए!

96. **[RRB Scale-I]** भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 'Kisan Credit Card' (KCC) के तहत किसानों को कितने रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर 3% समय पर भुगतान प्रोत्साहन (Prompt Repayment Incentive) मिलने के बाद प्रभावी ब्याज दर मात्र **4% प्रति वर्ष** पड़ती है?

• **उत्तर: ₹3 लाख** तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर।

• **व्याख्या:** मूल ब्याज दर 9% होती है, जिस पर सरकार 2% ब्याज सबवेंशन देती है (प्रभावी 7%) और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त छूट मिलती है जिससे उन्हें मात्र 4% ब्याज देना पड़ता है; तथा ₹1.60 लाख (अब ₹2 लाख तक विस्तारित) के फसल ऋण पर किसी गारंटी/गिरवी (Collateral) की आवश्यकता नहीं होती।

97. **[IBPS PO 2024]** 'Electoral Bonds' (चुनावी बॉन्ड योजना — 2018 में प्रारंभ, जिसे केवल भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा जारी किया जाता था) को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कब और किस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया?

• **उत्तर:** 15 फरवरी 2024 को (5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा — *Association for Democratic Reforms vs. Union of India*); संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत मतदाताओं के 'सूचना के अधिकार' (Right to Information) के उल्लंघन के आधार पर।

• **व्याख्या:** सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और कंपनी अधिनियम की संबंधित संशोधन धाराओं को भी निरस्त कर दिया।

98. **[SBI PO 2024]** धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA — Prevention of Money Laundering Act, 2002, जो 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA — 1999, जो 1 जून 2000 से FERA 1973 के स्थान पर लागू हुआ) का प्रवर्तन कौन-सी एजेंसी करती है?

• **उत्तर:** प्रवर्तन निदेशालय (ED — Directorate of Enforcement, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन; मुख्यालय: नई दिल्ली)।

• **व्याख्या:** काले धन को वैध दिखाने की मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं — **1. Placement (प्लेसमेंट)** -> **2. Layering (लेयरिंग)** -> **3. Integration (इंटीग्रेशन)**!

99. **[LIC AAO 2024]** बीमा में 'Bancassurance' समझौते के तहत एक बैंक अपने ग्राहकों को अधिकतम कितनी बीमा कंपनियों के उत्पाद बेच सकता है?

• **उत्तर:** अधिकतम **27 बीमा कंपनियों** के (9 जीवन बीमा + 9 साधारण बीमा + 9 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियां — 2022 के IRDAI संशोधित नियमों के अनुसार, पहले यह सीमा 3-3 कंपनियों अर्थात कुल 9 थी)!

• **व्याख्या:** इससे बैंक ग्राहकों को एक ही शाखा में विविध कंपनियों की पॉलिसियों की तुलना करने का विकल्प मिलता है।

100. **[IBPS PO Mains 2024]** वैश्विक वित्तीय अपराध और आतंकवादी वित्तपोषण पर नजर रखने वाली अंतर-सरकारी संस्था **FATF (Financial Action Task Force — स्थापना 1989 G7 द्वारा, मुख्यालय: पेरिस)** की दो निगरानी सूचियां कौन-सी हैं और भारत इसका सदस्य कब बना?

• **उत्तर:** दो सूचियां: **ग्रे लिस्ट** (Jurisdictions under Increased Monitoring) और **ब्लैक लिस्ट** (High-Risk Jurisdictions Subject to a Call for Action — जिसमें वर्तमान में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार हैं); भारत वर्ष **2010** में FATF का 34वां पूर्ण सदस्य बना।

• **व्याख्या:** बैंकों में KYC (Know Your Customer — 2002 में प्रारंभ) और AML (Anti-Money Laundering) मानक FATF की सिफारिशों और RBI अधिनियम/PMLA के तहत ही लागू किए जाते हैं।

भाग (ग): बुक 20 का मास्टर एनसाइक्लोपीडिया टेबल (Master Encyclopedia Reference Table)

क्र.	श्रेणी / नियामक	समिति / अधिनियम / धारा / संस्थान	स्थापना / वर्ष / मुख्यालय	मुख्य प्रावधान / सिफारिश / परीक्षा-उन्मुख सूत्र	आधिकारिक संदर्भ लिंक
1	RBI की स्थापना	हिल्टन यंग कमीशन (1926) व RBI एक्ट 1934	1 अप्रैल 1935 (मुंबई — 1937 से)	राष्ट्रीयकरण: 1 जनवरी 1949; धारा 22: नोट निर्गमन; धारा 42(1): CRR; धारा 45ZB: 6-सदस्यीय MPC	RBI Official
2	बैंकिंग विनियमन	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	16 मार्च 1949 (संपूर्ण भारत)	धारा 22: बैंक लाइसेंस; धारा 23: शाखा विस्तार; धारा 24: SLR (अधिकतम 40%); 12 PSBs कार्यरत	RBI Data
3	बैंकिंग समितियां-I	गोरेवाला (1955), नरसिम्हम (1975, 1991, 1998)	अखिल भारतीय बैंकिंग सुधार	गोरेवाला: SBI (1 जुलाई 1955); नरसिम्हम: RRBs (1975 — 50:15:35), NPA मानक, CRAR व बैंकों का विलय	RBI DBIE
4	बैंकिंग समितियां-II	शिवरामन (1982), नचिकेत मोर, उषा थोराट, उर्जित पटेल	वित्तीय समावेशन एवं मौद्रिक नीति	शिवरामन: NABARD (12 जुलाई 1982); नचिकेत मोर: Payments Banks; उषा थोराट: SFBs; उर्जित पटेल: MPC (4%±2%)	RBI DBIE
5	डिजिटल भुगतान	NPCI (भुगतान व निपटान अधिनियम, 2007)	2008 (मुख्यालय: मुंबई)	UPI (2016 - सामान्य ₹1L, विशेष ₹5L), IMPS (₹5L), RuPay, FASTag (RFID), NACH, AePS, BBPS, CTS	NPCI Portal
6	RTGS बनाम NEFT	RBI द्वारा संचालित फंड ट्रांसफर (e-Kuber)	24x7x365 उपलब्ध	RTGS: रियल-टाइम सकल निपटान, न्यूनतम ₹2 लाख; NEFT: 48 आधे घंटे के बैच (DNS), कोई न्यूनतम/अधिकतम सीमा नहीं	NPCI UPI
7	बेसल-III एवं NPA	BIS (बेसल, स्विट्जरलैंड) एवं RBI मानक	CRAR: 9% (+2.5% CCB = 11.5%)	NPA: >90 दिन बकाया (Standard -> Sub-standard ≤12m -> Doubtful >12m -> Loss); SARFAESI (2002), IBC (2016)	RBI Data
8	मुद्रा बाजार	T-Bills, CMB, CP, CD, Call/Notice Money	परिपक्वता ≤ 1 वर्ष (नियामक: RBI)	T-Bills: 91, 182, 364 दिन (न्यूनतम ₹25,000); CP व CD: 7 दिन से 1 वर्ष (न्यूनतम ₹5 लाख); Call Money: 1 दिन	RBI Data
9	पूंजी बाजार व SEBI	SEBI अधिनियम, 1992 (स्थापना: 1988)	मुख्यालय: मुंबई (प्रथम महिला अध्यक्ष: माधबी बुच)	BSE (1875 - SENSEX 30), NSE (1992 फेरवानी समिति - NIFTY 50); डिपॉजिटरी: NSDL व CDSL; T+1 / T+0 निपटान	SEBI Portal
10	5 अखिल भारतीय AIFI	EXIM, NABARD, NHB, SIDBI, NaBFID	मुंबई (3), नई दिल्ली (NHB), लखनऊ (SIDBI)	EXIM (1982), NABARD (1982), NHB (1988), SIDBI (1990), NaBFID (2021 — 5वां AIFI)	RBI Official
11	बीमा इतिहास व LIC	LIC अधिनियम, 1956 एवं GIBNA, 1972	LIC: 1 सितंबर 1956 (मुंबई); GIC: 1972	LIC आदर्श वाक्य: 'योगक्षेमं वहाम्यहम्'; 4 सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियां: NIACL, NICL, OICL, UIIC	RBI Reference

क्र.	श्रेणी / नियामक	समिति / अधिनियम / धारा / संस्थान	स्थापना / वर्ष / मुख्यालय	मुख्य प्रावधान / सिफारिश / परीक्षा-उन्मुख सूत्र	आधिकारिक संदर्भ लिंक
12	बीमा नियामक IRDAI	आर.एन. मल्होत्रा समिति एवं IRDA एक्ट, 1999	अप्रैल 2000 (मुख्यालय: हैदराबाद)	10 सदस्यीय निकाय; बीमा लोकपाल सीमा: ₹50 लाख (17 कार्यालय); Bima Trinity: सुगम, विस्तार, वाहक	RBI Reference
13	बीमा के 7 सिद्धांत	Utmost Good Faith, Insurable Interest, Indemnity	बीमा अधिनियम, 1938 (धारा 38 व 39)	Indemnity व Subrogation जीवन बीमा पर लागू नहीं; धारा 38: Assignment, धारा 39: Nomination; Free-Look: 30 दिन	RBI Data
14	सरकारी बीमा योजनाएं	PMJJBY, PMSBY, APY, AB-PMJAY, PMFBY	2015–2018 (वित्तीय व सामाजिक सुरक्षा)	PMJJBY: ₹436 (18-50 वर्ष, ₹2L); PMSBY: ₹20 (18-70 वर्ष, ₹2L); PMFBY: खरीफ 2%, रबी 1.5%, बागवानी 5%	RBI Data
15	राष्ट्रीय आय व कर	NSO (MoSPI) एवं GST परिषद (अनुच्छेद 279A)	GST: 1 जुलाई 2017 (101वां संशोधन)	NNP_{FC} = राष्ट्रीय आय; राजकोषीय घाटा = कुल उधारी; प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान	RBI DBIE

क्वालिटी ऑडिट, तथ्य सत्यापन एवं बैंकिंग/वित्तीय जागरूकता महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य अपग्रेड पैक (2024–2026)

(क) 10 सबसे अधिक भ्रमित करने वाले बैंकिंग नियम, नवीनतम संशोधन व परीक्षा गलतियाँ

• **1. यूपीआई (UPI) और यूपीआई लाइट (UPI Lite) की नवीनतम लेनदेन सीमाएँ:** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और NPCI के अनुसार सामान्य P2P UPI लेनदेन की सीमा **₹1 लाख** है, किंतु **कर भुगतान (Tax Payment), अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, IPO और RBI Retail Direct के लिए UPI सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति लेनदेन** कर दी गई है। UPI Lite वॉलेट की कुल सीमा **₹5,000** (प्रति लेनदेन **₹1,000**) है।

• **2. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की संख्या (12 बैंक):** 2020 के मेगा विलय के बाद भारत में **कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक** हैं (1 भारतीय स्टेट बैंक + 11 राष्ट्रीयकृत बैंक)।

• **3. बैंक जमा बीमा कवर (DICGC — ₹5 लाख एवं 90 दिन का नियम):** DICGC द्वारा प्रत्येक जमाकर्ता को प्रति बैंक अधिकतम **₹5,00,000 (मूलधन + ब्याज)** का बीमा कवर दिया जाता है और बैंक संकटग्रस्त होने पर **90 दिनों के भीतर** अंतरिम भुगतान अनिवार्य है।

• **4. रेपो दर, MSF, बैंक दर और SDF का अंतर: बैंक दर** और **MSF दर** सदैव समान होती हैं (रेपो दर + **0.25%**)। **SDF (स्थायी जमा सुविधा)** में RBI बिना किसी सरकारी प्रतिभूति (Collateral-free) के बैंकों से अतिरिक्त तरलता अवशोषित करता है (रेपो दर - **0.25%**)।

• **5. NEFT बनाम RTGS के नियम:** दोनों **24×7×365** उपलब्ध हैं। NEFT (48 आधे-आधे घंटे के बैच) में कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, जबकि **RTGS (Real-Time) की न्यूनतम सीमा ₹2,00,000 (2 लाख रुपये)** है।

• **6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में पूंजी अनुपात (50 : 35 : 15):** RRBs (स्थापना: 2 अक्टूबर 1975, प्रथमा बैंक, नरसिंहम समिति) में पूंजी योगदान: **केंद्र सरकार (50%) : प्रायोजक बैंक (35%) : राज्य सरकार (15%)**।

• **7. भुगतान बैंक (Payments Bank) बनाम लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank):** भुगतान बैंक (नचिकेत मोर समिति) **ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते** और अधिकतम **₹2 लाख** जमा ले सकते हैं। लघु वित्त बैंक (उषा थोराट समिति) ऋण दे सकते हैं और इन्हें अपने कुल ऋण का **75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (PSL)** को देना होता है (जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए PSL लक्ष्य **40%** है)।

• **8. बीमा क्षेत्र में FDI सीमा (74%) एवं IRDAI लक्ष्य:** बीमा कंपनियों में FDI की सीमा **74%** (बीमा मध्यस्थों में **100%**) है। IRDAI ने **'2047 तक सभी के लिए बीमा (Insurance for All by 2047)'** का लक्ष्य रखा है।

• **9. मौद्रिक नीति समिति (MPC — धारा 45ZB):** इसमें **6 सदस्य** (3 RBI + 3 सरकार द्वारा नामित) होते हैं। RBI गवर्नर पदेन अध्यक्ष होते हैं और टाई होने पर उन्हें **निर्णायक मत (Casting Vote)** का अधिकार होता है।

• **10. मुद्रा बाजार बनाम पूंजी बाजार: मुद्रा बाजार** (1 वर्ष तक की अवधि— T-Bills [91, 182, 364 दिन], Commercial Paper, Certificate of Deposit) का नियामक **RBI** है, जबकि **पूंजी बाजार** (दीर्घकालिक शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड) का नियामक **SEBI** है।

(ख) नवीनतम बैंकिंग/बीमा परीक्षाओं पर आधारित 15 अति-महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं मास्टर चीट-शीट सारणी

क्र.	परीक्षोपयोगी प्रश्न (IBPS PO/Clerk/RRB, SBI, RBI Grade B, NABARD, LIC AAO, JAIIB)	सटीक एक-पंक्ति उत्तर
1	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर और कब हुई?	**हिल्टन यंग आयोग** की सिफारिश पर **1 अप्रैल 1935** को (राष्ट्रीयकरण: **1 जनवरी 1949**)
2	RBI के प्रथम गवर्नर और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे?	प्रथम: **सर ओसबोर्न स्मिथ**; प्रथम भारतीय: **सर सी. डी. देशमुख (1943)**
3	नाबार्ड (NABARD), सिडबी (SIDBI), सेबी (SEBI) और इरडाई (IRDAI) के मुख्यालय कहाँ हैं?	**NABARD (1982) व SEBI (1988/1992) = मुंबई; SIDBI (1990) = लखनऊ; IRDAI (1999) = हैदराबाद; PFRDA व NHB = नई दिल्ली**
4	किसी ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) कब घोषित किया जाता है और इसकी 3 श्रेणियाँ क्या हैं?	किस्त **90 दिनों से अधिक** बकाया रहने पर; 3 श्रेणियाँ: **Sub-standard (≤12 माह), Doubtful (>12 माह), Loss Asset**

क्र.	परीक्षोपयोगी प्रश्न (IBPS PO/Clerk/RRB, SBI, RBI Grade B, NABARD, LIC AAO, JAIIB)	सटीक एक-पंक्ति उत्तर
5	बेसल-III मानकों के अनुसार भारत में बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR/CRAR) कितना है?	**9%** (अंतरराष्ट्रीय बेसल मानक 8% है; + 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर)
6	सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act, 2002) किस ऋण राशि और किस संपत्ति पर लागू नहीं होता?	**₹1 लाख से कम** के ऋण पर तथा **कृषि भूमि (Agricultural Land)** पर लागू नहीं होता
7	भारत का पहला 'बैड बैंक' (तनावग्रस्त ऋण समाधान संस्था) कौन-सा है?	**NARCL (National Asset Reconstruction Company Ltd.) एवं IDRCL**
8	MICR कोड और IFSC कोड में कितने अंक/अक्षर होते हैं तथा चेक की वैधता कितनी होती है?	**MICR = 9 अंक; IFSC = 11 अल्फ़ान्यूमेरिक वर्ण (5वाँ वर्ण '0')**; चेक/DD की वैधता = **3 माह (90 दिन)**
9	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) में नई 'तरुण प्लस' श्रेणी की ऋण सीमा क्या है?	**शिशु:** ₹50,000 तक; **किशोर:** ₹50,000–5 लाख; **तरुण:** ₹5–10 लाख; **तरुण प्लस: ₹10 लाख से ₹20 लाख तक**
10	भारत में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक (D-SIBs) और बीमाकर्ता (D-SIIs) कौन हैं?	**D-SIBs:** SBI, HDFC Bank, ICICI Bank; **D-SIIs:** LIC, GIC Re, New India Assurance
11	बैंकों में 10 वर्ष से अधिक से निष्क्रिय (Unclaimed Deposits) खातों को खोजने हेतु RBI का पोर्टल कौन-सा है?	**उद्गम पोर्टल (UDGAM — Unclaimed Deposits Gateway to Access inforMation)**
12	शेयर बाजार में लागू नया निपटान चक्र (Settlement Cycle) क्या है?	**T+1 एवं T+0 (Same-Day Instant Settlement Framework)**
13	प्रधानमंत्री जन-धन योजना (28 अगस्त 2014), PMJJBY और PMSBY के मुख्य लाभ क्या हैं?	**PMJDY:** ₹10,000 ओवरड्राफ्ट व ₹2 लाख दुर्घटना बीमा; **PMJJBY (₹436 प्रीमियम, 18–50 वर्ष):** ₹2 लाख जीवन बीमा; **PMSBY (₹20 प्रीमियम, 18–70 वर्ष):** ₹2 लाख दुर्घटना बीमा
14	केंद्र सरकार द्वारा घोषित 'एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS)' में न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन क्या है?	कम से कम **25 वर्ष की सेवा** पर सेवानिवृत्ति पूर्व के 12 माह के औसत मूल वेतन का **50% सुनिश्चित पेंशन** (10 वर्ष सेवा पर न्यूनतम **₹10,000 प्रतिमाह** — PIB)
15	बैंकिंग सुधारों से जुड़ी प्रमुख समितियाँ कौन-सी हैं?	**नरसिंहम** (बैंकिंग सुधार व RRB), **शिवरामन** (NABARD), **मल्होत्रा** (बीमा/IRDAI), **गोरावाला** (SBI), **नचिकेत मोर** (पेमेंट्स बैंक), **उर्जित पटेल** (MPC), **पी.जे. नायक** (BBB/FSIB)